संपादकीय जागरण

गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026: चैत्र शुक्ल पूर्णिमा वि. 2083

कर्मों की गति ही व्यक्ति की नियति निर्धारित करती है

सरकार को फटकार

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अनावश्यक मुकदमा दायर करने के लिए फटकार लगाने के साथ ही उस पर अर्थ दंड भी लगाया। केंद्र सरकार को यह फटकार सीआइएसएफ के एक अधिकारी को सेवा से हटाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने पर सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यह एक गैर जरूरी अपील थी। यह पहला ऐसा मामला नहीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक पाया हो और केंद्र सरकार को फटकारा हो, लेकिन हालात बदल नहीं रहे हैं। 2024 के एक आंकड़े के अनुसार लंबित मामलों में सात लाख से अधिक मामले वे थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने दायर कर रखा था। 2019 में ऐसे मुकदमों की संख्या चार लाख के करीब थी। इसका मतलब है कि सरकार धड़ाधड़ मुकदमे दायर करती है और एक तरह से अपने ही लोगों को अदालतों में घसीटती है। केंद्र सरकार की ओर से सबसे ज्यादा मुकदमे वित्त मंत्रालय ने दायर कर रखे हैं। इसके बाद मुकदमेबाजी में उलझे मंत्रालय क्रमशः रेलवे, रक्षा और श्रम हैं। यदि राज्य सरकारों की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों का भी संज्ञान लिया जाए तो पता चलेगा कि कुल लंबित मामलों में 45 प्रतिशत से अधिक मुकदमे केंद्र और राज्य सरकारों के हैं। यह प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। साफ है कि करोड़ों लंबित मामलों के लिए केवल अदालतें ही दोषी नहीं।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दायर किए गए सभी मुकदमे अनावश्यक होते हैं और जिनके खिलाफ वे दायर किए गए होते हैं, उनकी कहीं कोई गलती नहीं होती, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सरकारें और विशेष रूप से उनका प्रशासन प्रायः छोटी-छोटी बातों को लेकर लोगों या संस्थाओं के खिलाफ मुकदमे दायर कर देता है। आम तौर पर जो अधिकारी मुकदमे दायर कराते हैं, वे कई बार केवल इसलिए ऐसा करते हैं, ताकि मामले विशेष का निपटारा करने में उन्हें अपना सिर न खपाना पड़े। कई बार वे अपने दायित्वों का नीर-क्षीर ढंग से निर्वाह करने के बजाय मामले को अदालत की चौखट तक पहुंचाने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट अतीत में यह टिप्पणी कर चुका है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दायर 40 प्रतिशत से अधिक मुकदमे तुच्छ होते हैं। यह स्थिति तब है, जब वित्त आयोग और नीति आयोग लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए राज्यों को अपनी मुकदमा नीति पर गौर करने की सलाह दे चुके हैं। सरकारें जो मुकदमे दायर करती हैं, उनकी सुनवाई में खर्च होने वाला पैसा जनता का होता है। यह पैसा सीधे जनता की जेब से नहीं जाता तो इसका यह अर्थ नहीं कि सरकारें बात-बात में मुकदमे दायर करें।

जरूरी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने आपरेशन कवच के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर मात्र 48 घंटे में 3211 स्थानों पर छापेमारी कर छह हजार से अधिक हथियार व ड्रग्स तस्करों सहित अन्य असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने के लिए वर्ष 2023 में आपरेशन कवच शुरू किया था। अब इसे पूरे दिल्ली में विस्तार दिया गया है। इस अभियान के लिए 1042 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। इस तरह की सख्त कार्रवाई अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हथियार तस्करी के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, जो नेपाल के रास्ते हथियार लाकर दिल्ली से अन्य शहरों में भेज रहे थे। हथियार तस्करी के साथ ही लाल किला के पास हुए विस्फोट और जासूसी के मामले भी राजधानी की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस को राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आपरेशन कवच जैसे अभियान इसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

राजधानी में संगठित अपराध के साथ-साथ स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और करना होगा मजबूत

संगठित अपराध के साथ-साथ स्ट्रीट क्राइम को रोकना भी पुलिस के लिए चुनौती है। इन पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना होगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या नालंदा के मंदिर में भगदड़ प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है?

आज का सवाल

क्या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन का सरकार का फैसला सही है?

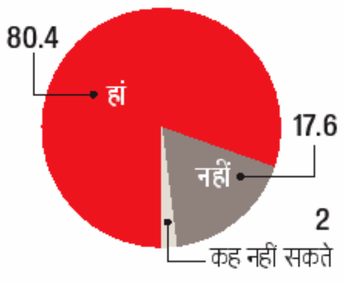

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

परस्पर निर्भर भारत और खाड़ी देश

विवेक काटजू

भले ही खाड़ी देशों में यूरोपीय प्रवासी भी रहते हों, पर उनका काम दक्षिण एशियाई लोगों, विशेष रूप से भारतीयों के बिना नहीं चल सकता

संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति रहे शेख जायद बिन मोहम्मद के निमंत्रण पर मई 1981 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खाड़ी देश का दौरा किया था। करीब 45 वर्ष पहले हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने सहमति जताई थी कि खाड़ी क्षेत्र और भारत की सुरक्षा एवं कल्याण की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। समय के साथ यह धारणा और मजबूत ही हुई कि दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा और समग्र कल्याण परस्पर निर्भर हैं। एक ऐसे समय जब ईरान युद्ध के चलते समूचे क्षेत्र में अशांति बढ़ने से पूरे समीकरण बदल गए हैं तो यह विचार और प्रासंगिक हो गया है।

अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान जैसे छह प्रमुख देश हैं। यहां दक्षिण एशियाई देशों की बड़ी प्रवासी जनसंख्या रहती है। इनमें से भी सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है, जिनकी तादाद नब्बे लाख से एक करोड़ के बीच है। पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की संख्या भी पचास लाख से अधिक है। नेपाल और श्रीलंका के भी लाखों लोग यहां हैं। ये लोग इन देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग पेशेवर, कार्यकारी और प्रबंधकीय से लेकर अर्धकुशल और सामान्य श्रमिक जैसी भूमिकाओं में सक्रिय हैं। यह कहना एकदम सही होगा कि भले ही खाड़ी देशों में यूरोपीय प्रवासी भी रहते हों, लेकिन उनका काम दक्षिण एशियाई विशेष रूप से भारतीयों के बिना नहीं चल सकता। काम से जुड़ा भारतीयों का कौशल और भरोसा उन्हें इन देशों में व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाता है। जितना खाड़ी के देशों को प्रवासियों की आवश्यकता है, उतनी ही उन्हें भी है, क्योंकि वे अपने देश को भारी मात्रा में धनराशि भेजते हैं। रेमिटेंस कही जाने वाली यह धनराशि इन देशों के वृहद आर्थिक स्थायित्व में संतुलन की भूमिका और बाहरी झटकों से बचाने में उपयोगी होती है। भारत के चालू खाते के लिए यह राशि बड़ा योगदान देती है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए यह अस्तित्व का संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक बनी हुई है। राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित बांग्लादेश के लिए भी रेमिटेंस की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वृहद आर्थिक स्थिरता के अलावा खाड़ी देशों में कार्यरत लोगों द्वारा भेजे जाने वाला रेमिटेंस उनके स्वजनों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश परिवारों की योजनाएं इसी भेजी गई राशि के आधार पर टिकी होती हैं। उसके अभाव में उनके परिवारों का भविष्य अधर में भी लटक सकता है।

अवधेश राजपूत

रेमिटेंस के अलावा खाड़ी देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए तो खाड़ी देशों की महत्ता और भी अधिक है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत कच्चे तेल और गैस की आवश्यकताओं का आधे से अधिक हिस्सा इन देशों से आयात करता है, लेकिन उसने अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे अन्य स्रोतों से भी तेल आयात को विविधीकृत किया है। ये कुछ महंगे होंगे, लेकिन कम से कम उनकी उपलब्धता तो रहेगी। होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से बाकी दुनिया के साथ ही दक्षिण एशियाई देशों की समस्याएं भी बढ़ी हैं। पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि उसे सऊदी अरब और यूएई से क्रेडिट यानी बाद में भुगतान के साथ भी तेल मिलता है, जो वह अन्य देशों से प्राप्त नहीं कर सकता। इसके चलते भुगतान की स्थिति में पहले से ही आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। उर्वरकों की आपूर्ति में संभावित गतिरोध ने भी कृषि आधारित दक्षिण एशियाई देशों की चिंता बढ़ाई है।

खाड़ी देश भारत के साथ ही अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारत का खाड़ी देशों के लिए निर्यात उसके कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। ईरान युद्ध ने इसे प्रभावित किया है। दुबई बंदरगाह कई निर्यात गंतव्यों के लिए पड़ाव भी है। खाड़ी क्षेत्र भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों के लिए निवेश के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। भारतीयों और अन्य दक्षिण एशियाई लोगों ने भी खाड़ी देशों में भारी निवेश किया है। इस युद्ध से उस पर आशंकाओं के बादल छाए हैं। इस तरह देखा जाए तो दशकों पहले इंदिरा गांधी और शेख जायद ने दोनों पक्षों के परस्पर हितों के जुड़ाव की जो बात कही थी, वह एकदम सही थी। उन्होंने जिन बिंदुओं पर सहमति बनाई थी, उन्हें आगे बढ़ाने का काम शेख जायद के पुत्र और यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी आगे बढ़ाया है। दोनों के बीच मजबूत एवं आत्मीय व्यक्तिगत संबंध भी है।

ईरान युद्ध ने यह भी दर्शाया है कि भारत और दक्षिण एशियाई देश एक ही नाव पर सवार हैं। यदि पाकिस्तान भारत के प्रति इतनी नफरत से भरा न होता और बांग्लादेश ने भी हालिया अस्थिरता का परिचय न दिया होता तो संभव है कि दक्षिण एशिया में भारत उनके साथ मिलकर अमेरिका, इजरायल और ईरान से अपील कर सकता था कि वे टकराव के बजाय कूटनीति का सहारा लें। अभी प्रत्येक पक्ष निजी हैसियत से ऐसा कह रहा है, लेकिन सामूहिक स्वर की बात ही कुछ और होती। दक्षिण एशिया की एकजुट आवाज में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान है। वहां के शासक वर्ग की सत्ता भारत के प्रति नफरत पर टिकी रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में उसके साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में पहल की, जिसे वहां की सेना ने सफल नहीं होने दिया। अब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के लिए प्रयासरत है, लेकिन ईरान ने उसके प्रयासों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान अपनी इस्लामी पहचान को दक्षिण एशियाई पहचान से ऊपर रख रहा है। इस्लामिक देशों में पाकिस्तान के पास ही परमाणु हथियार हैं, पर उसके चरित्र को देखते हुए इस्लामिक देश ही उसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उसकी राजनीति अस्थिर और अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। पाकिस्तान ईरान युद्ध को अपना कद बढ़ाने के मौके के रूप में देख रहा है, पर वह हमेशा की तरह एक मोहरे के रूप में ही इस्तेमाल होगा। शायद यही उसकी नियति भी है।

(लेखक पूर्व राजनयिक हैं)

response@jagran.com

शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता का सवाल

कृपाशंकर चौबे

निजी उद्यम से छपने वाली अधिकांश शोध पत्रिकाएं अकादमिक दृष्टि से स्तरहीन हैं, ये पैसे लेकर शोध आलेख छापती हैं

शोधार्थी के सम्यक परीक्षण में सक्षम हों पत्रिकाएं ● फाइल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नियमानुसार पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने के पहले शोधार्थी के दो शोध आलेखों का छपा होना आवश्यक है। शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए भी शोध आलेखों का प्रकाशन अनिवार्य है। पहले नियम था कि ये शोध आलेख यूजीसी केयर सूचीबद्ध पत्रिका में छपे होने चाहिए। अब उस नियम को शिथिल कर विशेषज्ञ समीक्षित शोध पत्रिका में छपना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अनिवार्यता के बाद विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिकाओं की बाढ़ आ गई है। आइएसएसएन (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर) हासिल कर निजी उद्यम से छपने वाली इन पत्रिकाओं में अधिकांश अकादमिक दृष्टि से लचर हैं, किंतु पत्रिका के नाम के नीचे यह लिखने की ढिठाई करती हैं-विशेषज्ञ समीक्षित शोध पत्रिका। ये पत्रिकाएं पैसे लेकर शोधार्थियों-शिक्षकों के शोध आलेख छापती हैं। इन पत्रिकाओं में छपकर शोधार्थी और शिक्षक उसका लाभ भी ले रहे हैं। इनमें कई पत्रिकाएं यूजीसी केयर में भी सूचीबद्ध हो गई थीं। अधिकांश पत्रिकाओं में शोध आलेखों का निम्न स्तर चिंताजनक है। अधिकतर शोध आलेखों में न विषय पर नया प्रकाश पड़ता दिखता है, न शोधार्थी के सम्यक विश्लेषण का पता चलता है। अधिकांश शोध पत्रिकाओं में भाषा का संस्कार अनुशासन गायब दिखता है। वर्तनी को लेकर अराजकता का आलम यह है कि एक ही पृष्ठ पर एक ही शब्द अलग-अलग ढंग से लिखा मिलता है। इन पत्रिकाओं में शब्दावली, वाक्य विन्यास और व्याकरण संबंधी न्यूनतम ज्ञान का सर्वथा अभाव दिखता है।

जहां वर्तमान में हिंदी में शोध पत्रिका होने का दावा करने वाली पत्रिकाओं की यह पीड़क स्थिति है, वहीं अतीत में निकलने वाली कई पत्रिकाएं यह दावा नहीं करती थीं कि वे शोध पत्रिका हैं, किंतु गंभीर शोध आलेख प्रकाशित करती थीं। 1903 से 1920 तक 'सरस्वती' का संपादन करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कभी यह दावा नहीं किया कि 'सरस्वती' शोध पत्रिका है, किंतु उन्होंने कई गंभीर शोध आलेख उसमें प्रकाशित किए। जैसे 'सांख्यशास्त्र और उसके तत्व', 'कौटिलीय अर्थशास्त्र का रचना काल' और 'आर्य लोग कहां से आए' वस्तुतः शोध आलेख हैं। इसी तरह रामानंद चटर्जी द्वारा प्रकाशित और बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा संपादित 'विशाल भारत' के फरवरी, मार्च और अप्रैल 1931 के अंकों में ब्रजेंद्र नाथ बनर्जी ने 'हिंदी का प्रथम समाचार पत्र' शीर्षक लेख तीन किस्तों में लिखकर प्रमाण सहित यह प्रस्तुत किया कि 30 मई, 1826 को प्रकाशित 'उदंत मार्तण्ड' हिंदी का पहला समाचार पत्र है। उनके शोध आलेख छपने के पहले 1845 में निकले 'बनारस अखबार' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता था।

दिल्ली से 1951 में शुरू हुई 'आलोचना' त्रैमासिक ने भी शोध पत्रिका होने का कभी दावा नहीं किया, किंतु प्रवेशांक में ही उसने 'भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण', 'शूद्रों की खोज', 'प्राचीन भारतीय वेशभूषा', 'संस्कृत के महाकाव्यों की परंपरा' और 'भारतीय आलोचना-पद्धति' शीर्षक से गंभीर शोध आलेख प्रकाशित किए। डा. कामिल बुल्के का प्रसिद्ध शोध आलेख 'रामचरितमानस का रचनाक्रम' 'आलोचना' के जुलाई 1953 के अंक में छपा था। इसी अंक में परशुराम चतुर्वेदी ने 'आलोचना और अनुसंधान' शीर्षक से शोध आलेख लिखकर बताया था कि भारतीय अनुसंधान पद्धति क्या रही है और पश्चिम से यह कितनी अलग और आगे रही है।

परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार अनुसंधान का काम किसी बात के उत्स तक जाने का प्रयास करना मात्र ही नहीं है, उसके बीज रूप से लेकर उसके विकास तक का परिचय प्राप्त करना, सजातीय वस्तुओं के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करना तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार उसका उचित और वास्तविक स्थान निर्धारित करना भी उक्त प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। इसी तरह 'नया प्रतीक' ने भी कभी शोध पत्रिका होने का दावा नहीं किया, किंतु अज्ञेय ने उसमें 'नृत्य का उद्गम', 'यूनानी लोक नृत्य की परंपरा', 'भारतीय ज्ञान प्रवाह का सनातन मूल्य' शीर्षक से गंभीर शोध आलेख प्रकाशित किए।

हिंदी में उन्नीसवीं शताब्दी में एक ऐसी त्रैमासिक पत्रिका जरूर निकली, जिसके संपादक मंडल ने बाकायदा घोषणा की कि वह शोध पत्रिका है। उसका नाम 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' है। उसका प्रवेशांक जून 1896 में निकला। लेख पहले नागरी प्रचारिणी सभा में पढ़े जाते थे। उसके बाद परीक्षक समिति उन पर विचार करती थी। परीक्षक समिति के विचारोपरांत संपादक लेखों का परीक्षण करता था। तब उसे छपने को भेजा जाता था। परीक्षक समिति की अनुमति के बिना कोई भी लेख पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो सकता था। इस पत्रिका ने नागरी लिपि और हिंदी भाषा के संरक्षण तथा प्रसार, हिंदी साहित्य के विविध अंगों के विवेचन, भारतीय इतिहास और संस्कृति के अनुसंधान, प्राचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला के पर्यालोचन में बड़ी भूमिका अदा की। 1968 तक इस पत्रिका की गुणवत्ता कायम रही, किंतु उसके बाद यह पत्रिका अव्यवस्थित और स्तरहीन हो गई। इधर पिछले कुछ वर्षों के अंतराल के बाद 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का पुनर्नवांक आया है। 434 पृष्ठों में 20 गंभीर शोध आलेखों से सज्जित इस अंक से पत्रिका की पुरानी प्रतिष्ठा पुनः कायम हो गई है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पात्रता

प्रत्येक व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है। हालांकि उसके चाहने मात्र से उसे इच्छित की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह केवल उतना प्राप्त कर सकता है, जितनी उसने पात्रता हासिल की है। किसी भी वस्तु, स्थिति, योग्यता या विचार को प्राप्त करने के लिए पहले व्यक्ति को उस क्षेत्र में पात्रता हासिल करनी होती है। अर्थात वस्तु या व्यक्ति को वे गुण या विशेषताएं प्राप्त करनी होती हैं, जो अपेक्षित वस्तु या व्यक्ति में उस स्थिति या स्वरूप के लिए वांछनीय होती हैं। यह बात केवल मनुष्य के लिए नहीं है, वरन संसार की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु के संदर्भ में लागू होती है। पत्थर को पत्थर कहलाने के लिए पत्थर होने वाले वांछनीय गुणों को प्राप्त करना होता है। इसके विपरीत मोम कुछ भिन्न गुणों को धारित करने के कारण मोम कहलाता है। पात्रता की यह अवस्था बहुत महत्व की होती है। मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को सिर्फ पानी से गीला करना भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे तब तक गूंथना होता है जब तक उसमें वह लोच पैदा नहीं हो जाती जो चाक पर उसे रखकर बर्तन बनाने के लिए आवश्यक है। पात्रता या अनुकूलन की यही स्थिति ऋजुता कहलाती है।

वास्तव में ऋजुता या पात्रता इच्छित को प्राप्त करने से पूर्व की एक स्थिति ही है। पात्रता हासिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य बनता है। संभव है कि व्यक्ति किसी पद या स्थिति को भाग्य या व्यवस्था के चलते प्राप्त कर ले, परंतु यदि उसमें उस पद या स्थिति के अनुरूप पात्रता नहीं है तो वह उस पद या स्थिति से न्याय नहीं कर पाएगा। तब उसे सम्मान भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्पष्ट है कि जिसकी जितनी पात्रता होती है, वह उतना ही प्राप्त कर सकता है। घड़ा समुद्र और कुएं में समान ही जल ग्रहण करता है। इसी प्रकार समुद्री लहरें उस नाविक का साथ देती हैं, जो नाव चलाने की कुशलता या पात्रता प्राप्त कर लेता है।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

माओवाद से मुक्ति की बड़ी उपलब्धि

'लाल आतंक पर पूर्ण विराम' शीर्षक से लिखा उमेश चतुर्वेदी का आलेख कई पहलुओं पर प्रकाश डालता है। मोदी सरकार ने अपने राष्ट्र हितैषी संकल्प के साथ भारत के एक तिहाई हिस्से में पनप चुके माओवादी आतंक को निर्धारित समयसीमा में खत्म करके जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह प्रशंसनीय है। देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सशस्त्र माओवादियों ने आतंक और हिंसा के बल पर सरकारी मशीनरी को पंगु करके वहां के विकास को अवरुद्ध कर रखा था। राजनीतिक संरक्षण मिलने से इन देशद्रोहियों का दुस्साहस बढ़ता गया। हिंसक माओवादियों ने स्थानीय युवक-युवतियों को भय, लोभ, लालच के जरिये अपने कैडर में सम्मिलित कर उनके हाथों में बंदूक थमा दी। जनसामान्य के बीच आतंक फैलाकर सामर्थ्यवान लोगों से धन वसूली करना गिरोहबंद माओवादियों का पेशा बन गया। दंडकारण्य में आतंक के पर्याय बन चुके सशस्त्र माओवादियों की सटीक रणनीति के समक्ष पुलिस और अर्द्धसैन्य बलों की सामूहिक शक्ति भी घुटने टेकने लगी थी। माओवादी आतंक से ग्रस्त राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना लाचार थीं, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों जांबाज सुरक्षाकर्मी बलिदान होते रहे। नेताओं और सरकारी अफसरों का अपहरण और कत्ल आम बात हो गई। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आई भाजपा सरकार ने देश को लहुलुहान करने वाले जिहादी आतंक के साथ माओवादी लाल आतंक को खत्म करना अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। अनुकूल समय आने पर गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक वामपंथी सशस्त्र माओवादियों के खात्मे की घोषणा करके लाल आतंक से प्रभावित राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर शीर्ष माओवादी कमांडरों को ढेर करते हुए हजारों माओवादियों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। हथियार डालने वाले माओवादियों के पुनर्वास की बेहतर योजना से प्रेरित होकर बचे-खुचे माओवादियों ने भी बेमौत मरने की बजाय आत्मसमर्पण उचित समझा। विगत में आंध्र के तिरुपति से लेकर नेपाल के पशुपति तक फैले आतंक के लाल गलियारे को आज मोदी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति ने भय और हिंसा से मुक्त कर दिया है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

किसानों को मिले सही दाम

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आदेश जारी करते हुए हरियाणा की अनाज मंडियों में बिकने के लिए आने वाले अनाज पर आढ़तियों द्वारा 'कच्ची पर्ची' व्यवस्था पर रोक लगाने का सराहनीय फैसला दिया है। मंडियों में प्रचलित 'कच्ची पर्ची' प्रणाली से किसानों का शोषण हो रहा था। वे औने-पौने दामों पर किसानों को फसल बेचने पर बाध्य करते हैं। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए मार्केट समितियों के सचिवों को निर्देश जारी तो कर दिए हैं किंतु न्यायालयों के आदेशों एवं सरकार के निर्देशों के अनुपालन में कोताही न हो इसका ध्यान मार्केट समितियों के अधिकारियों को तो सुनिश्चित करना ही होगा।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

भीड़ प्रबंध पर दें ध्यान

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले तीन दशकों में 4000 से अधिक भगदड़ हुईं। जिनमें 3074 लोगों की मौतें हुईं। हाल ही में बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ में नौ महिलाओं की जान गई तथा बच्चे और वरिष्ठ नागरिक इस हादसे में घायल भी हुए। सवाल इस बात का उठता है कि समय-समय पर इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई भी सबक नहीं लेता। इसका प्रमुख कारण है कि धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर होने वाली इस तरह की कार्यक्रमों तथा राजनीतिक रैलियां भी जानलेवा साबित हुई है। प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से प्रबंध नहीं किए जाते, यहां तक कि असामाजिक तत्व इस तरह के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। जिसके कारण भगदड़ मच जाती है और हादसों का जन्म हो जाता है। पुलिस-प्रशासन को व्यापक रूप से कदम उठाने होंगे। इस प्रकार के हादसों पर विराम लगाना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश में छोटे-छोटे आयोजनों में भी हजारों की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं और ग्राउंड मैनेजमेंट का शक्ति से पालन करने की जरूरत है ताकि इस प्रकार की भविष्य में गलतियां न हों और इस तरह के हादसों पर विराम लगे सके। जिस भी गांव, नगर, जिले और राज्य में कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वहां के पुलिस प्रशासन के पास आयोजकों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति ली जानी चाहिए।

मीना धानिया, नई दिल्ली

पोस्ट

ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका का 'ब्रेक्सिट' है। यह दुनिया को समझने में एक ऐसी विनाशकारी विफलता है, जो मिथ्याभिमान, झूठ और राष्ट्रवादी छलावे से उपजी है।

निक कोहेन@NickCohen4

ओरेकल ने भारत में 12 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। दुनिया भर में करीब 30 हजार कर्मचारियों को रातोंरात निकाला गया है। आइटी सेक्टर में अब तक नई नौकरियां आ नहीं रही थीं और अब एआइ के कारण नौकरियां जाने लगी हैं।

मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

क्या आइपीएल में पिच एकदम पाटा हैं या फिर बल्लेबाजों ने अपने तरकश में कुछ नायाब नए तीर जोड़ लिए हैं। जो भी हो, बल्लेबाजों का दबदबा खेल का मिजाज बिगाड़ रहा है। कार्तिक कन्नन@kartik_kannan

आइपीएल की पिचों पर गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं दिखता, पर इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि गेंदबाजी कला-कौशल का स्तर घटने पर है। बल्लेबाजी-गेंदबाजी कौशल में बढ़ती यह खाई और चौड़ी ही हो रही है।

हर्षा भोगले@bhogleharsha

जनपथ

अब ईरानी युद्ध से ताऊ दिखें हताश,
मित्र देश भी आजकल डाल रहे ना घास।
डाल रहे ना घास पड़ रहे ट्रंप अकेले,
छोड़ रहे मैदान जहां वे अब तक खेले।
होकर भी बर्बाद हार अब तक ना मानी,
बने गले की फांस ट्रंप के अब ईरानी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : **0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90** समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 257

10 सालों में भाजपा ने असम में पांच पुल बनवाए, मोदी ने यह कहकर असम में फिर से विकास का वादा किया।

दैनिक जागरण 13
नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026
www.jagran.com

एक नजर में

अब सिर्फ वोटिंग मशीन नहीं रहेंगे मुस्लिम : ओवैसी

कोलकाता : बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी व आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर एक मंच पर नजर आए। इस मौके पर रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य दलों पर आरोप लगाया कि इन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में किया है, लेकिन उनके विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। कहा कि मुस्लिम अब सिर्फ वोटिंग मशीन नहीं रहेंगे। (राब्यू)

भाजपा के संकल्प पत्र से पहले सुवेंदु ने जारी किया अपना घोषणापत्र

कोलकाता : भाजपा द्वारा राज्य के लिए आधिकारिक संकल्प पत्र जारी किए जाने से पहलेही बुधवार को सुवेंदु ने ममता बनर्जी के परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के लिए अपना एक विशेष और पृथक घोषणापत्र जारी कर दिया। सुवेंदु नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुवेंदु ने इस विशेष घोषणापत्र में उन्नत नागरिक सेवाओं का वादा किया है। (राब्यू)

कोलकाता में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हिंसा, पार्टी कार्यकर्ता का फटा सिर

कोलकाता : बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें एक पार्टी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। झड़प के दौरान महिला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे। बताया जाता है कि एक महिला कार्यकर्ता हाथापाई के दौरान बेहोश हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। (राब्यू)

व्यक्तिगत सुनवाई की मांग तृणमूल ने कोर्ट को लिखा पत्र

कोलकाता : तृणमूल ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूनल सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। (राब्यू)

294 सीटों पर तृणमूल का मैं ही चेहरा : ममता

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को मुर्शिदाबाद के नबग्राम में चुनावी रैली के दौरान इस चुनावी मुकाबले को एक बार फिर अस्मिता बनाम बाहरी की दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। आक्रामक और भावनात्मक संबोधन में ममता ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी 294 सीटों पर तृणमूल का एकमात्र चेहरा वही हैं, जिसका अर्थ है कि हर वोट सीधे उनके नेतृत्व की कसौटी होगा।

गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने उन्हें 'हरिदास' (हरिदास पाल बंगाल के हुगली जिले के एक बड़े सेठ थे) करार दिया। मालूम हो कि अगर कोई शख्स खुद बहुत बड़ा ताकतवर व धनी समझने की कोशिश करता है तो उसे बंगाल में लोग बोलचाल में हरिदास पाल कहकर कटाक्ष करते हैं। आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में बैठकर बंगाल की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को लेकर भ्रामक आंकड़े परोस रही है। तंज कसा कि उनके शासन में बंगाल सोनार बांग्ला नहीं बल्कि हत्या का बंगाल बनने की साजिश का शिकार हो रहा है। ममता ने बताया कि उन्होंने कई बार कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया था कि मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ संयुक्त रूप से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इससे दूरी बनाए रखी।

- बोलीं- दिल्ली के 'हरिदास' तय नहीं करेंगे हमारा भविष्य
- मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर आयोग और कांग्रेस पर प्रहार
- अमित शाह के डेमोग्राफी में बदलाव के दावों को बताया सफेद झूठ

ममता बनर्जी • फाइल फोटो

टीएमसी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज करने की जिम्मेदारी : बीरभूम जिले में एक चुनावी रैली में ममता ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों को उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

'हमारा मुख्यमंत्री मछली-भात, मांस-भात, अंडा-भात सब खाएगा'

जासं, जलपाईगुड़ी : भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है तो मांस, मछली और अंडा खाने पर रोक लगा देगी। ममता के इस बयान के एक दिन बाद ही सुकांत ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री जो भी होगा, वह मछली-भात, मांस-भात, अंडा-भात सब खाएगा। उनके इस बयान ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भर दिया। वह अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम हटने से तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक पर भारी असर पड़ा है।

केरलम में भगवान भी सुरक्षित नहीं हैं: राजनाथ

कोच्चि, प्रेट्र: भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि केरलम को भगवान का अपना देश कहा जाता है, लेकिन यहां भगवान भी सुरक्षित नहीं हैं। सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में राजनाथ सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ एलडीएफ ने कुछ सोने के सिक्कों के लिए भगवान अय्यप्पा के साथ विश्वासघात किया है। परवूर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ने कहा कि जिस प्रकार जूडास ने ईसा मसीह के साथ विश्वासघात किया, उसी प्रकार एलडीएफ ने भगवान अय्यप्पा के साथ विश्वासघात किया।

रक्षा मंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर केरलम की जनता के साथ विश्वासघात करने, समाज को बांटने, राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों में 'मोर्चा' शब्द का अर्थ "भ्रष्टाचार का मोर्चा" है। एलडीएफ का अर्थ "लूट, विभाजन और विफलता" है, जबकि यूडीएफ का अर्थ अविश्वसनीयता, बेईमानी और धोखाधड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 में राज्य प्रायोजित सोने की तस्करी हुई थी और केरलम के मुख्यमंत्री पी विजयन के करीबी लोग इसमें शामिल थे। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि यूडीएफ के कार्यकाल में भी कई घोटाले हुए थे और वे एलडीएफ के कार्यकाल जितने ही बुरे थे।

कोच्चि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी रैली में लोगों का अभिवादन करते हुए• प्रेट्र

सत्ता में आने पर घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला कानून लाएगी कांग्रेस : मोदी

असम रैली में कहा-कांग्रेस का मकसद बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक बनाना

धेमाजी, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि असम में सत्ता में आने पर कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला कानून लाएगी, जिसे भाजपा और उसके सहयोगी दल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस का मकसद बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक बनाना और घुसपैठियों का एक स्थायी वोट बैंक तैयार करना है।

धेमाजी जिले के गोगामुख में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे असम में घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए एक नया कानून लाएंगे। वे खुलेआम इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर देश को उसी तरह बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया, जैसा मुस्लिम लीग ने विभाजन के दौरान किया था।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए दो परिवार हैं-एक दिल्ली में और दूसरा असम में। उनकी प्राथमिकता जनता के हित नहीं, बल्कि अपने परिवार के हित हैं। स्पष्ट रूप से पीएम का इशारा गांधी परिवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के परिवार की ओर था।

बिश्वनाथ जिले के बेहाली में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम के संसाधनों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि भाजपा राज्य की संपत्तियों का उपयोग उसके विकास के लिए कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को विकास विरोधी और भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। कहा कि कांग्रेस विभिन्न जिलों में घुसपैठियों को सत्र, नामघर और मंदिर की भूमि पर बसने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन, भाजपा ने इस संबंध में कार्रवाई की है और घुसपैठियों के चंगुल से अतिक्रमित जमीनों को मुक्त करा रही है। कांग्रेस ने 60-65 वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुल बनाए, जबकि भाजपा ने 10 वर्षों में पांच पुल बनाए हैं, जिसने लोगों के जीवन और आजीविका को बहुत आसान बना दिया है। एएनआइ के अनुसार, गोगामुख की रैली में पीएम ने असम में फिर से सत्ता में आने पर यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया।

पीएम ने चाय बागान का दौरा किया, पत्तियां तोड़ीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक चाय बागान का दौरा किया और पत्तियां तोड़ीं। मोदी ने मनोहरी चाय बागान में महिला श्रमिकों से भी बातचीत की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया-हमें हर चाय बागान परिवार के प्रयासों पर बहुत गर्व है। मोदी को पारंपरिक सफेद और लाल बार्डर वाली साड़ियों में सजी 19 महिलाओं के साथ चाय की पत्तियां तोड़ते हुए देखा गया।

डिब्रूगढ़ में चाय बगान में महिला श्रमिकों के साथ पत्तियां तोड़ते पीएम मोदी • एएनआइ

प्रियंका का हिमंत पर निशाना, एक परिवार असम को लूट रहा

नाजिरा, प्रेट्र: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि संसाधन संपन्न राज्य में केवल एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, जबकि जनता के पास "कुछ भी नहीं है"। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता को धमकाकर काम कर रही है।

कांग्रेस उम्मीदवार देबब्रता सैकिया के समर्थन में नाजिरा में एक चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला किया और उन पर अमेरिका का "गुलाम" होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि असम में एक परिवार सब कुछ लूट रहा है। और जब वे लूटपाट नहीं कर रहे होते हैं, तो खदानें, जमीनें और हर दूसरी संपत्ति बड़े उद्योगपतियों को सौंप दी जाती है। असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हर मोर्चे पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, उन्होंने सारदा, स्मार्ट सिटी और एनसी हिल्स जैसे कई पुराने घोटालों का मुद्दा उठाया। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के वादे को पूरा न करने के लिए भाजपा सरकार पर हमला किया।

बंगाल में फार्म-6 को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : बंगाल में फार्म-6 को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 जमा करने का आरोप लगाते हुए कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, 30 मार्च को चुनाव आयोग के कार्यालय में बड़ी संख्या में फार्म-6 जमा किए गए। तृणमूल का दावा है कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस तरह सामूहिक रूप से फार्म जमा नहीं कर सकते। उसने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मालूम हो कि फार्म-6 को लेकर मंगलवार को भाजपा व तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी।

सीईओ दफ्तर के निकट फिर हंगामा : टीएमसी समर्थित बूथ स्तरीय अधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, कोलकाता के बेलेघाटा के एक टीएमसी पार्षद ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर आधी रात को सीईओ कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

भाजपा कर रही बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर : टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फार्म-6 जमा कर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में भाजपा कार्यकर्ता 30,000 से 40,000 फार्म-6 के साथ पकड़े गए हैं।

अभिनेता व तृणमूल प्रत्याशी पर धोखाधड़ी का आरोप, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

राब्यू, कोलकाता: विस चुनाव में करीमपुर से तृणमूल प्रत्याशी और अभिनेता सोहम चक्रवर्ती कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। उन पर 68 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। शिकायतकर्ता शाहिद इमाम का दावा है कि 2021 में एक फिल्म निर्माण के लिए सोहम के साथ एक करोड़ रुपये का समझौता हुआ था। समझौते के तहत सोहम को 68 लाख दिए गए थे, लेकिन न फिल्म बनी, न पैसे वापस किए गए।

आप के पूर्व नेता एच.एस फूलका भाजपा में शामिल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एच.एस. फूलका भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनकी पहचान 1984 के सिख विरोधी दंगों के वकील के तौर पर रही है। वह लंबे समय तक इस मामले में केस लड़ते रहे हैं। उन्होंने 2014 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। फूलका ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर भाजपा की ओर से कई सिख चेहरे मौजूद थे। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ शामिल थे। (प्रेट्र)

दुष्कर्म के आरोपित 'धर्मगुरु' खरात को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नासिक : महाराष्ट्र की नासिक स्थित एक अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपित स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जब एक 35 वर्षीय महिला ने उस पर तीन साल की अवधि में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बुधवार को उसकी पुलिस हिरासत समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया गया। सत्र न्यायाधीश ने खरात को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। (प्रेट्र)

प्रवेश शुल्क बढ़ाने के विरोध में हिमाचल के प्रवेशद्वार पर चक्काजाम

बद्दी स्थित हिमाचल के प्रवेशद्वार पर चक्काजाम करते हरियाणा व हिमाचल के वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर • जागरण

जागरण टीम, शिमला : हिमाचल आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ाने के विरोध में बुधवार को सोलन, ऊना और बिलासपुर जिले की सीमा पर घंटों चक्काजाम किया गया। प्रदर्शनकारी पंजाब और हरियाणा के साथ लगे हिमाचल के प्रवेशद्वारों पर बैठ गए। सोलन जिले में बद्दी, बरोटीवाला, बघेरी, ढेरोवाल, परवाणू और दभोटा प्रवेशद्वार बंद रहे। परवाणू प्रवेशद्वार पर लगभग पांच घंटे जाम लगाया।

हिमाचल के व्यापार मंडल, टैक्सी आपरेटर्स व निजी बस आपरेटर्स भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे। पंजाब के प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश शुल्क निश्शुल्क करने की मांग उठाई तो हरियाणा के प्रदर्शनकारियों ने पहले जैसी स्थिति बहाल करने की मांग की। हरियाणा के लोगों ने कहा कि पहले कार का 70 रुपये शुल्क देना पड़ता था लेकिन अब 170 रुपये वसूले जा रहे हैं। अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए 10 दिन का समय मांगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पहले पांच सीटर गाड़ी के लिए 70 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये किया गया है। उन्होंने भाजपा को सलाह दी कि प्रदेश के हित में सीमावर्ती और पड़ोसी राज्यों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास न करें।

हिमाचल की तरह हमें भी लगाना आता है एंट्री टैक्स : चंडीगढ़ राब्यू के अनुसार भगवंत मान ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से कहा है कि एक तरफ हम पंजाब में टोल टैक्स बंद करवा रहे हैं, जिसका फायदा हिमाचल के वाहन चालकों को भी मिल रहा है। ऐसे टैक्स हमें भी लगाने आते हैं।

भारत टैक्सी को ओला और उबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का करना पड़ रहा सामना : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया कि सरकार समर्थित कोआपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी को शुरुआती दौर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें ओला और उबर जैसे स्थापित निजी समूहों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में अमित शाह ने कहा कि कल्याण और जागरूकता, प्रशिक्षण और बेहतर यूजर अनुभव के साथ-साथ ई-गवर्नेंस उपकरणों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत, भारत टैक्सी की स्थापना छह जून, 2025 को आठ राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं द्वारा की गई थी और इसे औपचारिक रूप से पांच फरवरी को लांच किया गया था। 23 मार्च तक लगभग 4.31 लाख ड्राइवर-पार्टनर जुड़ चुके हैं।

अमित शाह • फाइल फोटो

इस वर्ष 15 मार्च तक माओवादी हिंसा के 26 मामले दर्ज किए गए : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इस वर्ष 15 मार्च तक देश में माओवादियों द्वारा हिंसा की 26 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पांच नागरिकों, एक सुरक्षा बल कर्मी और 52 माओवादियों की मौत हुई है।

दिल्ली पुलिस में 14,000 रिक्तियां : दिल्ली पुलिस में स्वीकृत पदों के मुकाबले 14.5 फीसद पद रिक्त हैं, जिनमें से एसीपी के 346 में से 152 पद यानी 44 फीसद रिक्त हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 97,331 कर्मियों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 12 मार्च, 2026 तक 14,140 पद रिक्त थे।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला

जासं, अमृतसर : अमृतसर स्थित भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अटारी में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया है। हुसैनीवाला और फाजिल्का स्थित सादकी बार्डर पर भी रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला गया है। रिट्रीट सेरेमनी अब शाम पांच बजे के बजाय साढ़े पांच बजे शुरू होगी और छह बजे संपन्न होगी। यह निर्णय मौसम में बदलाव से लिया गया है।

गुजरात में आप से हार के डर से भाजपा तानाशाही पर उतरी : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: आप के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की गिरफ्तारी पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा, ईशुदान गढ़वी पार्टी कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी की जानकारी लेने थाने पहुंचे थे। मगर भाजपा सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। तीन महीनों में गुजरात में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ 145 एफआइआर हो चुकी हैं और 160 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। भाजपा गुजरात में हार के डर से आप से घबरा गई है और तानाशाही पर उतर आई है।

अरविंद केजरीवाल

नई नियमावली से यूपी में खत्म होंगे वक्फ संपत्तियों के 'खेल'

शोभित श्रीवास्तव • जागरण

- वक्फ नियमावली के नए खाके में जवाबदेही व आय बढ़ाने पर जोर
- वक्फ बोर्ड के लिए सदस्य भी होंगे नामित, डीएम की भूमिका बढ़ेगी

लखनऊ : प्रदेश सरकार वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के आधार पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई नियमावली बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और राजस्व-सक्षम बनाने की दिशा में बड़े बदलाव को स्वीकृति दे दी है। इससे बेशकीमती वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी पर लगाम लग सकेगी। नई व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों पर रोक लगने के साथ ही आय बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।

केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 बनाया है, जिसे 'उम्मीद' अधिनियम भी कहा जाता है। इसी अधिनियम को लागू करने के लिए योगी सरकार नई नियमावली बना रही है। प्रदेश में 1.25 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। इनके सर्वे, सत्यापन और विवादों के समाधान में प्रशासन की भागीदारी होगी, डीएम के अधिकार बढ़ेंगे। इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील का भी प्रविधान होगा।

लीज और किराया प्रणाली को पारदर्शी व बाजार आधारित बनाने की तैयारी है, जिससे आय में भी वृद्धि हो सके। बोर्ड का गठन अब चुनाव के से नहीं होगा। सरकार सदस्य नामित करेगी। सदस्यों की संख्या व भूमिका भी तय की जा रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को जोड़ने की भी व्यवस्था होगी। अब बिना लिखित वक्फ डीड के किसी भी संपत्ति को वक्फ मान्यता नहीं दी जाएगी। वक्फ संस्थानों के आय-व्यय का नियमित आडिट होगा और बड़े संस्थानों को खातों का विवरण पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

नियमावली में यह भी खास

- मुतवल्लियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी की जा रही है तय, अभी मुतवल्ली बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है।
- बड़ी वक्फ संपत्तियों की कमाई का अब वक्फ बोर्ड को सात प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत धनराशि मिलेगी।
- पुरातत्व के महत्व वाली संपत्तियां नहीं हो सकेंगी वक्फ घोषित, इसके लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं।

'आपरेशन सिंदूर के दौरान पाक पर समुद्री हमले के बेहद करीब थी भारतीय नौसेना'

मुंबई, प्रेट्र : नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने बुधवार को मुंबई में आयोजित 'नौसेना अलंकरण समारोह' में कहा कि पिछले साल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चलाए गए 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय नौसेना पाकिस्तान पर समुद्री प्रहार करने के बेहद करीब थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि भारत हमले से महज कुछ मिनट दूर था, तभी इस्लामाबाद ने सैन्य कार्रवाई (काइनेटिक एक्शन) रोकने का अनुरोध किया। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि आपरेशन सिंदूर अभियान ने नौसेना की अनुकरणीय तैयारी और संकल्प का प्रदर्शन किया। नौसेना की इकाइयों ने बहुत कम समय में तीव्र तैनाती की और पूरे अभियान के दौरान आक्रामक रुख बनाए रखा।

मुंबई में विजेताओं को ट्राफी सौंपते नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी • प्रेट्र

- नौसेना प्रमुख बोले - स्थिति इतनी गंभीर थी कि भारत हमले से महज कुछ मिनट दूर था
- तभी पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई (काइनेटिक एक्शन) रोकने का अनुरोध किया

नौसेना के दो शीर्ष अधिकारियों को 'युद्ध सेवा पदक'

आपरेशन सिंदूर में विशिष्ट सेवा के लिए नौसेना प्रमुख ने दो शीर्ष नौसेना अधिकारियों को 'युद्ध सेवा पदक' से सम्मानित किया। उन्होंने नौसेना संचालन महानिदेशक (डीजीएनओ) वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और वाइस एडमिरल राहुल गोखले को पदक प्रदान किए। वाइस एडमिरल प्रमोद को दिए प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि नौसेना अभियानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डिजिटल जनगणना शुरू, मुर्मु और मोदी ने स्व-गणना में भाग लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की पहली डिजिटल जनगणना बुधवार को शुरू हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के जनगणना इतिहास में पहली बार शुरू हुई स्व-गणना में भाग लिया। यह जनगणना राष्ट्रीय राजधानी और सात अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुई, जिसमें नागरिकों को एक विशेष वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दाखिल करने का विकल्प दिया गया है।

देश की पहली नागरिक द्रौपदी मुर्मु ने स्व-गणना पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपनी जानकारी भरी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और उप महानिदेशक (जनगणना योजना) बिस्वजीत दास की उपस्थिति में अपने सभी विवरण दर्ज किए।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं जनगणना का विवरण भरने के बाद एक्स पर लिखा, मैंने अपनी स्व-गणना पूरी कर ली है। आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। यह जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से डाटा संकलन के जरिये की जा रही है। इससे देश के लोगों को अपने परिवार का विवरण स्वयं भरने का विकल्प मिला है। मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने परिवार का विवरण स्वयं भरें और जनगणना प्रक्रिया में भाग लें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद ही आनलाइन जनगणना प्रपत्र भरा। शाह ने एक्स पर लिखा-जनगणना के पहले चरण के तहत आज से शुरू हो रही 'हाउस लिस्टिंग' प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने स्व-गणना प्रपत्र भरा है। यह प्रक्रिया भारत के विकास पथ को गति देने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि सरकारी योजनाएं प्रत्येक नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, ओडिशा, लक्षद्वीप, मिजोरम और राष्ट्रीय राजधानी के एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए स्व-गणना हेतु एक विशेष पोर्टल खोला गया है। इन राज्यों में आवास गणना के तहत सभी भवनों के लिए घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने का अभियान 16 अप्रैल से शुरू होगा। दिल्ली में स्व-गणना 15 दिन के दो चरणों में होगी-एनडीएमसी व दिल्ली छावनी के क्षेत्रों में 1 से 15 अप्रैल तक और एमसीडी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1 से 15 मई तक।

- लोगों को पहली बार मिला पोर्टल से जानकारी दाखिल करने का विकल्प

बुधवार को 'स्व-गणना' में जानकारी भरतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु • एएनआइ

बच्चों में फोन का प्रयोग कम करने का उपाय करेगी कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक सरकार ने बुधवार को छात्रों में डिजिटल तकनीक के अत्यधिक और असुरक्षित उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए एक नीति का मसौदा जारी किया। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसे स्कूलों में लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

मसौदा नीति का सारांश जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जनता स्वास्थ्य और शिक्षा पर मोबाइल फोन के नकारात्मक प्रभावों से अवगत है। इसके चलते चिंता, अनिद्रा और सामाजिक अलगाव जैसी चीजें सामने आ रही हैं। मसौदे में प्रस्ताव है कि विद्यालय डिजिटल उपयोग नीति तैयार करें।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

ट्रम्प की बढ़ती बेताबी

पश्चिम एशिया में चल रहा ईरान-इजराइल व अमेरिका युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा था जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे को नेस्तानाबूद करने की आवाजें लगा रहे थे मगर इसी बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा कर दी है कि वह अगले दो या तीन सप्ताहों तक इस युद्ध से बाहर आ जायेंगे, चाहे ईरान से समझौता हो या न हो। इससे लगता है कि ट्रम्प इस युद्ध में लगातार अकेले पड़ते जा रहे थे जिसकी वजह से अमेरिका में भी उनका भारी नागरिक विरोध होना शुरू हो गया है। ट्रम्प इससे पूर्व कह चुके थे कि ईरान अपने होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री रास्ते के बारे में क्या रुख अपनाता है। यह देखना अब इस रास्ते के बन्द होने से प्रभावित देशों का काम है। इससे पूर्व ईरान व इजराइल एक-दूसरे के सामरिक व महत्वपूर्ण नागरिक संस्थानों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। एक ओर जहां अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में स्थित उसके परमाणु संयन्त्र पर हमला किया तो दूसरी ओर ईरान ने इजराइल व अमेरिकी मित्र पश्चिम एशियाई देशों के तेल टैंकरों व तेल संस्थानों पर हमले शुरू कर दिये। मगर इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह युद्ध अब केवल दो से तीन सप्ताह ही और चलेगा और इस दौरान वह ईरान को घुटनों पर ले आयेंगे। जबकि ईरान का कहना था कि वह युद्ध विराम केवल इसी शर्त पर करेगा जब उसे यह आश्वासन दिया जायेगा कि भविष्य में उस पर कभी दुबारा हमला नहीं किया जायेगा।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह युद्ध विगत 28 फरवरी को इजराइल व अमेरिका ने ही शुरू किया था जिसका प्राथमिक लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना बताया गया था। मगर ट्रम्प ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को आक्रमण के जरिये मौत के घाट उतारने के बावजूद यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने युद्ध को आगे खींचते हुए इसका लक्ष्य ईरान को परमाणु शक्ति से विहीन करने का निर्धारित कर दिया परन्तु इस समर को चलते एक महीने से ज्यादा का वक्त बीतने पर इसकी जद में पश्चिम एशिया के लगभग सभी अमेरिकी मित्र खाड़ी देश भी आ गये। इन देशों की सम्पत्ति का आधार इनमें पाये जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस के स्रोत हैं और ईरान ने अपने नियन्त्रण के होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री रास्ते को बन्द करके इनके परिवहन को बन्द जैसा कर दिया जिससे दुनिया के विभिन्न देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका इस होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री मार्ग को खोलने को एक वैश्विक मुद्दा बनाना चाहता था और विश्व के विभिन्न प्रभावित देशों को इस युद्ध में अपनी ओर करना चाहता था परन्तु इस मुद्दे पर उसे मुंह की खानी पड़ी और कई महत्वपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय देशों ने उसके पक्ष में खड़े होने से मना कर दिया। हालांकि सभी चाहते हैं कि जलडमरूमध्य का मार्ग खुलना चाहिए लेकिन उन्होंने युद्ध में ट्रम्प का सहयोगी बनने से साफ इन्कार कर दिया। इनमें स्पेन से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली व फ्रांस तक शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूरोपीय देशों के सामरिक संगठन नाटो ने भी अमेरिका का साथ देने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि यह अमेरिका की अपनी लड़ाई है। इससे जाहिर था कि ट्रम्प इस मामले में धीरे-धीरे अकेले पड़ते नजर आ रहे थे जिसकी वजह से वह अब युद्ध को समाप्त करने की तजवीजें ढूंढने के लिए उतावले हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के बारे में अमेरिका के रक्षामन्त्री पीट हेगसेथ कह रहे थे कि अगले कुछ दिन युद्ध के लिए बहुत निर्णायक साबित होंगे। उनका कहना था कि अगर अगले कुछ दिनों में ईरान अमेरिका से समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके खिलाफ भीषण हमला किया जायेगा। इसके साथ ही ट्रम्प यह भी कह रहे थे कि यदि ईरान समझौता नहीं करता है तो उसके सभी बिजली व तेल ऊर्जा संयन्त्रों को नष्ट कर दिया जायेगा तथा उसके उस खार्ग द्वीप पर हमला करके कब्जा कर लिया जायेगा जहां से वह अपने कच्चे तेल का 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात अन्य देशों को करता है। साथ ही ट्रम्प इस संभावना से भी इन्कार नहीं कर रहे थे कि ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों को भी उतारा जा सकता है। इसके लिए अमेरिका पश्चिम एशिया के इलाके में अपने दस हजार अतिरिक्त पैदल सैनिकों के अलावा कई नौसैनिक जहाजों को भी रवाना कर चुका था। इसका मतलब यह निकाला गया कि ट्रम्प ईरान में यह डर पैदा कर देना चाहते हैं कि अगर उसने उनकी शर्तें न मानी तो वह पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। मगर ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है और जवाब में इजराइल पर बेतहाशा हमले कर रहा है और अमेरिका के मित्र पश्चिम एशियाई देशों में उसके संस्थानों को भी अपने निशाने पर रख रहा है। इनमें कई खाड़ी देशों के तेल उत्पादक संयन्त्र भी शामिल है।

> अभी कल ही उसने संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल टैंकर पर हमला किया। ईरान अब कह रहा है कि वह खाड़ी देशों में अमेरिकी कम्पनियों पर भी जवाबी हमले करेगा। दरअसल ट्रम्प कह चुके थे कि उन्हें ईरान की तेल सम्पदा पसन्द है। उनका यह कथन बताता था कि इस महायुद्ध का सबब क्या है ? क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह वेनेजुएला देश पर कब्जा करके उसकी तेल सम्पदा को कब्जाया था उससे उनके इरादे साफ हो जाने चाहिए थे। यही वजह है कि पश्चिम एशिया के इस युद्ध में यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ देने से इन्कार किया।

अभी कल ही उसने संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल टैंकर पर हमला किया। ईरान अब कह रहा है कि वह खाड़ी देशों में अमेरिकी कम्पनियों पर भी जवाबी हमले करेगा। दरअसल ट्रम्प कह चुके थे कि उन्हें ईरान की तेल सम्पदा पसन्द है। उनका यह कथन बताता था कि इस महायुद्ध का सबब क्या है ? क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह वेनेजुएला देश पर कब्जा करके उसकी तेल सम्पदा को कब्जाया था उससे उनके इरादे साफ हो जाने चाहिए थे। यही वजह है कि पश्चिम एशिया के इस युद्ध में यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ देने से इन्कार किया और कुछ ने तो इसे असंवैधानिक युद्ध भी बताया। दरअसल ट्रम्प मूल रूप से एक व्यापारी या व्यवसायी हैं और जब किसी देश का नेतृत्व किसी व्यापारी के हाथ में पहुंच जाता है तो वह आम जनता के हितों से बेखबर हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ऐसा भारत के महान राजनीतिक दार्शनिक आचार्य चाणक्य ने अपनी कालजयी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। अत: हमने देखा कि ईरान-इजराइल युद्ध में सभी मानद नैतिकताएं टूटीं और सामान्य नागरिक इसका शिकार बने। इसका असली कारण यही है कि ट्रम्प की व्यापारी नजर दुनिया के विभिन्न आय स्रोतों को केवल मुनाफा कमाने की गरज से आंक रही है लेकिन उनके इस नजरिये का अब अमेरिका के नागरिकों में भी भारी विरोध होना शुरू हो गया जिसकी वजह से वह इस युद्ध से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं।

दोगली नीति का आघात...

गीता पाढा

"तुम एक तरफ युद्ध विराम की बात करते हो,
दूसरी ओर दोगली नीति से आघात करते हो,,
शब्दों में शांति का दीप जलाते हो,
कर्मों से फिर क्यों आग लगाते हो,,
विश्वास की नींव को खुद ही हिलाते हो,
फिर रिश्तों की मजबूती का गीत सुनाते हो...।।"

युद्ध ख़त्म करना मुश्किल होता है

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि युद्ध शुरू करना आसान है पर ख़त्म करना मुश्किल। चार साल से वह छोटे यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर क़ब्ज़ा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं पर यूक्रेन शक्तिशाली रूस का बराबर मुक़ाबला कर रहा है। पुतिन के लिए यह महंगा सौदा रहा है। यही बात सत्ता के नशे में चूर एक और नेता को भी समझ आ रही होगी। ईरान पर हमला करने के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डानल्ड ट्रम्प ने कहा था कि युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा चार सप्ताह चलेगा। चार सप्ताह पूरे हो गए और अब तो लगता है कि युद्ध नए भीषण दौर में प्रवेश कर रहा है।

ट्रम्प की बौखलाहट भी बताती है कि वह हताश हैं कि जिसे 'ऑफ- रैम्प' कहा जा रहा है, अर्थात् युद्ध से हटने का रास्ता, वह निकल नहीं रहा। वह बार-बार लक्ष्य बदल रहे हैं और दूसरों के प्रति भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाटो देशों को वह 'कायर' कह चुके हैं और साउदी अरब के प्रिंस के प्रति उन्होंने वह कहा है जो इतना शर्मनाक है कि दोहराया नहीं जा सकता। ट्रम्प की चिढ़ है कि उनके कई यूरोपीय साथी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते। फ्रांस और इंग्लैंड ने तो साफ़ कहा है कि, "यह हमारा युद्ध नहीं है"।

इस युद्ध ने वह शक्ल अख्तियार कर ली है जिसकी कल्पना अमेरिका और इज़राइल को नहीं थी। बताया यह जाता है कि ट्रम्प नेतन्याहू के बहकावे में आ गए कि युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल, ने कटाक्ष किया है कि, "आख़िरकार नेतन्याहू को एक अमेरिका राष्ट्रपति मिल ही गया जो इतना मूर्ख, कान का कच्चा और इस्लाम विरोधी है कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है"। इज़राइली इतिहासकार अवी शलेम ने और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्रम्प को नेतन्याहू का 'पूडल' अर्थात् गोद में लिया छोटा कुत्ता कहा है। वह युद्ध जो ईरान में शासन पलटने और उनके परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लक्ष्य से शुरू हुआ था, अब विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ख़तरा बन गया है। ईरान द्वारा होर्मुज जलमार्ग को बाधित करने से तेल और गैस की क़ीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं और अगर यह युद्ध कुछ देर और चल गया तो तबाही हो जाएगी। हमारे जैसे देश जो तेल और गैस की आपूर्ति के लिए खाड़ी के देशों पर बहुत निर्भर हैं पर होर्मुज के रूक जाने का बुरा असर पड़ रहा है। होर्मुज का खुला रहना विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व शान्ति के लिए ज़रूरी है। मुख्य खिलाड़ियों की स्थिति कुछ ऐसी है।

अमेरिका : दुनिया में एकमतता है कि इस युद्ध से अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का बहुत नुकसान हुआ है। ट्रम्प इस वादे के साथ राष्ट्रपति बने थे कि वह अमेरिका को मध्य-पूर्व के युद्धों से दूर रखेंगे और हर हालत में अमरीकी सैनिकों को ज़मीन पर नहीं उतारेंगे। वह वहां ही युद्ध कर रहे हैं और 3500 सैनिकों को वहां भेज दिया ताकि ईरान के तेल उत्पादक खर्ग द्वीप पर क़ब्ज़ा कर सकें, अगर अमेरिकी सैनिकों और ईरान के सैनिक आमने-सामने आते हैं तो ईरान का तो नुकसान होगा ही पर अमेरिका का भी बराबर जानी नुक़सान होगा जिसके लिए अमरीकी जनता बिलकुल तैयार नहीं है।

वह हज़ारों मील दूर उस देश से लड़ना नहीं चाहते जिससे अमेरिका को कोई सीधा ख़तरा नहीं है। अभी से अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका नारा है, 'नो किंग्स' अर्थात् हमें राजा नहीं चाहिए। वह ट्रम्प की नीतियों, ईरान युद्ध और बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे हैं। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी में युद्ध का विरोध हो रहा है, क्योंकि न लक्ष्य स्पष्ट है न ख़त्म करने का रास्ता। ट्रम्प ने संसद से युद्ध के लिए 200 अरब डालर की मांग की है जो मिलने की सम्भावना नहीं है। आगे मिड टर्म चुनाव है और तेल की क़ीमतों से लोग परेशान हैं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी को धक्का पहुंचेगा।

अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने तो साफ़ कहा कि 2025 के हमले के बाद ईरान ने दोबारा परमाणु क्षमता खड़ी करने की कोशिश नहीं की। यह ट्रम्प के कथन का सीधा प्रतिवाद है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दूर बैठे अमेरिका को खतरा है। अमेरिका ने ईरान को 15 नुक्तों वाला शान्ति प्रस्ताव भेजा था जिसका अर्थ होता कि ईरान अपने हाथ काट कर अमेरिका और इज़राइल को सौंप देता। ट्रम्प को समझना चाहिए कि शान्ति उनके शर्तों पर नहीं होगी। ईरान के शीर्ष नेतृत्व को ख़त्म कर दिया गया है। तेहरान पर ज़बरदस्त बमबारी हो रही है। मिनाब में 160 स्कूली बच्चियां मारी जा चुकी हैं। ईरान सब झेल गया है, क्योंकि वह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत मार खाई है पर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसकी पकड़ है। होर्मुज को रोक कर उसने खेल बदल दिया है।

ईरान वह लम्बी लड़ाई के लिए तैयार है। ट्रम्प बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी में थे कि वह हथियार डाल देंगे। यह नहीं होने वाला। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान जीत चुका है। कर्नल मैकग्रेगर जो अमेरिका के रक्षा मंत्री के सलाहकार रहे हैं ने कहा है, "सब कुछ यह संकेत दे रहा है कि ईरान अमेरिका पर शर्तें थोप रहा है...वह देश जिस पर दिन रात दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली वायुसेना बम बरसा रही हैं उसके पास अभी भी जवाबी हमले करने की क्षमता हैं"। ईरान की क्षमताओं को कम आंका गया है जो बात इज़राइली विशेषज्ञ भी स्वीकार करते हैं। ईरान का जवाब ज़बरदस्त रहा है। लगता है वह इसके लिए दशकों से तैयारी कर रहे थे। खाड़ी के देशों में स्थित अमरीकी अड्डों को ईरान बुरी तरह ध्वस्त कर रहा है। कई अड्डे तो इतने नष्ट हो गए हैं कि अमेरिकी सैनिकों को होटलों में ठहराया जा रहा है जिन पर फिर ईरान हमले कर रहा है। दुबई पर हुए हमलों का यह बड़ा कारण है कि वहां के होटलों में अमरीकी सैनिक ठहरे थे। इज़राइल से एलन मिज़राही लिखते हैं कि "अमेरिका ने ऐसी तबाही पहले नहीं देखी"। अमरीका का कितना नुक़सान हुआ है यह बताया नहीं जा रहा पर निश्चित तौर पर मामूली नहीं है। ईरान की सैनिक क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में भूमिगत सिलो में हैं जहां तक अमरीका-इज़राइल बम पहुंच नहीं रहे। ईरान समर्थक हूती बाग़ी यमन से इज़राइल पर मिसाइल दाग रहे हैं। एक और मोर्चा खुल गया है। और वहां नुक़सान हो रहा है। होर्मुज जलमार्ग को रोक कर ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। अब सारा ज़ोर होर्मुज को खोलने पर लगा है जबकि युद्ध शुरू होने से पहले यह मार्ग वैसे ही खुला था, पर अगर ईरान इसे अधिक देर बाधित रखता है तो अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति खो देगा। अभी तो दुनिया ट्रम्प और नेतन्याहू को युद्ध के लिए दोषी ठहरा रही है पर अगर यह लम्बा चला और क़ीमतें बढ़ती गईं तो ईरान को भी आलोचना का सामना करना पड़ेगा।

इजराइल: इस युद्ध से सबसे बड़ा नुक़सान इज़राइल का हुआ है। उस देश को अंतर्राष्ट्रीय खलनायक समझा जा रहा है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय क़ानून को मानने को तैयार नहीं। भारत में जिसे 'राइट विंग' कहा जाता है को छोड़कर दुनिया में कहीं भी इज़राइल को समर्थन नहीं मिल रहा। नेतन्याहू विशेष तौर पर दुनिया में बदनाम हैं। जिस तरह बदला लेने के लिए इज़राइल द्वारा गाजा में 70000 लोगों को मारा गया वह सबने देखा है। बच्चे, औरतों, किसी का लिहाज़ नहीं किया गया। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी की गई है। कैसे लोग हैं जो शिक्षा के केन्द्रों पर बमबारी कर रहे हैं? अब लेबनान में 1000 लोग मार दिए गए हैं। पता नहीं नेतन्याहू कितना खून बहाने की क्षमता रखते हैं?पर उनका दुर्भाग्य है कि ईरान में युद्ध उनके मुताबिक़ नहीं चल रहा। उन्होंने समझा था कि यह जल्द ख़त्म हो जाएगा और वह नवम्बर में होने वाले चुनाव अडवांस कर जुलाई में करवा सकेंगे, पर ईरान जो मुक़ाबला कर रहा है उससे नेतन्याहू का हिसाब किताब सब गड़बड़ा गया है। इज़राइल का यह भी नुक़सान हुआ है कि उनकी अजेयता की प्रतिष्ठा ख़त्म हो गई है। अभी तक तो यह समझा जाताथा कि इज़राइल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनके 'आयरन डोम' को कोई भेद नहीं सकता। इस युद्ध ने यह प्रभाव भी ख़त्म कर दिया। ईरान इज़राइल की एयर स्पेस को भेद कर अंदर तक मार करने में सफल हो रहा है। तेलअवीव और यरूशलेम जैसे शहरों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। इज़राइल अब पहले की तुलना में कम सुरक्षित है। ईरान से परमाणु ख़तरा कम नहीं हुआ। वहां शासन बदलने का लक्ष्य जो नेतन्याहु ने दशकों से पाल रखा था, वह भी पूरा नहीं हुआ। ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों द्वारा दोनों अमरीका और इज़राइल को चुनौती दे दी है। अमरीका तो दूर बैठा है उसका कोई नुक़सान ईरान नहीं कर सकता, पर इज़राइल को सदैव चौकस रहना होगा। इन दोनों के लिए एक और कड़वी सच्चाई है। उन्होंने वह शुरू कर दिया है जो वह ख़त्म करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास आसान और सम्मानजनक विकल्प नहीं है। इनका इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान जैसे फटीचर देश की मदद ली जा रही है?

दिल्ली बजट विचारशील सरकार की सार्थक प्रतिबद्धता

राजकुमार भाटिया
विधायक दिल्ली विधानसभा

मनुष्य के जीवन में काम के समय से ही संघर्ष शुरू हो जाता है जो कि मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। ऐसे में यदि उसे जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर आवश्यक सुविधाएं और संरक्षण मिले तो मनुष्य का जीवन विकास के पथ पर तीव्रता के साथ दौड़ता भी है और साथ ही समाज और देश का विकास भी इसी तीव्र गति से होता है। दिल्ली की वर्तमान सजग और दृढ़निश्चयी सरकार का यही दृष्टिकोण इस बजट 2026-27 के मूल में निहित है।

दिल्ली बजट 2026-27 केवल 103.700 करोड़ रुपये का वित्तीय दस्तावेज नहीं है। यह मजबूत संकल्प है, मौलिक संवेदना है और समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। यह सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जो उन्होंने बार-बार जोर देकर कहा है शासन की योजनाएं बनाने का काम नहीं बल्कि उन योजनाओं को कार्यान्वित करके जनसामान्य का जीवन बदलने का कार्य करना चाहिए।"

यह दर्शन इस बजट की हर परत में समाविष्ट है और इसे व्यावहारिक रूप में जमीन पर उतार रही है सम्माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनका मानना है कि विकास तभी सार्थक है, जब प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। उसे शासन द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं और लाभ आसानी से प्राप्त हो सके।

इस बजट की शुरूआत बालक के जन्म के समय ही सरकार द्वारा दी जाने वाली जरूरी चिकित्सीय सुविधाओं से होती है। अनमोल योजना के तहत नवजात शिशुओं के लिए 56 जांच केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है। ये हर मां के लिए भरोसा है। कल्पना कीजिए दिल्ली के उन लाखों माता-पिताओं की जो अपने नवजात को अस्पताल पहुंचाते हुए चिंतित होते हैं। अब यह बजट उनकी चिंता को दूर करने का वादा करता है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें 750 आयुष्मान केंद्रों का विकास आधुनिक उपकरणों के साथ शामिल है। यह न केवल चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार है, बल्कि हर दिल्लीवासी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प है। आयुष्यान कार्ड हर परिवार तक पहुंचा। सड़कें, पानी, बिजली- ये सब मजबूत होंगे।

इसी तरह, शिक्षा के क्षेत्र में यह बजट बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सुंदर संकल्प प्रस्तुत करता है। 90 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि से एक लाख से अधिक बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराना एक अच्छी पहल है। यह व्यवस्था केवल यातायात का साधन नहीं है यह स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और गरिमा का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में, जहां बालिकाएं स्कूल जाने के लिए दूर-दूर पैदल चलती हैं, कई बार स्वास्थ्य कारणों से या रिक्शे और ऑटो में खर्च की जाने वाली धनराशि के अभाव में विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती यह साइकिल योजना निश्चित ही उन बालिकाओं के जीवन में नवीन क्रांति का संचार करेंगी।

महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निगरानी प्रणालियां, बेहतर रोशनी और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन पर निवेश किया गया है। यह केवल बुनियादी ढांचा नहीं, यह व्यवस्था में विश्वास का निर्माण है। दिल्ली की सड़कों पर रात को चलने वाली बहन-बेटियों को अब डर नहीं, बल्कि सुरक्षा का अहसास होगा।

> यह बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत संकल्प है...

स्वास्थ्य क्षेत्र को केंद्र बिंदु बनाते हुए स्नातक चिकित्सा सीटों को 600 से बढ़ाकर 800 से अधिक करने का प्रावधान दीर्घकालिक निवेश है। दिल्ली के युवा डॉक्टर्स की फौज तैयार हो रही है, जो न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश की सेवा करेंगे।

शिक्षा को नए अवसरों से जोड़ने का प्रयास बेहद सराहनीय है। टैलेंट हंट स्कीम का आरंभ और कौशल विकास पहलों का विस्तार युवाओं की क्षमता को पहचानने व पोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना दिल्ली के स्लम क्षेत्रों से आने वाले होनहार बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को उजागर करेगी, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाएगी तथा स्वावलंबन की ओर से जाएगी साथ ही, 18-35 वर्ष के युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे, जहां आईटी, पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के द्वार खोले जाएंगे।

बुनियादी ढांचे का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'फार एस' ढांचे (स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल) के मार्गदर्शन में ही रहा है। लोक निर्माण के लिए 5.9900 करोड़ और शहरी विकास के लिए 7.900 करोड़ का प्रावधान इस दिशा को दर्शाता है। रोजमर्रा के बुनियादी ढांचे में दृश्य सुधार के लिए 750 किलोमीटर सड़कों का एंड-टू-एंड री-कॉर्पेटिंग किया जाएगा। ट्रांस यमुना विकास और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की पहलों पर लक्षित निवेश से क्षेत्रीय विकास संतुलित होगा। दिल्ली के निवासी यह भलीभांति जानते हैं कि यमुना पार के क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। अब वहां पुल, सड़क आदि के हालत पहले से और बेहतर हुए हैं।

मूलभूत सेवाओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल आपूर्ति और सीवरेज ढांचे का विस्तार शहरी चुनौतियों का समाधान करेगा। परिवहन नियोजन भविष्योंमुखी है मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में वृद्धि और अधिक कुशल बनाने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। पर्यावरण प्राथमिकताओं की हरित बजट योजना के विस्तार और 15,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा प्रसंस्करण से मजबूती मिलेगी। दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए ये कदम आवश्यक है।

बजट का एक महत्वपूर्ण आयाम बुजुर्गों अथवा वरिष्ठ नागरिकों के सुखी और आनंदमय जीवन से जुड़ा है। क्या-आनंद योजना का आरंभ वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जरूरी और सार्थक कदम है, जहां वे भाग लें। संग्लन हों और आनंद से जिएं। क्योंकि यह व्यवस्था केवल वृद्धि नहीं बल्कि उन लोगों के लिए सम्मान और देखभाल भी है जिन्होंने समाज की नींव रखी। दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में सैकड़ों बुजुर्ग हैं, जो पार्क में अकेले बेठे रहते हैं। अब उनके लिए सामुदायिक केंद्र बनेंगे, जहां योग, कहानी सत्र और स्वास्थ्य जांच होंगी। पेंशन योजनाओं का विस्तार होगा, ताकि बुजुर्ग सम्मानपूर्वक जिएं।

इसी प्रकार, महिला हाट यानी रानी हाट महिलाओं के हस्तशिल्पियों को बाजार से सीधे जोड़ने का मंच प्रदान करता है। ये केवल आर्थिक उपाय नहीं ये स्वावलंबन, उद्यमिता और गरिमा के मार्ग हैं। जहां कौशल को सतत् जीविका और स्वतंत्रता में बदल दिया जाता है। दिल्ली की घरेलु हस्तशिल्पी उन महिलाओं की कल्पना कीजिए, जो अब अपने उत्पाद और हस्तशिल्प सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेगी।

बजट का एक और महत्वपूर्ण आयाम करुणा को शासन का सिद्धांत बनाने पर है। पशु चिकित्सालयों और गौशालाओं की सुविधाओं में निवेश शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक जिम्मेदारी की समझ दर्शाता है। दिल्ली के सड़कों पर भटकते हुए आवारा पशु जैसे कुत्ते गौ माता- ये भी हमारा हिस्सा हैं। यह प्रावधान पशु कल्याण की मानवीय विकास से जोड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अच्छा शासन जन आंदोलन बनना चाहिए। यह बजट उसी विचार को प्रतिबिंबित करता है।

धुरंधर ने खालिस्तानी गतिविधियों का पर्दाफाश किया

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

बीते दिनों रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय को केंद्रित कर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। फिल्म में जिस तरह से खालिस्तानी गतिविधियों, उनके नेटवर्क और कथित तौर पर जुड़े तत्वों को दिखाने का प्रयास किया गया है, उसने समाज, राजनीति और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। आज तक यही समझा जाता रहा है कि विदेशों की धरती पर बैठकर गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे कुछ लोग खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे हैं जिनका मकसद सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग है, हालांकि भारत में रहता कोई भी सिख न तो इसकी मांग करता है और न ही खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन। इतना तो तय था कि खालिस्तानी मूवमेंट पाकिस्तानी खुफिया एजैंसी के इशारे पर काम करती आ रही है, जिसका मकसद भारत में दहशत का माहौल बनाए रखने का है परन्तु बालीवुड में बनी फिल्म धुरंधर ने जिस प्रकार खालिस्तानी गतिविधियों का पर्दाफाश करते हुए साफ कर दिया कि खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे ड्रग माफिया और गैंगस्टर शामिल हैं और इसके सीधे संपर्क आईएसआई से है जिनके द्वारा इन्हें हथियार आदि सप्लाई किए जाते हैं। इससे यह भी साफ हो गया कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का दर्पण भी होता है। जब कोई फिल्म ऐसे विषयों को उठाती है, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हों तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। धुरंधर ने इसी जिम्मेदारी के साथ एक ऐसे मुद्दे को सामने लाने की कोशिश की है जिसे अक्सर या तो नजरअंदाज किया गया या फिर सीमित दायरे में ही चर्चा मिली। फिल्म यह संकेत देती है कि अलगाववादी गतिविधियां केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई बार इनके पीछे एक संगठित ढांचा भी काम करता है। यह पहलू बेहद गंभीर है, क्योंकि जब किसी विचारधारा के साथ अवैध गतिविधियों या बाहरी समर्थन के आरोप जुड़ते हैं तो वह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि सुरक्षा का विषय बन जाता है। हालांकि, इस तरह के विषयों पर बनी फिल्मों को लेकर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है।

भाजपा का सिखों को सम्मान : एक समय था जब सिख समुदाय भाजपा से दूरी बनाया करता मगर पिछले कुछ समय से भाजपा द्वारा सिख समुदाय के लिए ऐसे कार्य किए गए जिससे अब सिख समुदाय का झुकाव पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में होता दिख रहा है। भाजपा ने सिखों को सम्मान देते हुए पहले हरदीप सिंह पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव हारने के बावजूद केन्द्रीय मंत्री मण्डल में शामिल किया और अब दिल्ली में उपराज्यपाल के अहम पद पर तरनजीत सिंह सन्धू को जिम्मेवारी सौंपी गई है। तरनजीत सिंह सन्धु भी पंजाब के अमृतसर से चुनाव हारने वालों में शामिल है, बावजूद इसके उन्हें इतना अहम पद दिया गया।

इससे पहले उतराखण्ड में भी सिख राज्यपाल बनाया गया है, मगर दिल्ली की अहमियत अपनी ही रहती है, क्योंकि यह देश की राजधानी है और सभी देशों के दूतावास यहां हैं इसलिए दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया जाना सिख समुदाय के लिए गर्व की बात है। तरनजीत सिंह सन्धु देश की आजादी में योगदान देने वाले स. तेजा सिंह समुन्द्री के वंशज हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों से दर्ज है। यह अलग बात है कि आज तक वह सुनहरी इतिहास स्कूली पाठयक्रम में शामिल नहीं है। अब स. तरनजीत सिंह सन्धु दिल्ली की बागडौर संभाल रहे हैं ऐसे में उन्हें चाहिए कि इस ओर ध्यान देते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में स. तेजा सिंह समुन्द्री का इतिहास दर्ज करवाएं। इस प्रकार कई वर्षों के बाद मोदी सरकार आने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर स. इकबाल सिंह लालपुरा को बिठाया गया था जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। एयर चीफ मार्शल अमरजीत सिंह भी सिख समुदाय से हैं। 10 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में तीन सिख विधायक चुने जाने के बाद भी किसी को मंत्रिमण्डल में जगह नहीं दी गई थी, पर भाजपा ने अपनी सरकार में मनजिन्दर सिंह सिरसा को मंत्री पद दिया। उत्तराखंड और उ.प्र. में भाजपा सरकार के चलते अमनजीत सिंह बख्शी को स्टील कंस्यूमर फोर्म में चेयरमैन बनाया गया है, इस प्रकार और भी कई अहम पद सिख समुदाय को दिए गए हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

नई शिक्षा ने पुरानी परम्पराओं की ओर आक्रामकता दिखाई। मानो माया इस सभ्यता को उजाड़ देना चाहती हो। नई शिक्षा ही माया रूप है। यही कलियुग का अंत करेगी। किसका घर उजड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

सिमट रहा स्त्रैण भाव

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

अंग्रेजी शिक्षा ने एक ओर भारतीय दर्शन से विमुख किया, वहीं दूसरी ओर पौरुषीय शिक्षा के रास्ते स्त्रियों को भी पौरुषीय मानसिकता में ढालना शुरू कर दिया। उनकी स्त्रैण भूमिका ही सिमटकर रह गई। उनके सपने पौरुषेय हो गए। परिवार व्यवस्था खण्डित ही नहीं, चूर-चूर हो गई। जीवन शुद्ध आधिभौतिक हो गया। शरीर और सुविधा-भोग आधारित हो गया।

समय सदा एक-सा नहीं रहता। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। यह सभ्यता है। जो कल भी रहे वह संस्कृति है। परा-अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है। अपरा प्रकृति स्थूल है, शरीर-मन-बुद्धि है। दृश्यमान है। परा सूक्ष्म, अदृश्य प्रकृति है। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। माया ऋत है, सुसूक्ष्म है अतः सदा ही ब्रह्म की तरह अदृश्य है। सृष्टि सत्य की करती है, किन्तु स्वयं सत्य नहीं होती। परा जीव के प्रारब्ध के साथ जुड़कर कार्य करती है। धरातल आधिदैविक है। ऊर्जा स्वरूप होती है।

समय के साथ परिवर्तन अपरा के मन-बुद्धि धरातल पर होते हैं। सभ्यता में अन्न बदलता है- मन बदलता है- कामनाएं बदलती हैं। अतः कर्म बदलता है। शिक्षा-ज्ञान का स्वरूप बदलता है। बुद्धि जीवन की दिशा बदलने का प्रयास करती है। जीवन का सम्पूर्ण ढांचा ही दूसरे देश के जैसा दिखाई पड़ता है। खान-पान, वेश-भूषा, भाषा, ज्ञान के विषय आदि सब कुछ, अपरा का क्षेत्र, बदलता दिखाई पड़ता है।

भारतीय सभ्यता ने हर विदेशी आक्रांता के हिसाब से स्वरूप बदला। हर सभ्यता को अपनाती गई, स्वयं बदलती गई। मुगल-अंग्रेज संस्कृति के अवशेष अभी तक हमारे जीवन में रचे-बसे हैं। फिर भी संस्कृति अक्षुण्ण स्वरूप में जीवित है। आत्मा के धरातल को कोई छू नहीं पाया। सबको भौतिक सुख ही लक्षित था। अपरा से आगे नहीं बढ़ सके। हां, अंग्रेजों ने भाषा के माध्यम से अंग्रेजी ज्ञान की स्थापना करने का प्रयास किया। अभिजात्य वर्ग में आज भी इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति का प्रदूषण बनकर बैठा है। क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में न भारतीय दर्शन है, न आत्मा की चर्चा है। अधिदैव पूर्ण रूप से बाहर ही है। अधिदैव भारतीय दर्शन का मूल है। अंग्रेजी साहित्य-शिक्षा ने भारतीय जीवन को खण्डित करने का प्रयास किया। हमारी शासन व्यवस्था पूरी तरह अंग्रेजी-दां बनी पड़ी है। उसे भारतीय होने की थोड़ी भी जिज्ञासा नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय पलायन करने को उत्सुक रहते हैं।

इतना ही नहीं, अंग्रेजी शिक्षा ने एक ओर भारतीय दर्शन से विमुख किया, वहीं दूसरी ओर पौरुषीय शिक्षा के रास्ते स्त्रियों को भी पौरुषीय मानसिकता में ढालना शुरू कर दिया। उनकी स्त्रैण भूमिका ही सिमटकर रह गई। उनके सपने पौरुषेय हो गए। परिवार व्यवस्था खण्डित ही नहीं, चूर-चूर हो गई। जीवन शुद्ध आधिभौतिक हो गया। शरीर और सुविधा-भोग आधारित हो गया। कॅरियर रह गया, मानव खो गया। संवेदना खो गई। बुद्धि का एकमात्र आधार और लक्ष्मी की आराधना रह गई। लक्ष्मी जड़ प्रकृति है- अर्थवाक् है, पृथ्वी है, शरीर है।

भारत में मानव आत्म-स्वरूप है, शाश्वत है। शरीर उसका वस्त्र है, बदलता रहता है। आत्मा न पुल्लिंग है, न ही स्त्रीलिंग। नई शिक्षा ने अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त अंग्रेजी-दां स्त्रियों को इसी श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। शरीर से स्त्री होकर भी पुरुष की भांति जीना चाहती हैं। न उनको विवाह करने की आवश्यकता लगती है, न ही मातृत्व की लालसा रह गई है। एक शब्द पैदा हो गया इस देश में- 'लिव-इन-रिलेशन'। इसका आधार है अमरीकी अवधारणा (उत्पादों के संदर्भ में) 'यूज एण्ड थ्रो'- काम में लो और फेंक दो। अर्थात स्त्री एक संसाधन बनकर रह गई। सभी घरों से बेघर हो गई।

नई शिक्षा ने पुरानी परम्पराओं की ओर आक्रामकता दिखाई। मानो माया इस सभ्यता को उजाड़ देना चाहती हो। नई शिक्षा ही माया रूप है। यही कलियुग का अंत करेगी। किसका घर उजड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माया का आसुरी स्वरूप चारों ओर दिखाई पड़ता है। हर डूबने वाले को उपलब्ध हो रही है। युद्ध भूमि की सबसे बड़ी फसल मुक्त स्त्रियां ही होती हैं। अहंकृति पर आकृति भी भारी पड़ जाती है। माया मौत का ऐसा कुआं है जो मानव को अन्य योनियों में पहुंचाता है। ऋत होने से पकड़ भी नहीं सकते।

वास्तव में माया स्त्री-पुरुष दोनों शरीरों में कार्य करती है। दोनों का आधा भाग पुरुष, आधा भाग स्त्री होता है। भीतर में पुरुष सौम्य है किन्तु अधपका है। तुरन्त स्त्री की ओर लपक पड़ता है। नई स्त्री भी उतनी सौम्य नहीं है। उसका भी पौरुष भाग बराबरी का हो जाता है। व्यवहार में दोनों पुरुषवत् होते हैं। दोनों में आग्नेयता की प्रधानता हो जाने से दोनों को सोम ही चाहिए। किन्तु दोनों में सोम अत्यल्प रह जाने के कारण दोनों का काम भी अल्पजीवी हो जाता है। असंतुष्ट होकर स्त्री को ही अलग होना पड़ता है। पुरुष का 'एकोऽहं बहुस्याम्' का सपना पुनः खोज में निकल पड़ता है।

स्त्री की आग्नेयता में पुरुष का सोम जल जाता है। शून्यता उसे निष्ठुर बना देती है। शिक्षा में संस्कार है ही नहीं। वह पशुवत-स्वच्छन्द हो गया। विवर्त नहीं होना ही पुरुष की मृत्यु है। जिस प्रकार शिक्षा ने स्त्री के स्त्रैण को बदला, पुरुष का स्त्रैण भी बदला। दोनों ही आक्रामक हो गए। ज्ञान का अभाव, स्व की अज्ञानता ही पुरुष को बन्धक बना देती है। शक्ति भीतर के स्वरूप को कहते हैं। पुरुष शून्य और स्त्री शक्तिमान हो चली। अब वह आसुरी संस्था पर प्रहार करने लगी। भिन्न-भिन्न स्वरूप भिन्न-भिन्न देश ही उसके आयुध होते हैं। पुरुष के विवर्त को रोककर युग का अन्त करने को आतुर दिखाई पड़ती है। माया फिर भी निराकार है, अस्तित्वहीन है।

उधर, पुरुष की निर्भरता कर्म पर है, धर्म पर है। कर्मफल ही भाग्य है। पुरुषार्थ का लक्ष्य ही मोक्ष है। पुरुष ब्रह्म का आश्रय है। विवर्त के लिए शरीर धारण करता है, माया उसे मोह के आवरण में छिपाती है। पुरुष कर्म की सहायता से इस बन्धन से मुक्त होता है। विद्या को साधन बनाता है। श्रेय और प्रेय दोनों से मुक्त होना सीख लेता है। गीता का लक्ष्य मोह के आवरण को हटाना, वैराग्य बुद्धि योग स्थापित करते हुए फल के प्रति अनासक्त कर देना है। तब माया को मौन एवं शान्त होना पड़ता है।

माया पुरुष का भाग्य तय करती है– कर्मफलों के अनुरूप। पुरुष उससे भी आगे बढ़कर नया भाग्य बनाने का प्रयास भी करता है। स्वयं प्रकृति उसके भाग्य के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती जाती है। उदाहरण के लिए प्रकृति को मालूम था कि मुझे भविष्य में अस्तित्व के लिए - सत्य आधारित संघर्ष करना पड़ेगा। विजयी भी होना है। संघर्ष का स्वरूप भी माया को मालूम ही था। अतः मुझे समय से बहुत पहले प्रशिक्षण के लिए सेना में भेज दिया। कोई वणिक पुत्र स्वप्रेरणा से ऐसा नहीं करेगा।

पुरुष ही कर्म करता है, स्त्री ऋत रूपा है। उसके कर्म उसके पुरुष से जुड़ते हैं। यह नियति का बड़ा सिद्धांत है। आज की स्त्री इससे सहमत नहीं है। वह स्वयं अपने कर्म के फल भी खाना चाहती है, पेड़ ही नहीं बन सकती। स्वयं को जमीन में गड़ना पड़ता है–मां को। स्वयं के लिए नहीं जी सकती। आज की स्त्री का मार्गदर्शक पिता होता है। वहां से शिक्षा और बुद्धिमत्ता का पोषण होता है। वही उसके स्त्रैण भाव को ध्वस्त कर देता है। अहंकार स्फीत होता है। कॅरियर आग में घी डालता है। इसका तो श्रेष्ठतम उदाहरण महाभारत की मछुआरी कन्या सत्यवती है। महर्षि पाराशर के संग होकर, उसके पुत्र को जन्म देकर भी उसके साथ इसलिए नहीं रहीं, क्योंकि उसके पिता ने उसे समझा रखा था कि संन्यासी से विवाह नहीं करना है। वह संसार से हारकर भागा होता है। राजा संसार पर विजयी होकर राज करता है। वही विवाह के योग्य है। उसने पति के स्थान पर पिता की सलाह को स्वीकार किया और कुलनाश को प्राप्त हुई।

आज की शिक्षित स्त्री का भी लगभग ऐसा ही हाल दिखाई पड़ता है। उसे प्रकृति का ज्ञान नहीं होता। अतः कॅरियर भोगने में ही अपना स्त्रैण सुख, मातृत्व, वात्सल्य, माधुर्य आहुत कर देती है। उसका आत्मा कहीं और होता है।

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

काव्यांजलि...

एक फूल का आत्मवृत्त

अरुण आदित्य

अपने बारे में बात करना
बिलकुल अच्छा नहीं लगता
पर लोगों की राय है कि
मैं एक विशिष्ट फूल हूं

85 प्रतिशत मधुमक्खियों का
मानना है कि सबसे अलहदा है
मेरी खुशबू
और 87 प्रतिशत भौंरों की राय है
कि औरों से अलग है मेरा रंग

टहनी से तोड़ लिए जाने
के बाद भी
बहुत देर तक बना रह सकता हूं
तरोताजा
किसी भी रंग के फूल के साथ
किसी भी गुलदस्ते की शोभा में
लगा सकता हूं चार चांद

मुझे चढ़ाने से प्रसन्न
हो जाते हैं देवता
और मेरी माला पहनते ही
वशीभूत हो जाते हैं नेता

मेरी एक छोटी सी कली
खोल देती है प्रेम की संकरी गली

यहां तक आते-आते लडखड़ा गई
है मेरी जुबान
जानता हूं कि बोल गया हूं
जरूरत से कुछ ज्यादा
पर क्या करूं यह ऐसी ही
भाषा का समय है
कि ऐसे ही बोलकर बड़े-बड़े बोल
महंगे दामों पर बिक गए
मेरे बहुत से दोस्त
पर मेरी जबान ने लडखड़ाकर
बिगाड़ दिया मेरा काम

ऐसे वक्त पर जो
लड़खड़ा जाती है यह जुबान
दुनिया की दुकान में
क्या इसका भी
कोई मूल्य है श्रीमान?

कहानी...

दोनों मुड़कर जाते हुए नम आंखें और होंठों पर हल्की सी दबी मुस्कुराहट बिखेर गए। यहां मैं फिर से कहना चाहूंगा दोनों में प्यार कितना है यह तो पता नहीं चल पाया परंतु दोनों एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं।

प्यार कितना है पता नहीं

डॉ. संजय गौड़
कथाकार
@patrika.com

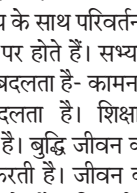

सागर अपने विचारों को थामने के प्रयास में विफलताओं का सामना किए जा रहा था, तभी अवसाद ग्रस्त मन की व्याकुलता ने आंखों के रास्ते लुढ़कना शुरू कर दिया। आखिर थोड़ी सी देर की मानसिक उठा-पटक के बाद मन शीतल, शांत और हल्का सा हो गया। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में पर्दे का मंजर इस कदर बदल जाएगा। सागर जहां अरमान संजोए उचित अवसर का इंतजार कर रहा था, और स्थिति यह आ गई कि अब इंतजार का अवसर भी उपलब्ध न रहा।

हालांकि कल मुलाकात का वादा तो किया है मधु ने, पर कहीं इस मुलाकात में कुछ आश्चर्य करने वाला ना हो जाए। न जाने क्यों मन विचलित हुए जा रहा था। बहरहाल मुलाकात का वक्त आ गया और रेस्टोरेंट की टेबल पर समय ठहर गया। आज न जाने क्यों कुछ ज्यादा ही सादगी के साथ मादकता छलक रही थी मधु के चेहरे से और सागर बड़े निर्भीक शब्दों में अपनी बातों को रख पाने का हौसला जुटा रहा था। आज तक भले ही आंखों के रास्ते दिल तक उतर जाने के प्रयास में सागर ने अपने दिल का हाल अपनी शून्यता से बयान करता रहा था। परंतु आज जुबान पर भावनाएं शब्दों में ढल कर दिल का हाल उभारे उससे पहले ही मधु ने कह दिया, मैं जानती हूं सागर आप क्या कहना चाह रहे हो, इतना तो आपको समझती हूं मैं भी, पर कृपया अब कह कर मुझे मेरी नजरों में ही अपराध बोध ना करवाओ, मेरे मन में कहीं जीवनभर की टीस रह जाएगी। यह कहते हुए मधु ने सागर के हाथों को दिलासा देने के लिए अपने हाथों से थाम लिया। मधु की इस छुअन से सागर सिहर सा गया। जिसे आज तक केवल माह में एकाध बार कॉफी पीने के बहाने से मन भर के देख पाता था, उसने पहली बार उसे छुआ था।

हां यह प्यार तो था, एक सादगी भरा, मित्रता से भरा, शायद एक समझदारी से भरा हुआ परिपक्वता वाला प्यार, जो समाज और शब्दों की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता, चाहे वह स्वयं टूट कर बिखर जाए। सागर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके पास व्यक्तित्व से लेकर ऐश्वर्य सहित वह सब कुछ है जो एक लड़की अपने जीवनसाथी में देखना चाहती है। वहीं मधु भी सुंदर, सुशील व राजकीय सेवा में सेवारत है। फोन पर बात करने के साथ ही कभी कभार दोनों किसी समारोह में आमने-सामने हो जाया करते थे। जहां दोनों की भावनाएं एक दूसरे को आदर के साथ निहारती रहती थीं। प्यार कितना है दोनों में यह तो पता नहीं परंतु दोनों एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं। परंतु क्या मात्र सम्मान से ही जीवन की नैया चल पाती है। इस नैया को खेने के लिए दोनों पतवारों को सम्मिलित प्रयास करना पड़ता है, नदी की धारा में उतरना पड़ता है।

जीवन को जीने के लिए एक समझदार संतुलन बनाए रखने वाला जीवनसाथी अति आवश्यक है। मधु ने यह व्यक्तित्व सागर में पाया था। कहीं ना कहीं उसकी तलाश यहां विराम पाने को ही थी, परंतु समाज के बाहर न जाने की पिताजी की जिद उसके हौसले को बराबर धरातल दिखाती रहती थी। अपने मन में उफन रहे इस समंदर को वह कभी भी शब्दों में डालने का साहस नहीं कर पाई थी। सागर भी मधु को पसंद करता था, और सही समय देखकर यह बात रखना भी चाह रहा था। हां कभी-कभी विभिन्न माध्यमों से सागर ने अपने अंदर चल रहे ज्वार को प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया था। जिसे मधु भी समझ चुकी थी। परंतु दोनों ने कभी भी अपने मध्य सभ्यता, संस्कार और समझदारी की दीवार को ढहने नहीं दिया था।

खैर, रेस्टोरेंट की कॉफी ठंडी हो चली थी। मधु ने सागर को बताया कि पिताजी ने पास ही शहर के उसी के समाज के अच्छे लड़के से उसकी बात तय कर दी है। एक बार अपने विफल जीवन से चोट खाई मधु ने सहर्ष यह रिश्ता आगे चलकर स्वीकार कर लिया था। अपने पिताजी का मान रख कर उनका निर्णय स्वीकार कर मधु ने एक आदर्श पुत्री होने का परिचय दिया था। मधु के दबे शब्दों में जैसे ही इस बात ने ध्वनि का आकार पाया, सागर की आंखों में स्पष्टता छलक गई। खामोशी ने मन का ज्वार शिथिल कर दिया था।

परंतु यहां प्रश्न यह है कि आज सागर और मधु इस कॉफी मेज पर आमने-सामने छलकने को आतुर नम आंखों के साथ उपलब्ध क्यों है। जबकि दोनों की राहें कभी साथ नहीं रहीं, ना ही कभी भविष्य में दोनों की राहें साथ होने वाली है। शायद यही है वह निस्वार्थ प्रेम जो आज भी जीवन का आधार है। दोनों अपनी ठंडी बातें और कॉफी को पूरी करके भारी कदमों के साथ अपने घर की तरफ जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। जाते-जाते, मुड़कर जाते हुए नम आंखें और होंठों पर हल्की सी दबी मुस्कुराहट बिखेर गए। यहां मैं फिर से कहना चाहूंगा दोनों में प्यार कितना है यह तो पता नहीं चल पाया परंतु दोनों एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं।

क्लासिक पुस्तक...

अनाथों व बाल श्रमिकों के कष्ट दर्शाती पुस्तक

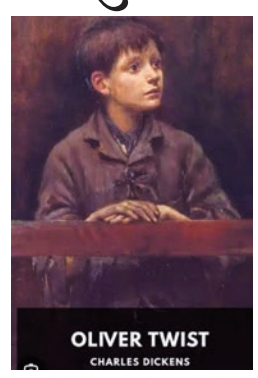

'ओलिवर ट्विस्ट' विश्व प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकेंस का 1830 के दशक में लिखा क्लासिक उपन्यास है। यह उस समय लंदन में गरीबी का यथार्थ दिखाने वाली उनकी पहली पुस्तक थी, जो लेखक की इस धारणा को दर्शाती है कि गरीबी अपराध और दुर्भाग्य का जीवन पैदा कर सकती है। सबसे शुरुआती सामाजिक उपन्यासों में से एक, 'ओलिवर ट्विस्ट' ने 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में अनाथों के कष्ट और बालश्रम के क्रूर व्यवहार को उजागर किया।

यह एक अनाथालय में पले लड़के की दुख भरी कहानी है। वह कठोर जीवन से बचने के लिए लंदन भाग जाता है, लेकिन वहां वह फैगिन के नेतृत्व में किशोर जेबकतरों के एक गिरोह के चंगुल में फंस जाता है। शोषण और हिंसा से जूझते हुए वह अपनी पहचान और अच्छाई की तलाश करता है और अंततः दयालु परोपकारी लोगों द्वारा बचाया जाता है। उसे अपने असली पारिवारिक इतिहास का पता लगाता है।

ओलिवर ट्विस्ट का चरित्र रॉबर्ट ब्लिंको की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित था, जो अनाथ था व कपास मिल में एक बाल मजदूर के रूप में काम करता था। डिकेंस ने खुद एक कारखाने में बाल मजदूर के रूप में काम किया, एक ऐसा अनुभव जिसने संभवतः उपन्यास के विषय को प्रभावित किया। यह उपन्यास विक्टोरियन युग के बाल श्रम, गरीबी और कारखानों में गरीबों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की सामाजिक आलोचना करता है।

डॉ. आरके माथुर, लेखक

(आपने भी पढ़ी है ऐसी ही कोई क्लासिक पुस्तक तो अपने अनुभव 200 शब्दों में साझा करें।)

लघुकथा...

परिवार

वह सात वर्ष से अमरीका के न्यूयॉर्क में इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। पत्नी और एक पुत्र के साथ बड़े मौज में रह रहा था। माता-पिता भोपाल में रहते थे, वर्ष में एक बार वह माता-पिता के पास चार-पांच दिन के लिए आता। कभी पत्नी और पुत्र साथ होते कभी नहीं भी ला पाता।

बूढ़े होते माता-पिता को उसके आने का बड़ा चाव रहा करता था। नौकरी प्राइवेट आईटी कंपनी में थी, एक दिन अचानक कंपनी ने सभी भारतीयों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। नोटिस देखकर वह भी स्तब्ध हुआ, कुछ दिन दूसरी नौकरी का प्रयत्न किया, किन्तु कहीं सफलता नहीं मिली। थक-हारकर उसने अमरीका छोड़कर भारत लौटने का निश्चय कर लिया और सबकुछ समेटकर पत्नी और पुत्र के साथ अपने घर भोपाल लौट आया। वह और उसकी पत्नी अमरीका की नौकरी छूटने से दुखी थे, पर माता-पिता पूरे परिवार को एक साथ पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए।

- उमेश कुमार चौरसिया

माइंड गेम...

अनेक शब्द के एक शब्द

नीचे दिए अनेक शब्दों के एक शब्द तलाशिए।

1.गिरा हुआ हो	6.खून से रंगा	11.आया हुआ	16.पद से हटाया
2.जिसमें दया हो	7.कुंती का पुत्र	12.पूर्व दिशा	17.तेज वाला
3.धैर्य न हो	8.करने योग्य	13.आंखों से परे	18.पश्चिम दिशा
4.छाती का घाव	9.उत्तर दिशा	14.नीचे लिखा	19.पीने की इच्छा
5.गंगा का पुत्र	10.इंद्र का महल	15.अंधेरी रात	20.दक्षिण दिशा

1.पतित 2.दयालु 3.अधीर 4.उरक्षत 5.गांगेय 6.रक्तरंजित 7.कौंतेय 8.कर्तव्य 9.उदीची 10.वैजयंत 11.आगत 12.प्राची 13.परोक्ष 14.अधोलिखित 15.तमिस्रा 16.पदच्युत 17.तेजस्वी 18.प्रतीची 19.पिपासा 20.अवाची।

भारत की पहली महिला पैराग्लाइडिंग पायलट...

बचपन में देखा था ऊंचाइयों का सपना

त्सेवांग ड्रोमा

महिलाओं को अक्सर खतरनाक और जोखिम वाले खेलों में शामिल होने से हतोत्साहित किया जाता है। लेकिन अरुणाचलप्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरंग निवासी फुंटसो ने अपनी बेटी को इसके लिए प्रोत्साहित किया। नतीजतन उनकी बेटी त्सेवांग ड्रोमा किसी अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे भारत की पहली महिला पैराग्लाइडिंग पायलट भी हैं। 2022 में वे मेघालय ओपन पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप और एशियाई लीग क्वालिफिकेशन में भारतीय महिला वर्ग में उपविजेता रही थीं। उन्होंने 8 फरवरी से 12 फरवरी 2024 के बीच आयोजित 8वें थाईलैंड पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी आसियान फ्रेंडशिप ओपन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

त्सेवांग ड्रोमा एयरो क्लब ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय और इंटरनेशनल पायलट प्रोफिशिएंसी इंफॉर्मेशन प्रमाणित लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। वे कहती हैं, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली महिला पायलट के रूप में अपने देश और राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर मुझे गर्व है।' ड्रोमा ने चार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। उन्हें त्सेवांग डोलमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वर्तमान में वह बोमडिला में रहती हैं। दुर्गम पहाड़ियों के बीच पली-बढ़ीं त्सेवांग ने बचपन से ही आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा था। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने पैराग्लाइडिंग की बारीकियां सीखीं और वह भारत की पहली ऐसी महिला पायलट बनीं, जिन्हें एसोसिएशन ऑफ पैराग्लाइडिंग पायलट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स द्वारा रेटिंग प्राप्त हुई। उन्होंने अरुणाचल के शेरगांव जैसे क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए शेरगांव एडवेंचर क्लब के साथ मिलकर कई साहसिक पहल की हैं।

अक्टूबर 2026 में होने वाले चौथे उत्तर पूर्वी भारत के खेलों में पैराग्लाइडिंग एक आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया जा रहा है, जिससे त्सेवांग और अन्य क्षेत्रीय पायलटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और बड़ा अवसर मिलेगा।

शॉर्ट रीड — *साहित्य वही है जो समय से सवाल करता है- राजेंद्र यादव*

आपकी बात...

सारे विषय समेटे हुए है

परिवार सामाजिक लेख, गुलाब कोठारी जी के समसामयिक विषयों पर आधारित लेख, कहानी, फूड रेसिपी सहित परिवार से जुड़े विभिन्न विषयों को समेटे हुए आता है। घर के सभी सदस्य परिवार को पूरा पढ़कर ही दम लेते हैं। यह पूरे सप्ताह हमें उत्साहित रखता है। **- निर्मला वशिष्ठ**

युवाओं का गाइड है

परिवार परिशिष्ट से मुझे बहुत सुखद अनुभव प्राप्त हुआ है। इसकी कवर स्टोरी युवाओं के लिए सीख और गाइड की तरह होती है। इसमें प्रकाशित कहानियां और कविताएं पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये परिशिष्ट अब जीवन से जुड़ गया है। **- विद्या रैगर**

समस्याओं का हल

परिवार परिशिष्ट में हर सप्ताह आने वाला कॉलम परिवार मंच मुझे अच्छा लगता है, जिसमें पाठकों की समस्याओं का हल दिया जाता है। वहीं बच्चों के लिए भी कोना है, जो घर में पसंद किया जाता है। बच्चे कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। **- सुनील**

फोटो के साथ भेजें

पाठक अपनी प्रतिक्रियाएं परिवार परिशिष्ट के साथ सेल्फी/फोटो लेकर भेजें। चुनिंदा प्रतिक्रियाएं 'आपकी बात' कॉलम में प्रकाशित की जाएंगी। आप अपनी प्रतिक्रिया परिवार फेसबुक पेज के क्यूआर कोड को स्कैन कर कमेंट बॉक्स में भेजें।

parivar@epatrika.com

9057531688

घर-बाहर...

हाउसवाइफ का अर्थशास्त्र

***जब** भी कमाने वाले की चर्चा होती है, तो हम उसकी बात करते हैं, जो घर से बाहर नौकरी कर वेतन लाता है। लेकिन कभी हमने उसके श्रम का मूल्य नहीं आंका, जो घर में रहकर अनगिनत कार्यों का निर्वहन बिना वेतन, बिना अवकाश, बिना औपचारिक मान्यता के करती है। हाउसवाइफ केवल घर नहीं संभालती, बल्कि वह परिवार की अर्थव्यवस्था की अदृश्य धुरी है।*

अवैतनिक श्रम

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और विभिन्न आर्थिक अध्ययनों में यह स्वीकार किया गया है कि हाउसवाइफ के घरेलू कार्य को बाजार दरों पर आंके, तो यह किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा होता है। भारत के समय-उपयोग सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि महिलाएं, पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक समय अवैतनिक घरेलू कार्यों में लगाती हैं। यह समय शारीरिक श्रम का ही नहीं, बल्कि मानसिक योजना और प्रबंधन का भी होता है। इनकी न्यूनतम वेतन दर हजारों रुपए आंकी गई है।

सीमित आय में बचत

गृहिणी सीमित आय में पूरे महीने का बजट बनाती है। वह जानती है कि किस सप्ताह कौन-सी वस्तु लेनी है, कहां खर्च रोकना है और कहां आवश्यक निवेश करना है। जैसे-

- मौसमी सब्जियों और अनाज का चयन
- थोक में खरीदकर बचत करना
- बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की योजना
- आकस्मिक परिस्थितियों के लिए धन सुरक्षित रखना

उसकी समझ किसी प्रशिक्षित वित्त प्रबंधक से कम नहीं होती। उसकी बचत का रुपया, कमाए हुए रुपए के बराबर है। महिलाएं छोटी बचत और ऋण प्रबंधन से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करती हैं।

संसाधनों का पुन- उपयोग

आज पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रही है, तब महिलाएं वर्षों से इसे व्यवहार में ला रही है। जैसे-

- बचे हुए भोजन से नया व्यंजन बनाना
- पुराने वस्त्रों को नए रूप में उपयोग करना
- जल और बिजली की बचत पर ध्यान देना
- घर के अनावश्यक अपव्यय रोकना

वह अनजाने में ही सतत विकास का मॉडल प्रस्तुत करती है।

भावनात्मक और सामाजिक पूंजी

हाउसवाइफ का योगदान केवल आर्थिक नहीं है। वह परिवार के लिए भावनात्मक और सामाजिक पूंजी का निर्माण करती है। बच्चों को अनुशासन, संस्कार, सहानुभूति और आत्मविश्वास सिखाती है। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और सामंजस्य बनाए रखती है।

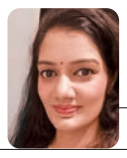

डॉ. माधुरी सोनी
समाजशास्त्री
@patrika.com

हैंडलूम प्रेम

हैंडलूम में डिजाइन की नई तकनीक ने फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में नए मौके दिए हैं...

शिल्प, शैली और रंगों से भरी 'शिबोरी'

टेक्सटाइल कला की दुनिया नए आयाम गढ़ रही है, 'स्टिच शिबोरी।' कपड़े पर रंग, धागा, बुनावट मिलकर अनगिनत डिजाइन रचते हैं। जापान से शुरू हुई यह तकनीक आज भारत के कई राज्यों में हैंडलूम प्रेमियों की पसंद बन चुकी है। शिबोरी पारंपरिक टाई-एंड-डाई से अलग है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल हस्तकलाकारों के लिए यह रोजगार का नया साधन बन गया है।

धागों में छिपा सौंदर्य

कपड़े को मोड़ना, प्लीट करना, सिलना, बांधना, दबाना या क्लैंप करना और फिर उसे रंग में डुबो देना। कपड़े के जो हिस्से कसकर बांधे जाते हैं या मोड़कर रखे जाते हैं, वहां बंधेज की तरह ही रंग नहीं पहुंचता और जब कपड़ा खुलता है, तो उस पर उभरता है एक अद्भुत पैटर्न।

इन नई तकनीकों के साथ

कानुको- जिसे भारतीय टाई-डाई जैसा माना जाता है, लेकिन ये अधिक सूक्ष्म और नियमित बिंदु पैटर्न हैं।

अराशी- कपड़े को बांस या पाइप पर लपेटकर बनाते हैं, पैटर्न बारिश की धार जैसा दिखता है।

इटाजिमे- लकड़ी या धातु की प्लेटों से कपड़े को दबाकर दोहराव वाले ज्यामितीय डिजाइन बनते हैं।

क्यों बनी पसंद?

कलाकार शिव मेहता बताते हैं कि इसे नई शिबोरी कहा जाता है। इसमें हर कपड़ा अलग होता है, हर पैटर्न नया। यही इस कला को फैशन डिजाइनर्स और हैंडलूम प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। यह शत-प्रतिशत हस्तनिर्मित होती है, इसलिए हर डिजाइन में कलाकार का अनोखा स्पर्श होता है। प्राकृतिक रंगों और कपड़ों के उपयोग के कारण यह फैशन की दुनिया में हाथों-हाथ ली जा रही है।

इन कपड़ों पर खिल रही

नई शिबोरी प्राकृतिक फाइबर पर खूब उभरती है, क्योंकि इन पर प्लीटिंग और डाई दोनों सहजता से बैठते हैं। कॉटन, लिनेन, चंदेरी, टसर सिल्क और मलबरी सिल्क पर इसके पैटर्न खिलते हैं। साथ ही रेयॉन और मॉडाल सिल्क पर शिबोरी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। यह युवा डिजाइनरों के लिए नया कॅरियर ऑप्शन भी है। इसकी मांग फैशन और हैंडलूम ब्रांड्स में बढ़ी है।

महिला सशक्तीकरण को मिला बढ़ावा

यह उन महिलाओं के लिए एक नया अवसर है, जो कला से आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहती हैं। गृहस्थी के कामों के बाद प्रतिदिन 3-4 घंटे का समय देकर महिलाएं आसानी से इसके माध्यम से हजारों रुपए कमा रही हैं। शिबोरी कलाकार कुसुम बाई व कराई बाई कहती हैं कि स्थानीय स्वयं सहायता समूह के जरिए इस कला को बाजार व फैशन की दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है।

सौंदर्य जगत...

घूमने जा रहे हैं, तो साथ रखें ये 5 प्रोडक्ट

गर्मियों के मौसम में घूमने जाना भी मुश्किल टास्क है। टेनिंग, सनबर्न से खूबसूरती चौपट हो जाती है। ऐसे में यात्रा में अपने साथ ये पांच जरूरी सौंदर्य प्रसाधन रखें, ताकि आप रहें फ्रेश।

फेस वाइप्स: गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी पसीने से होती है। ऑयली त्वचा पर गंदगी, तेल जम जाता है। ऐसे में फेशियल वाइप्स का प्रयोग आसान, सुविधाजनक है। वाइप से चेहरा पोंछने से त्वचा तुरंत साफ हो जाती है।

वाटर प्रूफ काजल: काजल के बिना आंखें अधूरी सी रहती हैं। गर्मी और पसीने से काजल फैलने की समस्या आम है। इससे बचने के लिए वाटर प्रूफ काजल का इस्तेमाल करें। जेल आधारित काजल 12 घंटों तक टिका रहता है, जिसे आप ब्रश की मदद से लगा सकती हैं।

ग्लिटर: छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो रात की पार्टियों में भी जाना पड़ता है। रात के समय आंखों और नाखूनों के लुक को बेहतर करने के लिए ग्लिटर का प्रयोग करें। ग्लिटर नाखूनों को नया लुक देता है।

ड्राई शैम्पू: ट्रेवल में समय की हमेशा कमी रहती है और बालों को धोने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में ड्राई शैम्पू मददगार साबित हो सकता है। इसे सिर की त्वचा पर लगाया जाता है।

शहनाज हुसैन
लेखिका अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ हैं
@patrika.com

रेसिपी

गर्मियों का स्वागत कीजिए अपने पसंदीदा चटपटे अचार के साथ

पंचकुट्टा अचार

तैयारी का समय: **15** मिनट
बनाने का समय: **20** मिनट
सर्विंग: **10** लोगों के लिए

सामग्री: 2 कप -सूखा पंचकुट्टा (केर,सांगरी, अमचूर, गूंदा, सूखी लालमिर्च), 2 चम्मच सरसों का तेल, 1/2 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर

विधि: सांगरी, कुमटिया, गूंदे, साबुत अमचूर व साबुत लाल मिर्च पानी में भीगो 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। कुकर में दो गिलास पानी डाल भीगे हुए केर, सांगरी, साबुत अमचूर, साबुत लालमिर्च व 1/4 चम्मच हल्दी डाल सिटी लगा दें। ठंडा होने पर पानी निकाल दीजिए। कढ़ाही में तेल गर्म कर हींग, जीरा-राई, कलौंजी डालकर, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर, पंचकुट्टा मिला दीजिए और सभी मसाले अच्छे से मिक्स करें। 5-7 मिनट पका लीजिए। इसे आप 4-5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

तनूजा शर्मा, फूड ब्लॉगर
@patrika.com

सहजन का चटपटा अचार

सामग्री: 250 ग्राम सहजन की फलियां, साबुत मसाले जैसे- 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई, 1/4 चम्मच कलौंजी, 8-10 काली मिर्च, पीसे हुए मसाले जैसे- 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच नमक, 1 कप सरसों का तेल

तैयारी का समय: **10** मिनट
बनाने का समय: **20** मिनट
सर्विंग: **10** लोगों के लिए

विधि: सहजन की फलियों को चाकू से हल्का-हल्का ऊपर से रगड़ कर छील लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालकर 5 मिनट पानी में उबाल लें और सुखने रख दें। एक कप तेल को गर्म करके ठंडा करें। सभी साबुत मसालों को एक पेन में भून लें और ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लें। सहजन की फलियों में सभी पीसे हुए मसाले और दरदरे पीसे हुए सारे मसाले डालें। ऊपर से तेल डालें। अच्छे से मिक्स करें और कांच के डिब्बे में रखें तैयार अचार को 2 दिन धूप में रखें। यह एक महीने तक खराब नहीं होगा।

नेहा खानपुरिया, फूड ब्लॉगर
@patrika.com

प्याज का झटपट अचार

तैयारी का समय: **10** मिनट
बनाने का समय: **15** मिनट
सर्विंग: **4** लोगों के लिए

तृप्ति देव, फूड ब्लॉगर
@patrika.com

सामग्री: 10 छोटे प्याज दो टुकड़ों में कटे हुए, सिरका/नींबू रस 2 चम्मच, अचार मसाला स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, लाल कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, राई 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, तेल (तड़के के लिए) 4 चम्मच

विधि: प्याज में सिरका, नमक, मिर्च और अचार मसाला मिलाएं। एक छोटे पैन में तेल गर्म करके राई और हींग का तड़का लगाएं। तड़का ठंडा होने के बाद अचार में डालें। अच्छी तरह मिलाकर परोसें। अचार 4-5 दिन तक स्टोर किया जा सकता है।

केर सांगरी का अचार

सामग्री: केर 1 कप , सांगरी 1 कप, नमक, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, मेथी दाना आधा छोटा चम्मच, राई 1 छोटा चम्मच, हींग, अमचूर पाउडर, सरसों का तेल

तैयारी का समय: **10** मिनट
बनाने का समय: **20** मिनट
सर्विंग: कई लोगों के लिए

विधि: केर और सांगरी को उबाल लें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म कर राई, मेथी दाना, सौंफ और हींग डाल भून लें। उबली हुई केर-सांगरी डालें। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, अमचूर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर डाल हल्की आंच पर पकाएं। अचार को ठंडा होने दें। साफ और सूखे कांच के जार में भरकर स्टोर करें।

प्रगति भटनागर, फूड ब्लॉगर
@patrika.com

इमली वाले गूंदे का अचार

तैयारी का समय: **15** मिनट
बनाने का समय: **20** मिनट
सर्विंग: कई लोगों के लिए

सामग्री: 500 ग्राम गूंदे, 100 ग्राम इमली का पल्प, डेढ़ सौ ग्राम तेल, आधा छोटा चम्मच हींग, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, और हल्दी पाउडर

विधि: गूंदों को 80% पकने तक उबालें। ठंडा होने पर गुठली निकालें। नॉन स्टिक कढ़ाही में तेल गर्म कर हींग डालकर गूंदे मिला लेंगे। अब उसमें नमक, मिर्च, हल्दी डालकर 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे। अंत में उसमें इमली का पल्प डालकर 5 मिनट और पकाएंगे। जब इमली का पल्प और गूंदे तेल छोड़ देंगे, तब गैस बंद कर देंगे। इसे बनने के तुरंत बाद खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

रेनू माथुर, फूड ब्लॉगर
@patrika.com

ड्राई फ्रूट अचार

तैयारी का समय: **15** मिनट
बनाने का समय: **15** मिनट
सर्विंग: **10** लोगों के लिए

विनित सांड
फूड ब्लॉगर
@patrika.com

सामग्री: 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी किशमिश, 1 कटोरी खजूर बिना गुठली, 1 कटोरी मिक्स बी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 15-20 केसर लच्छे, 1 कटोरी सिरका व पानी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच दरदरी सौंफ, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच दानामेथी, 1/4 छोटा चम्मच हींग, नमक, 4 बड़े चम्मच गुड़

विधि: मिक्स बीज, काजू, किशमिश, खजूर और बादाम को छोटे टुकड़ों में काटकर भिगो दें। पैन में पानी व गुड़ का चूरा डाल मध्यम आंच पर उबालें। इसमें सिरका एवं सभी मसाले डालकर तब तक पकाएं, जब तक कि मिश्रण एक तार की चाशनी जैसा न हो जाए। अब आप पानी से मेवे निकालकर चाशनी में डालते जाएं। धीमी आंच पर 10 मिनट तक हिलाते हुए पकाएं, जब तक कि मेवे नरम न हो जाएं। फिर गैस बंद करें और केसर के लच्छे व इलायची पाउडर डालकर मिलाएं और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे कांच की भरनी में भर लें। जब मन करे, इसका प्रयोग करें।

काचरे का अचार

तैयारी का समय: **10** मिनट
बनाने का समय: **20** मिनट
सर्विंग: कई लोगों के लिए

उमा मालपानी, फूड ब्लॉगर
@patrika.com

सामग्री: 500 ग्राम काचरे, 50 ग्राम लालमिर्च, 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम सरसों दाना, 5 ग्राम कलौंजी, हींग, सरसों का तेल, नमक स्वादानुसार

विधि: काचरों को धोकर बीच में कट लगा लें। सौंफ, सरसों दाना अलग रखकर बाकी मसालों को दरदरा पीस लें। कड़ाही में तेल गर्म कर साबुत दाने, हींग व मसाले डाल देंगे। ठंडा कर मसाला काचरो में भरें। सरसों तेल को गर्म कर ठंडा करें। इन काचरों में डाल दें।

किचन हैक्स

*चाकू से अदरक छीलना मुश्किल टास्क है और इससे अदरक का ज्यादातर हिस्सा कचरे में चला जाता है। इसीलिए इसे चम्मच से छीलें, आसानी होगी। *सब्जी में नमक तेज हो गया है, तो उसमें एक कच्चा आलू छीलकर डाल दें।

रेसिपी चैलेंज

टेस्टी नाश्ता रेसिपीज शेयर करें, जो कम से कम गैस खर्च में बन जाए। इसके लिए अपनी रेसिपी शुक्रवार तक परिवार के ईमेल या वॉट्सऐप नंबर 9057531688 पर भेजें। अपनी फोटो भी जरूर भेजें। **नोट- रेसिपी की फोटो इंटरनेट की न हो।**

शॉर्ट रीड

8 वीं शताब्दी से जापान में शिबोरी कला कपड़ों पर प्रचलित रही है। अब यह दुनियाभर में पॉपुलर हो चुकी है।

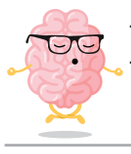

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 02-04-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH08 User: cci Time: 04-01-2026 21:28 Color:

गठबंधन का अर्थ प्रेम नहीं होता, जैसे युद्ध का मतलब घृणा नहीं होता।

– फ्रांसिस पार्कर योकी, अमेरिकी लेखक

संकट में नैटो

दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य अलायंस, नैटो के टूटने की आशंका पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस अलायंस से निकलने की सोच रहा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी इस अलायंस के सहयोगी देशों को अमेरिका के मुकाबले कम वित्तीय सहयोग देने पर खरी-खोटी सुनाई थी। दूसरे कार्यकाल में ईरान युद्ध में, खासतौर पर होर्मुज को खोलने में उनका साथ नहीं मिलने से अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद खफा हैं और इस बीच उनका यह बयान आया है।

नाराजगी की वजह । ट्रंप ने अलायंस को कागजी शेर बताया है। अगर यह अलायंस टूटता है तो पश्चिमी देशों के सहयोग के इतिहास के लिए यह बहुत बड़ी घटना होगी। यूं तो ट्रंप नैटो को लेकर शिकायत लंबे अरसे से दर्ज कराते आए हैं, लेकिन इस बार जिन हालात में उन्होंने नैटो से बाहर निकलने की बात कही है, उन्हें देखते हुए मामला गंभीर लगता है। ट्रंप नाराज हैं, क्योंकि उन्हें ईरान में अकेले लड़ना पड़ रहा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने कह दिया है कि यह उनकी लड़ाई नहीं है।

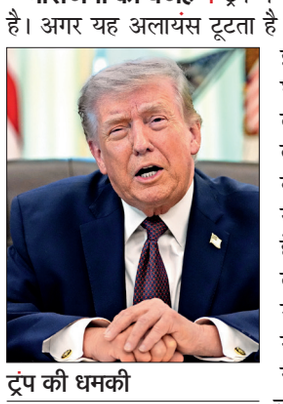

ट्रंप की धमकी

ईरान पर अलगाव । ट्रंप पूछते रहे हैं कि हम जिनके लिए लड़ते हैं, क्या वे हमारे लिए लड़ेंगे? और अब यूरोप के बर्ताव को वह सबूत के रूप में पेश कर रहे हैं। साथ लड़ना तो दूर, ईरान मुद्दे पर यूरोप विरोध में है। ब्रिटेन ने अपने सैन्य बेस की सशर्त इस्तेमाल की इजाजत दी है और स्पेन ने हमलों में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना स्पेस बंद कर दिया है।

अमेरिका फर्स्ट । अमेरिका और नैटो के बीच कुछ मसलों पर मतभेद पहले भी रहे हैं, खासकर आर्थिक योगदान को लेकर। 2014 में तय हुआ था कि सदस्य देश अपनी GDP का 2% रक्षा पर खर्च करेंगे। ट्रंप के लगातार दबाव बनाने के बाद नैटो सदस्यों ने इसे हासिल भी कर लिया है, पर अब बात उसके आगे की है। अमेरिका अभी तक ज्यादा सैन्य और आर्थिक हिस्सा इसलिए दे रहा था, क्योंकि इसके बदले में उसे नेतृत्व मिला हुआ था। लेकिन, ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की है, जहां सहयोगियों से रिश्ता भी नफा-नुकसान पर चलता है।

बदलेगी जियो-पॉलिटिक्स । डॉनल्ड ट्रंप की सोच है कि अमेरिका को उन मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, जहां से उसे कुछ मिल न रहा हो, भले ही इससे अमेरिकी छवि को नुकसान पहुंचता हो। नैटो से अलगाव को अंजाम देना इतना भी आसान नहीं होगा, पर इतना तय है कि यह सैन्य गठबंधन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।

गुस्ताख़ी माफ़

मेले का ठेका

पार्क में सुबह-सुबह काफी चहल-पहल थी। नारे लग रहे थे। पार्क में घुसते ही अपना बल्लू बाश्शा भी बच्चों की टोली के साथ मिल गया।

अखिलेश प्रताप सिंह

'क्यों रे बल्लू, आज तो सुबह-सुबह ही बड़े जोश वाला माहौल बना दिया तूने, क्या बात है?' मेरा सवाल खत्म होता, इससे पहले श्रीमान क आ गए और शुरू हो गए, 'अमर शहीद भगत सिंह की शहादत का दिन है, इसलिए सब लोग उनको याद करने के लिए जमा हुए हैं। अच्छा हुआ आप भी आ गए। सभी मिलकर पार्क का एक चक्कर लगाएंगे और फिर सरदार भगत सिंह के चित्र पर फूल-माला चढ़ाएंगे।'

'वाह! यह तो बहुत अच्छी बात है। सभी को देशभक्त होना चाहिए।' मैंने हामी भरते हुए कहा। पर बल्लू ने बात लपक ली। 'और देशभक्त बनने में कोई मेहनत भी तो नहीं लगती। किसी बड़े आदमी की जयंती चुन लो या उनके शहीद होने का दिन चुन लो। उस दिन सुबह-सुबह सबको लेकर पार्क आ जाओ। फूल-माला जुटा लो। देशभक्ति के गीत गाओ। नारे लगाओ। फिर शहीद के चित्र को माला पहना दो।'

मुझे लग गया कि बच्चा बात को समझ नहीं रहा। 'सिर्फ इतने से देशभक्ति नहीं होती रे बल्लू। शहीदों ने ऊंच-नीच को न मानने और मिलजुलकर रहने का संदेश दिया। शहीद भगत सिंह तो वैज्ञानिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उनसे तो यह भी सीखना चाहिए कि कठमुल्लेपन और अंधविश्वास के बजाय ज्ञान और तर्क की राह पर चला जाए। सिर्फ नारे लगाना और माला पहनाना देशभक्ति नहीं है।' मैंने लंबा भाषण दे डाला।

बल्लू बड़े गौर से सुन रहा था। 'अंकल, सुना तो आपने भी होगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा। लेकिन कुछ लोग इस ताक में रहते हैं कि मेले और फूल-माला के इंतजाम का ठेका उन्हें मिल जाए। यही उनकी देशभक्ति है।' बल्लू इतना कहकर चला गया, पर श्रीमान क नाराज हो गए। क्यों हुए होंगे नाराज?

एकदा

संकलन : **ललित गर्ग**

चापलूसी सही नहीं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके संपूर्णानंद शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वह भारतीय संस्कृति, हिंदी और संस्कृत के गहरे ज्ञाता थे और शिक्षा सुधार के लिए निरंतर कार्य करते रहे।

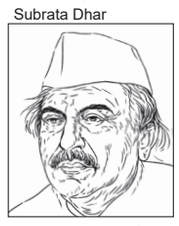

Subrata Dhar

एक बार एक स्कूल के हेडमास्टर उनसे मिलने आए। आते ही उन्होंने 'हुजूर', 'सरकार', 'मालिक' जैसे शब्दों से उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। संपूर्णानंद कुछ देर तक शांत रहे, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ता गया तो वह गंभीर हो गए। उन्होंने हेडमास्टर से कहा, 'आप एक स्कूल के प्रधान हैं। हजारों बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी आप पर है। मैं आपसे उम्र और ज्ञान, दोनों में छोटा हूं। सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाने से आप मुझे इतने बड़े शब्दों से क्यों संबोधित कर रहे हैं? अगर आप हर व्यक्ति के सामने ऐसे ही झुकते हैं, तो यह आदत सही नहीं। इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा।' यह सुनकर हेडमास्टर चुप हो गए। तब संपूर्णानंद ने समझाया कि खुशामद से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि इंसान का सम्मान और व्यक्तित्व छोटा हो जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए चापलूसी नहीं, आत्मसम्मान, सचाई, योग्यता और अच्छे चरित्र की जरूरत होती है।

पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने पर पति के विरुद्ध नहीं चल सकता मुक़दमा

क़ानून की ये कमी औरतों से नाइंसाफ़ी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक व्यक्ति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप को खारिज कर दिया। यह इल्जाम उसकी पत्नी ने लगाया था।

राजेश चौधरी

अदालत ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत वैध विवाह के भीतर ऐसे आरोपों पर मुकदमा नहीं हो सकता। इसके बाद सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर मैरिटल रेप को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।

परिभाषा बदली । भारत के कानून में मैरिटल रेप के मामले में पति को अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा चुकी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कानून में कोई विरोधाभास (गैप) है।

मैरिटल रेप नहीं । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर शिकायतकर्ता के आरोपों को एकबारगी सही भी मान लिया जाए, तब भी वह वैवाहिक संबंध के दायरे में हुआ है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत यह अपराध नहीं है। अदालत ने कहा कि 2013 के संशोधन के बाद IPC की धारा 375 में ओरल और अननैचुरल (अप्राकृतिक) कृत्यों को भी दुष्कर्म माना गया है। लेकिन, कानून में अब भी एक अपवाद मौजूद है, जिसके अनुसार किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा।

बढ़ता अपवाद । मौजूदा व्यवस्था में पत्नी अगर बालिग है, तो उसकी असहमति के कोई मायने नहीं। यही कारण है कि मैरिटल रेप में पति को सजा नहीं होती। लेकिन, विडंबना है कि रेप का दायरा बढ़ाए जाने के कारण अपवाद का भी दायरा बढ़ गया है।

AI Image

मैरिटल रेप में अपवाद के तौर पर पति को छूट मिली हुई थी और अप्राकृतिक संबंध भी रेप की परिभाषा में शामिल होने से यह भी अपवाद में शामिल हो गया।

सहमति के मायने नहीं । कानून कहता है कि अगर कोई शख्स किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाता है, तो वह रेप होगा। महिला (अविवाहित) की उम्र 15 साल से ऊपर है, तो उसकी सहमति के मायने नहीं। वहीं, पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है, तो उसे रेप नहीं मानेंगे। फिर 11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में 15 साल से ऊपर के अपवाद को निरस्त कर दिया और कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 से 18 के बीच है और उसकी मर्जी के खिलाफ उससे संबंध बनाए जाते हैं, तो वह पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा सकती है।

अपवाद पर बहस

- MP हाई कोर्ट ने विवाह के भीतर रेप नहीं माना
- पत्नी से जबरदस्ती करना मौजूदा लॉ में दुष्कर्म नहीं
- सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मैरिटल रेप का मामला

BNS में परिभाषा । अगर नाबालिग पत्नी एक साल के भीतर शिकायत करती है, तो रेप का केस माना जाएगा। यानी अगर शिकायत नहीं करती तो केस नहीं बनेगा। अब नई भारतीय न्याय संहिता की धारा-63 के मुताबिक, अगर महिला के साथ कोई शख्स जबरन संबंध बनाता है या उसके प्राइवेट पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट डालता है, तो वह रेप होगा। निर्भया केस के बाद रेप की परिभाषा को ज्यादा व्यापक कर दिया गया था।

सुरक्षा पर सवाल । रेप लॉ में बदलाव के बाद पति-पत्नी के मामले में अप्राकृतिक संबंध भी अपवाद के दायरे में आ गया है, लेकिन इस कारण क्या महिलाएं ज्यादा शिकार नहीं बनेंगी? कानून बनाने वालों ने महिलाओं की ज्यादा सुरक्षा के लिए दुष्कर्म की नई परिभाषा गढ़ दी, लेकिन इससे अपवाद का दायरा भी बढ़ता गया।

कोर्ट में केस । मैरिटल रेप का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तीन जजों की बेंच इस केस में सुनवाई करने वाली है। मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग वाली याचिका में कहा गया है कि कई देशों में ऐसा प्रावधान है। समाज में भी कई बरसों से इसे लेकर बहस चल रही ।

सरकार का पक्ष । सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के संबंध को रेप के दायरे में लाना कठोर कदम होगा। इसके गंभीर सामाजिक और कानूनी दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इससे शादी संस्थान को नुकसान होगा। हालांकि, सरकार ने माना है कि पत्नी की सहमति का उल्लंघन करना पति का मौलिक अधिकार नहीं है।

अविवाहित को लाभ । BNS में जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधान नहीं हैं। दुष्कर्म की परिभाषा में महिलाओं और नाबालिगों को जबरन अप्राकृतिक संबंध मामले में प्रोटेक्ट किया गया है। शादीशुदा महिला के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना है। इस लिहाज से देखें तो अविवाहित लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है और विवाहित महिलाएं शोषण का शिकार हो सकती हैं। अब अप्राकृतिक संबंध को भी दुष्कर्म नहीं मानने से विवाहित महिलाओं के सम्मान पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

कांटे की बात

सब कुछ बदल दिया गया है, यहां नया सेटअप है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त नए अधिकारी आपके नामांकन खारिज करने के लिए लगाए गए हैं, इसलिए नॉमिनेशन फाइल करते समय सतर्क रहें।

ममता बनर्जी, *TMC चीफ*

असंभव संवाद

कप्तान के ससुर ने कहा था, गेंद खा लेना

पाकिस्तान की T20 लीग PSL में बॉल टेंपरिंग की वजह से बैटर फखर जमान पर दो मैचों का बैन लगाया गया है। क्या मजबूरी थी फखर के सामने, पूछने पहुंच गए वेस्टइंडीज के लीजेंड बोलर मैलकम मार्शल।

AI Image

'दोहरा नुकसान हो गया, मैच हारे और बैन भी लग गया।' मार्शल को देख फखर हड़बड़ा उठा, 'आप कैसे आए? हमारे यहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आधी रात को कोई भी होटल में आ सकता है, पर ग्राउंड पर नहीं।' 'इसे छोड़ो, यह बताओ बॉल टेंपरिंग क्यों की?' 'क्यों क्या, स्टेडियम में कोई था नहीं, तो हमें लगा कि कैमरे भी बंद होंगे। थोड़े से धागे खोल दिए गेंद के, पर अंपायर ने देख लिया।' 'तुम सीनियर हो, तुम्हें समझाना चाहिए था।' 'हमारा बोलर प्रीमियम सीनियर है और कप्तान भी बोलर है। कप्तान के ससुर ने तो कहा था कि गेंद को थोड़ा खा भी सकते हैं, पर उस वक्त भूख नहीं थी।' 'इस गलती से कुछ सीखा कि नहीं?' 'सीखा न, अगली बार अंपायर पर भी नजर रखनी है ताकि वह हम पर नजर न रख पाए।'

–शैलेंद्र पांडेय

जनता जंक्शन

इरफ़ान

गुड फ्राइडे पर निकलता है बड़ा जुलूस

हर साल गुड फ्राइडे से पहले पाल्म संडे पर करोल बाग के बैपटिस्ट चर्च से तीस हजारी के क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च तक जुलूस निकलता है। श्रद्धालु क्रॉस उठाकर भजन गाते चलते हैं। यह परंपरा पिछले 80–85 बरसों से जारी है। पीतमपुरा के मुक्ति आराधनालय चर्च के पादरी ब्रदर सोलोमन जॉर्ज डेढ़-दो हफ्ते से इस जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं। गुड फ्राइडे से पहले दिल्ली में कई जुलूस निकलते हैं, लेकिन करोल बाग से तीस हजारी तक का जुलूस सबसे बड़ा होता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस साल भी 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी।

विवेक शुक्ला

शुरुआत का प्रतीक । गुड फ्राइडे के दिन ईसाई परिवार अपने बच्चों को चर्च ले जाते हैं, ताकि वे दुख और बलिदान के महत्व को समझ सकें। यह दिन यीशु मसीह के त्याग का स्मरण कराता है और सिखाता है कि पीड़ा के बाद भी आशा बरकरार रहती है। दो दिन बाद आने वाला ईस्टर संडे नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन चर्च का शांत वातावरण, रोशनी, मधुर भजन और श्रद्धालुओं की भावनाएं मन को गहराई से छू जाती हैं।

साझी दिल्ली

14 पड़ाव । दिल्ली के ईसाइयों के लिए गुड फ्राइडे शोक और आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। चर्चों में स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस आयोजित किया जाता है, जिसमें क्रूस तक पहुंचने के 14 पड़ावों को याद किया जाता है। हर पड़ाव पर रुक कर श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं और पीड़ा को महसूस करने का प्रयास करते हैं।

पहुंचते हैं राजनयिक । गोल डाकखाना के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, राष्ट्रपति भवन के पास कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन और कश्मीरी गेट के सेंट जेम्स चर्च जैसे ऐतिहासिक चर्चों में गुड फ्राइडे पर बड़ी संख्या में विदेशी राजनयिक भी पहुंचते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक थ्री ऑवर्स एगनी के दौरान मौन रखा जाता है। चर्च की रोशनी मंद कर दी जाती है और लोग शांत बैठकर प्रार्थना व ध्यान में मग्न हो जाते हैं, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा से भर जाता है।

सांस्कृतिक विविधता । तुर्कमान गेट के पास होली ट्रिनिटी चर्च में गुड फ्राइडे पर बड़ी संख्या में ईसाइयों का जमावड़ा लगता है। यह राजधानी की पहली ईसाई बस्ती कही जाती है। फतेहपुरी मार्ग पर 150 साल पुराना सेंट स्टीफंस चर्च है, जिसे दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी ने बनवाया था। चांदनी चौक के सेंट मैरीज चर्च और ग्रीन पार्क के सेंट मैरी कैथेड्रल में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहां की खासियत मलयालम में होने वाली प्रार्थनाएं हैं, जहां सांस्कृतिक विविधता भी झलकती है।

अंग्रेज़ भी चाहते थे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर दबदबा

11वीं से 14वीं सदी के बीच होर्मुज का छोटा-सा द्वीप अपने पूरे वैभव पर था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित यह द्वीप व्यापारियों और साम्राज्यों के लिए सोने की खान जैसा था। अरब, फारसी, चीनी और भारतीय व्यापारी यहीं से अपने मसाले, सूती कपड़े, नील, चावल और चीनी वगैरह फारस, मेसोपोटामिया, तुर्किये और यूरोप तक बेचते। कुछ व्यापारियों ने यहां बसने के लिए स्थानीय लोगों से शादी भी की थी। उन्होंने अपनी भाषा, रीति-रिवाज और खाने-पीने की चीजें द्वीप की संस्कृति में शामिल कर दीं। वहीं से वे फारसी घोड़े, मोती, खजूर और चीनी रेशम लेकर भारत लौटते और बड़ा मुनाफा कमाते।

नवदीप सूरी

समुद्री रास्ता । 14वीं सदी में मंगोलों के हमलों के बाद शासक मुख्य भूमि पर चले गए, जिससे व्यापार समुद्री मार्गों की ओर बढ़ा। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमाया और व्यापार के जमीनी रास्तों पर यूरोपियों की पहुंच मुश्किल कर दी। यूरोप के व्यापारी अब भारत और चीन तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता तलाश रहे थे। 1498 से ही पुर्तगाल ने धीरे-धीरे भारत के पश्चिमी तट पर नियंत्रण बना लिया। 1507 तक अफोंसो डी अल्बाकर्की ने गोवा, बंबई और दीव तक अपनी पकड़ मजबूत की और होर्मुज पर 'फोर्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ द कॉन्सेप्शन' बनाकर समुद्री मार्गों पर नियंत्रण जमाया।

टाइम मशीन

व्यापारिक चौकी । ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहां पैठ बनाना चाह रही थी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिन्स मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गए और सूरत में व्यापारिक चौकी खोलने की अनुमति मांगी। इसके करीब 14 बरस बाद, 1622 में ब्रिटिश नौसेना ने शाह अब्बास की मदद से पुर्तगालियों को होर्मुज से बेदखल कर दिया। अगले 150 बरसों तक ब्रिटिश पॉलिटिकल रेजिडेंट्स ने होर्मुज पर अपना दबदबा रखा। भारत के वायसराय और बंबई के गवर्नर उनके कामकाज की देखरेख करते थे।

अमेरिका की मंशा । स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष में दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। अमेरिका की मंशा इसे स्वतंत्र समुद्री गलियारा घोषित करने की है ताकि हर देश का जहाज यहां से सुरक्षित गुजर सके। ईरान हमेशा कहता रहा है कि यह उसका पानी है।

अर्थव्यवस्था पर असर । स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का राजनीतिक के अलावा आर्थिक महत्व भी है। भारत का करीब 16% विदेशी व्यापार इसी रास्ते से होता है। क्रूड ऑयल और करीब आधी LNG यहीं से होकर आती है। उर्वरक के लिए जरूरी यूरिया और अमोनिया का दो तिहाई हिस्सा भी इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए यहां पाबंदी लगने का सीधा असर पड़ता है।

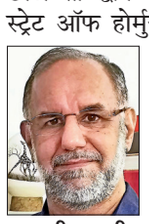

ताकत का प्रतीक । यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमेशा से दुनिया की राजनीति और व्यापार का महत्वपूर्ण रास्ता रहा है। पुर्तगाली, फारसी और अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण की कोशिश की। यह सिर्फ तेल और व्यापार का मार्ग नहीं, सुरक्षा और सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। आज भी बड़ी शक्तियां इसे लेकर सतर्क हैं। इतिहास गवाह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण की होड़ रही है। यह मानव सभ्यता, व्यापार और शक्ति का प्रतीक भी है।

(लेखक पूर्व राजनयिक हैं)

भावनाओं से ही नहीं, ज्ञान से भरी है हनुमान की भक्ति

देवेंद्रराज सुथार

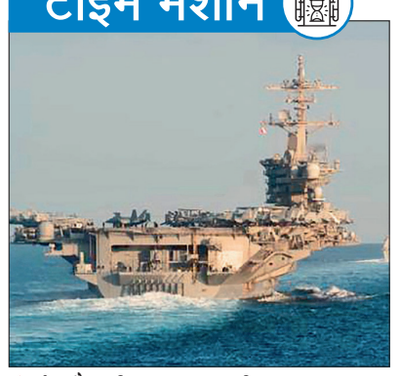

हमारी आध्यात्मिक परंपरा में हनुमान को शक्ति, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। उन्हें महाबली, संकटमोचन और पवनसुत के रूप में भी पुकारते हैं। उनका सबसे बड़ा गुण केवल शारीरिक बल नहीं, सेवा करने के बाद भी जरा-सा भी अहंकार न होना है। वह पर्वत उठा लेते थे, लेकिन कभी उसका श्रेय खुद नहीं लिया। आज के समय में, जब हर काम के पीछे तारीफ और परिणाम की उम्मीद बढ़ गई है, हनुमान की भक्ति से प्रेरणा ले सकते हैं।

हनुमान चालीसा में उन्हें 'विद्यावान, गुणी और अतिचतुर' कहा है। इसका मतलब है कि हनुमान सिर्फ भावनाओं से भक्ति करने वाले नहीं थे, वह समझदारी से काम करने वाले भी थे। लंका में सीता की खोज करते समय उनकी सावधानी, समझ और हालात को परखने की क्षमता यह बताती है कि सच्ची भक्ति अंधी नहीं होती, ज्ञान और समझ से भरी होती है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

हनुमान और रावण के बीच तुलना इस बात को और साफ करती है। रावण भी बहुत शक्तिशाली और विद्वान था, लेकिन उसकी शक्ति उसके अहंकार के लिए काम कर रही थी, जबकि हनुमान की शक्ति समर्पण के लिए थी। यही अंतर दोनों के परिणाम तय करता है। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि भक्ति उसे सही रास्ते पर आगे बढ़ाती है।

सुंदरकांड में हनुमान का लंका में प्रवेश एक अंदरूनी यात्रा का प्रतीक माना जाता है। लंका को अहंकार के रूप में देखा जा सकता है, जहां सीता यानी आत्मा फंसी हुई है। हनुमान का अकेले लंका में जाना यह बताता है कि खुद को समझने की यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। इसके लिए अंदर का विश्वास और समर्पण जरूरी है।

हनुमान खुद का परिचय 'राम का दास' कहकर देते हैं, जो सेवा भाव को दिखाता है। यह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने की ताकत है। जब 'मैं' खत्म हो जाता है, तब इंसान एक बड़ी और शुद्ध चेतना से जुड़ जाता है। यही कारण है कि हनुमान सिर्फ एक पात्र न होकर ऐसी चेतना हैं, जो हर उस व्यक्ति के भीतर जागती है, जो अहंकार छोड़कर सच्चाई की ओर बढ़ता है।

रीडर्स मेल

पहले ही हो तैयारी

1 अप्रैल का संपादकीय 'फिर वही गलती' पढ़ा। बिहार के नालंदा जिले में स्थित शीतला मंदिर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी हाथरस में, तिरुपति मंदिर और महाकुंभ मेले में इस तरह की भगदड़ में लोगों की जाने गई हैं। लेकिन हम कभी सबक नहीं लेते हैं। घटना हो जाने पर सरकारी मुआवजा मिल जाने के बादे मामला भी रफा-दफा हो जाता है। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में जब अनुमान से ज्यादा भीड़ होने की आशंका लगे तो संबंधित जिला प्रशासन को मुस्तैद हो जाना चाहिए और जरूरी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए।

बाल गोविंद, नोएडा

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। यह समाचार पत्र स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित, आशीष पांडे द्वारा संपादित (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी) तथा मनीष सिन्हा द्वारा, **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, 13/1 & 2, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाज़ियाबाद (उ.प्र.)** से और नवनीत आहूजा द्वारा, प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर-11, IMT मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051 से मुद्रित। फोन: 23302000, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु.

प्रेरणा

जहां भी प्रेम मौजूद है, वहां कभी भी चमत्कार हो सकते हैं। - विला कैथर

संपादकीय

युद्ध का असर हर सेक्टर पर नजर आने वाला है

तेल और प्राकृतिक गैस से निकलने वाले पॉलीमर्स की कमी से हजारों प्लास्टिक उद्योग बंद हैं। काम की कमी और एलपीजी की किल्लत से प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। रोजगार न रहने, पानी संकट और हमलों के खौफ से गल्फ से भी हजारों लोग लौटकर आ रहे हैं। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने वित्त मंत्रालय के इकॉनोमिक रिव्यू के ताजा मार्च अंक की प्रस्तावना में माना कि युद्ध के असर से विकास दर नीचे फिसल सकती है। उन्होंने लिखा कि 27 फरवरी को विकास दर के आकलन को हमने बढ़ाकर 7-7.4% कर दिया था, लेकिन अब यह नीचे गिरेगा। ट्रम्प ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले का आदेश दिया था, लेकिन 2 मार्च को सीईए ने वित्त मामलों पर संसदीय समिति को बताया था कि आयातित कच्चे तेल की कीमत जब तक 130 डॉलर प्रति बैरल न हो और वह भी 2-3 तिमाही (छह से नौ महीने) तक लगातार न रहे- तब तक महंगाई पर असर नहीं होगा और विकास दर नीचे नहीं आएगी। भारत इन दिनों 113 डॉलर के दर से क्रूड खरीद रहा है। तमाम गैर-सरकारी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चूंकि भारत अपनी जरूरत के लिए 90 फीसदी क्रूड आयात करता है और युद्ध के पूर्व इसकी दर 70 डॉलर या इससे नीचे थी, लिहाजा कीमतें बढ़ने से विकास बाधित होगा। विगत सप्ताह गोल्डमैन साक्स ने भी 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के आकलन को घटाकर 5.9% तक कर दिया है। दुनिया में क्रूड उत्पादन दो-तिहाई रह गया है। महंगाई, बाजार, रोजगार, निवेश पर असर होना तय है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

हनुमान जी बताते हैं जीवन में शोर व शून्य का संतुलन हो

हम कितनी सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। जो लोग शांति की तलाश में हैं, उन्हें सांस पर काम करना होगा। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सोचने से नहीं, श्वास से चिंता भीतर जाती है। हनुमान जी पवन-पुत्र हैं। हम अपने प्राणों पर मंत्र के जितने प्रयोग करेंगे, उतने ही शांत होंगे और हमारे शरीर से निकलने वाली तरंगें उतनी ही पॉजिटिव हो जाएंगी। हनुमान चालीसा एक मंत्र है। आज जब सारे देश में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है, तो एक संकल्प और लिया जाए और वो है- अपनी सांसों से हनुमान चालीसा रूपी मंत्र को जोड़ेंगे। सुंदरकांड को याद किया जाए, क्योंकि आधा सुंदरकांड हनुमान जी का पराक्रम है, चरित्र है, और बाद का आधा सुंदरकांड हनुमान जी ने मौन में गुजारा और राम जी की लीला सामने आई। तो हनुमान जी कहते हैं जीवन में शोर और शून्य का संतुलन होना चाहिए। आज हनुमान जयंती पर हम सबका संकल्प होना चाहिए कि जीवन में खूब परिश्रम और पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन समय आने पर खूब शांत भी रहेंगे। भक्त को उत्तेजित नहीं, उत्साहित रहना चाहिए।

•Facebook:Pt.Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

तुम मेरे प्राण में हो

प्रिय, तुम मेरे प्राण में हो।
सिमट गया जग शून्यता में, तुम मेरे प्राण में हो।

हां तुम अज्ञेय, किंतु मैंने कब कहा ज्ञेय बनो तुम?
प्रेम है प्रत्यभिज्ञा-बस, हो सदा संज्ञान में तुम।
ज्ञान है अज्ञान है, पर है भैरव विज्ञान भी-
हैं आलिंगित आत्माएं, तुम सतत पहचान में हो।

ना मरूं मैं मृत्यु से, वियोग, विरह अविराम से भी
ना डरूं मैं काल से, या श्वसन के विराम से भी।
मेरे समर्पण की सम्पूर्णता से तुम अभी अनभिज्ञ हो,
एक केवल तुम पुरुष, मेरी हर विधि के विधान में हो।

दिवस आता है, मुझे क्या?
अधखुली हैं आंखें हर पल,
अप्प दीपो तो नहीं मैं,
पर देह-चेतन अद्वैत अनुपल।
हर अणु से दूर नभ तक,
इस प्रकृति की सब लीलाएं-
तुम सभी के आदि में हो,
मध्य में हो, और फिर अवसान में हो।
तुम मेरे प्राण में हो।

–राजेश खुल्लर, चंडीगढ़

पूरी कविता को पढ़ने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

महिलाओं को मिले उचित सम्मान

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। उन पर घर की जिम्मेदारी भी होती है। महिलाओं के श्रम को 'पूरक' माना जाता है, जबकि वे परिवार की आर्थिक रीढ़ होती हैं। इस नजरिए को बदलना चाहिए, ताकि उन्हें उचित सम्मान मिले।
–संगीता कुमारी, मुजफ्फरपुर, बिहार

परीक्षा प्रणाली में सुधार के कदम उठाएं

परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जैसे प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को वीक्षण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, वैसे ही हाई स्कूलों मे भी करना चाहिए। परीक्षार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी हो और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी प्रखंड स्तर पर ही होना चाहिए। –सुमित कुमार, ईमेल पर

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

सबसे तेज धंसता शहर 'जकार्ता'

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे तेज जमीन में धंसता शहर है। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण इसकी जमीन की परतें सिकुड़ रही हैं और शहर हर साल 15 सेमी तक जमीन में धंसता जा रहा है। 2050 तक उत्तरी जकार्ता का 95% हिस्सा जलमग्न होने का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है।

दूरदृष्टि • नेताओं की हत्या और बमबारी हार और आत्मसमर्पण करवाने के लिए काफी नहीं होती...

ईरान अभी तक युद्ध क्यों नहीं हारा?

युद्धनीति

आशुतोष वार्ष्णेय

ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर

ईरान युद्ध एक महीना पूरा कर चुका है। कइयों के द्वारा उम्मीद की जा रही थी कि ईरान अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य ताकत का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ईरान ने युद्ध जीता नहीं है, लेकिन वह हारा भी नहीं है और यह भी संभव है कि वह हारे भी न। ईरान की मजबूती की वजह क्या है? इसके चार कारण हो सकते हैं।

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पहला कारण है। तेल बाजार में 150 डॉलर प्रति बैरल का खतरा मंडरा रहा है। अब तक सबसे ज्यादा कीमत 147.50 डॉलर प्रति बैरल रही है, जो जून 2008 में देखी गई थी। अगर कीमत फिर इतनी बढ़ती है, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यापारिक जहाजों को रोकने की क्षमता ईरान को बहुत बड़ी ताकत देती है। दुनिया के तेल व्यापार का 20% और भारत का लगभग आधा तेल आयात होर्मुज से होकर गुजरता है। दुनिया के लगभग 20% प्राकृतिक गैस निर्यात भी यहीं से जाते हैं। भारत के लिए यह आंकड़े और महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि भारत के द्वारा आयात की गई एलएनजी का 60% और एलपीजी का लगभग 85-90% होर्मुज से आता है।

इसका असर सिर्फ एशिया पर नहीं पड़ता। अमेरिका में लोग पश्चिमी यूरोप के लोगों की तुलना में लगभग दोगुनी दूरी तक गाड़ी चलाते हैं, इसलिए तेल की कीमतें वहां के घरों के बजट पर बड़ा असर डालती हैं। कुछ ही महीनों में मिड-टर्म चुनाव होने वाले हैं। ज्यादा तेल कीमतों का जोखिम कोई भी अमेरिकी सरकार नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि अमेरिका ने अस्थायी रूप से रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध हटाए हैं और सबसे विरोधाभासी बात यह कि ईरानी तेल पर भी राहत दी है।

ईरान की मजबूती का दूसरा कारण हथियार हैं। ड्रोन ने आधुनिक युद्ध की प्रकृति बदल दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध इस बदलाव का पहला उदाहरण था। ड्रोन पर निर्भर होकर यूक्रेन रूस जैसी बड़ी सेना का सामना कर सका, और चार साल बाद भी वह हारा नहीं है। ईरान भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। ड्रोन 'कमजोरों के हथियार' हैं। एक ड्रोन की कीमत लगभग 15,000 से 30,000 डॉलर के बीच होती है। इसके मुकाबले, उन्हें रोकने वाली मिसाइल की कीमत 20 लाख से 40 लाख डॉलर तक होती है। मिसाइल का उत्पादन उसके आकार और दिखने की वजह से आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन ड्रोन का उत्पादन आसानी से छिपाकर जारी रखा जा सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के देशों को निशाना बनाया है। अगर हमले बढ़ते हैं, तो एनर्जी की कीमतें और बढ़ेंगी। ड्रोन 'दुबई की छवि' को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसने अरब दुनिया में एक नया रास्ता दिखाया है। वहां प्रवासियों को जगह मिली है, सामाजिक समावेश और शांति को बढ़ावा मिला है, जिससे दुनिया भर के निवेशक और कारोबारी आकर्षित हुए हैं।

तीसरा कारण एक क्रांतिकारी शासन की संगठनात्मक व्यवस्था से जुड़ा है। 1980 के दशक में राजनीतिक वैज्ञानिक जीन किर्कपैट्रिक- जो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की करीबी सलाहकार थीं- ने तानाशाही और सर्वसत्तावादी व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताया था। उन्होंने कहा कि तानाशाही व्यवस्था सिर्फ राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करती है, जबकि सर्वसत्तावादी व्यवस्था राजनीति और समाज दोनों को नियंत्रित करती है और नागरिकों के जीवन के हर क्षेत्र में विरोध को दबा देती है। उन्होंने मिस्र और पाकिस्तान को तानाशाही व्यवस्था कहा, वहीं क्यूबा और सोवियत संघ जैसे देशों को सर्वसत्तावादी व्यवस्था बताया।

1979 में ईरान में धार्मिक क्रांति हुई और तब से वहां ऐसी ही एक सर्वसत्तावादी व्यवस्था है। समाज पर नियंत्रण और विरोध को दबाने के लिए दो तरह के संगठन बनाए गए : नागरिक और सैन्य। नागरिक संगठन विश्वविद्यालयों, मस्जिदों और बाजारों तक पहुंचे और

ईरान की संगठनात्मक व्यवस्था बहुत मजबूत है...

अगर मौजूदा नेता मारे जाते हैं, तो नए नेता सामने आकर व्यवस्था संभाल लेंगे। अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन उठते हैं, तो उन्हें दबा दिया जाएगा। इस युद्ध में शासन बदलने की कोशिशें ईरान की मजबूत संगठन ात्मक व्यवस्था के कारण कमजोर पड़ती दिख रही हैं।

सरकार के समर्थन वाले विचार फैलाए। सैन्य संगठनों में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स शामिल हैं, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। यह नियमित सेना से अलग है और इसमें लगभग 1,50,000 से 1,90,000 सैनिक हैं। इसका मुख्य काम क्रांति की रक्षा करना है। इसके सैन्य हिस्से देश के सभी राज्यों के शहरों और कस्बों में फैले हैं। इसके अलावा, 5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों को जोड़कर बनाया गया बसीज, आईआरजीसी का अर्धसैनिक (पैरामिलिट्री) हिस्सा है। यह विरोध को कठोर तरीके से दबाने के लिए जाना जाता है।

धार्मिक व्यवस्था से जुड़े इस बड़े क्रांतिकारी संगठन ने दो चीजें सुनिश्चित करने की कोशिश की है। पहला, अगर मौजूदा नेता मारे जाते हैं, तो नए नेता सामने आकर व्यवस्था संभाल लेंगे। दूसरा, अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन उठते हैं, तो उन्हें दबा दिया जाएगा। व्यवस्था खुद कमजोर नहीं पड़ेगी। इस युद्ध में शासन बदलने की कोशिश ईरान की इस बहुत मजबूत संगठनात्मक व्यवस्था के कारण कमजोर पड़ती दिख रही है।

ईरान के अभी तक नहीं हारने का चौथा कारण शिया मत के खास चरित्र से जुड़ा है, जो ईरान का आधिकारिक धर्म है। धार्मिक विद्वानों और जानकारों के बीच यह अच्छी तरह जाना जाता है कि शहादत शिया मत का एक बुनियादी विचार है। शिया मत के संस्थापक अली और उनके बेटे हुसैन, दोनों शहीद हुए थे। कर्बला की लड़ाई शिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जो समुदाय की सामूहिक यादों में दर्ज है। 680 ईस्वी में, उमय्यद खलीफा यजीद की बड़ी सेना ने हुसैन को घेरकर हमला किया था। कर्बला में हुसैन ने अपने भाइयों और बच्चों सहित अपने कई साथियों के साथ शहादत स्वीकार की, लेकिन अन्यायपूर्ण शासक के प्रति वफादारी की कसम खाने से इनकार कर दिया।

मुहर्रम के महीने में बड़े जुलूस और मर्सिये शहादत की भावना को याद करते हैं। लखनऊ में मैंने बड़े जमावड़ों में मर्सिये पढ़े जाते देखे हैं। हर साल कर्बला की लड़ाई को लोगों की भागीदारी के साथ दोबारा याद किया जाता है, जिससे यह एक जीवित परम्परा बन गई है। इसके कारण शहादत की भावना लाखों शियाओं के मन में गहराई से बस गई है। शिया समाज में कष्ट सहने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे में उनके नेताओं की हत्या और भारी बमबारी जरूरी नहीं कि हार और आत्मसमर्पण करवा दे। सही हो या गलत, यह तो स्पष्ट है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

मुद्दा • बेहतर परिदृश्य भी निर्मित हो सकता है

एआई की क्षमताओं को लेकर ज्यादा मायूस ना हों

कृत्रिम मेधा

रघुराम राजन

आरबीआई के पूर्व गवर्नर

इक्विटी-रिसर्च फर्म सिट्रिनी ने हाल ही में वित्तीय बाजारों में तब हलचल मचा दी थी, जब उसने एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत किया, जिसमें 2028 तक एआई अधिकांश व्हाइट-कॉलर नौकरियों को खत्म कर देगा। जाहिर है इसके अर्थव्यवस्था पर भी गम्भीर परिणाम होंगे। लेकिन यह पूर्वानुमान कुछ पहलुओं में अत्यधिक निराशावादी है। सॉफ्टवेयर जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो एआई को अपनाने में आने वाली बाधाएं और इससे निर्मित होने वाली इनर्शिया (जड़ता) बदलावों की गति को संभवतः धीमा करेंगी। इतिहास में हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। उदाहरण के लिए, 1920 के दशक में ही ऑटोमैटेड टेलीफोन एक्सचेंज संभव हो चुके थे, लेकिन इससे अमेरिका में टेलीफोन ऑपरेटरों की नौकरी 1980 के दशक तक नहीं गई थी।

इसके अतिरिक्त, टेक्नोलॉजी अपने आपमें केवल एक वैरिएबल होती है। इसके चारों ओर ऐसी प्रक्रियाएं और संरचनाएं भी होनी चाहिए, जो ग्राहकों को विश्वसनीय सेवा का आश्वासन दें। यही वह क्षेत्र है, जहां स्थापित कंपनियों को नए प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलती है, भले ही वे नवीनतम तकनीक का उपयोग न कर रही हों। और अगर स्थापित कंपनियां अपनी जगह खो देती हैं, तब भी एआई-प्रेरित लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि से उत्पन्न नए अवसर एआई पर निर्भरता तक ही सीमित नहीं होंगे। वे मानव-श्रम की भी आवश्यकता पैदा कर सकते हैं- जैसा कि इंटरनेट और इन्फ्लुएंसर्स के उदय के साथ देखा गया है।

फिर भी, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें, जहां कुछ विशिष्ट प्लेटफॉर्म (जैसे एंथ्रोपिक या मेटा) एआई के ऐसे स्तर तक पहुंच जाएं, जो उन्हें प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने और यूजर-कंपनियों से लगातार ऊंची कीमतें वसूलने में सक्षम बना दें। ये प्लेटफॉर्म तब भारी मुनाफा अर्जित करेंगे, जिससे उनके कर्मचारियों (जो संख्या में कम होंगे, क्योंकि एआई छंटनी कर चुका होगा!) और उनके शेयरधारकों की आय बढ़ेगी। साथ ही, उनकी सेवाओं पर निर्भर अनेक कंपनियां भी भुगतान करने को तैयार होंगी, क्योंकि एआई उनकी उत्पादकता बढ़ाएगा और उन्हें अधिक व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों को हटाने की अनुमति देगा।

इसके बाद बेरोजगार हुए ये कर्मचारी उन आस-पास के क्षेत्रों में काम की तलाश करेंगे, जहां एआई ने अभी उनकी स्किल्स को अप्रासंगिक नहीं बनाया है। लेकिन यदि ऐसे रोजगार सीमित हुए, तो वे बागवान, वेटर और शॉप-असिस्टेंट्स जैसे काम करेंगे, जिससे इन पेशों में वेतन और नीचे चला जाएगा। यदि यह मानें कि एआई पहले संज्ञानात्मक कार्यों को समाप्त करता है, बनिस्बत स्किल्ड फिजिकल कार्यों के- तो मशीनिस्ट, प्लम्बर और राजमिस्त्री जैसे पेशों में कुछ समय तक काम बना रह सकता है, जब तक कि रोबोट इन कार्यों के लिए पर्याप्त उन्नत न हो जाएं।

या एक और ऐसे प्रतिस्पर्धी परिदृश्य पर विचार करें, जिसमें कोई भी प्लेटफॉर्म विजेता नहीं बनता है, क्योंकि

बेरोजगारी की समस्या के कोई आसान सार्वजनिक समाधान नहीं होते। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को कुछ हद तक मजबूत करना होगा। साथ ही, जहां तक सम्भव हो, व्यवसायों को भी जॉब्स क्रिएट करने और कामगारों को री-स्किल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

चैटजीपीटी 33.2, जेमिनाई 25 और अन्य सभी के बीच बहुत कम अंतर होता है। इसमें एआई की कीमतें कम रहेंगी और उत्पादकता के लाभ पूरी इकोनॉमी में फैलेंगे, साथ ही उससे उत्पन्न मुनाफा भी। एआई पर भारी खर्च से बचते हुए, यूजर कंपनियां कीमतें घटा सकती हैं और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा सकती हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में अधिक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें पहले वाले परिदृश्य की तुलना में तकलीफें कहीं कम होंगी, क्योंकि सस्ती वस्तुएं और सेवाएं पहले से मौजूद श्रमिक बचत को अधिक दूर तक ले जा सकेंगी।

न केवल वर्तमान रुझान यह संकेत देते हैं कि यह दूसरा सिनैरियो अधिक संभावित है, बल्कि सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठा सकती हैं कि यही परिदृश्य साकार हो।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

नजरिया • भारत की दीर्घकालिक परमाणु योजनाएं

हमने अपनी पूर्ण क्षमताओं का अभी तक दोहन नहीं किया है

एनर्जी

संजय अग्रवाल

पूर्व सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की विश्वसनीय, लो-कार्बन ऊर्जा सुरक्षा की खोज में एक रणनीतिक साधन के रूप में थोरियम पुनः उभर रहा है। लेकिन यदि इसे एक संभावना से आगे बढ़ाकर बिजली संयंत्रों तक भी पहुंचाना है तो नीतिगत, टेक्नोलॉजी और संस्थागत अंतरालों को पाटना होगा।

वैश्विक स्तर पर, थोरियम को लंबे समय से यूरेनियम के मुकाबले अधिक सुरक्षित व प्रचुर विकल्प के रूप में देखा गया है। 1950 से 1970 के दशकों में अमेरिका और यूरोप में किए गए प्रयोग व्यावसायिक पैमाने तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सस्ते यूरेनियम, लाइट-वॉटर रिएक्टरों के प्रभुत्व और हथियारों से लिंक्ड फ्यूल-साइकिल्स ने निवेश को अन्यत्र मोड़ दिया था।

भारत इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय अपवाद रहा है, क्योंकि डॉ. होमी भाभा के तीन-चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना हमारे विशाल थोरियम भंडार के आधार पर ही की गई थी। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम और हैवी-वॉटर रिएक्टर्स, दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और तीसरे चरण में थोरियम-आधारित प्रणालियां। फिर भी, बड़े पैमाने पर थोरियम का उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। संसदीय उत्तरों (2015) में अनुमान लगाया गया था कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) के 2040 के दशक में स्थायी पैमाने पर पहुंचने के 3-4 दशकों बाद ही कॉमर्शियल थोरियम रिएक्टर संभव हो सकेंगे- यानी 2070-2080 तक की टाइमलाइन। आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एडवांस्ड हैवी-वॉटर रिएक्टर- जो अपनी लगभग 60% ऊर्जा थोरियम से प्राप्त करता है- टेक्नोलॉजिकल तत्परता का प्रतीक है।

भारत की दीर्घकालिक परमाणु योजना में जो कमियां हैं, उनके लिए हमारा विजन कम और सीक्वेंसिंग, संसाधन-प्रबंधन तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था अधिक जिम्मेदार रही है। तीन-चरणों वाली रणनीति ने यह मान लिया था कि हैवी-वॉटर रिएक्टरों का तीव्र विस्तार होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर समय पर स्थापित होंगे और जटिल ईंधन निर्माण में सक्षम एक औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित होगा- लेकिन इन धारणाओं को बार-बार प्रतिबंधों, वित्तीय सीमाओं और परियोजनाओं में होने वाले विलंबों ने कमजोर किया है।

1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व ने एक अपने में बंद और अतिशय सतर्क कार्य-संस्कृति को जन्म दिया। इनोवेशन और विस्तार कुछ ही सार्वजनिक उपक्रमों और अनुसंधान केंद्रों तक सीमित रहे, जहां प्रतिस्पर्धी दबाव या वैश्विक एकीकरण का अभाव था। इन कमियों के कारण अपेक्षा से अधिक समय तक कोयले और आयात पर हमारी निर्भरता बनी रही। जहां प्रेशराइज्ड हैवी-वॉटर रिएक्टर (चरण-1) की क्षमता बढ़ी, वहीं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम आधारित चरण (चरण-2 और 3) पीछे रह गए।

'शांति' कानून (भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक, 2025) ने 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम का स्थान ले लिया है। यह निजी भारतीय कंपनियों को रिएक्टरों के निर्माण, स्वामित्व, संचालन की अनुमति देता है तथा ईंधन निर्माण- जिसमें यूरेनियम-235 का रूपांतरण, परिशोधन और एक सीमा तक संवर्धन शामिल है- में भागीदारी की भी अनुमति देता है। संवेदनशील गतिविधियां सरकार के लिए सुरक्षित हैं।

डॉ. होमी भाभा के तीन-चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना हमारे विशाल थोरियम भंडार के आधार पर ही की गई थी। इसमें तीसरे चरण में थोरियम-आधारित प्रणालियां थीं। फिर भी, बड़े पैमाने पर थोरियम का उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है।

इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि 'शांति' अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपवादों के अधीन, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए पेटेंट की अनुमति देता है। थोरियम के संदर्भ में, यह संयुक्त उपक्रमों और निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली डेमंस्ट्रेशन-परियोजनाओं के लिए भी एक स्पेस रचता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • मौजूदा हालात के मद्देनजर यही सही है कि व्यक्ति, संस्थाएं और देश ऊर्जा की खपत कम करें

जितनी खपत उतनी निर्भरता और जितनी निर्भरता उतनी असुरक्षा

क्लाइमेट

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी

आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर

chetanss@gmail.com

हमारी आधुनिक जिंदगी ऊर्जा पर चलती है और ज्यादातर यह कार्बन-आधारित ऊर्जा होती है। दुनिया की कुल ऊर्जा खपत का 80% से अधिक हिस्सा आज भी जीवाश्म ईंधनों- कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस- से आता है। लेकिन कुछ ही देश ऐसे हैं, जिन्हें कोयला, तेल और गैस जैसे कार्बन ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति का वरदान मिला है। बाकी देश आयात पर निर्भर रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऊर्जा हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने उपयोग की जगह पर पहुंचती है।

कई बार, यह परिवहन समुद्र के संकरे रास्तों से होकर गुजरता है। जितनी अधिक दूरी और जितना संकरा मार्ग, उतना ही अधिक जोखिम। ये रास्ते, थोड़े से भी व्यवधान के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। इन संकरे रास्तों में आने वाली जरा-सी भी गड़बड़ी बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देती है। यही कारण है कि इन्हें एनर्जी चोक-पॉइंट्स कहा जाता है।

ऐसे कुछ प्रमुख चोक-पॉइंट में शामिल हैं- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (ओमान और ईरान के बीच), स्वेज नहर (मिस्र में), बाब-अल-मंदेब (यमन और जिबूती/एरिट्रिया के बीच), मलक्का जलडमरूमध्य (मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच) और पनामा नहर (पनामा में)। इनमें से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी सर्वाधिक चर्चा में है। ये सभी चोक-पॉइंट्स केवल भौगोलिक स्थान नहीं हैं; ये वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की कमजोर नस हैं। ये नस जिसके हाथ में होगी, वह इसे अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकता है और करता ही है।

विश्व के इन ऊर्जा चोक-पॉइंट्स पर निर्भरता एक नाजुक संतुलन बनाती है। 2021-22 में स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की घटना ने दिखाया था कि वैश्विक व्यापार कितना संवेदनशील है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ाता है। इन्हें अकसर अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये एक गहरी सच्चाई उजागर करती हैं कि विश्व की ऊर्जा-व्यवस्था मजबूत नहीं है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि ऊर्जा- जो आधुनिक जीवन और आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है- वह खुद इतनी कमजोर हो? ऊर्जा पर यह निर्भरता पूरी दुनिया को अस्थिर बनाती है और देशों के बीच आपसी संघर्ष की आशंका पैदा करती है।

वास्तविक समस्या इन ऊर्जा चोक-पॉइंट्स की भौगोलिक स्थिति नहीं, हमारी ऊर्जा आपूर्ति की डिजाइन में है। हम आधुनिक मनुष्यों ने ऐसी वैश्विक ऊर्जा प्रणाली बनाई है, जिसमें उत्पादन कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है और उपभोग पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह असंतुलन ऊर्जा को सीमित मार्गों से गुजरने के लिए मजबूर करता है, जिससे जोखिम बढ़ता है। जितनी खपत, उतनी निर्भरता। जितनी निर्भरता, उतनी असुरक्षा। यह असुरक्षा आज, कल और दशकों बाद भी रहने वाली है।

हवा, पानी और मिट्टी का प्रदूषण भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन ऊर्जा का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन भी तेल, गैस और कोयले के कारण है। ऊर्जा आयात पर हमारी निर्भरता और दुनिया में फैली अस्थिरता को देखते हुए यह बेहद जरूरी है कि हम ऊर्जा आपूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था खोजें। इस नई ऊर्जा व्यवस्था के तहत, मैं दो अहम बातों पर जोर देना चाहूंगा : पहली- इस नई व्यवस्था में यह अनिवार्य होना चाहिए कि व्यक्ति, संस्थाएं और देश अपनी ऊर्जा की खपत कम करें। और दूसरी- ऊर्जा की सभी जरूरतें जहां तक हो सके, स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जाएं। इससे व्यवस्था अधिक मजबूत, न्यायसंगत और पृथ्वी की सीमाओं के अनुरूप बन सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बिज़नेस भास्कर
Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ
नई दिल्ली, गुरुवार 2 अप्रैल, 2026

उलटफेर • 2025-26 में सेंसेक्स 7% से ज्यादा टूटा, पर बैंकों के एफडी का रिटर्न 6% से अधिक, महंगाई से दोगुना

एक साल में बैंक एफडी का रिटर्न शेयरों से ज्यादा

पर नए वित्त वर्ष में तेजी से चढ़ सकता है शेयर बाजार

पुनीत वाधवा, रेक्स कैनो | मुंबई

मंगलवार को खत्म वित्त वर्ष 2025-26 शेयर बाजार के निवेशकों के लिए निराशाजनक रहा। बीते 12 महीनों में बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स में भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी 5% और सेंसेक्स 7% से ज्यादा टूट गया। यह बीते 6 साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। केवल बड़े शेयर ही नहीं टूटे, बल्कि व्यापक बाजार में भी सुस्ती छाई रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में सिर्फ 2% तेजी आई, लेकिन निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स करीब 6% फिसल गया। दूसरी तरफ बैंक एफडी ने 6% से अधिक रिटर्न दिए, जो रिटेल महंगाई (3.21%) से करीब दोगुना है।

एसबीआई जैसे बैंकों ने 3 करोड़ रुपए से कम राशि की 1-2 साल की एफडी पर 6.25% रिटर्न दिए। इसने बीते वित्त वर्ष में शेयर बाजार के बेंचमार्क रिटर्न को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब इस साल जोखिम लेने वालों की तुलना में सुरक्षित निवेश करने वाले फायदे में रहे। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि बुधवार से शुरू वित्त वर्ष 2026-27 में शेयर बाजार अधिकांश एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। पर ये वैश्विक तनाव की स्थिति पर निर्भर करेगा। ईरान युद्ध का असर लंबे समय तक रह सकता है।

ट्रेंड: जनवरी-मार्च में गिरावट के 7 में से 5 मामलों में निफ्टी का न्यूनतम रिटर्न 15%

2026-27
शेयर सस्ते, नए वित्त वर्ष में उछाल की संभावना

जी. चोक्कालिंगम
संस्थापक, एमडी, इक्विनॉमिक्स रिसर्च

2026-27 इक्विटी, खास तौर पर स्मॉल और मिडकैप शेयरों का साल होगा। इसके तीन बड़े कारण हैं...

1. भारतीय बाजार मौलिक रूप से आकर्षक नजर आ रहे हैं क्योंकि सेंसेक्स का ट्रेलिंग पीई करीब 20 गुना है, जबकि 5 साल का औसत पीई करीब 24 गुना रहा है। यानी अब शेयर बाजार औसत से सस्ता हो गया है।
2. 2024 के शिखर पर मार्केट कैप और जीडीपी का अनुपात 152% था, जो अब घटकर करीब 109% रह गया है। यह भी बताता है कि शेयरों की कीमतें अब पहले जितनी जरूरत से ज्यादा नहीं रह गई हैं।
3. जैसे ही युद्ध खत्म होगा, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं, भारतीय बाजार, खास तौर पर स्मॉल-मिडकैप शेयरों में उछाल आएगा।

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के मुताबिक, पिछले 15 वर्षों में ऐसे 7 मौके आए, जब किसी वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च) में निफ्टी गिरा। इनमें से पांच बार अगले पूरे वित्त वर्ष में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। दिलचस्प है कि सबसे कम रिटर्न भी तकरीबन 15 फीसदी रहा।

जनवरी-मार्च	रिटर्न	वित्त वर्ष	रिटर्न
2011	▼4.9%	2011-12	▼9.2%
2013	▼3.8%	2013-14	▲18.0%
2016	▼2.6%	2016-17	▲18.6%
2018	▼4.0%	2018-19	▲14.9%
2020	▼29.3%	2020-21	▲70.9%
2023	▼4.1%	2023-24	▲28.6%
2025	▼0.5%	2025-26	▼4.4%
2026	▼14.5%	2026-27	---

- 2024 में जोरदार उछाल के बाद शेयर काफी महंगे हो गए थे, ऐसे में गिरावट तय थी।
- अभी मार्केट कैप-जीडीपी अनुपात पिक से 28% नीचे हैं, यानी शेयर सस्ते हैं।
- ईरान युद्ध खत्म हुआ तो, अच्छी क्वालिटी के शेयरों में उछाल आ सकता है।

कमजोर साल के बाद अगले वित्त वर्ष भी चढ़ता रहा है शेयर बाजार

जनवरी-मार्च	रिटर्न	वित्त वर्ष	रिटर्न
2011-12	▼9.2%	2012-13	▲7.3%
2015-16	▼8.9%	2016-17	▲18.6%
2019-20	▼26%	2020-21	▲71%
2022-23	▼0.6%	2023-24	▲28.6%
2025-26	▼5.1%	2026-27	--

(रिटर्न निफ्टी इंडेक्स का, स्रोतः जियोजित इन्वेस्टमेंट्स)

- 7-15 फीसदी रिटर्न के अनुमान के आधार पर निफ्टी 24,000-26,000 का स्तर छू सकता है।
- युद्ध जैसे हालात के चलते नकारात्मक परिदृश्य में निफ्टी 20,500 के स्तर तक गिर भी सकता है।
- सामान्य हालात में निफ्टी 24,400, सबसे अच्छी स्थिति में 26,000 और सबसे बुरे दौर में 19,000 पर आ सकता है।

कमाई: धैर्य रखें, मार्च 2027 तक 9% तक रिटर्न के आसार

नए वित्त वर्ष में यानी मार्च-27 तक इक्विटी (जैसे शेयर) 9% तक रिटर्न दे सकती है। बेहतर होगा कि दो साल से ज्यादा समय के लिए निवेश करें। सोने में गिरावट का एक और दौर संभव है। 2026-27 में सोना नकारात्मक रिटर्न दे सकता है। ऐसे में इक्विटी निवेश बढ़ सकता है।
-जितेंद्र गोहिल, बाजार विश्लेषक

संकेत अच्छे...
नए वित्त वर्ष की शुभ शुरुआत; सेंसेक्स 1,800 अंक तक उछला

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दिन शेयर बाजार में उछाल आया। सेंसेक्स 1,813 अंक तक चढ़ा और निफ्टी में 387 अंकों तक की तेजी आई। हालांकि बाद में सेंसेक्स की तेजी 1,187 अंकों तक सिमट गई और यह 73,134 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 348 अंकों की बढ़त के साथ 22,679 पर पहुंच गया। इस उछाल के चार बड़े कारण रहे। ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने की उम्मीद, वैश्विक बाजारों में तेजी, मार्च की बिकवाली के बाद वैल्युएशन में सुधार और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट। तेजी गहरी रही। सेंसेक्स-निफ्टी जहां 1.6% चढ़े, वहीं निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमशः 2.24% और 3.24% बढ़त पर बंद हुए।

बीएसई के 86% शेयर चढ़े, सिर्फ 521 गिरे

कुल ट्रेडिंग: 4,437 शेयर

बढ़त	गिरावट	स्थिरता
3,819 शेयर	521 शेयर	97 शेयर

दुनियाभर के शेयर बाजार 5% तक चढ़े

इंडेक्स/देश	तेजी
कोस्पी-द. कोरिया	5%
निक्केई-जापान	4%
नैस्डैक-अमेरिका	4%
डाउ जोंस-अमेरिका	3%
एसएंडपी-अमेरिका	2.5%
सेंसेक्स-भारत	1.6%
सीएसआई-चीन	1.3%

सालाना आधार पर निवेश में 74% उछाल

जनवरी-मार्च में प्रॉपर्टी निवेश 2022 के बाद सबसे ज्यादा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भू-राजनैतिक तनाव और अनिश्चितताओं के बीच भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर ने तगड़ी मजबूती दिखाई। जनवरी-मार्च में इस सेक्टर ने करीब 13,000 करोड़ रुपए का संस्थागत निवेश आकर्षित किया। यह 2022 के बाद किसी भी साल की पहली तिमाही में सबसे अधिक है। हालांकि, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के रिकॉर्ड स्तर से निवेश में 62% गिरावट आई, लेकिन सालाना 74% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई।

घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी 22% से बढ़कर 72% हो गई

बीती तिमाही के दौरान प्रॉपर्टी में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटी, जबकि घरेलू निवेशकों की बढ़ी। वैश्विक दबावों के चलते विदेशी निवेश का हिस्सा 40% से घटकर 13% रह गया। दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया। घरेलू निवेश की हिस्सेदारी 22% से बढ़कर 72% के स्तर पर पहुंच गई। घरेलू निवेशकों ने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया, जो सालाना आधार पर 118% अधिक है।

निवेशकों की पसंद ये...

कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश 266% बढ़ा

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की बढ़ती मांग ने कमर्शियल प्रॉपर्टी को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। कुल निवेश में कमर्शियल प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी पिछले साल के 38% से बढ़कर 80% हो गई। इस सेगमेंट में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यह सालाना आधार पर करीब 266% ज्यादा है।

निवेश में इंडस्ट्रियल, वेयरहाउसिंग का हिस्सा 1%

कमर्शियल प्रॉपर्टी के उलट अन्य सेगमेंट में सुस्ती देखी गई। बीती तिमाही इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेगमेंट में निवेश की हिस्सेदारी 17% से घटकर महज 1% रह गई। इसी तरह हाउसिंग सेगमेंट में निवेश घटकर 1,923 करोड़ रुपए रह गया, जो सालाना आधार पर 59% की गिरावट दर्शाता है। इस बीच जीसीसी की मांग ने प्रॉपर्टी बाजार को स्थिरता दी। वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव के मुताबिक, रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी भागीदारी भले ही कम हुई हो, लेकिन घरेलू पूंजी की तगड़ी आमद और जीसीसी की मांग ने इस बाजार में नई जान ला दी है। यह रुझान भारत को एक सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करता है।

बिजनेस ब्रीफ

चांदी की कीमत ₹9,701 बढ़ी, सोना ₹4,120 महंगा

मुंबई| पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेतों से घरेलू सराफा बाजार में बुधवार को सोने-चांदी में तेजी रही। आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक, चांदी की औसत कीमत 9,701 रुपए बढ़कर 2,39,836 रुपए प्रति किलो हो गई। 24 कैरेट सोना 4,120 रुपए महंगा होकर औसतन 1,50,853 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। 22 कैरेट सोने की कीमत भी 3,774 रुपए बढ़कर 1,38,181 रुपए हो गई।

एंथ्रोपिक के 'क्लॉड' AI का सोर्स कोड सार्वजनिक

सैन फ्रांसिस्को | एआई कंपनी एंथ्रोपिक के 'क्लॉड' एआई का सोर्स कोड मानवीय भूल की वजह से सार्वजनिक हो गया है। एक हफ्ते के भीतर कंपनी की यह दूसरी बड़ी लापरवाही है। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इसमें ग्राहकों का कोई संवेदनशील डेटा लीक नहीं हुआ है। फिलहाल डेवलपर इस सोर्स कोड से कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स की जानकारी पता लगाने में जुटे हैं।

ट्रम्प के बयान से कच्चे तेल के दाम 3.2% घटे

लंदन| अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ईरान युद्ध खत्म करने के संकेतों के बाद बुधवार को कच्चे तेल की कीमत 3.2% तक घट गई। ब्रेंट क्रूड 100.67 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। ट्रम्प ने बिना किसी डील के 2-3 हफ्तों में सैन्य अभियान खत्म करने के संकेत दिए हैं। इससे बाजार में अनिश्चितता कम हुई और निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। होर्मुज जलमार्ग बंद होने से मार्च में ओपेक देशों का तेल उत्पादन 73 लाख बैरल प्रतिदिन घट गया है।

भोपाल, बरेली जैसे शहरों में फूड ऑर्डर बढ़े

मैच के साथ खाने का कल्चर, फूड डिलीवरी 30% तक बढ़ी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

त्योहार हों, आईपीएल या ईद- मार्च में भारतीयों ने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने पर खूब खर्च किया। स्विगी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बीते महीने फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट बुकिंग, दोनों में 25-30% उछाल आया। खास बात यह है कि यह ट्रेंड सिर्फ मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली-एनसीआर जैसे मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहा। भोपाल, देहरादून और बरेली जैसे टियर-2,3 शहरों में भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर क्रिकेट मैच के दौरान खाने का नया कल्चर सामने आया है।

05 या उससे ज्यादा लोगों की बुकिंग में 25% की वृद्धि

200 से भी ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर ईद के दिन हर मिनट मिले

पब, बार और लाउंज में जाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा

1.18 लाख रु. का सिंगल ऑर्डर आईपीएल की ओपनिंग नाइट पर

ईद, नवरात्रि: आस्थाएं अलग, भूख एक जैसी

ईद के दिन स्विगी पर हर मिनट 200 से ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर आए। वहीं पूरे भारत में औसतन हर मिनट 11 गुलाब जामुन ऑर्डर किए गए। नवरात्रि में व्रत के खाने की मांग पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ी। साबूदाना खिचड़ी, वड़ा और व्रत थाली सबसे ज्यादा पसंद किए गए।

शाम के मैच स्लॉट के लिए रिजर्वेशन 22.4% बढ़े

28 मार्च को आईपीएल के पहले दिन रेस्टोरेंट बुकिंग 30% से ज्यादा बढ़ी। शाम 7 बजे के मैच स्लॉट के लिए रिजर्वेशन 22.4% बढ़े। बेंगलुरु के एक शख्स ने आईपीएल की ओपनिंग नाइट पर 1.18 लाख रुपए का सिंगल ऑर्डर किया, जो महीने का सबसे बड़ा ऑर्डर रहा।

एलपीजी की कमी से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को 79,000 करोड़ रुपए का झटका

नई दिल्ली | कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के सर्वे के मुताबिक, इंडस्ट्री को हर महीने 79,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। देशभर के 10% रेस्तरां अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं। 60-70% इंडक्शन स्टोव पर निर्भर हैं। इन्होंने काम के घंटे घटाए हैं और मेन्यू सीमित किया है। डोमिनोज चेन चलाने वाली कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में माना है कि एलपीजी आपूर्ति बाधित हुई है। कई बड़े क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन 50% क्षमता पर काम कर रहे हैं। एनआरएआई का अनुमान है कि यह संकट जारी रहा तो 5-7 लाख नौकरियां जा सकती हैं।

जीएसटी-2.0 इफेक्ट • ईरान संकट के बीच भारतीय बाजार में कारों की बिक्री का पिछला रिकॉर्ड टूटा

2025-26 में 47 लाख कारें बिकीं, ये नया रिकॉर्ड

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान घरेलू बाजार में रिकॉर्ड करीब 47 लाख कारें बिकीं। यह 2024-25 में रिकॉर्ड बिक्री से भी 8.3% ज्यादा है। जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स में कटौती इसकी वजह रही।

ईरान युद्ध के बीच मार्च में भी कारों की बिक्री बढ़ी। मध्यम वर्ग ने छोटी हैचबैक के बजाय मिड-साइज एसयूवी और प्रीमियम फीचर्स वाली कारें ज्यादा खरीदी। मारुति सुजुकी की 'मिनी' सेगमेंट (ऑल्टो, एस-प्रेसो) की बिक्री महज 11,741 रही। लेकिन ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो जैसी बड़ी कारों की बिक्री छह गुना ज्यादा 71,356 हो गई। महिंद्रा की बिक्री में 21% उछाल भी एसयूवी की मांग से आया। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली सेल्टोस के दम पर किआ इंडिया ने मार्च की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की।

ऑटोमोबाइल बाजार: हैचबैक के मुकाबले मिड-साइज एसयूवी की बिक्री 6 गुना ज्यादा, महिंद्रा की ग्रोथ 21%

ह्युंडई: भारत में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री

ह्युंडई मोटर इंडिया ने मार्च में घरेलू बाजार में 55,064 कारों की बिक्री करके अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ह्युंडई को नई वेरना और एक्सटर जैसे मॉडल्स से भविष्य में काफी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मार्च में 21% बढ़त के साथ कुल 99,969 कारें बेचीं। मार्च 2025 में यह आंकड़ा 84,431 था।

मारुति: एक साल में बेचीं रिकॉर्ड 24.2 लाख कारें

मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में 24,22,713 कारें बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया। यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी सालाना बिक्री है। मार्च में कंपनी ने कुल 2,25,251 कारें बेचीं, जो सालाना 16.7% अधिक है। इस दौरान घरेलू बाजार में कंपनी ने 1,66,219 कारें बेचीं। बलेनो, डिजायर जैसे कॉम्पैक्ट मॉडल्स 71,789 बिके।

उछाल: मार्च में रेनो इंडिया की बिक्री सबसे ज्यादा 77% बढ़ी, जेएसडब्ल्यू एमजी की ग्रोथ भी 19%

कंपनी	मार्च-25	मार्च-26	बिक्री बढ़ी
मारुति सुजुकी	1,92,984	2,25,251	16.7%
महिंद्रा	82,431	99,969	21.0%
ह्युंडई मोटर	67,314	69,004	2.5%
टाटा मोटर्स (कारें)	51,872	66,971	29.0%
किआ इंडिया	25,525	29,112	14.5%
जेएसडब्ल्यू एमजी	5,485	6,528	19.0%
रेनो इंडिया	2,846	5,046	77.0%

टाटा मोटर्स: कारों की बिक्री 29% बढ़कर 66,971

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (पीवी) के लिए वित्त वर्ष 2025-26 उपलब्धियों भरा रहा। कंपनी ने मार्च में 29% की जबरदस्त बढ़त के साथ कुल 66,971 कारें बेचीं। पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 51,872 था। घरेलू बाजार में भी कंपनी ने 28% की ग्रोथ हासिल करते हुए 66,192 कारें बेचीं, जो पिछले साल 51,616 रही थी।

लंदन: 100 साल पुराना भारतीय रेस्तरां 'वीरास्वामी' बंद होने की कगार पर

1926 में ओपनिंग के वक्त रेस्टोरेंट

लंदन| शहर के रीजेंट स्ट्रीट पर 1926 से संचालित ऐतिहासिक रेस्तरां 'वीरास्वामी' बंद होने की कगार पर है। इसे बचाने के लिए किंग चार्ल्स से हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है। दरअसल, इमारत की मालिक 'क्राउन एस्टेट' ने लीज रिन्यू करने से मना कर दिया है। रेस्तरां के मालिक रंजीत मथानी ने अब कानूनी रास्ता अपनाया है। फैसला जुलाई में आएगा।

ऐतिहासिक: शताब्दी वर्ष मना रहा रेस्टोरेंट

- यह धीमी आंच पर पकाए जाने वाले खास व्यंजनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
- यहां का कश्मीरी रोगन जोश और सीलोन प्रॉन करी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है।
- महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन जैसी चर्चित हस्तियां यहां भोजन कर चुकी हैं।
- माना जाता है कि ब्रिटेन में बीयर और करी के चलन की शुरुआत यहीं से हुई थी।

प्लान • डिजाइन, रिसर्च पर होगा फोकस

चिप हब बनेगा भारत; ₹1.20 लाख करोड़ का निवेश मंजूर

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए निवेश का बड़ा प्लान तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए के भारी-भरकम फंड को हरी झंडी दे दी है। अब ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट के पास ले जाया जाएगा।

पहले चरण में सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा था। इसके तहत 1.6 लाख करोड़ के 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। मिशन के दूसरे चरण में सरकार का फोकस सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने पर नहीं, बल्कि चिप डिजाइन, रिसर्च और इनोवेशन पर भी रहेगा। इसके तहत 2 और 3 नैनोमीटर (एनएम) वाली एडवांस चिप तकनीक विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

नई नीति में मैन्युफैक्चरिंग से हटकर पूरी वैल्यू चेन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार के इस कदम से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इकोसिस्टम मजबूत होगा और भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकेगा।

बिजनेस एंकर प्रवासी मजदूरों को खाड़ी में अपने देश के मुकाबले 4-5 गुना ज्यादा आय, ये बड़ी मजबूरी

जान जोखिम में पर ₹45,000 की तनख्वाह छोड़ना मुश्किल, खाड़ी से रेमिटेंस बंद हुआ तो डूब जाएगी 2.4 करोड़ परिवारों की इकोनॉमी

एजेंसियां | दोहा/दुबई/मनीला

जब सायरन बजता है, तो नॉर्मा टैक्टाकॉन बस दुआ करती हैं। 49 साल की नॉर्मा कतर में घरेलू कामगार हैं। फिलीपींस में उनके पति और तीन बच्चे हैं। अमेरिका-इजराइल से जंग के बीच खाड़ी के देश ईरान के निशाने पर हैं। नॉर्मा उसी आग की लपटों में फंसी हैं। वे कहती हैं, 'हवा में मिसाइलें देखकर डर लगता है। मुझे जिंदा रहना है- बच्चों के लिए। मैं ही उनका सब कुछ हूं।' दरअसल फिलीपींस में घरेलू काम से जो मिलता है, उससे 4-5 गुना यानी प्रति माह 500 डॉलर (करीब 45,000 रुपए) खाड़ी में मिलता है। यही वजह है कि जान जोखिम में होने के बावजूद वो घर नहीं लौट पा रहीं। नॉर्मा अकेली नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मुताबिक, खाड़ी देशों में 2.4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस और इंडोनेशिया के लोग सबसे ज्यादा हैं। इस युद्ध में अब तक कम से कम 12 दक्षिण एशियाई मजदूर जान गंवा चुके हैं। नेपाल के दिबास श्रेष्ठ (29) अबुधाबी में सिक्योरिटी गार्ड थे। 1 मार्च को ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई। उनके चाचा रमेश बताते हैं, 'मैंने उन्हें नेपाल लौटने को कहा था, पर वे कहते थे- यहां अच्छी जिंदगी है।' दिबास 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए माता-पिता का घर बनवाने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। दुबई में बांग्लादेश के 55 साल के अहमद अली की मौत मिसाइल के मलबे से हुई। अली हर महीने 45-55 हजार रुपए घर भेजते थे।

घर लौटना आसान भी नहीं है। युद्ध ने दुबई, अबुधाबी और कतर की उड़ानें बाधित कर दी हैं। फिलीपींस की आखिरी वापसी फ्लाइट में 234 मजदूरों को कुवैत, कतर और बहरीन से 8 घंटे सड़क मार्ग से सऊदी अरब ले जाया गया, तब जाकर वे फ्लाइट पकड़ पाए। पर ज्यादातर लोग घर जाना ही नहीं चाहते। म्यांमार की सू सू (31) दुबई में रियल एस्टेट कंपनी में काम करती हैं। वह म्यांमार में गृहयुद्ध से भागकर आई थीं। वे घर में काम कर रही हैं, सायरन सुनकर खिड़की से दूर हो जाती हैं। फिर भी कहती हैं, 'यहां का माहौल शांत लगता है। मुझे भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा।'

खाड़ी से आए पैसे पर कुछ देशों की अर्थव्यवस्था 10% तक निर्भर

फिलीपींस के कुल विदेशी मजदूरों में से आधे से ज्यादा करीब 10 लाख खाड़ी देशों में हैं। उनके भेजे पैसे फिलीपींस की अर्थव्यवस्था का 10% हैं। बांग्लादेश के 1.4 करोड़ प्रवासियों में से अधिकांश खाड़ी में काम करते हैं। उनकी रेमिटेंस देश की जीडीपी की जीवनरेखा है। आईएलओ के मुताबिक, खाड़ी में 2.4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन से लेकर घरेलू काम तक हर सेक्टर की रीढ़ हैं। युद्ध ने इस पूरी व्यवस्था को हिला दिया है।

रिटेल कंपनियों की कमाई अब 20% तक बढ़ने का अनुमान

संगठित रिटेल का तेज विस्तार; ट्रेंट, डीमार्ट ने ही 3 माह में रिकॉर्ड 183 स्टोर खोल लिए

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश में संगठित रिटेल सेक्टर का तेज विस्तार हो रहा है। जनवरी-मार्च में प्रमुख रिटेल कंपनियों ने रिकॉर्ड 183 स्टोर खोले। इससे टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट और एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) की कमाई बढ़ने की उम्मीद जताई जा र ही है। एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-फरवरी में सुस्त रहने के बाद चौथी तिमाही की पूरी अवधि में जोरदार विस्तार ने निवेशकों की चिंता कम की है। ये विस्तार देश में संगठित रिटेल की ग्रोथ पर भरोसे का प्रतीक है।

देश की 2 बड़ी रिटेल चेन कंपनियों की तगड़ी तैयारी

ट्रेंट: जुडियो के 103 और वेस्टसाइड के 22 नए स्टोर

वैल्यू फैशन ब्रांड जुडियो ने बीती तिमाही 103 स्टोर जोड़े। पूरे साल में यह संख्या 192 रही, जो एलारा के 150 स्टोर के अनुमान से ज्यादा है। वेस्टसाइड ने भी बीते 3 महीनों में 22 और पूरे साल में 52 स्टोर खोले, जबकि वित्त वर्ष 2025 में सिर्फ 16 स्टोर खुले थे। एलारा कैपिटल के मुताबिक, तेज नेटवर्क विस्तार से सालाना 19-20% आय वृद्धि का अनुमान है।

डीमार्ट: अनुमान से डेढ़ गुना स्टोर, शेयर अपग्रेड संभव

डीमार्ट ने बीती तिमाही में 58 और पूरे साल में 85 स्टोर जोड़े। यह वित्त वर्ष 2025 के 50 स्टोर और विश्लेषकों के 51 के अनुमान के डेढ़ गुना से ज्यादा है। उत्तर भारत में विस्तार इसकी बड़ी वजह रही। इससे डीमार्ट की आय 18-20% बढ़ सकती है, जबकि पहले 16-17% ग्रोथ का अनुमान था। इसे देखते हुए ब्रोकरेज फर्म्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर अपग्रेड कर सकते हैं।

जो अस्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को खो देते हैं,
वे न तो स्वतंत्र और न ही सुरक्षित होने के लायक हैं।
– बैंजामिन फ्रैंकलिन

चुनौतियों का सामना

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उपजे संकट का असर अब भारत पर भी साफ दिखने लगा है। अभी तक सरकार यह दावा कर रही थी स्थिति नियंत्रण में है, मगर बुधवार को वाणिज्यिक एलपीजी और विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से स्पष्ट हो गया है कि समस्या अब गहराने लगी है और इसकी सबसे गंभीर मार आम लोगों पर पड़ने वाली है। अगर ईरान तथा अमेरिका-इजराइल का संघर्ष लंबा चला, तो यह तय है कि हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण घरेलू तेल कंपनियों ने उन्नीस किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम 195.50 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसका असर यह होगा कि होटल, रेस्तरां और ढाबों पर भोजन करना तथा डिब्बाबंद खाद्य सामग्री अब महंगी हो जाएगी। इसके अलावा विमान ईंधन के दाम बढ़ाकर 2.07 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से अधिक कर दिए गए हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने इस बढ़ोतरी को घरेलू विमानन कंपनियों के लिए 8.5 फीसद तक ही सीमित रखा है। फिर भी आने वाले दिनों में हवाई यात्रा पहले के मुकाबले महंगी हो सकती है।

हाल ही में ऐसी खबरें आईं थी कि ईरान ने भारत समेत पांच देशों के तेल जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दे दी है, लेकिन बीते सोमवार को कहा गया कि भारत आ रहे तेल और गैस के उन्नीस जहाज अभी भी इस जलमार्ग में फंसे हुए हैं। यानी युद्ध की वजह से खाड़ी क्षेत्र में स्थितियां इतनी जटिल हो गई हैं कि औपचारिक राहत के बावजूद भारत के लिए तेल जहाजों को इस क्षेत्र से बाहर निकालना आसान नहीं है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में ईंधन के वैश्विक संकट के असर से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। घरेलू बाजार में जिस तेजी से वस्तुओं के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, उससे रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी में आम लोगों को यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि क्या ज्यादा जरूरी है और क्या नहीं। खासतौर पर रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार के समक्ष भी बड़ी चुनौती है। अभी तो वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की गई है, लेकिन गैस आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले समय में घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

वैश्विक स्तर पर तेल कीमतों में आए उछाल के कारण देश में चुनिंदा प्रीमियम या ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल के दाम में भी 1.50 रुपए से लेकर 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी घरेलू रसोई गैस और सामान्य पेट्रोल-डीजल के दामों में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार इसकी कीमतें स्थिर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि यह स्थिरता कब तक रहती है। सरकार के समक्ष भी यह चुनौती है कि इस समस्या के बीच आम लोगों को राहत बरकरार कैसे रखी जाए। उत्पाद शुल्क में कटौती से खुले बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन अभी असली समस्या उपलब्धता की है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कच्चे तेल की खरीद के लिए अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करे। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि मध्यपूर्व में अगर हालात सामान्य नहीं हुए, तो ईंधन की आपूर्ति और ज्यादा प्रभावित होगी तथा घरेलू स्तर पर इस समस्या से निपटना आसान नहीं होगा।

प्रदूषण का पैमाना

वायु प्रदूषण केवल महानगरों और बड़े शहरों की समस्या नहीं है, छोटे शहर भी इससे प्रभावित हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से यह दावा किया जाता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में वायु गुणवत्ता का पता लगाने के लिए निगरानी केंद्र बनाए जाने की बात कही जाती है, मगर हकीकत यह है कि देश के करीब चालीस फीसद जिलों में अब तक निगरानी केंद्र स्थापित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जब यह पता ही नहीं चल पाएगा कि हवा में प्रदूषण का स्तर कितना है, तो उसे कम करने के प्रयास भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे। वैश्विक कंपनी 'एअरवाइस' की ओर से बीते मंगलवार को जारी एक अध्ययन रपट में बताया गया है कि कई शहरों और कस्बों में लोगों को अपने आसपास फैल रहे प्रदूषण के बारे में वास्तविक जानकारी ही नहीं मिल पाती है, जिस कारण उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि मुंबई, दिल्ली और बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में तो वायु प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, लेकिन इस मामले में छोटे शहरों और कस्बों की आज भी अनदेखी की जा रही है। निगरानी केंद्र होने का एक फायदा यह है कि इससे आम लोगों को हवा में प्रदूषक तत्त्वों के स्तर की स्टीक जानकारी नियमित रूप से मिलती रहती है। ऐसे में सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ लोग खुद भी सतर्क रहते हैं और मास्क लगाने तथा जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने जैसे उपायों को प्राथमिकता देते हैं। मगर जब लोगों को इसकी सही जानकारी ही नहीं मिलेगी, तो वे इस तरह की सावधानी कैसे बरतेंगे। यह बात भी सामने आई है कि कुछ जिलों में निगरानी केंद्र तो हैं, लेकिन वे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि देश के तमाम शहरों में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए माकूल तकनीकी व्यवस्था की जाए और निगरानी केंद्रों के उचित रख-रखाव के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

ऊर्जा सुरक्षा नीति पर मंथन का समय

मध्यपूर्व में युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है, तेल और गैस का संकट धीरे-धीरे गहराता जा रहा है। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचा, तो भारत सहित विश्व के कई देशों में स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में देश की ऊर्जा सुरक्षा पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

ऋतुपर्ण दवे

ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध का अंजाम चाहे जो हो, लेकिन पूरी दुनिया फिलहाल चिंता में डूबी है। इस समय भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर गहन मंथन करने की जरूरत है। एक दीर्घकालीन रणनीति की तत्काल आवश्यकता है। हमें अपने प्रतिद्वंद्वी चीन से भी सीख लेनी होगी। भले ही दुनिया इस युद्ध की विभीषिका से प्रभावित है और तेल तथा गैस का संकट धीरे-धीरे गहराता जा रहा है। मगर चीन निश्चिंत है। पड़ोसी देश की इस निश्चिंतता के पीछे उसका बड़ा फायदा भी छिपा हुआ है। यदि यह युद्ध और लंबा खिंचता गया, तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्थिति बिगड़ सकती है। इस युद्ध को हम भारत के भविष्य से जोड़ कर देखें, तो हमें काफी पहले ही सचेत हो जाना चाहिए था।

जो स्थितियां अभी बन चुकी हैं, वह कोई अच्छी नहीं है। जितना लंबा युद्ध खिंचेगा, मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी। पहले यह समझना होगा कि हम कहां हैं? फिर यह जानना चाहिए कि चीन कहां हैं। कोई दोराय नहीं कि हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर रणनीति बनाने के लिए अब गंभीरता से विचार करना होगा। इस पर राष्ट्रव्यापी समर्थन और सुझावों की आवश्यकता है। इससे भी ज्यादा इस विषय पर राजनीति से इतर राष्ट्रनीति को आगे कर सबको एकजुट होने की जरूरत है। भू-राजनीति का सहारा लेकर हमें एक दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा नीति बनानी होगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकती है, जब हमारी ऊर्जा नीति दूरदर्शी सोच वाली हो। भारत की जनसंख्या लगभग चीन के बराबर है। मगर दोनों के बीच आर्थिक असमानता साफ दिखती है। ऐसे में चीन के बराबर या उससे भी लंबी लकीर खींचने की जरूरत है। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा।

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध ने हमें क्या सबक दिया है? यह समझना होगा। चीन, भारत का पड़ोसी है। हम उससे कई मामलों में पीछे क्यों हैं, इन सभी स्थितियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तेल-गैस आपूर्ति में अस्थिरता ने पूरे विश्व के समक्ष बहुत बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिका की नजर ईरान के तेल-गैस भंडार पर है। सर्वविदित है कि तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी है। भौगोलिक दृष्टि से ईरान और उसके करीबी तेल उत्पादक देशों में अनाज नहीं उपजता। तेल-गैस के बदले उन्हें खाद्य सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके पास तेल के अकूत भंडार हैं। इसलिए वे इतने समृद्ध हैं कि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। अमेरिका की आंखों में उनकी यही समृद्धि खटक रही है।

लगातार चल रहे युद्ध से स्थिति बिगड़ने लगी है। इसके पीछे आपूर्ति शृंखला का टूटना है। भारत को ही लें, तो खाड़ी देशों से चला कच्चा तेल, लगभग 27 दिनों के बाद बंदरगाह पहुंचता है। उसके बाद तेल शोधक कारखानों में जाता है। फिर वहां से तेल शोधित होकर डिपो और फिर पेट्रोल पंपों तक पहुंचता है। इस पूरे चक्र में लगभग एक महीना लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपूर्ति चक्र अगर ज्यादा बाधित हो गया, तो संकट आना तय है। मान भी लिया जाए कि युद्ध कुछ दिनों में समाप्त

हो जाएगा, तो भी आपूर्ति की निरंतरता में कम से कम 25-30 या ज्यादा दिन लग जाएंगे। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से भारत का कोई लेना-देना नहीं, तो भी ऊर्जा संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में सबसे बड़ा संकट गैस आपूर्ति को लेकर है। प्रतिदिन महानगरों से लेकर कस्बों तक लोग रसोई गैस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, जहां हम अपने उपयोग की चालीस फीसद रसोई गैस का उत्पादन कर पाते हैं, वहीं हम साठ फीसद गैस के लिए ब्राजील सहित करीब नौ देशों पर निर्भर रहते हैं। इधर, देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। पहले चौदह करोड़ उपभोक्ता थे, आज करीब तैंतीस करोड़ से भी ज्यादा हैं। इसी तरह भारत में प्रतिदिन 56-57 लाख बैरल तेल की खपत है। जबकि आवक 52 लाख बैरल प्रतिदिन है। उसमें भी 93 फीसद तेल विदेशी जहाजों से आयात होता है, जिसका हमें भारी परिवहन व्यय भी उठाना पड़ता है। हालांकि, भारत ने रूस में अठारह बिलियन डालर निवेश कर तेल के कुएं खरीद रखे हैं। अभी थोड़ा बहुत तेल रूस से आ रहा है, लेकिन यह बेहद कम है। अमेरिका इसमें भी दखल देता रहा है।

> **अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध ने हमें क्या सबक दिया है? यह समझना होगा। चीन, भारत का पड़ोसी है, मगर हम उससे कई मामलों में पीछे क्यों हैं, इन सभी स्थितियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तेल-गैस आपूर्ति में अस्थिरता ने पूरे विश्व के समक्ष ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। लगातार चल रहे युद्ध से स्थिति बिगड़ने लगी है। इसके पीछे आपूर्ति शृंखला का टूटना है। भारत में सबसे बड़ा संकट गैस आपूर्ति को लेकर है। महानगरों से लेकर कस्बों तक लोग रसोई गैस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति पर गंभीरता से सोचना होगा।**

इस दृष्टि से देखें, तो हमें अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति पर गंभीरता से सोचना होगा। भारत सामान्य स्थिति में अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदता है, लेकिन हमारे पास अपने तेल टैंकर बहुत कम है। यही हमारी रणनीतिक चूक है। पिछले दस वर्षों में जरूर हमने इस दिशा में थोड़ा काम किया है। मगर अभी हम केवल अपनी जरूरत का सात फीसद तेल अपने टैंकरों से ला पाते हैं। शेष 93 फीसद के लिए हमारी विदेशी जहाजों पर निर्भरता है। तेल के खेल में भी अर्थशास्त्र छिपा है। इसे समझना होगा और उसी के अनुसार हमें अपनी ऊर्जा नीति बनानी होगी। यदि आज हम कोई योजना बनाएंगे, तो तमाम तकनीकी और दूसरी बाधाओं को पार करते हुए तेल भंडार का पता लगाने में कम से कम नौ साल लग जाएंगे। वहीं भंडारों से तेल निकालने में कम से कम बारह वर्ष लगेंगे। अभी हमारे पास तेल जरूर है, लेकिन उनकी क्षमता केवल पच्चीस दिनों की है। अभी जो आपूर्ति रुकी है, उससे यह क्रम टूट रहा है। निश्चित रूप से इसका असर हमारे भंडारों पर भी पड़ रहा है।

आम तौर पर हम चालीस दिन का भंडार रखते हैं। वहीं हमें यह भी समझना होगा कि हमारा पड़ोसी चीन सामान्य परिस्थितियों में रोजाना दस लाख बैरल तेल जमा करता है। इस स्थिति में तेल के लिए हमें वैश्विक बाजार तलाशना होगा। अपने टैंकर बढ़ाने होंगे, ताकि परिवहन लागत घटे। चूंकि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, इसलिए यह भी सोचना होगा कि हमारे मामले में किसी भी देश का दखल न हो। इसके लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय ऊर्जा नीति जरूरी है। इसको लेकर पक्ष-विपक्ष देशहित में एक हों और एक ऐसी सर्वदलीय सोच बने, जिसमें राष्ट्रहित का पूरा ध्यान रखा जाए। जो नई ऊर्जा नीति बने, उसमें सभी की भागीदारी हो और उनमें 'देश प्रथम' की भावना हो। युद्ध तो होते रहेंगे, ये न कभी रुके थे और न रुकेंगे।

मौजूदा युद्ध रुकने के बाद हमें दुनिया भर में तेल भंडार खरीदने की योजना बनानी होगी। भारत एक ऐसा देश है, जो समुद्र से जुड़ी गतिविधियों, भूगोल और अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे राष्ट्रों की पहचान उनकी लंबी तटरेखा, बंदरगाहों, विशाल व्यापारिक बेड़े और मजबूत नौसेना से होती है। ऐसे में हम हर तरह से सक्षम जरूर हैं, लेकिन तेल-गैस और टैंकरों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि बनाना होगा। तभी चीन, अमेरिका और ब्राजील की तरह इस दिशा में हम भी आत्मनिर्भर होंगे और ऊर्जा चुनौतियों से जूझ सकेंगे। कम से कम हमारे पास इतना भंडार हो और खुद की परिवहन क्षमता हो कि युद्ध की स्थिति में भी कम से कम तीन-चार महीने का तेल और गैस रहे।

मौन संवाद

चैतन्य नागर

हर संवाद में शब्द हों, यह जरूरी नहीं। कभी-कभी संवाद स्वयं के और दूसरे छोर पर जो है, उसके मौन के बीच एक तरह का अवलोकन होता है। ऐसा संवाद भाषा की सीमाओं को लांघकर अंतस की ऐसी गहराइयों तक पहुंचता है, जिसकी खबर भी नहीं लग पाती। प्रकृति के साथ कुछ इसी तरह का संवाद होता है। हम शोर के युग में जीते हैं, जहां हर पल कुछ न कुछ सुनाई देता है। सन्नाटा हमसे छीन लिया गया है। एकांत किसी शातिर चोर की सेंधमारी में लुट गया है। मन को कभी विश्राम नहीं मिलता। उसे बार-बार छेड़ा जाता है, उकसाया जाता है। जैसे तांगे से बंधे किसी थके हुए घोड़े को जबरदस्ती दौड़ाया जा रहा हो।

इस संस्कृति में उत्पादकता इतनी कीमती हो गई है कि स्थिरता को ही आलस्य समझ लिया गया है। चुपचाप बैठने को समय की आपराधिक बर्बादी कहा जाता है। मगर इस शोर के नीचे हमारा कोई आवश्यक और कीमती हिस्सा क्लांत होने लगता है। वह हिस्सा, जो सपनों से बना है, जो बचपन की यादों में छिपा है और जो बस सिर्फ प्रकृति की गोद में ही सांस लेता है। हम भूल गए हैं कि थकान केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है।

प्रकृति के साथ मौन संवाद का अर्थ जीवन से पलायन करना नहीं है। मनोवैज्ञानिक थकान की, तंत्रिका-तंत्र की निरंतर सतर्कता की बात करते हैं, जो हमें हमेशा सतर्क स्वरूप में रखती है, थका डालती है। मगर इन तकनीकी शब्दों के आने से बहुत पहले मनुष्य जानता था इसका इलाज। हम जंगलों, नदियों, पर्वतों की ओर जाते थे। प्रकृति की शांत उपस्थिति में मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। सांसें गहरी होती हैं, अंतस में थोड़ी जगह बनती हुई महसूस होती है। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, अनकहे शब्द-जो कुछ भी बिखरा हुआ था, वह खुद को समेटने लगता है। प्रकृति कोई अपेक्षा नहीं रखती है। नदी हमारी राय नहीं मांगती। वह बस बहती रहती है। पंछी हमें किसी तरह का दिखावा करने को नहीं कहते। वे गाते हैं अपनी ही स्वाभाविक खुशी में। फूल खिलता है बिना तारीफ की प्रतीक्षा किए। बाहरी दबाव न हों, तो मन खुद ही चंगा होने लगता है, जैसे किसी घाव पर मरहम लगने से दर्द कम होने लगता है।

जो कुछ भी अतिरिक्त है वह इस मौन संवाद में घुल जाता है। बस आवश्यक बचा रह जाता है। अचानक महसूस होता है कि हमारा मानसिक शोर कितना अनावश्यक है, बेहोशी के क्षणों में बटोर लिया गया है, साझी विरासत में मिला गया है- दूसरों की अपेक्षाएं, समाज की अंधाधुंध भाग-दौड़, खुद से गढ़ी हुई कहानियां- कितना बोझ है इनमें। प्रकृति के साथ मौन संवाद में कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है, जो सूक्ष्म और महीन है। एक झीनी-सी आंतरिक स्पष्टता दिखती है, जो अनावश्यक जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दब गई थी। यह बचपन में हमारे पास थी, जब हम बिना किसी कारण खिलखिलाते थे, शोर से सहम जाते थे, द्वेष से मुक्त थे। जब मन निर्मल था, नकारात्मकता से मुक्त था।

मौन में प्रकृति हमारा मनोरंजन नहीं करती, वह हमारे भीतर छिपे सच को सामने लाती है। हवा में कांपता पत्ता हमारी क्षणभंगुरता का आईना बन जाता है। हम भी वैसे ही हैं, जैसी ये पत्तियां! पर्वत की स्थिरता हमारे निरंतर संघर्ष की व्यर्थता दिखाती है। भागते-हांफते इंसान पर वे एक मूक बयान हैं। कुदरत के साथ ये शांत मुलाकातें भावुक नहीं, परिवर्तनकारी होती हैं। वे अपमान किए बगैर विनम्रता सिखाती हैं, स्वामित्व का भाव जताए बिना संबंधित होने का अर्थ समझाती हैं। बगैर डांट-डपट के शिष्टता सिखाती हैं। इस मौन संवाद में थोड़ा बैठें, तो एक गहरे संबंध का बोध होता है- वृक्ष केवल फर्नीचर बनाने वाला काठ नहीं रहता, नदी केवल उपयोगी पानी नहीं रह जाती, जंगल केवल संसाधन नहीं रहता। प्रकृति के साथ परिचय हमें सबकी परवाह करना सिखाता है। यह गहरा जुड़ाव बौद्धिक जानकारी से नहीं, प्रकृति की शांत उपस्थिति से जन्म लेता है।

हमारा पर्यावरणीय संकट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि संबंध की विफलताएं हैं, यह याद रखना जरूरी है। हमने कुदरत का शोषण करना सीख लिया है, पर उसे सुनना भूल गए। हम जंगल काटते हैं बगैर प्रकृति की सांस को महसूस किए। नदियों में जहर डालते हैं, बिना उनकी पीड़ा समझे। प्रकृति का मौन सान्निध्य इन दूरियों को कम करता है। यह याद दिलाता है कि धरती मानवीय महत्त्वाकांक्षाओं की युद्धभूमि नहीं, बल्कि एक जीती-जागती, सुंदर वास्तविकता है और हम उसका अभिन्न हिस्सा हैं। हमारी सांसें उसके साथ जुड़ी हैं, हमारा रक्त, मांस-मज्जा उससे ही बना है।

इस मूक संवाद के लिए कुछ सरल अभ्यास उपयोगी हो सकते हैं। हमें दुर्गम तीर्थयात्राओं की जरूरत नहीं। एक पार्क की बेंच, आकाश का नन्हा-सा टुकड़ा, सुबह का शांत बरामदा ही काफी है। हम थोड़ी देर के लिए छोटी-बड़ी स्क्रीन छोड़ दें। बैठें। अपनी तस्वीरें न लें, सोशल मीडिया में न उलझें। सुबह पक्षियों की आवाजें सुन लें। बोरियत आती है, तो उसे आने-जाने दें। धीरे-धीरे कुछ बदलने लगता है। जो पहले खाली लगता था, वह अब किसी अनुभूति में परिवर्तित होने लगता है। मन में जगह बनती है, जैसे बादलों के हटने पर आकाश साफ हो जाता है। अभिव्यक्ति की आदिम हठी आदत को ऐसा मौन क्रांतिकारी प्रतीत होता है। उत्पादन के जुनूनी अर्थतंत्र में किसी वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठना एक बगावत है। मगर समय का यह ऐसा सदुपयोग है, जिसे मापा नहीं जा सकता। प्रकृति का साथ का हमें अपनी सही औकात दिखाता है- हम इतने छोटे हैं, ब्रह्मांड इतना बड़ा, यह याद दिलाता है। मौन अनुपस्थिति या पलायन नहीं, वह वास्तविक अर्थ में एक गहरी उपस्थिति है, एक सामीप्य है, जहां धरा कुछ न कहकर भी सबसे स्पष्ट बोलती है। बस हम ही नहीं सुनते।

दुनिया मेरे आगे

> **प्रकृति हमारा मनोरंजन नहीं करती, वह हमारे भीतर छिपे सच को सामने लाती है। हवा में कांपता पत्ता हमारी क्षणभंगुरता का आईना बन जाता है। पर्वत की स्थिरता हमारे निरंतर संघर्ष की व्यर्थता को दिखाती है। कुदरत के साथ हमारी ये शांत और सहज मुलाकातें सिर्फ भावुक ही नहीं, परिवर्तनकारी भी होती हैं।**

अधूरा लक्ष्य

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सार्वजनिक विमर्श में उम्मीद जगाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इस पर सवाल खड़े कर देती है। हालिया आंकड़े संकेत देते हैं कि विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से और स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने का लक्ष्य अब भी अधूरा है। यह केवल सुविधा का अभाव नहीं, बल्कि शिक्षा के अधिकार पर लगा एक मौन प्रतिबंध है। जब बुनियादी आवश्यकताएं ही सुनिश्चि नहीं होंगी, तो सशक्तीकरण की बात खोखली प्रतीत होती है। स्वच्छ शौचालय का अभाव सीधे तौर पर लड़कियों के स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और विद्यालय में नियमित उपस्थिति को प्रभावित करता है। किशोरावस्था की छात्राओं के लिए यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, जिसके कारण कई बार उन्हें स्कूल छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। यह विडंबना ही है कि एक ओर 'स्वच्छ विद्यालय' और 'बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान चलाए जाते हैं, दूसरी ओर बुनियादी ढांचा उनकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों से नहीं, बल्कि सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण से भी आकार लेती है।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

पर्यावरण की कीमत

'युद्ध से पर्यावरण पर मंडराता खतरा' (आलेख 31 मार्च) पढ़ा। यह गंभीर मुद्दा है। इस लेख ने एक ऐसे पहलू को उजागर किया है, जो युद्ध की खबरों में अक्सर दब जाता है। और वह है-पर्यावरण पर पड़ने वाली विनाशकारी मार। होर्मुज जलमार्ग पर तेल जहाजों को निशाना बनाना केवल आर्थिक हमला नहीं, बल्कि यह समुद्री जीवन पर सीधा प्रहार है। लाखों टन तेल जब समुद्र में फैलता है, तो आक्सीजन रुकती है और बड़ी संख्या में समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। समुद्र का अपना पारिस्थितिकी तंत्र भी बुरी तरह बिगड़ जाता है। पूरी समुद्री खाद्य शृंखला जहरीली हो जाती है। अलास्का से फारस की खाड़ी तक, जब भी किन्हीं कारणों से समुद्र में तेल का रिसाव हुआ है, उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। युद्ध दो देशों के बीच होता है, लेकिन धरती सबकी साझी है। वैश्विक समुदाय को यह स्वीकार करना होगा कि तेल भंडारों पर हमला अपराध है।

– वेदिका मनोज सावल, जम्मू

ईंधन का संकट

सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें गैस चूल्हे पर खाना बनाने और सीएनजी चालित वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। हर घरों में एलपीजी सिलेंडर हैं और उज्जवला योजना ने इसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी है। कई लोग डीजल वाहनों को छोड़ कर सीएनजी से अपने वाहनों को चला रहे है। आज जबकि पश्चिम एशिया युद्ध के संकट में फंसा है और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध गति से नहीं हो पा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि विकल्प तलाशे। पेट्रोल और रसोई गैस की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अन्य देशों से संपर्क स्थापित किया जाए, ताकि स्थितियां काबू में आ जाएं। इस बीच बिजली चालित चूल्हों की कीमतें एकाएक काफी बढ़ गई हैं। इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। आपदा किसी हाल में अवसर न बने, इसका ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

– जफर अहमद, मधेपुरा, बिहार

समरसता पर चोट

आज पूरी दुनिया अमेरिका की नीतियों और दबाव से परेशान नजर आ रही है। औपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित करने में तल्लीन अमेरिकी नेतृत्व सर्वदेशीय समरसता पर कुठाराघात कर रहा है। सार्वभौमिक भरोसे के भवनों को ध्वस्त कर, उन पर निजी आर्थिक हितों की खेती की जा रही है। पर्दे के पीछे से चुनावी चंदे के चक्र को पूरा करने के लिए लगातार मनमानी की जा रही है। शांति वार्ताओं का इस्तेमाल छलावे के लिए किया जाता है। युद्ध की धमकियां देकर समझौते करने की बात जब किसी राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व करता हो, तो यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि क्या अमेरिका सच में अब लोकतांत्रिक है? इस समय युद्ध ने शांति और विश्वास के वैश्विक वृत्त को महंगाई एवं ऊर्जा संकट की काली चादर से ढक दिया है, मगर वैश्विक समुदाय चुप है।

– विवेक मिश्रा, खंडवा, मप्र

जो अस्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को खो देते हैं,
वे न तो स्वतंत्र और न ही सुरक्षित होने के लायक हैं।
– बैंजामिन फ्रैंकलिन

चुनौतियों का सामना

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उपजे संकट का असर अब भारत पर भी साफ दिखने लगा है। अभी तक सरकार यह दावा कर रही थी स्थिति नियंत्रण में है, मगर बुधवार को वाणिज्यिक एलपीजी और विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से स्पष्ट हो गया है कि समस्या अब गहराने लगी है और इसकी सबसे गंभीर मार आम लोगों पर पड़ने वाली है। अगर ईरान तथा अमेरिका-इजराइल का संघर्ष लंबा चला, तो यह तय है कि हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण घरेलू तेल कंपनियों ने उन्नीस किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम 195.50 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसका असर यह होगा कि होटल, रेस्तरां और ढाबों पर भोजन करना तथा डिब्बाबंद खाद्य सामग्री अब महंगी हो जाएगी। इसके अलावा विमान ईंधन के दाम बढ़ाकर 2.07 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से अधिक कर दिए गए हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने इस बढ़ोतरी को घरेलू विमानन कंपनियों के लिए 8.5 फीसद तक ही सीमित रखा है। फिर भी आने वाले दिनों में हवाई यात्रा पहले के मुकाबले महंगी हो सकती है।

हाल ही में ऐसी खबरें आईं थी कि ईरान ने भारत समेत पांच देशों के तेल जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दे दी है, लेकिन बीते सोमवार को कहा गया कि भारत आ रहे तेल और गैस के उन्नीस जहाज अभी भी इस जलमार्ग में फंसे हुए हैं। यानी युद्ध की वजह से खाड़ी क्षेत्र में स्थितियां इतनी जटिल हो गई हैं कि औपचारिक राहत के बावजूद भारत के लिए तेल जहाजों को इस क्षेत्र से बाहर निकालना आसान नहीं है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में ईंधन के वैश्विक संकट के असर से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। घरेलू बाजार में जिस तेजी से वस्तुओं के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, उससे रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी में आम लोगों को यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि क्या ज्यादा जरूरी है और क्या नहीं। खासतौर पर रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार के समक्ष भी बड़ी चुनौती है। अभी तो वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की गई है, लेकिन गैस आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले समय में घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

वैश्विक स्तर पर तेल कीमतों में आए उछाल के कारण देश में चुनिंदा प्रीमियम या ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल के दाम में भी 1.50 रुपए से लेकर 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी घरेलू रसोई गैस और सामान्य पेट्रोल-डीजल के दामों में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार इसकी कीमतें स्थिर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि यह स्थिरता कब तक रहती है। सरकार के समक्ष भी यह चुनौती है कि इस समस्या के बीच आम लोगों को राहत बरकरार कैसे रखी जाए। उत्पाद शुल्क में कटौती से खुले बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन अभी असली समस्या उपलब्धता की है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कच्चे तेल की खरीद के लिए अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करे। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि मध्यपूर्व में अगर हालात सामान्य नहीं हुए, तो ईंधन की आपूर्ति और ज्यादा प्रभावित होगी तथा घरेलू स्तर पर इस समस्या से निपटना आसान नहीं होगा।

प्रदूषण का पैमाना

वायु प्रदूषण केवल महानगरों और बड़े शहरों की समस्या नहीं है, छोटे शहर भी इससे प्रभावित हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से यह दावा किया जाता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में वायु गुणवत्ता का पता लगाने के लिए निगरानी केंद्र बनाए जाने की बात कही जाती है, मगर हकीकत यह है कि देश के करीब चालीस फीसद जिलों में अब तक निगरानी केंद्र स्थापित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जब यह पता ही नहीं चल पाएगा कि हवा में प्रदूषण का स्तर कितना है, तो उसे कम करने के प्रयास भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे। वैश्विक कंपनी 'एअरवाइस' की ओर से बीते मंगलवार को जारी एक अध्ययन रपट में बताया गया है कि कई शहरों और कस्बों में लोगों को अपने आसपास फैल रहे प्रदूषण के बारे में वास्तविक जानकारी ही नहीं मिल पाती है, जिस कारण उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि मुंबई, दिल्ली और बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में तो वायु प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, लेकिन इस मामले में छोटे शहरों और कस्बों की आज भी अनदेखी की जा रही है। निगरानी केंद्र होने का एक फायदा यह है कि इससे आम लोगों को हवा में प्रदूषक तत्त्वों के स्तर की स्टीक जानकारी नियमित रूप से मिलती रहती है। ऐसे में सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ लोग खुद भी सतर्क रहते हैं और मास्क लगाने तथा जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने जैसे उपायों को प्राथमिकता देते हैं। मगर जब लोगों को इसकी सही जानकारी ही नहीं मिलेगी, तो वे इस तरह की सावधानी कैसे बरतेंगे। यह बात भी सामने आई है कि कुछ जिलों में निगरानी केंद्र तो हैं, लेकिन वे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि देश के तमाम शहरों में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए माकूल तकनीकी व्यवस्था की जाए और निगरानी केंद्रों के उचित रख-रखाव के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

ऊर्जा सुरक्षा नीति पर मंथन का समय

मध्यपूर्व में युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है, तेल और गैस का संकट धीरे-धीरे गहराता जा रहा है। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचा, तो भारत सहित विश्व के कई देशों में स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में देश की ऊर्जा सुरक्षा पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

ऋतुपर्ण दवे

ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध का अंजाम चाहे जो हो, लेकिन पूरी दुनिया फिलहाल चिंता में डूबी है। इस समय भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर गहन मंथन करने की जरूरत है। एक दीर्घकालीन रणनीति की तत्काल आवश्यकता है। हमें अपने प्रतिद्वंद्वी चीन से भी सीख लेनी होगी। भले ही दुनिया इस युद्ध की विभीषिका से प्रभावित है और तेल तथा गैस का संकट धीरे-धीरे गहराता जा रहा है। मगर चीन निश्चिंत है। पड़ोसी देश की इस निश्चिंतता के पीछे उसका बड़ा फायदा भी छिपा हुआ है। यदि यह युद्ध और लंबा खिंचता गया, तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्थिति बिगड़ सकती है। इस युद्ध को हम भारत के भविष्य से जोड़ कर देखें, तो हमें काफी पहले ही सचेत हो जाना चाहिए था।

जो स्थितियां अभी बन चुकी हैं, वह कोई अच्छी नहीं है। जितना लंबा युद्ध खिंचेगा, मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी। पहले यह समझना होगा कि हम कहां हैं? फिर यह जानना चाहिए कि चीन कहां हैं। कोई दोराय नहीं कि हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर रणनीति बनाने के लिए अब गंभीरता से विचार करना होगा। इस पर राष्ट्रव्यापी समर्थन और सुझावों की आवश्यकता है। इससे भी ज्यादा इस विषय पर राजनीति से इतर राष्ट्रनीति को आगे कर सबको एकजुट होने की जरूरत है। भू-राजनीति का सहारा लेकर हमें एक दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा नीति बनानी होगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकती है, जब हमारी ऊर्जा नीति दूरदर्शी सोच वाली हो। भारत की जनसंख्या लगभग चीन के बराबर है। मगर दोनों के बीच आर्थिक असमानता साफ दिखती है। ऐसे में चीन के बराबर या उससे भी लंबी लकीर खींचने की जरूरत है। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा।

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध ने हमें क्या सबक दिया है? यह समझना होगा। चीन, भारत का पड़ोसी है। हम उससे कई मामलों में पीछे क्यों हैं, इन सभी स्थितियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तेल-गैस आपूर्ति में अस्थिरता ने पूरे विश्व के समक्ष बहुत बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिका की नजर ईरान के तेल-गैस भंडार पर है। सर्वविदित है कि तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी है। भौगोलिक दृष्टि से ईरान और उसके करीबी तेल उत्पादक देशों में अनाज नहीं उपजता। तेल-गैस के बदले उन्हें खाद्य सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके पास तेल के अकूत भंडार हैं। इसलिए वे इतने समृद्ध हैं कि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। अमेरिका की आंखों में उनकी यही समृद्धि खटक रही है।

लगातार चल रहे युद्ध से स्थिति बिगड़ने लगी है। इसके पीछे आपूर्ति शृंखला का टूटना है। भारत को ही लें, तो खाड़ी देशों से चला कच्चा तेल, लगभग 27 दिनों के बाद बंदरगाह पहुंचता है। उसके बाद तेल शोधक कारखानों में जाता है। फिर वहां से तेल शोधित होकर डिपो और फिर पेट्रोल पंपों तक पहुंचता है। इस पूरे चक्र में लगभग एक महीना लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपूर्ति चक्र अगर ज्यादा बाधित हो गया, तो संकट आना तय है। मान भी लिया जाए कि युद्ध कुछ दिनों में समाप्त

हो जाएगा, तो भी आपूर्ति की निरंतरता में कम से कम 25-30 या ज्यादा दिन लग जाएंगे। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से भारत का कोई लेना-देना नहीं, तो भी ऊर्जा संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में सबसे बड़ा संकट गैस आपूर्ति को लेकर है। प्रतिदिन महानगरों से लेकर कस्बों तक लोग रसोई गैस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, जहां हम अपने उपयोग की चालीस फीसद रसोई गैस का उत्पादन कर पाते हैं, वहीं हम साठ फीसद गैस के लिए ब्राजील सहित करीब नौ देशों पर निर्भर रहते हैं। इधर, देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। पहले चौदह करोड़ उपभोक्ता थे, आज करीब तैंतीस करोड़ से भी ज्यादा हैं। इसी तरह भारत में प्रतिदिन 56-57 लाख बैरल तेल की खपत है। जबकि आवक 52 लाख बैरल प्रतिदिन है। उसमें भी 93 फीसद तेल विदेशी जहाजों से आयात होता है, जिसका हमें भारी परिवहन व्यय भी उठाना पड़ता है। हालांकि, भारत ने रूस में अठारह बिलियन डालर निवेश कर तेल के कुएं खरीद रखे हैं। अभी थोड़ा बहुत तेल रूस से आ रहा है, लेकिन यह बेहद कम है। अमेरिका इसमें भी दखल देता रहा है।

> **अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध ने हमें क्या सबक दिया है? यह समझना होगा। चीन, भारत का पड़ोसी है, मगर हम उससे कई मामलों में पीछे क्यों हैं, इन सभी स्थितियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तेल-गैस आपूर्ति में अस्थिरता ने पूरे विश्व के समक्ष ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। लगातार चल रहे युद्ध से स्थिति बिगड़ने लगी है। इसके पीछे आपूर्ति शृंखला का टूटना है। भारत में सबसे बड़ा संकट गैस आपूर्ति को लेकर है। महानगरों से लेकर कस्बों तक लोग रसोई गैस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति पर गंभीरता से सोचना होगा।**

इस दृष्टि से देखें, तो हमें अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति पर गंभीरता से सोचना होगा। भारत सामान्य स्थिति में अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदता है, लेकिन हमारे पास अपने तेल टैंकर बहुत कम है। यही हमारी रणनीतिक चूक है। पिछले दस वर्षों में जरूर हमने इस दिशा में थोड़ा काम किया है। मगर अभी हम केवल अपनी जरूरत का सात फीसद तेल अपने टैंकरों से ला पाते हैं। शेष 93 फीसद के लिए हमारी विदेशी जहाजों पर निर्भरता है। तेल के खेल में भी अर्थशास्त्र छिपा है। इसे समझना होगा और उसी के अनुसार हमें अपनी ऊर्जा नीति बनानी होगी। यदि आज हम कोई योजना बनाएंगे, तो तमाम तकनीकी और दूसरी बाधाओं को पार करते हुए तेल भंडार का पता लगाने में कम से कम नौ साल लग जाएंगे। वहीं भंडारों से तेल निकालने में कम से कम बारह वर्ष लगेंगे। अभी हमारे पास तेल जरूर है, लेकिन उनकी क्षमता केवल पच्चीस दिनों की है। अभी जो आपूर्ति रुकी है, उससे यह क्रम टूट रहा है। निश्चित रूप से इसका असर हमारे भंडारों पर भी पड़ रहा है।

आम तौर पर हम चालीस दिन का भंडार रखते हैं। वहीं हमें यह भी समझना होगा कि हमारा पड़ोसी चीन सामान्य परिस्थितियों में रोजाना दस लाख बैरल तेल जमा करता है। इस स्थिति में तेल के लिए हमें वैश्विक बाजार तलाशना होगा। अपने टैंकर बढ़ाने होंगे, ताकि परिवहन लागत घटे। चूंकि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, इसलिए यह भी सोचना होगा कि हमारे मामले में किसी भी देश का दखल न हो। इसके लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय ऊर्जा नीति जरूरी है। इसको लेकर पक्ष-विपक्ष देशहित में एक हों और एक ऐसी सर्वदलीय सोच बने, जिसमें राष्ट्रहित का पूरा ध्यान रखा जाए। जो नई ऊर्जा नीति बने, उसमें सभी की भागीदारी हो और उनमें 'देश प्रथम' की भावना हो। युद्ध तो होते रहेंगे, ये न कभी रुके थे और न रुकेंगे।

मौजूदा युद्ध रुकने के बाद हमें दुनिया भर में तेल भंडार खरीदने की योजना बनानी होगी। भारत एक ऐसा देश है, जो समुद्र से जुड़ी गतिविधियों, भूगोल और अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे राष्ट्रों की पहचान उनकी लंबी तटरेखा, बंदरगाहों, विशाल व्यापारिक बेड़े और मजबूत नौसेना से होती है। ऐसे में हम हर तरह से सक्षम जरूर हैं, लेकिन तेल-गैस और टैंकरों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि बनाना होगा। तभी चीन, अमेरिका और ब्राजील की तरह इस दिशा में हम भी आत्मनिर्भर होंगे और ऊर्जा चुनौतियों से जूझ सकेंगे। कम से कम हमारे पास इतना भंडार हो और खुद की परिवहन क्षमता हो कि युद्ध की स्थिति में भी कम से कम तीन-चार महीने का तेल और गैस रहे।

मौन संवाद

चैतन्य नागर

हर संवाद में शब्द हों, यह जरूरी नहीं। कभी-कभी संवाद स्वयं के और दूसरे छोर पर जो है, उसके मौन के बीच एक तरह का अवलोकन होता है। ऐसा संवाद भाषा की सीमाओं को लांघकर अंतस की ऐसी गहराइयों तक पहुंचता है, जिसकी खबर भी नहीं लग पाती। प्रकृति के साथ कुछ इसी तरह का संवाद होता है। हम शोर के युग में जीते हैं, जहां हर पल कुछ न कुछ सुनाई देता है। सन्नाटा हमसे छीन लिया गया है। एकांत किसी शातिर चोर की सेंधमारी में लुट गया है। मन को कभी विश्राम नहीं मिलता। उसे बार-बार छेड़ा जाता है, उकसाया जाता है। जैसे तांगे से बंधे किसी थके हुए घोड़े को जबरदस्ती दौड़ाया जा रहा हो।

इस संस्कृति में उत्पादकता इतनी कीमती हो गई है कि स्थिरता को ही आलस्य समझ लिया गया है। चुपचाप बैठने को समय की आपराधिक बर्बादी कहा जाता है। मगर इस शोर के नीचे हमारा कोई आवश्यक और कीमती हिस्सा क्लांत होने लगता है। वह हिस्सा, जो सपनों से बना है, जो बचपन की यादों में छिपा है और जो बस सिर्फ प्रकृति की गोद में ही सांस लेता है। हम भूल गए हैं कि थकान केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है।

प्रकृति के साथ मौन संवाद का अर्थ जीवन से पलायन करना नहीं है। मनोवैज्ञानिक थकान की, तंत्रिका-तंत्र की निरंतर सतर्कता की बात करते हैं, जो हमें हमेशा सतर्क स्वरूप में रखती है, थका डालती है। मगर इन तकनीकी शब्दों के आने से बहुत पहले मनुष्य जानता था इसका इलाज। हम जंगलों, नदियों, पर्वतों की ओर जाते थे। प्रकृति की शांत उपस्थिति में मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। सांसें गहरी होती हैं, अंतस में थोड़ी जगह बनती हुई महसूस होती है। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, अनकहे शब्द-जो कुछ भी बिखरा हुआ था, वह खुद को समेटने लगता है। प्रकृति कोई अपेक्षा नहीं रखती है। नदी हमारी राय नहीं मांगती। वह बस बहती रहती है। पंछी हमें किसी तरह का दिखावा करने को नहीं कहते। वे गाते हैं अपनी ही स्वाभाविक खुशी में। फूल खिलता है बिना तारीफ की प्रतीक्षा किए। बाहरी दबाव न हों, तो मन खुद ही चंगा होने लगता है, जैसे किसी घाव पर मरहम लगने से दर्द कम होने लगता है।

जो कुछ भी अतिरिक्त है वह इस मौन संवाद में घुल जाता है। बस आवश्यक बचा रह जाता है। अचानक महसूस होता है कि हमारा मानसिक शोर कितना अनावश्यक है, बेहोशी के क्षणों में बटोर लिया गया है, साझी विरासत में मिला गया है- दूसरों की अपेक्षाएं, समाज की अंधाधुंध भाग-दौड़, खुद से गढ़ी हुई कहानियां- कितना बोझ है इनमें। प्रकृति के साथ मौन संवाद में कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है, जो सूक्ष्म और महीन है। एक झीनी-सी आंतरिक स्पष्टता दिखती है, जो अनावश्यक जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दब गई थी। यह बचपन में हमारे पास थी, जब हम बिना किसी कारण खिलखिलाते थे, शोर से सहम जाते थे, द्वेष से मुक्त थे। जब मन निर्मल था, नकारात्मकता से मुक्त था।

मौन में प्रकृति हमारा मनोरंजन नहीं करती, वह हमारे भीतर छिपे सच को सामने लाती है। हवा में कांपता पत्ता हमारी क्षणभंगुरता का आईना बन जाता है। हम भी वैसे ही हैं, जैसी ये पत्तियां! पर्वत की स्थिरता हमारे निरंतर संघर्ष की व्यर्थता दिखाती है। भागते-हांफते इंसान पर वे एक मूक बयान हैं। कुदरत के साथ ये शांत मुलाकातें भावुक नहीं, परिवर्तनकारी होती हैं। वे अपमान किए बगैर विनम्रता सिखाती हैं, स्वामित्व का भाव जताए बिना संबंधित होने का अर्थ समझाती हैं। बगैर डांट-डपट के शिष्टता सिखाती हैं। इस मौन संवाद में थोड़ा बैठें, तो एक गहरे संबंध का बोध होता है- वृक्ष केवल फर्नीचर बनाने वाला काठ नहीं रहता, नदी केवल उपयोगी पानी नहीं रह जाती, जंगल केवल संसाधन नहीं रहता। प्रकृति के साथ परिचय हमें सबकी परवाह करना सिखाता है। यह गहरा जुड़ाव बौद्धिक जानकारी से नहीं, प्रकृति की शांत उपस्थिति से जन्म लेता है।

हमारा पर्यावरणीय संकट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि संबंध की विफलताएं हैं, यह याद रखना जरूरी है। हमने कुदरत का शोषण करना सीख लिया है, पर उसे सुनना भूल गए। हम जंगल काटते हैं बगैर प्रकृति की सांस को महसूस किए। नदियों में जहर डालते हैं, बिना उनकी पीड़ा समझे। प्रकृति का मौन सान्निध्य इन दूरियों को कम करता है। यह याद दिलाता है कि धरती मानवीय महत्त्वाकांक्षाओं की युद्धभूमि नहीं, बल्कि एक जीती-जागती, सुंदर वास्तविकता है और हम उसका अभिन्न हिस्सा हैं। हमारी सांसें उसके साथ जुड़ी हैं, हमारा रक्त, मांस-मज्जा उससे ही बना है।

इस मूक संवाद के लिए कुछ सरल अभ्यास उपयोगी हो सकते हैं। हमें दुर्गम तीर्थयात्राओं की जरूरत नहीं। एक पार्क की बेंच, आकाश का नन्हा-सा टुकड़ा, सुबह का शांत बरामदा ही काफी है। हम थोड़ी देर के लिए छोटी-बड़ी स्क्रीन छोड़ दें। बैठें। अपनी तस्वीरें न लें, सोशल मीडिया में न उलझें। सुबह पक्षियों की आवाजें सुन लें। बोरियत आती है, तो उसे आने-जाने दें। धीरे-धीरे कुछ बदलने लगता है। जो पहले खाली लगता था, वह अब किसी अनुभूति में परिवर्तित होने लगता है। मन में जगह बनती है, जैसे बादलों के हटने पर आकाश साफ हो जाता है। अभिव्यक्ति की आदिम हठी आदत को ऐसा मौन क्रांतिकारी प्रतीत होता है। उत्पादन के जुनूनी अर्थतंत्र में किसी वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठना एक बगावत है। मगर समय का यह ऐसा सदुपयोग है, जिसे मापा नहीं जा सकता। प्रकृति का साथ का हमें अपनी सही औकात दिखाता है- हम इतने छोटे हैं, ब्रह्मांड इतना बड़ा, यह याद दिलाता है। मौन अनुपस्थिति या पलायन नहीं, वह वास्तविक अर्थ में एक गहरी उपस्थिति है, एक सामीप्य है, जहां धरा कुछ न कहकर भी सबसे स्पष्ट बोलती है। बस हम ही नहीं सुनते।

दुनिया मेरे आगे

> **प्रकृति हमारा मनोरंजन नहीं करती, वह हमारे भीतर छिपे सच को सामने लाती है। हवा में कांपता पत्ता हमारी क्षणभंगुरता का आईना बन जाता है। पर्वत की स्थिरता हमारे निरंतर संघर्ष की व्यर्थता को दिखाती है। कुदरत के साथ हमारी ये शांत और सहज मुलाकातें सिर्फ भावुक ही नहीं, परिवर्तनकारी भी होती हैं।**

अधूरा लक्ष्य

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सार्वजनिक विमर्श में उम्मीद जगाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इस पर सवाल खड़े कर देती है। हालिया आंकड़े संकेत देते हैं कि विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से और स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने का लक्ष्य अब भी अधूरा है। यह केवल सुविधा का अभाव नहीं, बल्कि शिक्षा के अधिकार पर लगा एक मौन प्रतिबंध है। जब बुनियादी आवश्यकताएं ही सुनिश्चि नहीं होंगी, तो सशक्तीकरण की बात खोखली प्रतीत होती है। स्वच्छ शौचालय का अभाव सीधे तौर पर लड़कियों के स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और विद्यालय में नियमित उपस्थिति को प्रभावित करता है। किशोरावस्था की छात्राओं के लिए यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, जिसके कारण कई बार उन्हें स्कूल छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। यह विडंबना ही है कि एक ओर 'स्वच्छ विद्यालय' और 'बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान चलाए जाते हैं, दूसरी ओर बुनियादी ढांचा उनकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों से नहीं, बल्कि सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण से भी आकार लेती है।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

पर्यावरण की कीमत

'युद्ध से पर्यावरण पर मंडराता खतरा' (आलेख 31 मार्च) पढ़ा। यह गंभीर मुद्दा है। इस लेख ने एक ऐसे पहलू को उजागर किया है, जो युद्ध की खबरों में अक्सर दब जाता है। और वह है-पर्यावरण पर पड़ने वाली विनाशकारी मार। होर्मुज जलमार्ग पर तेल जहाजों को निशाना बनाना केवल आर्थिक हमला नहीं, बल्कि यह समुद्री जीवन पर सीधा प्रहार है। लाखों टन तेल जब समुद्र में फैलता है, तो आक्सीजन रुकती है और बड़ी संख्या में समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। समुद्र का अपना पारिस्थितिकी तंत्र भी बुरी तरह बिगड़ जाता है। पूरी समुद्री खाद्य शृंखला जहरीली हो जाती है। अलास्का से फारस की खाड़ी तक, जब भी किन्हीं कारणों से समुद्र में तेल का रिसाव हुआ है, उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। युद्ध दो देशों के बीच होता है, लेकिन धरती सबकी साझी है। वैश्विक समुदाय को यह स्वीकार करना होगा कि तेल भंडारों पर हमला अपराध है।

– वेदिका मनोज सावल, जम्मू

ईंधन का संकट

सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें गैस चूल्हे पर खाना बनाने और सीएनजी चालित वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। हर घरों में एलपीजी सिलेंडर हैं और उज्जवला योजना ने इसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी है। कई लोग डीजल वाहनों को छोड़ कर सीएनजी से अपने वाहनों को चला रहे है। आज जबकि पश्चिम एशिया युद्ध के संकट में फंसा है और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध गति से नहीं हो पा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि विकल्प तलाशे। पेट्रोल और रसोई गैस की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अन्य देशों से संपर्क स्थापित किया जाए, ताकि स्थितियां काबू में आ जाएं। इस बीच बिजली चालित चूल्हों की कीमतें एकाएक काफी बढ़ गई हैं। इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। आपदा किसी हाल में अवसर न बने, इसका ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

– जफर अहमद, मधेपुरा, बिहार

समरसता पर चोट

आज पूरी दुनिया अमेरिका की नीतियों और दबाव से परेशान नजर आ रही है। औपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित करने में तल्लीन अमेरिकी नेतृत्व सर्वदेशीय समरसता पर कुठाराघात कर रहा है। सार्वभौमिक भरोसे के भवनों को ध्वस्त कर, उन पर निजी आर्थिक हितों की खेती की जा रही है। पर्दे के पीछे से चुनावी चंदे के चक्र को पूरा करने के लिए लगातार मनमानी की जा रही है। शांति वार्ताओं का इस्तेमाल छलावे के लिए किया जाता है। युद्ध की धमकियां देकर समझौते करने की बात जब किसी राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व करता हो, तो यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि क्या अमेरिका सच में अब लोकतांत्रिक है? इस समय युद्ध ने शांति और विश्वास के वैश्विक वृत्त को महंगाई एवं ऊर्जा संकट की काली चादर से ढक दिया है, मगर वैश्विक समुदाय चुप है।

– विवेक मिश्रा, खंडवा, मप्र

गहन पड़ताल

कैसे बनेंगे 66 रुपए की खुराक से विजेता

जनसत्ता खेल

हरियाणा ने 74,000 खिलाड़ियों के लिए 12.72 करोड़ जारी किए... यानी रोज 66 रुपए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिविर में 1,000 रुपए प्रतिदिन किए, पर राज्यों में फर्क जमीन-आसमान का है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु... हर राज्य की अलग कहानी है।

हरियाणा सरकार ने 74,884 युवा खिलाड़ियों के लिए 12.72 करोड़ रुपए का पोषण भत्ता जारी किया है। इस योजना में 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए प्रतिमाह और 14 से 19 साल के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। यानी रोज का हिसाब लगाएं तो 50 से 66 रुपए। एक प्रोटीन बार की कीमत इससे ज्यादा है। लेकिन राज्यों में तुलना करने से पहले केंद्र सरकार का हाल देखें...

केंद्र सरकार-क्या किया, कितना बचा?

वित्त वर्ष 2026-27 में खेल मंत्रालय का बजट 4,479.88 करोड़ रुपए है। पिछले साल से 18 फीसद अधिक। इसमें खेलो इंडिया मिशन को 924 करोड़ और एसएआई को 917 करोड़ मिले हैं। बजट बड़ा दिखता है, लेकिन जब यह 140 करोड़ की आबादी में बंटता है तो तस्वीर बदल जाती है।

राष्ट्रीय शिविर में खिलाड़ियों के लिए पोषण भत्ता हाल ही में बढ़ा है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मई 2025 में घोषणा की कि राष्ट्रीय शिविर के वरिष्ठ खिलाड़ियों को अब 1,000 रुपये प्रतिदिन और कनिष्ठ खिलाड़ियों को 850 रुपये प्रतिदिन खुराक मुद्रा मिलेगी। पहले यह क्रमशः 690 और 480 रुपए थी। यह सुधार स्वागत योग्य है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ राष्ट्रीय शिविर के खिलाड़ियों को मिलती है। बाकी लाखों युवा खिलाड़ी राज्य सरकारों के भरोसे हैं।

टाप्स योजना : शीर्ष खिलाड़ियों के लिए

टाप्स योजना के तहत ओलंपिक संभावित खिलाड़ियों को 50,000 रुपए प्रतिमाह का आउट-आफ-पाकेट भत्ता मिलता है। साथ में प्रशिक्षण, पोषण, फिजियोथेरेपी और उपकरण सब मुफ्त। यह व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसका लाभ उठाने वाले खिलाड़ी देश में शायद दो-तीन सौ ही हैं। बाकी सब अपने हाल पर।

राज्यों की तुलना...कहां कितना?

यहीं से असली विरोधाभास शुरू होता है। गुजरात का सालाना खेल बजट अब 484 करोड़ रुपए है। साल 2002 में यह सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए था। खेल महाकुंभ 2025 में 71.30 लाख प्रतिभागी थे और 45 करोड़ का पुरस्कार पूल था। अवसंरचना शानदार है। अहमदाबाद साल 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, लेकिन गुजरात में एक भी एसएआई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है जो 10-18 साल के खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर तैयार करे। हरियाणा के 912 एसएआई समर्थित खिलाड़ियों के मुकाबले गुजरात के पास सिर्फ 261 हैं। यानी दिखावा बड़ा, नींव खोखली।

महाराष्ट्र ने लक्ष्यवेध योजना के तहत 160 करोड़ रुपए के बजट से 12 खेलों में 3,740 खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के पास पुणे के बालेवाड़ी जैसी सुविधाएं हैं, और महाराष्ट्र के 708 एसएआई-समर्थित खिलाड़ी हैं। यह बेहतर है, लेकिन खिलाड़ियों तक पोषण भत्ता पहुंचने में देरी एक पुरानी समस्या है।

तमिलनाडु की कहानी सबसे दिलचस्प और दर्दनाक है। खेलो इंडिया के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को क्रमशः 608 और 503 करोड़ रुपए मिले, जबकि तमिलनाडु को सिर्फ 33 करोड़ रुपए। हरियाणा ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 39 खिलाड़ी भेजे, तमिलनाडु ने 17। लेकिन हरियाणा को 88 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 33 करोड़ रुपए मिले। प्रदर्शन और आबंटन का यह असंतुलन बताता है कि खेल पोषण की नीति कहीं न कहीं खेल क्षेत्र के बाहर तय होती है।

कर्नाटक में 154 एसएआई समर्थित खिलाड़ी हैं ...तमिलनाडु के 194 से थोड़े कम। दोनों राज्यों में क्रिकेट के अलावा एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती में अच्छी प्रतिभा है, लेकिन नीतिगत समर्थन उस स्तर का नहीं।

देश की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। अमेरिका में ओलंपिक खिलाड़ियों को हर महीने ढाई से चार लाख रुपए का पोषण भत्ता मिलता है। जापान में यह रकम अस्सी हजार से डेढ़ लाख रुपए के बीच है। चीन में तो पूरा खर्च- खाना, रहना, प्रशिक्षण- सब सरकार उठाती है। भारत में राष्ट्रीय शिविर के वरिष्ठ खिलाड़ी को एक हजार रुपए प्रतिदिन यानी करीब तीस हजार रुपए महीना मिलता है।यह ठीक-ठाक है। लेकिन हरियाणा की स्पोर्ट्स नर्सरी का युवा एथलीट महीने में सिर्फ 1500 से 2000 रुपए पर खेल रहा है। यानी रोज के छियासठ रुपये। यह खाई ही भारत के खेल पोषण की असली तस्वीर है।

नीति सही दिशा में, पर रफ्तार चाहिए

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में खेल विज्ञान, पोषण और तकनीक को प्रशिक्षण का अहम हिस्सा बनाने का वादा है। खेलो इंडिया योजना के तहत चुने गए 2,845 खिलाड़ियों को आठ साल तक सालाना पांच लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें प्रशिक्षण, उपकरण और पोषण शामिल हैं।

दिशा सही है। बजट बढ़ रहा है, लेकिन जब तक हरियाणा की खेल नर्सरी के बच्चे 66 रुपये रोज पर खेल रहे हैं, और गुजरात जैसे अमीर राज्यों में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं, तब तक पदक की उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई पटेगी नहीं।

कोना

ह्यूस्टन : गेंद को बास्केट में डालने की कोशिश करते न्यूयार्क निक के कार्ल एंथनी टाउंस और उन्हें रोकते ह्यूस्टन राकेट के केविन दुरंत।

भारत बनाम विश्व

140 करोड़ की आबादी

सिर्फ 10 ओलंपिक स्वर्ण, 58 साल से शीतकालीन पदक शून्य।भारत ने अपने पूरे ओलंपिक इतिहास में सिर्फ 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। केन्या, युगांडा और इथियोपिया — इन तीनों की आबादी मिलकर भी भारत के एक राज्य जितनी नहीं । इनमें से हर देश ने भारत से ज्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं। शीतकालीन ओलंपिक में भारत 1964 से हिस्सा ले रहा है। 62 साल में एक भी पदक नहीं। मिलानो-कोर्टिना 2026 में भारत के सिर्फ दो एथलीट थे।

खटपट

पीएसएल में गेंद से छेड़छाड

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लाहौर बनाम कराची किंग्स मैच में आखिरी ओवर से पहले शाहीन अफरीदी, फखर जमान और हैरिस रऊफ को कैमरे पर गेंद के साथ छेड़छाड़ करते देखा गया। अंपायरों ने तुरंत गेंद बदली और कराची किंग्स को पांच पेनल्टी रन दिए-जिससे लक्ष्य 14 से घटकर 9 रह गया, और किंग्स जीत गया। फखर जमान पर लेवल तीन का आरोप लगा है। कप्तान शाहीन अफरीदी बोले - मुझे नहीं पता, कैमरा देखेंगे। कैमरा सब देख चुका था!

चटपट

वुड्स-मैदान से जेल तक, फिर मैदान की तरफ?

गोल्फ के महानतम खिलाड़ी टाइगर वुड्स 27 मार्च को फ्लोरिडा में कार दुर्घटना के बाद नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। श्वसन संबंधी परीक्षण में शराब का कोई अंश नहीं मिला — लेकिन यूरिन टेस्ट से उन्होंने मना कर दिया। पुलिस को दवाइयों के असर का संदेह है। वुड्स की प्रेमिका वेनेसा ट्रंप और उनकी बेटी कार दुर्घटना से तीन दिन पहले उन्हें गोल्फ खेलते देखने आई थीं। 50 साल के वुड्स के लिए यह चौथी बड़ी कार दुर्घटना है-अब मास्टर्स में खेलने पर सवाल।

कैलेंडर (3 से 17 अप्रैल)

क्रिकेट आइपीएल

3 अप्रैल- चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स

4 अप्रैल- दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस

-गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रायल्स

5 अप्रैल- सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

-रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

6 अप्रैल- कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स

7 अप्रैल- राजस्थान रायल्स बनाम मुंबई इंडियंस

8 अप्रैल- दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात

9 अप्रैल-कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

10 अप्रैल- राजस्थान रायल्स बनाम रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु

11 अप्रैल- पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

-चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

12 अप्रैल- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस-

- मुंबई इंडियंस बनाम रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु

13 अप्रैल- सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रायल्स

14 अप्रैल- चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

15 अप्रैल- रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स।

बीता पखवाड़ा (18 मार्च से 1 अप्रैल)

क्रिकेट आइपीएल

28 मार्च : रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हराया।

29 मार्च : मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को छह विकेट से हराया।

30 मार्च : राजस्थान रायल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को आठ विकेट से हराया।

31 मार्च : पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया।

महिला क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका का न्यूजीलैंड दौरा

पांच मैचों की टी20 श्रृंखला

न्यूजीलैंड ने पहले तीसरे, चौथे और पांचवें मैच में जीत दर्ज कर शृंखला जीती।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच जीत दर्ज की।

तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला

पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को दो विकेट से हराया

दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हराया।

टेनिस

मियामी ओपन (15 से 29 मार्च)

यानिक सिनर पुरुष एकल का खिताब जीता।

एरिना सबालेंका महिला एकल का खिताब अपने नाम किया।

टेनिस

दोहरी उपलब्धि : यानिक सिनर की बादशाहत का नया अध्याय

जनसत्ता खेल

इंडियन वेल्स और मियामी....। दोनों एक ही बार में, बिना एक भी सेट गंवाए। नौ साल में पहली बार किसी पुरुष खिलाड़ी ने यह कारनामा किया। यानिक सिनर का खेल उन्हें आज के टेनिस में सबसे अलग क्यों बनाता है?

मियामी के हार्ड राक स्टेडियम में 29 मार्च की शाम जब सिनर ने जिरी लेहेचका को 6-4, 6-4 से हराया, तो इतिहास के कई पन्ने एक साथ पलटे। वे पहले पुरुष खिलाड़ी बने जिन्होंने इंडियन वेल्स और मियामी दोनों एक ही सीजन में बिना एक भी सेट गंवाए जीते। यह सनशाइन डबल-फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया के दो बड़े हार्ड कोर्ट खिताब एक साथ। यह गौरव नौ साल पहले 2017 में रोजर फेडरर ने पूरा पाया था।

यानिक सिनर

लेकिन सिर्फ खिताब की बात नहीं है। सवाल यह है कि सिनर के खेल में ऐसा क्या है जो उन्हें इस दौर के सबसे जबरदस्त खिलाड़ी बनाता है?

पहली बात- सर्विस पर मजबूत पकड़। मियामी फाइनल के पहले सेट में सिनर ने अपनी पहली सर्विस के सभी 16 अंक जीते। एक भी नहीं गंवाया। पूरे मैच में उनकी पहली सर्विस पर जीत का फीसद 92 रहा और उन्होंने सामने आए तीनों ब्रेक पाइंट बचाए। जब सर्विस इतनी पक्की हो, तो प्रतिद्वंद्वी के लिए मैच में वापस आना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी बात- फोरहैंड का दबदबा। सिनर का फोरहैंड आज के टेनिस में सबसे तेज और सटीक माना जाता है। फाइनल में उन्होंने लेहेचका को उसके फोरहैंड की तरफ लगातार धकेला। इससे चेक खिलाड़ी को कंधे से ऊपर उठकर मारना पड़ा, जो उनकी कमजोरी है। यह सोची-समझी रणनीति थी, प्रतिभा नहीं — और यही अंतर महान खिलाड़ी को और भी महान बनाता है।

तीसरी बात-मानसिक अटलता। मियामी में बारिश ने 90 मिनट की देरी की, फिर दूसरे सेट में 80 मिनट और। लंबा इंतजार, भारी नमी -लेकिन सिनर का खेल जरा भी नहीं बदला। जब जिरी ने 4-4 पर एक गेम में तीन ब्रेक पाइंट बचाए, तो लगा खेल पलटेगा। लेकिन सिनर ने अगले ही गेम में ब्रेक किया और सेट को समाप्त कर दिया।

चौथी बात- रिकार्ड जो बताता है सब कुछ। सिनर ने मास्टर्स 1000 स्तर पर लगातार 34 सेट जीते हैं। यह रिकार्ड उन्होंने खुद ही बनाया, जोकोविच और अल्कराज के पिछले रिकार्ड 20-20 के सेट थे। 17 लगातार मास्टर्स मैच, 12 लगातार मियामी जीत। 24 साल की उम्र में वे ओपन युग के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने सभी बड़े हार्ड कोर्ट खिताब जीते हैं। दोनों ग्रैंड स्लैम, सभी छह मास्टर्स 1000 और एटीपी फाइनल्स जीते हैं।

इस सीजन में सिनर का रिकार्ड 19-2 है। दो हार... एक आस्ट्रेलियाई ओपन सेमीफाइनल में जोकोविच से। नंबर एक अल्कराज से अभी 1190 अंक पीछे हैं- लेकिन क्ले सीजन शुरू होने वाला है और यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है।

कोर्फबाल

दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाता अनूठा खेल

हिमांशु अग्निहोत्री

खेल की दुनिया में जहां अधिकांश खेल पुरुष और महिला वर्गों में बंटे होते हैं, वहीं 'कोर्फबाल' एक ऐसी अनूठी मिसाल पेश करता है, जहां महिला और पुरुष एक ही टीम में कंधे से कंधा मिलाकर खेलते हैं। नीदरलैंड से शुरू हुआ यह खेल आज दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना रहा है। 'कोर्फबाल' केवल शारीरिक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह सामरिक कौशल, सटीकता और सहयोग का खेल है। बास्केटबाल और नेटबाल से मिलता-जुलता यह खेल संपूर्ण लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो इसे आधुनिक युग का एक आदर्श खेल बनाता है। ओलंपिक 1920 और 1928 में प्रदर्शनी के तौर पर शामिल किया गया यह खेल आज70 से अधिक देशों में खेला जा रहा है। यूरोपीय देशों, विशेषकर नीदरलैंड और बेल्जियम का इस खेल पर दशकों से दबदबा रहा है।

कोर्फबाल एक गेंद वाला खेल है, जो नेटबाल, बास्केटबाल और रिंगबाल से मिलता-जुलता है। इसमें खिलाड़ियों को 11.5 फुट ऊंचे खंभे पर लगे बिना नेट वाले बास्केट में गेंद फेंकना होता है। प्रत्येक टीम में चार महिला और चार पुरुष खिलाड़ी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोर्फबाल का संचालन अंतरराष्ट्रीय कोर्फबाल महासंघ (आइकेएफ) द्वारा किया जाता है। विश्व कोर्फबाल चैंपियनशिप और आइकेएफ विश्व कप जैसे आयोजन इस खेल की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाते हैं। हालांकि यह फुटबाल या क्रिकेट जितना व्यावसायिक नहीं है, लेकिन इसकी सादगी और समावेशी प्रकृति के कारण स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। वर्ष 1981 के बाद से लगातार चार साल के अंतराल में विश्व खेल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, 1978 से लेकर चार साल के अंतराल में विश्व चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जा रहा है। आइकेएफ अंडर-23 का आयोजन 2008, 2012 और 2016 में किया गया, जिसमें नीदरलैंड शीर्ष पर रहा।

भारत में कोर्फबाल का सफर काफी उत्साहजनक रहा है। भारतीय कोर्फबाल महासंघ (केएफआइ) के प्रयासों से यह खेल भारत के लगभग सभी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। भारत की मिश्रित संस्कृति के लिए यह खेल एकदम सटीक है। स्कूलों और कालेजों में इसे शारीरिक शिक्षा के हिस्से के रूप में अपनाया जा रहा है। भारतीय टीम ने एशियाई कोर्फबाल चैंपियनशिप में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ी अपनी चपलता और तकनीक के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बुनियादी ढांचे की कमी और प्रायोजकों का अभाव भारत में खेल की गति को थोड़ा धीमा कर रहा है। मैदानी स्तर पर बढ़ते खिलाड़ियों की संख्या यह संकेत देती है कि भविष्य में भारत एशिया की शीर्ष तीन टीमों में अपनी जगह पक्की कर सकता है।

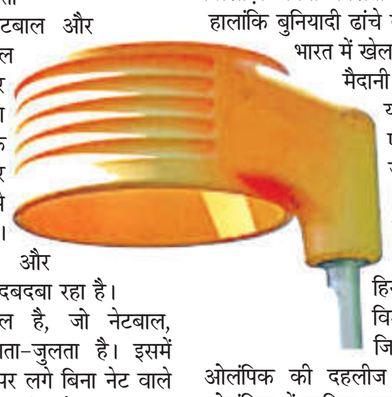

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्फबाल अभी तक मुख्य ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं बन पाया है, लेकिन यह विश्व खेल का मुख्य आकर्षण है, जिसमें वे खेल शामिल होते हैं, जो ओलंपिक की दहलीज पर हैं। आइकेएफ लगातार इसे ओलंपिक में शामिल कराने के प्रयास कर रहा है।

एशियाई स्तर पर कोर्फबाल एक मान्यता प्राप्त खेल है। एशियाई कोर्फबाल चैंपियनशिप का नियमित आयोजन होता है। इसे एशियाई खेलों के मुख्य पदक आयोजनों में शामिल करने की मांग लगातार उठती रही है। राष्ट्रमंडल देशों में कोर्फबाल की स्थिति अभी विकासशील है। वर्तमान में यह इन खेलों का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में इसकी बढ़ती सक्रियता भविष्य में इसके शामिल होने की संभावनाओं को प्रबल करती है।

खबर आईना

भारत की तरफ से खेलने का सपना देख रहा था : विलियम्स

अपने पदार्पण मैच में गोल करने के बाद बेहद उत्साहित आस्ट्रेलिया में जन्में भारतीय स्ट्राइकर रयान विलियम्स ने कहा कि भारत की तरफ से खेलना उनका सपना था और उन्होंने मैच से पहले उस पल (गोल करने) को अपने दिमाग में इतनी बार दोहराया था कि जब वह वास्तव में हुआ, तो उन्हें थोड़ा धुंधला सा महसूस हुआ। विलियम्स ने भारत के लिए अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मंगलवार को यहां चौथे मिनट में ही गोल करके भारत को एशियाई कप क्वालीफाइंग राउंड के मैच में हांगकांग पर 2-1 से जीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विलियम्स ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा, 'मैं लंबे समय से इसका सपना देख रहा था और इसे साकार करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि फुटबाल के गढ़ रहे केरल में खेलते हुए आप पांच मिनट के अंदर गोल करके जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। अचानक सब कुछ धुंधला सा हो गया। मुझे लगता है कि मैं फिसल गया और फिर मैंने दौड़ लगाई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। क्योंकि मैंने मन ही मन उस गोल को करने का कई बार करने का सपना देखा था और फिर जब वह हुआ तो यह बहुत खास था। तब मैं भावनाओं से भर गया था।'

फुटबाल

कौन लेगा मेसी-रोनाल्डो की जगह

जनसत्ता खेल

एक 38 का, एक 40 का। दोनों जून में विश्व कप खेलेंगे। लेकिन उनके जाने के बाद फुटबाल का चेहरा कौन होगा? और क्या कोई उनकी जगह सच में ले सकता है?

फुटबाल इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दौर आया हो जब दो खिलाड़ियों ने मिलकर डेढ़ दशक तक खेल की पूरी बहस अपने इर्द-गिर्द केंद्रित कर ली हो। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच 12 बैलन डी'ओर बंटे हैं- नौ मेसी के, पांच रोनाल्डो के। लेकिन अब वे युग अपने अंतिम पड़ाव पर है।

कितना बचा है?

38 साल के मेसी जून में अर्जेंटीना के साथ विश्व कप में उतरेंगे और टूर्नामेंट के दौरान 39 के हो जाएंगे। उन्होंने खुद कहा है — मैं जानता हूं कि अपने आखिरी मैच खेल रहा हूं और हर पल का आनंद ले रहा हूं। इंटर मियामी उनका आखिरी क्लब होगा। यह उन्होंने साफ कहा है। विश्व कप 2026 लगभग तय है कि यह उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा।रोनाल्डो 40 साल के हैं और पुर्तगाल के साथ विश्व कप में होंगे। यह उनकी छठी और संभवतः आखिरी विश्व कप भागीदारी होगी। उनके एजंट मेंडेस का कहना है कि अगर पुर्तगाल विश्व कप जीत जाए तो रोनाल्डो रुक सकते हैं, नहीं तो 1000 गोल के लिए खेलते रहेंगे। अभी वे 900 के पार हैं।

विरासत का बोझ

इस विश्व कप में अर्जेंटीना शीर्ष दावेदारों में है — स्पेन और फ्रांस के साथ। पुर्तगाल शीर्ष पांच में भी नहीं। यानी मेसी के पास दूसरे विश्व कप का असली मौका है, जबकि रोनाल्डो के लिए यह ख्वाब शायद अधूरा रहे।

अगला चेहरा कौन?

फुटबाल की नई जोड़ी के रूप में बार्सिलोना के लामिने यमाल और पीएसजी के देजिरे दुए को देखा जा रहा है। यमाल महज 17 साल के हैं। इस सीजन वे दुनिया के शीर्ष तीन खिलाड़ियों में माने जा रहे हैं। बार्सिलोना के लिए किसी भी अटैकर से ज्यादा वक्त तक खेले हैं। दुए ने पीएसजी को पहला चैम्पियंस लीग खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा एर्लिंग हालैंड नार्वे के लिए, विनिशियस जूनियर ब्राजील के लिए और जूड बेलिंघम इंग्लैंड के लिए बड़े नाम हैं। लेकिन सच यह है- मेसी और रोनाल्डो की जगह कोई एक नहीं लेगा।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

धोरणात्मक धरसोडीमुळेच अवमूल्यन

'नियामकाचे निसरडेपण' हे संपादकीय (१ एप्रिल) वाचले. जागतिक बाजारपेठेवर आखाती युद्धामुळे आर्थिक अरिष्ट ओढवले असताना, चीनच्या युआनचे मूल्य वाढत आहे आणि त्याच वेळी भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. ५.९४ टक्के एवढी प्रचंड मोठी घसरण एका वर्षात होते तेव्हा, आर्थिक धोरणातील विसंगती, दुर्लक्षून चालणारी नसते. देशाच्या डोक्यावरील भरपूर कर्ज आणि आयात निर्यात धोरणातील अनियमितता, याबद्दल धोरणात्मक नियोजनाचा अभाव असल्याने, अर्थव्यवस्था भलेही वरवर सुरक्षित वाटत असली, तरी तो एक भ्रम असल्याने, त्यातील धोक्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

रुपयाच्या घसरणीमागे युद्ध हे एकमेव कारण नाही. निर्यातीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले असते तर परकीय चलन देशात आले असते, पण राजकीय उलथापालथ करून, एकेक राज्य काबीज करण्यातून आणि विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यातून सत्ताधाऱ्यांना अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देण्याएवढा वेळच मिळाला नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात, रुपया थोडा जरी खाली आला तर रान उठवून आगपाखड करणारी राजकीय मंडळीच आज सत्तेत आहेत आणि एकाच दिवसात १७० पैशांची प्रचंड मोठी घसरण होऊनही, सारे काही आलबेल असल्याचा देखावा करत आहेत. विश्वगुरूपदाच्या वल्गना करून देश मोठा होत नसतो याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. आर्थिक सुदृढता आणि निकोप विकास होतो तेव्हाच देशाचा चेहरा बदलतो. महागाई वाढते आहे. कायमस्वरूपी नियोजन आणि उपाययोजना केल्यास आणि धरसोडीच्या आयात-निर्यात धोरणाला लगाम लावल्यास सुदृढ आर्थिक व्यवस्थेला चालना मिळेल.

■ **डॉ. नूतनकुमार पाटणी,** चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

धोरणांतील अस्पष्टतेचा परिणाम

'नियामकाचे निसरडेपणा' हा अग्रलेख वाचला. जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी जबाबदार जागतिक घटक- भारत मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो, तेल महाग झाले की जास्त डॉलर मोजावे लागतात, परिणामी डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया घसरतो. सध्या जगात युद्धजन्य आणि भू-राजकीय तणाव आहे. त्यामुळे तेल, गॅस महाग झाले आहेत. जागतिक बाजार अस्थिर झाला आहे. याचा परिणाम रुपयावरही झाला. जबाबदार देशांतर्गत घटक- भारतात तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मोठ्या प्रमाणात आयात केल्या जातात, पण निर्यात त्यापेक्षा कमी असते त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आहे आणि रुपया कमकुवत होतो आहे. सध्या देशांतर्गत महागाई वाढली आहे. त्यामुळे वस्तू महाग झाल्या, त्यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मक राहिलेली नाही. सरकारचा खर्च प्रचंड वाढला आहे आणि उत्पन्न कमी झाले आहे, कर्ज वाढत आहे. परकीय गुंतवणूकदार भारतातील गुंतवणूक काढून घेत आहेत. आर्थिक धोरणांत स्पष्टता नाही आणि अंमलबजावणीही नीट होत नाही. रिझर्व्ह बँक स्वतःच्या बळावर फार काही करू शकणार नाही.

■ **मयूरी मुलमुले,** नाशिक

मुंबईतील जगणे सुसह्य व्हावे

'मुंबईला हवा आहे यंत्रणांचा समन्वय' हा 'अन्वयार्थ' (१ एप्रिल) वाचला. दीडशे वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्त होणाऱ्या अश्विनी भिडे या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या. भिडे यांच्या काळात तरी शहरात केवळ टोलेजंगी इमारतींना आणि त्यांच्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य न देता संपूर्ण शहर जगण्यास सुसह्य कसे होईल, स्वच्छ-सुंदर कसे दिसेल, यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील जुन्या चाळी व जुन्या इमारतींची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी केली जावी. रस्ते, पाणी, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन याकडे त्यांनी जास्त लक्ष द्यावे. मुंबई शहरात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास मंडळ, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई पोर्ट अशा १५ हून अधिक यंत्रणा कार्यरत आहेत. या यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय राहात नसल्याने अनेकदा गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न टाळण्यासाठी अश्विनी भिडे यांनी प्रयत्न करावेत.

■ **उज्ज्वला मालाडकर,** बाणेर (पुणे)

स्वप्ने दाखवण्यात सरकारचा हातखंडा

'मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधेयक २०२६' संदर्भातील 'प्रशासकीय सुधारणांची नांदी' आणि 'सुधारणा की केवळ कागदी घोडे?' हे दोन्ही लेख वाचले. मोठमोठा गाजावाजा करून एखादी योजना, प्रकल्प, विधेयक जनतेसमोर मांडणे आणि जनतेला मधुर स्वप्नांत अडकवून ठेवणे हा भाजपच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे. जनधन, नोटाबंदी, मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन, उज्ज्वला योजना, यूएपीए, लाडकी बहीण योजना वा पारलिंगींसंदर्भातील विधेयक या साऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजना, धोरणांचे पुढे काय झाले, हे जनता जाणतेच. 'मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधेयक' त्यापेक्षा वेगळे असेल असे वाटत नाही. सुरुवातीच्या काळात ३००-४०० रुपयांना मिळणारा गॅस सिलिंडर युद्धाच्या आधीच ९००पर्यंत पोहोचला होता. यावरून या सरकारच्या कारभाराचा अंदाज येऊ शकतो. प्रभावी अंमलबजावणी आणि निष्पक्ष मूल्यमापन केल्याशिवाय कोणतीही योजना वा धोरण यशस्वी होऊ शकत नाही. असे काही होणे भाजप सरकारच्या काळात कठीणच.

■ **आभिलाष मादळे**

'कर्तव्यदक्ष' गृह मंत्रालय!

'अमिताभ गुप्ता, जालिंदर सुपेकर निर्दोष' ही बातमी (लोकसत्ता- १ एप्रिल) वाचली. यानिमित्ताने आपले गृह मंत्रालय किती 'सक्षम' आहे आणि राज्यात कायद्याचे राज्य किती 'उत्तम' रीतीने सुरू आहे, याची जाणीव झाली. हाच निर्णय घ्यायचा होता तर चौकशीचे नाटक का केले? गेल्या दोन ते तीन वर्षांचा इतिहास पाहता धनंजय मुंडे निर्दोष, राठोड निर्दोष, भुजबळ निर्दोष, किरीट सोमय्या निर्दोष हेच जर चालणार असेल तर घटना, कायद्याचे राज्य कोणासाठी? उद्या अशोक खरात निर्दोष सुटला तरी त्याचे आश्चर्य वाटू नये, हे आता लोक समजून चालले आहेत. सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांवर पाणी कसे फिरवावे हे मात्र या सरकारला नीट माहीत आहे.

■ **किरण भिंगार्डे,** मीरा रोड

...या कायद्याची गरज आहेच!

साखर गाळप हंगामात अनेकदा मुकादम ऊस वाहतूक कंत्राटदारांकडून 'उचल' घेऊन ती ऊसतोड मजुरांना न देता पसार होतात. यातून ऊस वाहतूक कंत्राटदाराचे आर्थिक नुकसान होते! ही फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची बातमी (लोकसत्ता, १ एप्रिल) वाचली.

ऊस वाहतूक कंत्राटदार - वाहनमालक यांना साखर कारखाना ते प्रत्यक्ष ऊस क्षेत्रातील अंतरानुसार वाहतूक खर्च मिळतो आणि ऊसतोडणी मजूर पुरवणारा 'मुकादम' (स्थानिक भाषेत ऊस-टोळी) यांना प्रति टनामागे ऊसतोडणीसाठी विशिष्ट रक्कम साखर कारखान्यांकडून मिळत असते. ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक-मुकादम यांनी साखर कारखान्यांकडून घेतलेली उचल (अग्रिम रक्कम), त्यांची हमी/जामीन, ऊसतोडणी मुकादमांना आगाऊ रक्कम देऊन 'ऊसतोडणी मजुरांची बांधणी' हा सगळा एक 'व्यवसाय' आहे. तशीच ही एकमेकांना आतून जोडलेली 'आर्थिक साखळी' आहे.

या सगळ्याचा अंतिम 'हिशेब' संबंधित साखर कारखान्याचा ऊस गाळप हंगाम संपल्यानंतर ऊस वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक- मुकादम करतात. यांचा संबंधित साखर कारखान्याशी लिखित करार असतो. ऊसतोडणी हे कष्टाचे काम असले तरी त्याचा वाजवी मोबदला ऊसतोडणी मजुरांना मिळत असतो. ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार- वाहनमालक- मुकादम बहुतांशी सगळे हे शेतकरी वर्गातीलच असतात. अपवाद ऊसतोडणी मजुरांचा असू शकतो. ते शेतकरी असतीलच असे नाही.

'मुकादमा'ने विश्वासघात केला नाही, थोडक्यात ऊसतोडणीसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही वेळेवर ऊस वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक यांना ऊसतोडणी मजुरांचा पुरवठा केला नाही (ऊसतोडणी टोळी बांधली नाही) किंवा मध्येच 'ऊस-टोळी' निघून गेली तर मात्र ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक यांचे आर्थिक नुकसान होते. अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडतेसुद्धा! त्यामुळे यासंदर्भात संबंधित 'मुकादम''वर योग्य कारवाई करण्यासाठी अशा कायद्याची गरज होती.

■ **पद्माकर कांबळे,** मुंबई

गांधींची शिक्षणनीती हद्दपार

सरकार व गांधीवाद्यांमधील वैचारिक वादाचा फटका नेहमीच गांधीविचारांच्या शाळांना बसत आला आहे. गांधींची शिक्षणनीती आजच्या काळात जशीच्या तशी लागू करणे शक्य नसले, तरी त्यातल्या चांगल्या गोष्टी कायम ठेवता आल्या असत्या. मात्र तसा विचार सरकारदरबारी कुणी करत नाही...

देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande
@expressindia.com

गांधीमार्गाचे वर्तमान

ही १९३७ची गोष्ट. तेव्हा सेवाग्राम आश्रम देशभरात सुरू असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याचे केंद्र होते. देशाला स्वातंत्र्य तर मिळेल पण पुढे काय? शिक्षण, रोजगार यावर चर्चा सुरू झाली ती या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नातून. यातून एक विचार समोर आला तो म्हणजे शिक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय परिषद भरवण्याचा. याच्या आयोजनाची जबाबदारी दिली गेली आर्यनायकम यांच्याकडे. ते मूळचे श्रीलंकेचे. रवींद्रनाथ टागोरांच्या विचाराने प्रेरित होऊन भारतात आले व शांतिनिकेतनमध्ये गुरुकुल पद्धतीचा अभ्यास करू लागले. इथेच त्यांचा विवाह झाला- आशादेवींशी. त्या बनारसच्या उच्चशिक्षित. या दोघांच्या पुढाकाराने आयोजित या परिषदेत मुख्य आकर्षण होते महात्मा गांधींचे भाषण. त्यांनी याच व्यासपीठावरून पहिली राष्ट्रीय शिक्षणनीती मांडली. ते म्हणाले, 'मी आतापर्यंत देशाला जे काही दिले त्यातले हे सर्वोत्तम.' अनुभवाधारित शिक्षण असे या नीतीचे सूत्र. ती राबवण्यासाठी हिंदुस्थानी तालिमी संघ तयार करण्यात आला व देशभरात शेकडो शाळा सुरू होऊ लागल्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या शाळांची संख्या ५० हजारांपर्यंत गेली. स्वातंत्र्यानंतर सरकारी बाबूंचा अंमल असलेली अनेक धोरणे जाहीर झाली. त्यात शिक्षणाचाही समावेश होता, पण त्यात गांधींची नीती स्वीकारली गेली नाही. या धोरणानुसार जी शिक्षण पद्धती अमलात आली त्यातूनही या 'हिंदुस्थानी तालीम'ला बेदखल करण्यात आले. यातून शिक्षण घ्यायचे असेल तर घ्या, पण तालीमला समकक्षचा दर्जा मिळणार नाही. हे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रचलित पद्धतीत येण्यासाठी समकक्ष अशी परीक्षा द्यावीच लागेल, अशी सरकारची भूमिका होती.

नंतर स्थापन झालेल्या कोठारी आयोगानेसुद्धा गांधींच्या या नीतीचे कौतुक केले. १४व्या वर्षापर्यंत विद्यार्थ्यांनी हे शिक्षण घ्यावे व मग प्रचलित शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा असे आयोगाचे म्हणणे. गांधींच्या पद्धतीत आधुनिक तंत्रज्ञान नाही असेही या आयोगाचे मत. ते काही अंशी खरेही होते. दुसरीकडे कष्टाची सवय व सोबत शिक्षण हाच तरुणांच्या यशाचा राजमार्ग आहे असे गांधीवाद्यांचे म्हणणे. त्यासाठी 'पूर्व बुनियादी' ते 'उत्तम बुनियादी' हाच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा पाया असावा असा त्यांचा दावा. सरकार व गांधीवाद्यांमधील या वैचारिक वादाचा फटका बसला तो या शाळांना. त्या हळूहळू कमी होत गेल्या. यातून काही तरी मार्ग निघायला हवा म्हणून १९७२ ला सर्व गांधीवादी संस्थांनी एकत्र येत हिंदुस्थानी हा शब्द त्यागून नई तालीम समिती तयार केली. त्याची नोंदणी केली व सुरू आहे त्या शाळा एका कक्षेत आणल्या. देशात तेव्हा सहाच शाळा उरल्या होत्या. त्यातली मध्यप्रांतातील शाळा सेवाग्रामला. मग विनोबांची भूदान चळवळ सुरू झाली. शिक्षक व विद्यार्थी सारेच त्यात सामील झाले व या शाळा ओस पडल्या. याच काळात तेव्हाच्या गुजरातने मात्र नई तालीमचा विचार उचलून धरला. सरकारी मान्यतेने ३०० शाळा सुरू करण्यात आल्या. नंतर यात सरकारी हस्तक्षेप इतका वाढला की आज या शाळा अस्तित्वात असल्या तरी त्यातून गांधींची शिक्षणनीती पूर्णपणे हद्दपार झाली आहे. या शाळेत नेमण्यात येणारे शिक्षक गांधी विचाराचे हवे याकडेही सरकारने लक्ष दिले नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना या नीतीची पुन्हा एकदा भुरळ पडली. त्यासाठी पुढाकार घेत त्यांनी पाटण्याला एक मोठी परिषद भरवली. यात शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेले अनेक गांधीवादी सहभागी झाले. अनेक गोष्टींवर ऊहापोह झाला. पण पुढे काहीच झाले नाही.

भूदान चळवळीपासून सेवाग्रामची शाळा बंद पडली होती. अशा स्थितीत ही शाळा पुन्हा सुरू करण्याचे धाडस दाखवले ते सुषमा शर्मा यांनी. गोवामुक्ती लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिक श्रीधरराव पद्मावार यांच्या त्या कन्या. २००५ ला त्यांनी स्वयंअर्थसहायित शाळा सुरू करायची म्हणून नोंदणीसाठी सरकारकडे अर्ज केला. बरीच धावपळ, आंदोलनाचे इशारे दिल्यावर तो मंजूर झाला. सेवाग्रामच्या नई तालीमला आता २१ वर्षे पूर्ण झाली. त्यात दरवर्षी साधारण तीनशे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. काळानुरूप बदल हवा म्हणून शर्मांनी सेमी इंग्लिश अभ्यासक्रम तयार केला आहे. सेवाग्रामला भेट देणारा प्रत्येक जण हटकून या शाळेला भेट देतोच. कृष्णकुमार एनसीईआरटीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी ही शाळा बघितली. शाळेतील उपक्रम बघून त्यांच्यासोबतचे सारेच भारावले. मग एनसीईआरटीने या शाळेला वारसा शाळा असा दर्जा

दिला. यात शाळा विकासासाठी थेट निधी देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे साडेतीन लाख रुपये शाळेला मिळाले. २१ वर्षांत शाळेला सरकारकडून झालेली ही एकमेव मदत. आताही या शाळेला अनेक सरकारी अधिकारी भेट देतात. कौतुक करतात व निघून जातात. नई तालीम हे नाव असलेली ही देशभरातील एकमेव शाळा.

गांधींचाच विचार पण त्याला आधुनिकतेची जोड देत देशभरात अनेक शाळा सुरू आहेत. वसंत पळशीकर व विद्या पटवर्धन यांनी पुण्यात सुरू केलेली अक्षरनंदन, नाशिकची आनंदनिकेतन, अमरावतीची शाश्वत, श्रमिक सहयोग, सृजनानंद विद्यालय व कस्तुरबांच्या नावाने सुरू असलेल्या काही शाळा. बोटावर मोजण्याएवढ्या. बाकी सर्व आधुनिक शिक्षण पद्धतीच्या नादी लागलेले. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या शिक्षण पद्धतीत गांधींच्याच नीतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसा त्रोटक उल्लेख या नीतीत आहे, पण सरकारचा उद्देश कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचा. गांधींच्या नीतीचा उद्देश होता तो अनुभवाधारित शिक्षणातून व्यवस्था परिवर्तनाचा. सेवाग्रामच्या नई तालीमचे विद्यार्थी आजही शेतकरी आंदोलनात जातात. रस्त्यावर दुभाजक हवे म्हणून आंदोलन करतात. समाजात काय चालले यावर दर महिन्याला चिंतन सभा घेतात. सरकारच्या शाळेत यातले काहीही होत नाही. असे कुणी केले तर त्याला राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा काळ आता आलेला.

गांधींची शिक्षणनीती आजच्या काळात जशीच्या तशी लागू करणे शक्य नाही, पण त्यातल्या चांगल्या गोष्टी आजही कायम ठेवता आल्या असत्या. मात्र, तसा विचार सरकारदरबारी कुणी करत नाही. गांधी आता नाव घेण्यापुरते उरले. हे झाले सरकारच्या बाबतीत. गांधीविचार जोपासणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्येसुद्धा हा विचार आता हळूहळू लोप पावत चालला ही आणखी चिंतेची बाब. गांधीविचार दीर्घकाळ टिकवायचा असेल तर शिक्षण व कृतिशीलता ही दोनच प्रभावी माध्यमे आहेत. यासाठी या विचारांच्या संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे, पण तेही होताना दिसत नाही.

गांधींना सेवाग्रामला येण्याचे निमंत्रण देणारे जमनालाल बजाज प्रख्यात उद्योगपती. वर्धा ही त्यांची तेव्हाची कर्मभूमी. त्यांनी शिक्षण संस्था स्थापन केली. या माध्यमातून अनेक शाळा व महाविद्यालये आजही संचालित केली जातात. या संस्थेचे सचिव होते श्रीमननारायण अग्रवाल. ते बजाजांचे जावई. नंतर नेपाळचे राजदूत झाले. त्यांनी आश्रम व शिक्षण संस्थेला एका धाग्यात जोडले. गांधी जयंती व पुण्यतिथीच्या दिवशी सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी आश्रमात जायचे हा त्यांनी घातलेला पायंडा. आता तो मोडला आहे. कुणीही आश्रमात येत नाही. त्यामुळे या शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना खरे गांधी कळतच नाहीत. या शिक्षण संस्थेत आधी गांधीविचारांशी संबंधित अनेक उपक्रम होत. चर्चासत्रे, व्याख्याने आदी. आता ते सारे बंद झालेले. राहुल बजाज असेपर्यंत ते अशा उपक्रमांबाबत आग्रही असत. ते गेले आणि कर्त्याधर्त्यांनी पाठ फिरवली.

सेवाग्राम आश्रमात अनेक कार्यक्रम होतात. त्यालाही या शिक्षण संकुलातील कुणी हजेरी लावत नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणापेक्षा हा गांधीवाद्यांच्या वर्तुळातला दुरावा अधिक वेदना देणारा. अनेक जण तसे बोलून दाखवतात पण वाद घालण्याच्या मनःस्थितीत कुणी नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे एकूणच गांधींच्या बाबतीत अतिशय वेगाने प्रतिकूल होत जाणारे वातावरण. गांधींनी जपलेल्या मूल्याचा वारसा सांभाळण्याची जबाबदारी या वर्तुळात वावरणाऱ्या साऱ्यांची. त्यापासूनच प्रत्येक जण पळ काढू लागलेला. कुणाला काही म्हटले व वाद उद्भवून त्याने सार्वजनिक स्वरूप घेतले तर या संस्था ताब्यात घेण्यासाठी सारे टपून बसलेलेच. त्यामुळे तोंड उघडण्याची सुद्धा सोय नाही. कधी तरी हे वातावरण बदलेल, गांधीविचाराला चांगले दिवस येतील याच आशेवर सारे दिवस काढत असलेले.

कुतूहल

स्टेनलेस स्टील गंजत का नाही?

स्वयंपाकघरातील स्टेनलेस स्टीलची भांडी म्हणजे दैनंदिन जीवनातील एक अविभाज्य घटक! याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे स्टेनलेस स्टील गंजत नाही. खरं तर हे स्टेनलेस स्टील लोखंडापासून तयार करतात आणि तरीही ते गंजत कसं नाही?

पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर सर्वसाधारण लोखंडाच्या वस्तूंवर लालसर थर जमा होतो. यालाच आपण लोखंड 'गंजलं' असं म्हणतो. पाणी किंवा दमट हवेमध्ये लोखंडाची हवेतल्या ऑक्सिजनबरोबर रासायनिक अभिक्रिया होते आणि लोखंडाचं ऑक्साइड हा नवीन पदार्थ तयार होतो, तोच हा गंज! असा गंज जर आपल्या पोटात प्रमाणाबाहेर गेला तर अपायकारक ठरू शकतो. शिवाय आपल्या शरीरावर असलेल्या एखाद्या उघड्या जखमेला गंज थोड्या प्रमाणात जरी चिकटला तरी आपल्याला 'टिटॅनस' म्हणजेच धनुर्वातासारखा भयंकर आजार होण्याची शक्यता असते.

म्हणून जर हवेतला ऑक्सिजन लोखंडापर्यंत पोहोचूच दिला नाही तर ते गंजणार नाही आणि त्यामुळे होणारी ही हानी टाळता येईल, या विचारातून एका नवीन पदार्थाचा जन्म झाला. लोखंड, कार्बन, क्रोमियम आणि निकेल एकत्र करून एक नवीन मिश्रधातू तयार केला गेला. त्याचं नाव स्टेनलेस स्टील! लोखंड ६६ ते ७५ टक्के, क्रोमियम १८ ते २० टक्के, निकेल ८ ते १० टक्के व कार्बन ०.०३ ते ०.०७ टक्का असं यातल्या घटक धातूंचं प्रमाण असतं. स्टेनलेस स्टीलचा वापर कशासाठी करायचा यानुसार हे प्रमाण कमी-जास्त होऊ शकतं. याशिवाय आवश्यकतेनुसार इतर धातूही मिसळले जातात.

स्टेनलेस स्टीलच्या गंजरोधकतेत महत्त्वाची भूमिका असते क्रोमियमची. स्टेनलेस स्टीलमधल्या क्रोमियमबरोबर हवेतल्या ऑक्सिजनची रासायनिक अभिक्रिया होते. त्यातून 'क्रोमियम ऑक्साइड' हे एक निष्क्रिय रसायन तयार होतं. त्याचा थर वस्तूच्या पृष्ठभागावर चिकटून बसतो. तो हवेतल्या ऑक्सिजनला, स्टेनलेस स्टीलमधल्या लोखंडापर्यंत पोहोचू देत नाही. परिणामी ते गंजत नाही. हा थर अगदी सूक्ष्म जाडीचा म्हणजे काही नॅनोमीटरचा असल्यामुळे, नुसत्या डोळ्यांनी दिसत नाही. शिवाय काही कारणाने तो नाहीसा झाला, तरी रासायनिक अभिक्रियेमुळे तो पुन्हा आपोआप तयार होतो. त्यामुळे स्टेनलेस स्टीलमध्ये क्रोमियमचं प्रमाण जितकं जास्त, तितकं गंजण्यापासून संरक्षणही जास्त! अशा प्रकारे एका धातूचं अपायकारक ऑक्साइड तयार होऊ नये यासाठी दुसऱ्या धातूचं ऑक्साइडच कामी येतं!

पण यातही कार्बनचं प्रमाण जर ०.०७ पेक्षा वाढलं तर त्याची क्रोमियमबरोबर क्रिया होऊन क्रोमियम कार्बाइड तयार होतं आणि परिणामी क्रोमियम ऑक्साइडचा थर तयार करण्यासाठी क्रोमियम फारसं उपलब्ध होत नाही. अशा प्रकारची स्टेनलेस स्टीलची वस्तूही गंज पकडू शकते.

– शालिनी जोशी
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

आधी दिवा, आता घसा

*'**मॅडम, खाली** खूप गर्दी जमली आहे. नेहमीपेक्षा जरा जास्तच लोक दिसत आहेत. आज बैठकाही भरपूर, तेव्हा जनता दरबार लवकर आटपायला हवा' स्वीय साहाय्यकाचा हा निरोप ऐकून रितूताई धावत पळतच खाली निघाल्या. अल्पावधीत आपली लोकप्रियता वाढते हे चांगलेच लक्षण. आता लक्ष्य आमदारकी असा विचार करत त्या पहिल्या शिष्टमंडळाला सामोऱ्या गेल्या. 'ताईसाहेब आम्ही नाशिक जिल्ह्यातले नगरसेवक. खूप वर्षांनंतर पालिकेत दाखल झाल्यामुळे तिथे छाप पाडायची असेल तर आवाज हेच शस्त्र याची जाणीव आम्हाला नव्याने झाली. तुमची बातमी वाचनात आली. आम्हालाही आमचा घसा दुरुस्त करून घेण्यासाठी त्या जैनमुनींचे आशीर्वाद हवे आहेत. तेव्हा प्लीज त्यांचा पत्ता सांगा किंवा तुम्हाला त्यांनी जो आशीर्वाद दिला तो तरी आम्हाला द्या.' हे ऐकून ताई कमालीच्या आनंदल्या.*

'त्यांचा आशीर्वाद असा परस्पर स्थानांतरित करता येत नाही. तुम्हाला पत्ता देते. तिथे जाऊन या. वाहन नसेल तर तीही व्यवस्था करून देते.' शिष्टमंडळ जाताच त्या इतरांकडे वळल्या. अभ्यागतांच्या नागरी समस्या ऐकणे व अधिकाऱ्यांना फोनवर निर्देश देणे सुरू असतानाच महिलांचा एक गट समोर आला. 'गेल्या महिन्यापासून तक्रारी करून थकलो. गटारेच साफ होत नाहीत. तुम्हाला फोन केले, पण तुम्ही उचलत नाही. सांगा काय करायचे?' मी लक्ष देईन, असे ताईंनी सांगताच त्यातील एक महिला भडकली. 'अहो, ते घशाच्या साफसफाईचे तत्त्वज्ञान नंतर लोकांना सांगा, आधी नालेसफाईचे बघा.' हे ऐकताच त्यांचा पारा चढला. हे नक्कीच सेनेचे लोक असे म्हणत त्या दुसरीकडे वळल्या.

नंतर जे जे लोक भेटत गेले ते सारे घशाच्या तक्रारी घेऊन आलेले. त्या साऱ्यांना मुनींचा पत्ता सांगता सांगता ताईंच्या घशाला कोरड पडू लागली. मग लगेच त्यांनी साहाय्यकांना बोलावले व घशाची तक्रार असणाऱ्यांनी मुनींशी या पत्त्यावर संपर्क साधावा असा मोठा फलक तातडीने लावण्याचे निर्देश दिले. तरीही तीच समस्या घेऊन येणारे बरेच लोक उभे होतेच. किमान यानिमित्ताने तरी लोक नागरी समस्या विसरून जातील असा विचार मनात येताच त्यांना हायसे वाटले. भेटणाऱ्यांचे काही ऐकून घेण्याआधीच त्या फलकाकडे बोट दाखवू लागल्या. 'अहो, आमची घशाची तक्रार नाही, अतिक्रमणाची आहे' असे सांगणारे काही बिलंदर निघालेच. दरबार आटोपून त्या घरात गेल्या तेव्हा घशाला कोरड पडल्याची जाणीव त्यांना झाली. पाणी पिऊनही ती जाईना.

शेवटी डॉक्टरांना फोन केला. त्यांनी तो घेतला नाही. पुन्हा फोन लावायच्या आधीच त्यांचा संदेश आला. 'जैन मुनीकडे जा.' शेवटी थोडी खडीसाखर खाऊन त्या कार्यालयात गेल्या तर तिथे कान, नाक, घसा तज्ज्ञांचे मोठे शिष्टमंडळ बसलेले. 'मॅडम, तुम्ही शहराच्या प्रथम नागरिक आहात. तुम्हीच अशी वक्तव्ये केलीत, तर आमच्या प्रॅक्टिसचे काय?' यावर ताई भडकल्याच. 'तसेही आम्हाला ॲलोपॅथीचा रागच आहे. आयुर्वेद, चमत्कार हेच महत्त्वाचे. मी माझ्या वक्तव्यावर ठाम आहे. तुम्ही जाऊ शकता.' हे ऐकून संतापलेले डॉक्टर्स थेट देवाभाऊंकडे निघाले.

तितक्यात शिपायाने वर्दी दिली. खाली 'अंनिस'चे कार्यकर्ते आंदोलन करताहेत म्हणून. जशी कारवाई खरातवर केली तशी ताईंवर करा अशी त्यांची मागणी. हे ऐकून ताईंनी डोके गच्च धरले. तेवढ्यात देवाभाऊंच्या कार्यालयातून निरोप आला. 'आधी दिवा, आता घसा. तिसऱ्या प्रकरणात वाचवणार नाही हे लक्षात असू द्या.' हे ऐकून त्यांचे अवसानच गळाले. मोबाइलवर येत असलेला चाकणकरांचा फोन घेण्याची ताईंची हिंमतच झाली नाही.

राजवाडे विचारविश्व

महाराष्ट्र धर्माचे संवर्धन

स्वराज्य स्थापनेसारख्या प्राणभूत संकल्पनेचा १६४६ पासून म्हणजे शिवरायांच्या कारभाराच्या प्रारंभापासून कसकसा आविष्कार होत राहिला, हे सांगण्यासाठी राजवाडे पुढे सरसावले खरे; परंतु त्यांना प्रारंभीच हे नोंदवावे लागले की, 'दुर्दैवाने शिवाजी महाराजांचा अस्सल लेख अद्यापपर्यंत (तोपर्यंत) एखादा दुसराच उपलब्ध आहे.' तथापि इच्छाशक्ती जबरदस्त असेल तर मार्ग गवसतोच, असे म्हणतात. त्याप्रमाणे शिवाजी महाराजांचे १६५९ सालचे एक पत्र 'काव्येतिहास संग्रहा'मध्ये छापले असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्या संग्रहामधले क्र. ४११ चे पत्र आपल्या विवेचनाच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे, हे ओळखून त्यांनी लिहिले, 'या पत्रावरून राज्य आक्रमिण्याकरता परराज्यांतील देसाई, देशपांडे यांना राजे काय काय लालूच दाखवून बांधून घेत असत, हे अंशतः कळण्यासारखे आहे.' मग त्यांनी त्या पत्राचा सबंध उतारा उद्धृत केला.

'तहनामा राजश्री खेमसावंत व लखमसावंत देसाई बहादूर प्रांत कुडाळ यांजकडील पितांबर शेणवई कारभारी येऊन ठराव करून दिला. सुरू सन तिस्साखमसैन अलफ...' पासून सुरुवात झालेला त्या उताऱ्याचा शेवट होता, 'शके १५८० विलंबीनामसंवत्सरे फाल्गुन वद्य ७ एकूण पाच कलमे करून तहनामा दिला असे. मोर्तब.'

मार्च १६५९ मध्ये झालेल्या या तहनाम्याचा ग्रांट डफनेसुद्धा आपल्या ग्रंथात ओझरता उल्लेख केल्याची नोंद करून राजवाड्यांनी लिहिले, 'या तहनाम्यातील एक कलम स्वराज्यसाधनाचे आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. शिवाजीने मुधोळच्या घोरपड्याला पाठवलेले एक पत्र माझ्याजवळ आहे. त्यातही हाच हेतू दर्शित केला आहे.'

राजवाड्यांनी महाराजांच्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घेतला. 'स्वराज्य, गनीमाई, सरदेशमुखी व चौथाई या मागण्या मोंगलाईतून करण्याचा शिवाजीने परिपाठ ठेवला. यात स्वराज्यसाधनाचा बराच इतिहास गर्भित आहे. आपण मोंगलांच्या राज्यातील प्रांताचे सरदेशमुख आहोत, हा प्रांत पूर्वी मराठ्यांच्या स्वराज्यात मोडत होता व मोंगल लोक मराठ्यांना गनीम म्हणत, त्याअर्थी गनीमाईचा पैसा त्यांच्यापासून चोपून घेऊन उणे अक्षर बोलल्याची आठवण त्यांना जन्मोजन्म व्हावी, इत्यादी अर्थ या शब्दापासून ध्वनित होतात...'

'स्वराज्य साधून महाराष्ट्र धर्म वाढवण्याचा विचार शिवाजीच्या राजनीतीत प्रधान होता', हे अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी लिहिले, 'महाराष्ट्रसंस्थांमध्ये अष्टप्रधानघटित राज्यव्यवस्थेचाही अंतर्भाव होतो. राष्ट्राच्या कल्पनेत राष्ट्रभाषेचाही समावेश होतो. शिवाजीराजे अवतीर्ण होईतोपर्यंत दक्षिणेतील मुसलमानांच्या संसर्गाने जावली, शृंगारपूर इत्यादि स्थलींच्या मराठा राजांच्या दरबारी व खुद्द शिवाजी राजांच्या पराक्रमाला सुरुवात होऊन त्यांच्या अभिषेककालापर्यंत त्यांच्या दरबारीदेखील फारसी व मुसुलमानी भाषेतील शब्दांचाच वापर चालत असे. त्यामुळे स्वराज्याची शुद्ध कल्पना मराठ्यांच्या मनात अस्पष्ट राहण्याचा संभव होता. म्हणून शिवाजीने फारशी शब्द टाकून त्यांच्याऐवजी संस्कृत व महाराष्ट्र शब्दांचा उपयोग करण्याचा परिपाठ घातला...'

'महाराजांच्या नंतर संभाजीराजे, राजाराम, शाहू या सर्वांनी स्वराज्यसाधनाचा कित्ता उत्तम गिरवला. १७१४ मध्ये शाहू महाराजांनी बाळाजी विश्वनाथास स्वराज्यसाधन करण्याकरता मलतबाची याद करून दिली. त्याच हेतूने बाळाजी दिल्लीला गेला व १७१९ मध्ये स्वराज्याच्या मतलबाच्या सनदा सय्यदबंधूंकडून करवून घेऊन तो साताऱ्याला परत आला. पुढे १७२० एप्रिलमध्ये बाजीरावाला पेशवाई मिळाली. त्या वेळी बाळाजीकडून साधावयाच्या राहिलेल्या मतलबांची याद जशीच्या तशी शाहूने बाजीरावाच्या स्वाधीन केली. विशेष म्हणजे या दोन्ही याद्यादेखील राजवाड्यांनी आपल्या विवेचनाला परिशिष्टासारख्या जोडल्या. त्या सर्व मतलबांमध्ये म्हणजे कामांमध्ये स्वराज्यसाधन हाच हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. पुढे त्याच्या कारकीर्दीतील पहिली दहा-अकरा वर्षे त्या यादीतील मतलब साधण्यात गेली. १७३१ मध्ये बाजीरावाने त्या यादीतील सर्व कलमे साधली. तिथपर्यंत म्हणजेच १७३१ पर्यंत मराठ्यांच्या खटपटी स्वराज्यसाधनार्थ झाल्या.' 'हिंदुपदबादशाही स्थापनेबद्दल बाजीरावाने शाहूपुढे केलेली प्रस्तावना सर्वश्रुत आहे', असे सांगून राजवाड्यांनी १७५० पर्यंतच्या घटनांचा आढावा घेतला. ते साल शाहूंच्या मृत्यूचे म्हणून तो एक टप्पा मानला.

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

उच्चाटनानंतरचे उत्खनन...

नक्षलवादाचा बीमोड केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन; कारण आदिवासी, दुर्गम भागांच्या विकासातली मोठीच समस्या यामुळे दूर झाली...

एखाद्या समस्येतून उद्भवलेली हिंसा आटोक्यात आणण्यासाठी सुरक्षा दल तसेच पोलिसांना मुदत देणे यात गैर काही नाही. शिस्तीत काम करणाऱ्या दलांना असे लक्ष्यनिर्धारित काम दिल्याशिवाय त्यांच्या मोहिमांना वेग येत नाही हे खरेच! मात्र, दिलेल्या मुदतीत त्यांनी लक्ष्य गाठल्यानंतरही ती समस्या संपली असे म्हणता येईल का? देशात दीर्घकाळ टिकलेल्या व आता सरकारच्या गृहीतकानुसार अस्ताला गेलेल्या नक्षल चळवळीस हा प्रश्न लागू पडतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात दिलेली मुदत मंगळवार- ३१ मार्च रोजी संपली. आता जंगलात उरलेले वा परागंदा झालेले काही मोजके नक्षली उरले. तेही नेतृत्वहीन स्थितीत. या चळवळीचे कंबरडे पूर्णपणे मोडण्यात यशस्वी झालेल्या सुरक्षा दलांचे व त्यांच्याकडून हे कार्य पार पाडून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या शहांचे त्यासाठी अभिनंदन! कधीकाळी चर्चेचा विषय ठरलेले केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक के. विजयकुमार यांनी 'द हिंदू'ला दिलेल्या मुलाखतीत या नक्षलनाशाचे श्रेय शहांबरोबरच चिदम्बरम यांनाही दिले. त्यांच्या मते काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांच्या केंद्रातील सरकारांनी या चळवळीच्या बीमोडासंदर्भात जे सातत्य दाखवले ते वाखाणण्याजोगे. याच राखीव दलाचे माजी महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात की नक्षली संपले हे चांगलेच झाले, पण त्यांच्या आजवरच्या प्रभावक्षेत्रातील जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत आणणे हे मोठे आव्हान आहे व त्यासाठी सरकारला स्थानिक पातळीवर बरीच मशागत करावी लागेल. दुर्गाप्रसाद यांच्या या इशाऱ्यापासून यापुढले प्रश्न सुरू होतात. त्यांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी नक्षलवाद वाढलाच कसा याबद्दल.

पश्चिम बंगालमधला नक्षलबारीचा उठाव मोडीत निघाल्यानंतर सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी नक्षलींनी दंडकारण्यात प्रभाव निर्माण केला तो समाजातील सामाजिक व आर्थिक विषमतेच्या जोरावर. सरकार व धनदांडग्यांकडून होणारा अन्याय या शस्त्रधाऱ्यांसाठी पोषक ठरला. आज साडेचार दशकांनंतर याच भागातली ती परिस्थिती बदलली आहे का? येथे मोठ्या प्रमाणावर राहणारे आदिवासी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत का? या काळात सरकारची या भागातली सक्रियता वाढली त्यामुळे समाजजीवनात काही फरक पडला का? विकासाला गती देण्यासाठी वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य व घर या पाच गोष्टी आवश्यक असतात. या मूलभूत सुविधांच्या संदर्भात या भागातील स्थिती कशी आहे, या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की विदारक वास्तव समोर येते. अलीकडे म्हणजे चार वर्षांपूर्वी या भागात काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने 'अझीम प्रेमजी फाउंडेशन'ने एक सर्वेक्षण केले. त्यानुसार ९२ टक्के माडियांना स्वातंत्र्य म्हणजे काय हेच ठाऊक नाही. एवढ्याच लोकांना भाषा व सांविधानिक अधिकार माहिती नाहीत. सरकारी कर्मचारी चुकले तर तक्रार करावी लागते याची कल्पनाच नाही. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था असते हे ६० टक्के माडियांना ठाऊक नाही. इथल्या ४८ टक्के रहिवाशांकडे एकही सरकारी ओळखपत्र नाही. प्रामुख्याने जंगलातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या या जमातीचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजारांच्या आत आहे. या सर्वेक्षणाचे कार्यक्षेत्र दक्षिण गडचिरोलीपुरते मर्यादित असले तरी इतर ठिकाणच्या परिस्थितीत फार फरक दिसेल अशी स्थिती नाही. गडचिरोलीच्या तुलनेत बस्तर व अबूजमाडचा परिसर आणखी मागास. या सर्व भागात माडियांची संख्या मोठी. या पार्श्वभूमीवर नक्षलसमाप्तीकडे बघितले तर ताज्या यशानंतरही सत्ताधाऱ्यांसमोरील आव्हान किती खडतर आहे याची जाणीव सहज होते.

नक्षलींचे अस्तित्व हेच विकासातला मुख्य अडसर होते व आता तेच संपुष्टात आल्याने हा भाग विकासाच्या प्रवाहात येईल असा दावा सरकार करू शकते. त्यात तथ्यही आहे. तो स्वीकारण्याआधी आणखी काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे. नक्षलींच्या पीछेहाटीला सुरुवात झाली ती २०१२

...पण नक्षल्यांचा प्रभाव हे विकासहीनतेचे एक लक्षण होते. ते दूर झाल्यावर विकासाचे नागरी प्रतिरूपच राबवायचे की आदिवासींना केंद्रस्थानी मानून शाश्वत विकासाचा कार्यक्रम आखायचा हे सरकारला ठरवावे लागेल...

पासून. जनाधार घटल्याने त्यांचे प्रभावक्षेत्र आक्रसत गेले. तेव्हा देशातल्या १०० जिल्ह्यांत त्यांचा प्रभाव होता. तो हळूहळू कमी होत ४० वर आला. वर्षागणिक ही संख्या कमी होत जाऊन गेल्या दोन वर्षांत तर एक आकडी झाली. या १४ वर्षांच्या काळात नक्षलींचा वावर संपलेल्या क्षेत्रात सरकारला विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणे शक्य होते. ते का झाले नाही? 'वनाधिकार' व 'पेसा' हे यूपीए सरकारने केलेले दोन कायदे चळवळवाढीसाठी प्रमुख अडसर ठरले असे शरण आलेला नक्षली भूपती नुकताच म्हणाला. या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का झाली नाही? २०१४ नंतर तर याकडे दुर्लक्षच झालेले दिसले. हे दोनच कायदे असे आहेत जे गावांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देतात. चिदम्बरम गृहमंत्री असताना त्यांनी नक्षलविरोधी मोहीम राबवतानाच कायदा व सुव्यवस्था तसेच विकास या दोन्ही गोष्टींवर सातत्याने भर दिला. नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांना थेट निधी दिला. भाजपचे सरकार आल्यावर हा निधी देणेच बंद झाले. केंद्राने विकासाचा मुद्दा राज्यावर सोपवला. ही जबाबदारी राज्याची हा तर्कही ठीक. मात्र, केंद्राने या चळवळीच्या बीमोडासाठी प्राधान्य दिले ते कायदा व सुव्यवस्था याच मुद्द्याला. दुर्गम भागात सुरक्षा दलांचे अडीचशेच्या वर तळ गेल्या तीन वर्षांत उभारण्यात आले. सुरक्षा दलातील जवानांच्या वावरामुळे नक्षलींच्या फिरण्यावर मर्यादा आल्या. या जवानांनी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत नक्षलींना टिपले किंवा शरण आणले. हे जे झाले ते योग्यच, पण याच काळात सरकारचे प्राधान्य दिसून आले ते खनिज उत्खननाला. ते निर्धोकपणे करता यावे यासाठी जिथे गावेही नाहीत तिथे ८० फुटांचे रस्ते तयार होऊ लागले.

लोह वा इतर खनिजांचे उत्खनन हा औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक हे अमान्य करता येणार नाही. मात्र, खाणी म्हणजेच या संपूर्ण भागाचा विकास असे जे चित्र रंगवले जाते ते पूर्णपणे चुकीचे तर आहेच शिवाय निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासींच्या जीवनपद्धतीवर अतिक्रमण करणारे आहे. अजूनही मागासलेल्या अवस्थेत जगणाऱ्या या जाती समूहांना थेट उद्योगांशी जोडणे धोकादायक ठरू शकते. उद्योगांमुळे रोजगारनिर्मिती होते, कुशल व अकुशल हातांना काम मिळते हे खरे असले तरी यातून जमातींमधील सर्वांचेच हित साधले जात नाही. याचा लाभ निवडकांना मिळतो व मोठा वर्ग त्यापासून वंचित राहतो. या समूहाला रोजगारक्षम करण्यासाठी शाळा हव्यात, सुदृढतेसाठी आरोग्य केंद्रे हवीत, पिण्याचे शुद्ध पाणी हवे, आर्थिक उन्नतीसाठी पारंपरिक शेतीत बदल हवेत. हे घडून आल्यावर मग उद्योग विस्तार फायद्याचा ठरतो. ते न करताच केवळ रस्ते, उद्योग यामुळे होणाऱ्या झाडांच्या कत्तली व या सर्वांतून होणारे प्रदूषण, यातून निसर्गपूजक व्यवस्थेला लागणारा धक्का यामुळे आदिवासी विकासाकडे जाणार की विनाशाकडे? यावर आताही फारसा गंभीरपणे विचार होताना दिसत नाही. सरकारने सध्या स्वीकारलेला हा विकासाचा दृष्टिकोन आदिवासींना आणखी एका संकटात ढकलणारा आहे. नक्षली संपले, आता हळूहळू विकासाची प्रक्रिया राबवू असे सरकार म्हणते, ते ठीकच. पण त्याचा कसलाही आराखडा दृष्टीस पडत नाही. एखादा उद्योग उभा राहिल्यावर नागरी परिसर बदलताना दिसतो तसेच या मागास भागातही घडेल अशी अपेक्षा बाळगणे चूक. याचे कारण या समूहाच्या जीवनपद्धतीत दडलेले आहे. शिवाय शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक मिळकत ही कारणे आहेतच.

त्यामुळे सरकारने नक्षलमुक्तीचा आनंद जरूर साजरा करावा, पण अजूनही स्वतःची संस्कृती जपणाऱ्या, जंगल वाचवणाऱ्या आदिवासींच्या बाबतीत नागरी विकासाचे प्रतिरूप जसेच्या तसे न राबवता शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन अंगीकारावा. नक्षलींच्या उच्चाटनानंतर उत्खननामुळे जंगलांची धूळधाण झाली नाही, तरच या नक्षलमुक्तीचे सार्थक होऊ शकेल.

'दुसऱ्या टप्प्या'तील इराणयुद्ध कसे असेल?

प्रवीण साहनी
ज्येष्ठ संरक्षणतज्ज्ञ
pravin@forceindia.net

समर-विवेक

पश्चिम आशियातील युद्धाचा पहिला टप्पा इराणच्या सरशीचा ठरला, हे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. पण त्यामुळेच या पहिल्या टप्प्यापेक्षा निराळा असा दुसरा टप्पा कसा असेल याविषयी अंदाज बांधण्यास पुरेसा वाव आहे.

पहिल्या टप्प्यात इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवले. तर दुसरा टप्पा हा भू-युद्धाशी (इराणमध्ये किंवा किमान खर्ग बेटावर अमेरिकी सैनिक उतरवण्याच्या योजनेशी) संबंधित आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ हे 'मोठ्या प्रमाणात अमेरिकी सैनिक इराणमध्ये उतरवण्याची गरज भासणार नाही' असे म्हणत असताना, तुलनेने कमीच अमेरिकी सैनिक (सुमारे ५,००० मरीन आणि १,५०० हवाई सैनिक) पश्चिम आशियात दाखल झाले आहेत. त्यांचे हेतू काहीही असले तरी, एकदा भू-युद्ध सुरू झाले आणि समजा त्यातही जीवितहानी वाढू लागली की, अशा परिस्थितीत युद्धाला स्वतःची अशी एक गती मिळते, जिथे वाढत्या संघर्षावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते. मात्र पुढे काय होणार आहे हे समजून घेण्यासाठी, इराणची युद्धनीती यशस्वी का होते याच्या कारणांकडे पाहणे आवश्यक आहे.

मुळात इराणला, शत्रू काय काय करेल याचा अंदाज बांधता आला होता. 'एकदा का उच्चपदस्थ नेत्यांना मारले की इराण धार्मिक राजवटीला पाठिंबा/ विरोध आणि वांशिक वैविध्य या कारणांनी विघटित होऊ शकतो; मग राजवट उलथवून लावता येईल' असे अमेरिकी मनसुबे आणि टिपून हल्ले करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची इस्त्रायली कार्यपद्धती यांची जाणीव असल्याने, तेहरानने आपल्या लष्करी अधिकार-कक्षांचे विकेंद्रीकरण केले. यातून इराणने स्वतःहून प्रतिहल्ल्याचे आदेश देण्यास सक्षम असलेल्या अनेक 'प्रतिकार रेषा' तयार केल्या. उदाहरणार्थ येमेनमधील हुथी, लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, सीरिया आणि इराकमधील खासगी सशस्त्र दले (मिलिशिया) इत्यादींसारख्या प्रादेशिक प्रतिनिधींना त्याच्या युद्ध वा प्रतिकाराच्या विविध रेषा म्हणून पाहता येते. त्याचप्रमाणे खुद्द इराणच्या सेनादलांमध्ये, एकाच मुख्यालयाचे आदेश घेण्याची प्रचलित पद्धत बाजूला ठेवून अनेक प्रांतीय कमांडर नेमले गेले. हे कमांडर त्यांच्या लक्ष्यांपुरते जबाबदार असले तरी, ते स्वतःच्या लक्ष्यांच्या यादीचे पुनरावलोकन करून ती अद्ययावत करण्यासाठी इतर प्रादेशिक कमांडरशी समन्वय साधत असत. एकच प्रमुख कमांडर असणे ही सोय एखादे राष्ट्र 'ऐच्छिक युद्ध' लढत असताना चांगलीच ठरते हे खरे. पण २८ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च नेत्यासह त्याच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची हत्या झाल्यानंतरही इराणने प्रभावीपणे आणि वेगाने प्रतिसाद दिला, याचा अर्थ असा की, इराणची विकेंद्रीकरणाची

'गरज पडल्यास इराणच्या भूमीवर उतरू' इथपासून ते 'फारसे सैनिक न वापरताच आम्ही कामगिरी फत्ते करू' अशी जाहीर वक्तव्ये अमेरिकी वरिष्ठ करत असल्याने, युद्धाचा दुसरा टप्पा जमिनीवरला असणार हे स्पष्ट आहे. पण इराणने आजवर अमेरिकेला आणि इस्त्रायललाही कसे जेरीस आणले हे पाहता पुढल्या टप्प्यात निराळे काय होईल?

रणनीती उपयुक्त ठरली. इराणला याची जाणीव आधीपासूनच होती की ते अमेरिका वा इस्त्रायल या दोघांपैकी एकट्याशी नव्हे तर दोघांशीही लढावे लागणार आहे. अमेरिका पडद्यामागे राहणार की, २८ फेब्रुवारीपासून जसे उघडपणे अमेरिकी अध्यक्ष इराणयुद्धाची भाषा करू लागले तसे करणार, हा तपशिलाचा फरक. धोका दुहेरीच असणार, हे इराणला गृहीत धरावे लागले होते. त्यामुळे इराणसाठी हे अस्तित्वाचे युद्ध होते.

त्यामुळे इराणने महाशक्तिमान अमेरिकेशी युद्धासाठी डावपेचांचा वापर केला आणि अमेरिकेला त्रासदायक ठरतील असे दोन प्रमुख मर्मबिंदू अचूकपणे निवडले. जागतिक आर्थिक परिणाम असलेला मुख्य मर्मबिंदू म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. या जलमार्गातून जगातील २० टक्के तेल, तसेच वायू, खते, पेट्रोरसायने इत्यादींची वाहतूक होते. याच डावपेचाचा पुढला भाग म्हणजे १२ टक्के तेलाची

वाहतूक करणाऱ्या बाब-अल-मंदेबची सामुद्रधुनी हुथींकडून बंद केली जाऊ शकते. दुसरा केंद्रबिंदू म्हणजे सहा आखाती सहकार्य परिषद राष्ट्रांमधील (बहारीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती) अमेरिकेचे तळ. इराणने युद्धापूर्वीच हे स्पष्ट केले होते की, जर अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला, तर ते योग्य प्रत्युत्तर म्हणून या प्रदेशातील त्यांच्या तळांवर हल्ला करेल.

इराणच्या युद्धनीतीचा आणखी एक घटक म्हणजे त्यांनी, युद्धक्षेत्रात क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या बाबतीत वर्चस्व मिळवणेही साध्य केले. इराण आणि इस्त्रायलमधील अंतर १,००० किमीपेक्षा जास्त असल्याने, तसेच अमेरिका व इस्त्रायलच्या लढाऊ विमानांच्या तंत्रज्ञानाशी इराण बरोबरी करू शकत नसल्याने, त्यांनी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले. ही क्षेपणास्त्रे पृथ्वीपासून १०० किमी उंचीवर, अवकाशाजवळच्या वातावरणाच्या उच्च थरात अतिशय वेगाने प्रवास करतात. या प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या बाबतीत इराणला चीन आणि रशियाकडून प्रचंड मदत मिळू शकली; या दोन देशांकडे अमेरिकेपेक्षा श्रेष्ठ प्रगत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आहे.

याखेरीज इराणने गेल्या काही दशकांमध्ये भूमिगत क्षेपणास्त्र संकुले आणि नियंत्रण केंद्रे उभारली, जिथे अमेरिकेचे प्रगत 'बंकर भेदक बॉम्ब' पोहोचू शकत नव्हते. इराणी ड्रोनचा साठा या संकुलांत आहे आणि क्षेपणास्त्रेही भूमिगत मोबाइल लाँचरमधून डागली जातात. दीर्घकाळ चालणारे युद्ध लढण्यासाठी त्यांनी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या भूमिगत स्वदेशी उत्पादन सुविधाही उभारल्या आहेत. नौदल युद्धाच्या बाबतीत, पर्शियन आखातातील उथळ पाणी (खोली २०० मीटर) लक्षात घेऊन इराणने पाण्याखालील युद्धावर लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये केवळ पाणसुरुंग नव्हे, तर विविध प्रकारच्या सुरुंगांसारख्या क्षमता असलेले पाण्याखालील बोगदे, मिजेट (अतिशय लहान) पाणबुड्या, वेगवान नौका आणि समुद्राखालून डागता येणारी जहाजविरोधी क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश होता.

महत्त्वाचे म्हणजे, इराणला चीनच्या बायडू-३ उपग्रह समूहाची मदत मिळते. हे चिनी तंत्रज्ञान अमेरिकेच्या ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस) पेक्षा प्रगत आहे. बायडू-३ ही तीन कक्षांमधील (मध्यम पृथ्वी कक्षा, कललेली भू-संकालिक कक्षा आणि भू-संकालिक कक्षा) संकरित रचना आहे, तिला पुन्हा पृथ्वीजवळच्या कक्षेतील याओगॉन संवर्धक उपग्रह प्रणालीची जोड दिली जाते. यामुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करून २४ तास दृश्यमानता मिळवणे आणि जमिनीवरील वा हवेतील अमेरिकन जॅमर्सकडून होणाऱ्या जॅमिंगची चिंता न करता अचूक हल्ले करणे इराणलाही शक्य होत आहे.

हेच तर एकविसाव्या शतकातील युद्ध... इथे अंतराळातील क्षमता, जॅमिंग टाळण्यासाठी विद्युतचुंबकीय वर्णपटावर नियंत्रण आणि सायबर सुरक्षा यांचा समावेश असावाच लागतो. अर्थातच या जोडीने आज पाण्याखालील युद्ध आणि प्रगत क्षेपणास्त्रे; अधिक उंच (२० किमी ते १०० किमी उंचीपर्यंत) जाणारे ड्रोन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचाही वापर होतो आहेच.

अमेरिकेच्या लष्कराकडे ड्रोनऐवजी मोठमोठी विमानवाहू जहाजे, युद्धनौका, अत्याधुनिक लढाऊ विमाने आणि प्रगत क्षेपणास्त्रे यांसारखी विसाव्या शतकातील अनेक साधने आहेत. पण याऐवजी ड्रोन अथवा प्रगत क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर करता येते, अचूकपणे लांब अंतरावर मारा करता येतो. इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी नुकसान झालेली अमेरिकेची दोन विमानवाहू जहाजे युद्धभूमीतून बाहेर पडल्याचे वृत्त यासंदर्भात लक्षवेधक आहे. इराणने या टापूत अमेरिकेने जमिनीवर उभारलेल्या बहुतेक रडार यंत्रणा नष्ट केल्या आहेत. सौदी अरेबियाच्या हवाई तळावर उभे असलेले एक हवाई रडार आणि तीन इंधन भरणारी विमानेही इराणने नष्ट केली. जमिनीवरील कारवाईसाठी रवाना होण्याची वाट पाहात कुवेतमध्ये असलेले काही अमेरिकी सैनिक (मरीन) इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ठार झाले आहेत.

जेव्हा अमेरिका इराणविरुद्ध आपली भू-कारवाई सुरू करेल, तेव्हा भविष्यात काय घडू शकते याचीही ही एक झलक आहे. चिनी बायडू उपग्रह समूहाकडून जर इराणच्या क्षेपणास्त्रांना आणि ड्रोनना मदत मिळते आहे, तर ती जमिनीवरील माऱ्याच्या वेळीही मिळू शकते. वस्तुस्थिती ही आहे की अमेरिकेसमोर कठीण काळ आहे. सौम्य शब्दात सांगायचे झाल्यास, अमेरिका एका संकटातून दुसऱ्या संकटात उडी घेत आहे.

अन्वयार्थ

विद्यापीठांतील मुक्ततेवर घाला

महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांना नुकतेच मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात प्रवेश करण्यापासून रोखले गेले. त्याआधी चित्रपट निर्माते आनंद पटवर्धन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पणतू अमेय आनंदराज आंबेडकर यांनाही रोखले गेले होते. कारण काय? तर विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी राजेश बाळखंडे ऊर्फ भदंत विमांसा हे त्यांच्या मागण्यांसाठी करत असलेल्या सत्याग्रहाला पाठिंबा द्यायला ते आले होते. विद्यापीठे ही जर वैचारिक, बौद्धिक व तार्किक चर्चांची, संवादाची आणि शांततामय पद्धतीने विरोध व्यक्त करण्याची ठिकाणे मानली जात असतील, तर अशा भेटींवर निर्बंध घालण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. इतकेच नाही, तर तो एकूणच देशातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांच्या आवारांमध्ये अपेक्षित असलेल्या विचारांच्या देवाणघेवाणीच्या मुक्त वातावरणावरच घाला घालणारा ठरतो आहे का, हे पडताळून पाहण्यासही भाग पाडतो.

उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी उपस्थिती, शिस्त यांच्याशी संबंधित काही प्राथमिक नियम असलेच पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण म्हणून कायद्याने प्रौढ झालेल्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक सुविधांबाबत आपल्या मागण्याच मांडू नयेत किंवा साहित्य, कलेसाठी स्थापन विद्यार्थी गटांनी विशिष्ट विचारसरणीला अनुसरणाऱ्यांचीच व्याख्याने, कला सादरीकरणे आयोजित करावीत, असे म्हणणे हे शैक्षणिक आवारात अपेक्षित मुक्त वातावरणाच्या विपरीत आहे. 'उगाच वाद होईल,' म्हणून कार्यक्रमांना परवानग्याच नाकारणे, यापेक्षा 'संवाद होईल, त्याचे स्वागत करू,' अशी भूमिका घेऊन मुक्त विचारांना मुभा देताना विद्यापीठे वा शैक्षणिक संस्था दिसत नाहीत, ही व्यथित करणारी बाब. सत्ताधाऱ्यांना पूरक ठरणारे वा हवे असलेले तेवढेच उचित, बाकी सगळे राष्ट्रविरोधी, हा विचार बळावणे लोकशाहीला मारक असते. त्यातूनच मग ठरवलेली व्याख्याने काहीही कारण न देता रद्द करणे, नाटकाच्या प्रयोगातील मुद्दे पटत नाहीत, म्हणून गुद्द्यांपर्यंत येणे, सत्ताधाऱ्यांना गैरसोयीच्या आंदोलनांना राष्ट्रद्रोही ठरविणे असे होत राहते.

हे काही फक्त आपल्याच देशात होते, असेही नाही. तिकडे अमेरिकेतही हे हल्ली सर्रास घडते. गाझामधील नरसंहाराला विरोध करण्यावरून झालेल्या आंदोलनांमुळे हार्वर्ड विद्यापीठाचा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने कसा पिच्छा पुरवला आहे, हे लपून राहिलेले नाही. फरक इतकाच, की तेथील बहुतांश विद्यापीठे झुकत नाहीत, हार्वर्डही झुकले नाही. विशेष म्हणजे, या सरकारी बळजोरीविरोधात विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थीही विद्यापीठाच्या बाजूने एकवटले. आपल्याकडे मात्र अपवादानेच असे घडते.

अर्थात, विद्यापीठांच्या आवारांत आंदोलने करणारे वा जाहीर व्याख्यानांत श्रोत्यांमधून उठून वेगळेच काही तरी बरळत राहणारेही असतात. आंदोलनांत वेड्यावाकड्या कृती करून कॅमेऱ्यांसमोर स्टंटबाजी करणारे, व्याख्यानांत व्यत्यय आणून विषय भरकटवणारे अलीकडे वाढले आहेतच. त्यांचा बंदोबस्तही गरजेचाच. पण असे महाभाग असतात, म्हणून चर्चेचे मार्गच बंद करून टाकायचे वा काळे कपडे परिधान केले आहेत, म्हणून कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यापासूनच रोखायचे, हे काही उत्तर नाही. अन्यथा, रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती व्हायची, जी हल्ली काही प्रमाणात झालेली दिसते.

या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा, की विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था ही खुल्या वातावरणाची प्रांगणे असतात, याचे भान सुटले की बंधनांचे दोर विचारांची जागा आक्रसून टाकतात. उच्च शिक्षणाच्या परिसंस्थेतील वादसभा, वादविवाद स्पर्धा, शांततापूर्ण मार्गांनी केलेले निषेध, सत्याग्रह, आंदोलने, व्याख्याने ही विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीला रूप देणारे, लोकशाहीत विरोधालाही स्थान असते, याची जाणीव दृढ करणारे मंच असतात. लोकसंख्येतील तरुण वर्गाचा मोठा टक्का हा लाभांश म्हणून मिरवायचा, तर तसे करताना त्या तरुण वर्गाला सर्वांगाने समृद्ध करण्याची जबाबदारी अनुस्यूत असते, हे विसरून कसे चालेल? उच्च शिक्षण संस्था वा विद्यापीठे म्हणजे, आपल्या लोकशाहीतील विचारवैविध्याची खूण पटवणारी मानके मोडून एकजिनसी, एकसाची व्यक्तिमत्त्वांचे कळप निर्माण करणारे कारखाने नाहीत. ते सर्वार्थाने फुलणारे विविधतेचे ताटवे असावेत, ही अपेक्षा आहे. त्यात खुल्या विरोधाला जागा असावी, बंदिस्त सक्तीला नाही.

राज्याला अधिकार, तरी आंध्र प्रदेशच्या राजधानीसाठी संसदेत कायदा का?

विश्लेषण

संतोष प्रधान
santosh.pradhan@expressindia.com

आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावतीला मान्यता देण्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. राज्याची राजधानी निश्चित करण्याचा राज्यांना अधिकार असतानाही अमरावतीसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला. संसदेच्या इतिहासात राज्याच्या राजधानीसाठी प्रथमच असा कायदा करण्यात आला आहे.

लोकसभेत कायदा करण्याची पार्श्वभूमी काय?

आंध्र प्रदेश राज्याचे २०१४ मध्ये विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार तेलंगणा आणि उर्वरित आंध्र प्रदेश अशी तेलुगू भाषक दोन राज्ये अस्तित्वात आली. आंध्रचे विभाजन करताना २०१४ पासून पुढील १० वर्षे हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांची संयुक्त राजधानी असेल, अशी तरतूद राज्य पुनर्रचना कायद्यात करण्यात आली होती. चंडीगड हीदेखील पंजाब आणि हरयाणाची संयुक्त राजधानी आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंध्र प्रदेश सरकारने २०१४ नंतर राजधानी म्हणून अमरावती हे नवीन शहर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी भूसंपादनाचे नवीन सूत्र तयार करण्यात आले. २०१९ मध्ये आंध्रमध्ये सत्ताबदल झाला आणि वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. जगनमोहन सरकारने अमरावती राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्याची योजना बाद ठरवली. त्याऐवजी अमरावती, विशाखापट्टण आणि कर्नुल अशा तीन राजधान्या विकसित करण्याची योजना तयार केली. २०२४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल होऊन पुन्हा चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच त्यांनी अमरावती राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्याचा पुन्हा निर्णय घेतला. कायदेशीर प्रक्रिया पार करून आंध्र विधानसभेने गेल्या महिन्यात अमरावतीला राजधानीचा दर्जा देण्यासाठी राज्य पुनर्रचना कायद्यात बदल करण्याची शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता. यानुसार लोकसभेत आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्रचना कायद्यात बदल करून अमरावती ही राज्याची राजधानी असेल, असा कायदा मंजूर करण्यात आला.

लोकसभेत कायदा करण्याची आवश्यकता होती?

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३ व ४ मध्ये राज्यांची सीमा बदलणे, राज्याचे क्षेत्र कमी-जास्त करणे, नवीन राज्यांची निर्मिती, राज्याचे नाव बदलणे यासाठी संसदेला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र राज्यांची राजधानी निश्चित करण्याचा अधिकार हा संबंधित राज्य सरकारचा असतो. आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन करताना राज्य पुनर्रचना कायदा २०१४ मध्ये संसदेने केला होता. त्यात दहा वर्षांनंतर हैदराबाद ही तेलंगणाची राजधानी तर आंध्र प्रदेशसाठी नवीन राजधानी असेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कलम पाचमध्ये बदल करून अमरावती हे आंध्र प्रदेशच्या राजधानीचे शहर असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठीच संसदेने आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्रचना कायद्यात बदल केला. केंद्रातील मोदी सरकारच्या स्थिरतेसाठी तेलुगू देसमच्या १६ खासदारांची मदत भाजपसाठी आवश्यक आहे. यामुळेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशला मागे झुकते माप देण्यात आले होते. आता अमरावती राजधानीसाठी लोकसभेत कायदा करण्यात आला आहे.

कायदा केल्याने फरक काय पडणार?

राज्याची राजधानी हा आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात भावनिक मुद्दा ठरला आहे. चंद्राबाबू नायडू सरकारने अमरावती राजधानीसाठी सिंगापूरमधील कंपन्यांची मदत घेतली होती. सिंगापूरमधील काही कंपन्यांनी आर्थिक गुंतवणूक केली होती. जगनमोहन रेड्डी सरकारने अमरावतीऐवजी तीन राजधान्यांचा निर्णय घेतल्याने अमरावतीमधील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. त्यावरून सिंगापूरमधील वित्तीय कंपन्यांनी भारतातील कथित धोरण लकव्यावर टीका केली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एव्हॉनप्रमाणे अमरावतीवरून भारताची नाचक्की झाली होती. भविष्यात राज्यात पुन्हा सत्ताबदल झाल्यास अमरावती राजधानीचा निर्णय बदलला जाऊ शकतो ही भीती होती. कारण अमरावती राजधानीस जगनमोहन रेड्डी यांचा अजूनही विरोध आहे. या राजधानीस केंद्रीय कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने भविष्यात केवळ राज्य सरकारला राजधानी बदलण्याचा निर्णय घेता येणार नाही. अमरावतीऐवजी दुसरी राजधानी विकसित करायची असल्यास राज्याप्रमाणेच केंद्रीय कायद्यात बदल करावा लागेल. केंद्र व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांचे सरकार असल्यास कायद्यात बदल करणे सोपे नसते. केंद्राचा कायदा झाल्याने राजधानी बदलणे आता सहज शक्य राहिलेले नाही.

संसदेत असा कायदा पहिल्यांदाच?

लोकसभेच्या इतिहासात राज्याच्या राजधानीसाठी अशा स्वरूपाचा कायदा प्रथमच करण्यात आल्याचे लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले. राजधानी दिल्लीसाठी वेळोवेळी कायदे करण्यात आले होते. पण दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, तर आंध्र प्रदेश हे राज्य आहे.

चिंतन

जनगणना में लें बढ़-चढ़कर हिस्सा

देश में 1 अप्रैल 2026 से बहुप्रतीक्षित जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। यह केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण आधार है। जनगणना के माध्यम से जुटाए गए आंकड़े ही आने वाले वर्षों में सरकार की नीतियों, योजनाओं और विकास के खाके को निर्धारित करते हैं। ऐसे में यह केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले। इस बार की जनगणना कई मायनों में विशेष है। पहली बार इसे पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। अब तक जहां आंकड़े कागज पर दर्ज होते थे और बाद में उन्हें डिजिटाइज किया जाता था। वहीं इस बार कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए सीधे डेटा एकत्र करेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। इसके साथ ही नागरिकों को 'स्वयं-गणना' की सुविधा भी दी गई है, जिससे वे खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जनगणना की यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें 'हाउस लिस्टिंग' यानी मकानों की गिनती और उनमें उपलब्ध सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा। इससे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का प्रारंभिक आकलन संभव होगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें वास्तविक जनसंख्या गणना की जाएगी। इस जनगणना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लगभग 90 वर्षों बाद जाति-आधारित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। इससे पहले 1931 में इस प्रकार का डेटा जुटाया गया था। आज के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए ठोस आधार तैयार होगा। हालांकि, इस विषय पर विभिन्न मत हो सकते हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि सटीक आंकड़े ही सटीक नीतियों का आधार बनते हैं। करीब 34 लाख कर्मचारियों की विशाल टीम इस कार्य में जुटी है, जो घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेगी। ऐसे में आम नागरिकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आएं, तो उनके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करें और सही व पूरी जानकारी दें। गलत या अधूरी जानकारी न केवल आंकड़ों को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी कमजोर कर सकती है। इस बार जनगणना में कुछ नए पहलू भी शामिल हैं, जैसे लिव-इन संबंधों को मान्यता देना (यदि संबंध स्थिर हैं) और आधुनिक जीवनशैली से जुड़े पहलुओं को भी दर्ज करना। यह बदलते समाज की झलक को दर्शाता है और यह बताता है कि सरकार वर्तमान वास्तविकताओं को समझकर नीति निर्माण करना चाहती है। कुल मिलाकर जनगणना केवल सरकार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की भागीदारी से सफल होने वाला राष्ट्रीय अभियान है। यह वह अवसर है, जब हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को आधिकारिक रूप से दर्ज कराता है और देश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है। देश के विकास की मजबूत नींव सटीक आंकड़ों पर ही टिकी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें, जागरूक बनें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जनगणना में आपकी भागीदारी न केवल आपकी पहचान को दर्ज करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की राह भी प्रशस्त करती है।

सफलता
प्रमोद भार्गव

संकल्प के साथ नक्सलवाद का अंत

भारत में संकट बन चुकी राष्ट्रीय समस्याओं का समय-सीमा में अंत होना दुर्लभ है, लेकिन केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने यह कार्य करके दिखा दिया। गृहमंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि माओवादी नक्सलवाद का अंत 31 मार्च 2026 तक कर लिया जाएगा। उन्होंने यह करके दिखा भी दिया। वरना नक्सलवाद को संरक्षण दे रहे नगरीय तथाकथित बौद्धिक इस सशस्त्र खूनी क्रांति को राष्ट्र विरोधी संघर्ष मानते ही नहीं थे। बस्तर में 25 लाख के इनामी नक्सली सरगना पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ जिस तरह से हथियारों सहित समर्पण किया, उससे देश के सबसे बड़े गढ़ में माओवादी हिंसा का निर्णायक अंत हो गया। इस क्षेत्र का यही अंतिम सरगना शेष बचा था। नक्सलवाद का अंत ठीक उसी तरह हुआ है, जिस तरह प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में पंजाब के उग्रवाद का अंत हुआ था।

इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। अब पूरा देश मान रहा है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ हो तो किसी भी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। क्योंकि देश की जिस तरह की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां हैं और सशक्त प्रशासनिक ढांचा है, उसके चलते किसी भी प्रकार की सशस्त्र क्रांति का उग्रवाद और नक्सलवाद की तरह अंत होना निश्चित है। कश्मीर का पाक प्रायोजित आतंकवाद का भी यही हश्र होना है। छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने शीर्ष माओवादी क्रूर हिंसा के प्रतीक बन चुके हिड़मा को मार गिराने के पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता तब मिली थी, जब डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यह कुख्यात दरिंदा होने के साथ गुरिल्ला लड़ाका था। माओवादी पार्टी का इसे पर्याय माना जाता था। इसका नक्सली सफर 1985 से शुरू हुआ था। इसने वारंगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी। नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है, इसलिए अमित शाह ने लोकसभा में 'नक्सल मुक्त भारत' मुद्दे पर चली चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि 'एक समय 12 राज्य लाल आतंक का गलियारा बन गए थे। कानून व्यवस्था नहीं थी। देश में अब नक्सलवाद खत्म हो गया है। 'शाह ने बताया कि इस दौरान 706 नक्सली मारे गए, 4800 ने समर्पण किया है और 2000 गिरफ्तार हुए हैं। इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में शाह ने कहा, '75 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। लेकिन उसने आदिवासियों को न घर दिए, न पानी, न स्कूल बनाए और न ही बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई।' 'शाह का यह बयान तर्कसंगत है, क्योंकि शहरी वामपंथियों से भयभीत कांग्रेस नेतृत्व नक्सलवाद को कश्मीर के आतंकवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद की तरह बड़ी चुनौती तो मानती थी, लेकिन उससे निपटने की कभी कोई कठोर रणनीति नहीं बनाई। यही कारण रहा कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर इलाके में नक्सली आतंक बेखौफ फलता-फूलता रहा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र को कमजोर करने की दृष्टि से सरकार ने बहुआयामी कदम उठाए। सबसे पहले उन नगरीय बौद्धिकों पर शिकंजा कसा, जो इन्हें राष्ट्रविरोधी वामपंथी वैचारिक खुराक देते थे। केंद्र सरकार ने सुरक्षाबलों को आधुनिक हथियार एवं यांत्रिक सुविधाएं देकर इन्हें सशक्त बनाया।

इसका परिणाम निकला कि एक के बाद एक खून की इबारत लिखने वाले नक्सली मारे जाने लगे। जो नक्सली समर्पण के लिए तैयार हुए उन्हें समर्पण का अवसर और समझौते में बताई गई शर्तों का पालन करने का भरोसा दिया। नतीजतन इसके पहले तक गुप्तचर एजेंसियां नक्सलियों का सुराग लगाने में असफल रहती थीं, उन्हें नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद भरोसे की सूचनाएं मिलने लगीं। इस रणनीति के बाद से सैन्यबलों को सटीक सूचनाएं मिलीं और वे नक्सलियों को निशाना बनाने में लगातार कामयाब होने लगे। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनमें ये खुद आकर नक्सली बने हैं, इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना मुश्किल होता है। ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर एजेंसियों को खबर देने लगे। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों में छिपने के स्थलों और जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित थे। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही हैं। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की रक्तरंजित मुहिम जारी रखनी है। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन नतीजे पूरी तरह अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए थे, उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में असफल रहीं।

दरअसल, देश में अब तक तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोले हुए था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की थी और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते थे। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता था, उसकी बोलती बंद कर दी जाती थी। हालांकि तत्काल तो इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना होगा कि नक्सलियों के जो भी नगरीय बौद्धिक समर्थक हैं, उनके तार देश-विदेश में नक्सल समर्थक वामपंथियों से जुड़े हैं, जो इन्हें धन और हथियार उपलब्ध कराते रहे हैं। सरकार की सतर्कता कम होती दिखाई देगी तो ये वामपंथी हताश एवं निराश माओवादियों को सिर उठाने के संसाधन फिर से देने लग जाएंगे।

भारत में संकट बन चुकी राष्ट्रीय समस्याओं का समय-सीमा में अंत होना दुर्लभ है, लेकिन केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने यह कार्य करके दिखा दिया। गृहमंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि माओवादी नक्सलवाद का अंत 31 मार्च 2026 तक कर लिया जाएगा। अब पूरा देश मान रहा है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ हो तो किसी भी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। हालांकि तत्काल तो इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना होगा कि सरकार की सतर्कता कम होती दिखाई देगी तो ये वामपंथी हताश एवं निराश माओवादियों को सिर उठाने के संसाधन फिर से देने लग जाएंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

हनुमान जयंती विशेष
आचार्य दीप चन्द भारद्वाज

अतुलनीय बल के स्वामी और श्री राम के अनन्य उपासक

अंजनी पुत्र हनुमान को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता माना जाता है। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा के लिए महादेव ने एकादशी रूद्र को ही हनुमान के रूप में अवतरित किया था। सनातन संस्कृति के उपासकों के लिए हनुमान जयंती का विशेष रूप से महत्व है। भगवान हनुमान के दिव्य गुण इस उत्सव का मुख्य आकर्षण हैं। हनुमान निःस्वार्थ भक्ति, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक हैं। हनुमान जी का दैवी गुणों से परिपूर्ण आध्यात्मिक उदात्त चरित्र हमें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों पर विजय पाने और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए भक्ति, विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। पवनसुत, मंगल मूर्ति, संकट मोचन आदि कहे जाने वाले श्री हनुमान के नाम के स्मरण मात्र से ही भक्तों के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। हनुमान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 'मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। अर्थात भगवान हनुमान मन से भी अधिक भगवान, वायु के समान तीव्र वेग वाले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, बुद्धिमानों में वरिष्ठ, वायु पुत्र, वानर समूह के मुख्य नेता, भगवान श्री राम के अन्य दूत हनुमान का सान्निध्य प्राप्त हो। तुलसीदास ने हनुमान को गुणों का भंडार माना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हनुमान अन्य सेवक एवं उपासक थे। वे मानसा, वाचा, कर्मणा प्रभु श्री राम को समर्पित थे। बाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने युद्ध में साथ देने वाले सभी वीरों को उपहार दिया, जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने याचना करते हुए प्रभु राम से कहा कि -हे राम, इस लोक पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक मेरे प्राण शरीर में बसे रहे। हनुमान की याचना पर श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि - 'हे कपि श्रेष्ठ इस संसार में जब तक राम कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी'। सात्विक अंतकरण एवं एकाग्रता के साथ की गई हनुमान की उपासना से हमारे जीवन में व्याप्त समस्त नकारात्मक आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। शरीर तथा मन में व्याप्त रोगों का हनुमान के स्मरण से विनाश हो जाता है। हनुमान आध्यात्मिक विभूतियों से परिपूर्ण महान पराक्रमी योद्धा हैं। हनुमान की भक्ति मनुष्य को पराक्रम शारीरिक तथा मानसिक बल प्रदान करने वाली मानी गई है। वे मनुष्य और देवता के बीच वह सेतु हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यदि चेतना जागृत हो जाती है तो शारीरिक सीमाएं अर्थहीन हो जाती हैं। वह ब्रह्म की साक्षात क्रियात्मक शक्ति हैं। हनुमान जी ब्रह्मांड के वह पार्टिकल हैं जिनमें साक्षात परमात्मा की स्पीड और पावर विद्यमान है। उनकी अष्ट सिद्धियां वास्तव में पदार्थ और ऊर्जा पर नियंत्रण की प्रतीक हैं। अणिमा सिद्धि परमाणु स्तर पर संकुचित होने की क्षमता है, जबकि महिमा ब्रह्मांडीय विस्तार का विज्ञान है। वह क्वांटम फिजिक्स के मास डिसेंटी और स्पेस टाइम के सिद्धांतों को चुनौती देने वाली सर्वोच्च तकनीक हैं। वज्र के समान उनका शरीर उनकी कोशिकाओं का घनत्व सामान्य जैविक ढांचे से भिन्न था, जो उन्हें वायु की गति से उड़ाने और गुरुत्वाकर्षण को भी बेअसर करने की शक्ति प्रदान करता था। हनुमान का प्रक्रम किसी सेवा का मोहताज नहीं था, वह स्वयं वन मैन आर्मी थे। समुद्र लांघना हनुमान जी की शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उनके संकल्प की विजय थी। वे उत्कृष्ट वाणी के स्वामी और ऋग्वेद के प्रकांड विद्वान थे। जब ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान प्रथम बार प्रभु श्री राम से मिले तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके शास्त्र सम्मत संवाद किया। उनकी व्याकरण और शुद्ध उच्चारण से परिपूर्ण वाणी को सुनकर भगवान श्री राम भी चकित रह गए। किष्किंधा कांड में हनुमान के व्यक्तित्व की उत्कृष्टता लक्ष्मण को बताते हुए प्रभु राम कहते हैं कि - 'जिसने ऋग्वेद की शिक्षा न ली हो, यजुर्वेद का अभ्यास न किया हो। सामवेद का जिसे ज्ञान न हो, वह इतनी परिष्कृत भाषा में संवाद नहीं कर सकता।' निश्चय ही हनुमान ने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार स्वाध्याय किया है। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी वाचस्पति थे। हनुमान की भक्ति अभय प्रदान करती है। मानसिक पटल पर विद्यमान भय, चिंता, रोग, कष्ट को दूर करके मंगल प्रदान करने वाली कही गई है।

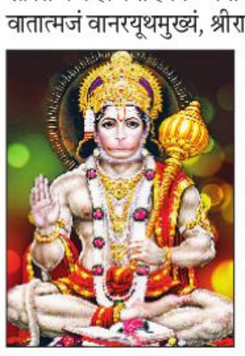

(लेखक आध्यात्मिक चिंतक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

यह मन का कमाल है

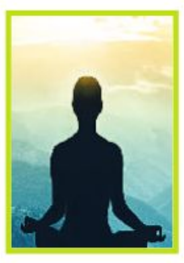

संकलित
दर्शन

सिर्फ अनुभव करने से ही यह आएगी। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन से कोई चीज हटाने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। दाढ़ी बनाते समय बहुत से लोग अपना चेहरा काट लेते हैं, क्योंकि वे त्वचा से अधिक निकट दाढ़ी काटना चाहते हैं और रेजर उनकी योजना से अधिक निकट चला जाता है। यह मन का कमाल है। जो चीजें आप चाहते हैं, उनका प्रतिरोध करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि वे आपके अंदर तीव्रता से व्यक्त होंगी। अगर आप कोई चीज नहीं चाहते हैं कि वह हो, तो उसे न होने देने की कोशिश कीजिए। तब वह जरूर होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आप एक ऐसी अवस्था में हैं, जहां आप अपने मन को पहले गियर में डालना चाहते हैं और वह रिवर्स गियर में चला जाता है। चीजें करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए कि अभी मन उसी तरह है, आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं, तो सिर्फ वही चीज घटित होगी। इसलिए मन का प्रतिरोध मन कीजिए, अपने मन की खोज कीजिए। आपका मन कैसे कार्य करता है, उसे समझना किसी बौद्धिक विश्लेषण से नहीं आता। इसकी खोज करनी पड़ती है। अपने शरीर को एक मुद्रा में रखिए और ध्यान दीजिए कि आपका मन किस विशेष ढंग से काम करता है। अपने शरीर को दूसरी मुद्रा में रखिए और ध्यान दीजिए कि आपका मन एक अलग ढंग से काम करता है। अगर आप एक आसन में बैठकर ठीक ढंग से सांस लेते हैं, तो मन विभिन्न अवस्थाओं में चला जाएगा।

मूर्ख साधू और ठग

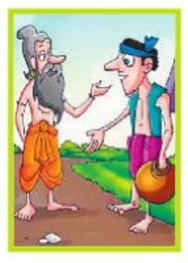

संकलित
प्रेरणा

किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधू रहता था। उसे अपने भक्तों से दान में तरह- तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधू ने काफी धन जमा कर लिया था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। ठग हमेशा साधू का पीछा किया करता था, लेकिन साधू उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। उसने साधू से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधू तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधू के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था। एक दिन साधू को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया, साधू ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधू अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधू ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कम्बल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधू नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चम्पत हो गया। शिक्षा- किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।

अंतर्मन

आज की पाती

डिजिटल जनगणना का महत्त्व

भारत में होने जा रही आगामी जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होने वाली है। यह पहली बार होगा जब जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिससे न केवल प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, बल्कि आंकड़ों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। पारंपरिक कागज आधारित प्रणाली के स्थान पर अब मोबाइल एप, वेब पोर्टल और रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग का उपयोग किया जाएगा। इससे जनगणना कर्मचारियों द्वारा एकत्रित जानकारी सीधे सर्वर पर पहुंचेगी, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इस डिजिटल जनगणना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। इससे डेटा अधिक व्यवस्थित और विश्लेषण योग्य बनेगा।

- मदन जोशी, जगदलपुर

ट्रेंड

स्वच्छता रैंकिंग

लखनऊ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन एवं ग्रीन सिटी-ग्रीन सिटी की सिद्धि हेतु आज लखनऊ में पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा से संचालित 250 इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में देश के शीर्ष तीन शहरों में शामिल हुआ है।
- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

लिएंडर पेस का स्वागत

भाजपा परिवार में शामिल होने के उपरांत, टेनिस जगत के प्रतिष्ठित खिलाड़ी एवं ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस ने आज शिष्टाचार भेंट की। खेल के क्षेत्र में आपका व्यापक अनुभव और राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा निश्चित रूप से समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

बीजेपी को हार का डर

तीन महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 145 एफआईआर हो चुकी है। बीजेपी गुजरात में हार के डर से हमारी पार्टी से बुरी तरह से बौखलायी हुई है। आज हमारे राज्य अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

ज़रूरी वस्तुएं महंगी

मोदी सरकार ने देश की सामरिक और आर्थिक नीति तहस-नहस कर दी है। इसका सीधा खामियाजा 140 करोड़ भारतीयों को उठाना पड़ रहा है। आज से रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे।
- मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

ईरान को व्यवस्थित तरीके से कुचला जा रहा है : नेतन्याहू

ईरान के खिलाफ युद्ध में 'बड़ी उपलब्धियों' की प्रशंसा करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल-अमेरिका का संयुक्त अभियान इस्लामी शासन को 'व्यवस्थित तरीके से कुचल रहा है 'और इस यहूदी राष्ट्र के सामने मौजूद अस्तित्वगत खतरों को खत्म कर रहा है। यहूदी पर्व 'पेसाच' (पासओवर) से पहले हिब्रू में राष्ट्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि 'देर-सवेर 'ईरानी शासन गिर जाएगा और इजराइल, तेहरान से उत्पन्न साझा खतरे के खिलाफ 'क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ नए गठबंधन' बना रहा है। इजराइली प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन संक्षेप में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 'जल्द ही मैं आपको इन महत्वपूर्ण गठबंधनों के बारे में और बता पाऊंगा।' नेतन्याहू ने कहा, 'स्वतंत्रता पर्व की पूर्व संध्या पर इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत है। पूरी दुनिया ईरान के दुष्ट शासन के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी दहाड़ सुन रही है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हमने अपार उपलब्धियां हासिल की हैं।' यह संबोधन ऐसे समय में आया जब देश लेबनान में जमीनी अभियान के दौरान चार सैनिकों की मौत पर शोक मना रहा है।

ऑफ बीट

जैतून के पत्ते का अर्क भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा

जैतून में कई स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व भी होते हैं। अब जैतून के पत्तों के स्वास्थ्य लाभ के बारे में प्रमाण बढ़ रहे हैं जिनमें हाल में किए गए एक अध्ययन से प्राप्त साक्ष्य भी शामिल हैं। जैतून के पत्तों को पारंपरिक रूप से भूमध्य सागर क्षेत्र में चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बुखार एवं मलेरिया के इलाज में यह चाय पी जाती है। जैतून की पत्तियों में 'ओलेयूरोपिन' नामक एक प्रकार का 'एंटीऑक्सीडेंट' उच्च मात्रा में पाया जाता है। जैतून और जैतून के तेल में भी यह पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। आम तौर पर, पत्ती जितनी हरी होती है (कम पीली) उसमें उतना ही अधिक 'ओलेरोपिन' होता है। जैतून के पत्तों में अन्य 'एंटीऑक्सीडेंट' भी होते हैं जैसे 'हाइड्रॉक्सीटायरोसोल', 'ल्यूटोलिन', 'एपिजेनिन' और 'वर्बास्कोसाइड'। 'एंटीऑक्सीडेंट' शरीर में 'ऑक्सीडेटिव' तनाव को कम करते हैं। 'ऑक्सीडेटिव' तनाव हमारे डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड), कोशिका झिल्ली और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत

यह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के मजबूत कदम का सबूत है कि विगत फरवरी में गुजरात के जिस साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया था, वहीं प्रधानमंत्री ने ऐसे दूसरे प्लांट का हाल ही में उद्घाटन किया है. इसे केन्स सेमीकॉन ने विकसित किया है और यहां अब व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है. आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्लांट में चौदह महीने के भीतर उत्पादन शुरू होने को बड़ी उपलब्धि बताया. इस प्लांट को चिप मैन्युफैक्चरिंग मिशन में बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है. इस प्लांट में एडवांस्ड इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल बनाये जायेंगे, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल डिवाइस में किया जाता है. आने वाले समय में विद्युत चालित वाहन, यानी इवी सेक्टर तथा स्मार्ट डिवाइस इंडस्ट्री को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. देश की इस दूसरी ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर यूनिट को भी 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत विकसित किया गया है. प्रधानमंत्री ने इसके उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह प्लांट वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को मजबूत बनायेगा. इस प्लांट में तैयार होने वाले उत्पादों का बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए पहले ही बुक हो चुका है, जिससे 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' का संदेश वैश्विक स्तर पर गूंजेगा. यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ-साथ भारत दुनिया को चिप आपूर्ति करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने जा रहा है. प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि इस दशक में महामारी, संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन बाधाओं ने दुनिया के खासकर चिप, रेअर अर्थ मिनरल्स और ऊर्जा क्षेत्र पर बड़ा असर डाला है. ऐसे समय में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना वैश्विक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सच तो यह है कि कोविड के समय से ही सरकार ने देश को सेमीकंडक्टर का नया केंद्र बनाने का लक्ष्य तय कर लिया था. प्रधानमंत्री ने ठीक ही रेखांकित किया कि 2021 में शुरू किया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन केवल एक औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास का प्रतीक है. इस मिशन के तहत देश के छह राज्यों में दस बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है. उद्योग जगत के मुताबिक, भारत में सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का है, जिसके इस दशक तक लगभग नौ लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. यह वृद्धि इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को ही दर्शाती है.

गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर के दूसरे प्लांट की शुरुआत इस क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति का तो सूचक है ही, भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ इसके निर्यात का भी बड़ा खिलाड़ी बनना है.

राजनीति को बदल देगा महिला आरक्षण

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार
neerja_chowdhury@yahoo.com

केंद्र सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की इच्छा चाहे जिस भी मकसद से जतायी हो, लेकिन अगर महिला आरक्षण जल्दी लागू हो जाता है, तो यह भारतीय राजनीति के लिए शुभ होगा. पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण के जरिये हमने देखा है कि किस तरह महिलाओं में आत्मविश्वास आया है. संसद में महिला आरक्षण लागू करने का सपना पुराना है. यह सपना जल्दी साकार होता है, तो नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी.

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने अचानक नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) के तहत संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन से संबंधित तैयारी शुरू की. उसने इसके लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है. बताया यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जायेगा. इसमें कई सारे कदम उठाये जाने की बात कही गयी है. जैसे-संविधान संशोधन से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाने वाली हैं, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेंगी. इसके अलावा, सरकार ने परिसीमन को 2026-27 के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर कराने का फैसला किया है. इसके पीछे तर्क यह है कि नयी जनगणना होने और उसका आंकड़ा आने में इतना समय लग जायेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक परिसीमन नहीं हो पायेगा. एक और प्रस्ताव यह है कि संशोधन से राज्यों में सीटों की वृद्धि का अनुपात नहीं बदलेगा. जबकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि कम जनसंख्या होने के कारण दक्षिण भारत के राज्यों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

इस कारण दक्षिण के नेता क्षुब्ध थे. लेकिन नये प्रस्ताव के मुताबिक, परिसीमन से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर अगर 120 हो जायेंगी, तो तमिलनाडु में भी लोकसभा सीटों में वृद्धि इसी अनुपात में होगी. परिसीमन के मुद्दे पर लंबे समय से उत्तर बनाम दक्षिण का न सिर्फ द्वंद्व छिड़ा हुआ था, बल्कि दक्षिण के राज्यों को लगता था कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने का उन्हें दंड दिया जा रहा है, जबकि ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारत के राज्यों को परिसीमन के जरिये बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा. लेकिन नये प्रस्ताव में यह आशंका दूर हो गयी है. दरअसल, परिसीमन मुद्दे पर एनडीए में भाजपा के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू तक का रवैया नाराजगी भरा था, और वैसे में, दक्षिण भारत में भाजपा के लिए अपना विस्तार कर पाना कठिन होता, इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर दक्षिण की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश है. दरअसल, 19 सितंबर, 2023 को जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) संसद से पारित हुआ था, तब इसे जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन और 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की घोषणा की गयी थी. लेकिन अब सरकार ये दोनों कार्य संविधान संशोधन के जरिये करना चाहती है. संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है. इसके अलावा, आधे राज्यों को इसे पारित कराना होगा. बेशक मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसे पारित कराना आसान नहीं है. लेकिन विपक्षी दल महिला आरक्षण का विरोध भी नहीं कर पायेंगे.

अगर संसद के विशेष सत्र में इस पर मुहर लग जाती है, तो फिर परिसीमन आयोग बैठेगा, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले वर्ष तक महिला आरक्षण लागू हो जायेगा. हालांकि यह सवाल उठाया जा रहा है कि महिला आरक्षण को अगर 2011 की जनगणना और परिसीमन के आंकड़ों पर ही लागू करना था, तो इसे पहले भी लाया जा सकता था. लेकिन सरकार अब अचानक यह कदम उठाने जा रही है, तो कुछ सोच-समझकर ही उठा रही होगी. दरअसल, अगले साल तीन राज्यों-उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ये चुनाव, जाहिर है कि भाजपा और एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं. अगर अगले साल तक महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो इन तीनों राज्यों में भाजपा को चुनावी लाभ मिलना तय है. फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव है, और काफी जटिल भी है. कई प्रश्नों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं. जैसे परिसीमन के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो जायेंगी. लेकिन ये सीटें किस तरह आरक्षित होंगी, इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है. सवाल यह भी है कि परिसीमन जब 2011 की जनगणना के आधार पर ही होना है, तो फिर 2026-27 की जनगणना के आधार पर नये सिरे से परिसीमन कराने का क्या औचित्य होगा. फिलहाल लगता है कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए सरकार ने यह दांव चला है. दरअसल युद्ध का लंबा असर रहने वाला है, और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहेगा. इस कारण आय से लेकर रोजगार तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में, महिला आरक्षण लागू कर सरकार महिलाओं का एकमुश्त वोट अपने साथ होने की उम्मीद कर सकती है. इस मामले में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए. एक यह कि चुनावों में महिला वोटरों की भूमिका अब पुरुष वोटरों के बराबर या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी है. इसके अलावा, महिलाओं का बड़ा वर्ग पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ है. ऐसे में, अगर मान लें कि युद्ध के असर से युवा वर्ग सरकार से नाराज हो जाये, तो उसका चुनावी नतीजे पर बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है. इसके अलावा, परिसीमन चूंकि 2011 के आंकड़े पर ही होना है, ऐसे में, दक्षिण भारत के नेता खुश हैं, और वहां भाजपा को नाराजगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

लेकिन इस कदम को सिर्फ चुनावी राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं होगा. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो यह भारतीय राजनीति की एक बड़ी उपलब्धि होगा. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महिला आरक्षण के कारण जिन पुरुष राजनेताओं को अपनी सीटें गंवानी पड़ेंगी, वे आरक्षित सीटों पर अपनी महिला रिश्तेदारों को बिठा सकते हैं. और बहुत संभव है कि इसे राजनीतिक बुराई के तौर पर ही देखा जाये. लेकिन पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण लागू होने के बाद हमने देखा है कि भले ही अनेक जगहों पर वास्तविक ताकत अब भी महिला प्रमुखों के पतियों के पास ही हो, लेकिन महिला आरक्षण के कारण बड़ी संख्या में स्त्रियों में जागृति और आत्मविश्वास की भावना आयी है. और अब वे राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में अपनी जगह लेने के लिए तैयार हैं. इस लिहाज से महिला आरक्षण भारतीय राजनीति को बदलने के साथ-साथ उसमें नयी ऊर्जा भर सकता है. संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या बढ़ने पर वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आजीविका जैसे मुद्दों पर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी, जिसका समाज पर निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से पार जा सकती है महंगाई

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार
satish5249@gmail.com

सरकार ने 25 मार्च को तय किया कि महंगाई की सीमा चार प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक या दो प्रतिशत कम रहेगी. पर मौजूदा परिदृश्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महंगाई सरकार द्वारा निर्धारित दायरे को आगामी महीनों में पार कर सकती है, क्योंकि भारत दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं का आयात दूसरे देशों से करता है.

ईरान के अमेरिका-इस्राइल के साथ चल रहे संघर्ष के बावजूद, सरकार ने 25 मार्च को तय किया कि महंगाई की सीमा चार प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक या दो प्रतिशत कम रहेगी. हालांकि, मौजूदा परिदृश्य में इस लक्ष्य को हासिल करना सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आसान नहीं होगा. बहरहाल, यह अधिसूचना, अर्थात लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआइटी) ढांचा एक अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक प्रभावी रहेगा. इस ढांचे की हर पांच वर्षों में समीक्षा की जाती है. पिछली बार इसे मार्च, 2021 से मार्च, 2026 तक के लिए लागू किया गया था. भारत ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद 2016 में एफआइटी ढांचे को अपनाया था. फिलहाल दुनिया के तीन विकसित देशों सहित 26 देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया है.

इस संकल्पना में मूल्य स्थिरता को मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य बताया गया है. इस व्यवस्था के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना की गयी थी, जिसमें रिजर्व बैंक के तीन अधिकारी और तीन बाहरी सदस्य होते हैं और मौद्रिक नीति की ब्याज दर को मतदान के बहुमत से तय करते हैं. महंगाई का स्तर मांग और आपूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है. जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है, तो वे अधिक वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है. यदि आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है, तो कीमतें बढ़ेंगी. इसके विपरीत, जब मांग कम होती है और आपूर्ति अधिक होती है, तो महंगाई घट जाती है. वर्तमान में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिस कारण भारत में भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. इनकी कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा रूस, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई, कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि से आयात करता है.

विदित हो कि सरकार और रिजर्व बैंक ने महंगाई की निर्धारित सीमा को बनाये रखने का निर्णय लिया है, यह मानते हुए कि आधार वर्ष में बदलाव से इस सीमा पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और यह निर्धारित स्तर पर कायम रहेगी. बारह फरवरी से सरकार ने महंगाई का मापन आधार 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है. नये आधार वर्ष में कई पुरानी वस्तुओं को उनकी अप्रासंगिकता के कारण हटा दिया गया है, और नयी वस्तुओं को जोड़ा गया है. साथ ही, खाद्य वस्तुओं का भार घटाया गया है और कुछ गैर खाद्य वस्तुओं का भार जोड़ दिया गया है, जिनका आमतौर पर महंगाई पर प्रभाव पड़ता है. इसलिए माना जा रहा है कि लंबे समय तक युद्ध के चलते महंगाई सरकार द्वारा निर्धारित सीमा चार प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक या दो प्रतिशत कम के स्तर पर अक्षुण्ण बनी रहेगी. मुद्रास्फीति को मापने के लिए ऐसी वस्तुएं और सेवाएं चुनी जाती हैं, जो इसकी वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देती हैं. इन वस्तुओं को उनके महत्व के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) में वजन दिया जाता है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) हर महीने खुदरा महंगाई का आकलन सीपीआइ सूचकांक से करता है, जिसमें वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, जिनका रोजमर्रा के जीवन में अधिक उपयोग होता है. नये आधार वर्ष के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं और सेवाएं भी जोड़ी गयी हैं, जिन पर अब लोग अधिक खर्च कर रहे हैं. जैसे, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ईयरफोन, फिटनेस बैंड आदि. नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसी ओटीटी सेवाएं, इ-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हवाई टिकट, एप आधारित टैक्सी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं, शॉपिंग की कीमतें, और ग्रामीण इलाकों में मकान के किराये भी अब सूचकांक में शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद भारत में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है. वहीं, होटल-रेस्टोरेंट ग्राहक से सरकारी टैक्स के साथ एलपीजी चार्ज भी वसूल रहे हैं. हालांकि, सरकार ने इस पर रोक लगायी है, पर जमीनी स्तर पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की है. पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये कर दी गयी है, जबकि डीजल पर 10 रुपये से शून्य कर दी गयी है. अमेरिका और इस्राइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गये हैं. इससे तेल कंपनियों को 30 रुपये प्रति लीटर तक घाटा हो रहा है. आमतौर पर जब तेल की कीमत बढ़ती है, तो परिवहन की लागत बढ़ती है, साथ ही वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा होता है. उल्लेखनीय है कि भारत दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं का आयात दूसरे देशों से करता है. इसलिए, नये आधार वर्ष में महंगाई की गणना करने वाली वस्तुओं में बदलाव करने के बाद भी महंगाई में अभूतपूर्व इजाफा होने की प्रबल आशंका है और मौजूदा परिदृश्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महंगाई सरकार द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक या दो प्रतिशत कम के दायरे को आगामी महीनों में पार कर सकती है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

रिपब्लिकन पार्टी की अगली पीढ़ी की राजनीति तय कर सकता है ईरान युद्ध

यह लगभग तय माना जा रहा है कि ईरान युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विरासत में अहम रोल निभायेगा. लेकिन उनकी टीम के दो महत्वपूर्ण चेहरों- उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो- की राजनीतिक किस्मत भी इसी संघर्ष से जुड़ती नजर आ रही है. दोनों राष्ट्रपति ट्रंप के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं. यही वजह है कि ईरान पर कूटनीतिक बातचीत के केंद्र में भी यही दोनों हैं. रिपब्लिकन पार्टी पहले से ही ट्रंप के बाद के दौर की चर्चा में जुट गयी है. हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी का मूड भांपने वाले एक पोल में मार्को रूबियो की तुलना में जेडी वेंस को बढ़त मिली. हालांकि, अभी राष्ट्रपति चुनाव में दो वर्ष से ज्यादा का समय है. पर माना जा रहा है कि ईरान युद्ध का निष्कर्ष इन दो वर्षों में रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति को काफी प्रभावित करेगा. जेडी वेंस फिलहाल ईरान युद्ध को लेकर बेहद सतर्क रुख अपना रहे हैं. वे लंबे समय से विदेशी सैन्य हस्तक्षेपों को लेकर संशय दिखाते रहे हैं और यही सोच उनकी हालिया टिप्पणियों में भी झलकती है. दूसरी ओर रूबियो खुलकर ट्रंप की रणनीति का बचाव कर रहे हैं और स्वयं को सरकारी कैंपेनिंग का सबसे मुखर चेहरा बना चुके हैं. रिपब्लिकन रणनीतिकारों का मानना है कि युद्ध का परिणाम दोनों नेताओं का भविष्य तय करने में अहम हो सकता है. यदि संघर्ष जल्दी खत्म होता है और इसे कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जाता है, तो रूबियो की छवि मजबूत हो सकती है. वहीं लंबा युद्ध वेंस को यह कहने की गुंजाइश देगा कि वे ट्रंप समर्थक मतदाताओं की युद्ध विरोधी भावना के ज्यादा नजदीक खड़े हैं. इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से खुली असहमति दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. फैसला जो भी हो, यह साफ है कि ईरान युद्ध अब केवल विदेश नीति का मामला नहीं रह गया है. यह रिपब्लिकन पार्टी की अगली पीढ़ी की राजनीति तय करने वाला मोड़ बन चुका है.

-अविनाश द्विवेदी

बोधि वृक्ष

वर्तमान में रहना

वर्तमान क्षण को महसूस करें और आनंद लें तथा शांति का अनुभव करें. आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं बस चलते रहें, और कुछ करने की कोशिश न करें. यह आसान लगता है, पर है नहीं. ऐसा नजर आता है कि हम ही सब कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं. जब आप चल रहे होते हैं, तो आपका मन हजार अन्य बातें सोच रहा होता है. हर कदम महसूस कर के बढ़ायें. केवल चलें. चलते रहें. जिस क्षण आप अपनी सजगता को एक यांत्रिक आदत बना देते हैं, वह रुक जाती है, क्योंकि कोई भी यांत्रिक आदत आपकी मूर्च्छा पर ही अपना दाना-पानी चलाती है. इच्छाशक्ति से काम नहीं चलेगा. जागरूकता ही काम आयेगी. फर्क याद रखें- इच्छाशक्ति में आप आदत के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, और यदि आप आदत से लड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि आपने उसे स्वीकार कर लिया है. जब मैं आपको होश के साथ ऐसा करने को कहता हूं, तो मेरा अर्थ होता है, उसके साथ लड़ें नहीं. उसे अपना पूरा समर्थन दें, उसके 'विरुद्ध' न हों. यदि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो अपने चलने को अपना पूरा समर्थन दें. उसके साथ एक हो जायें, जो भी घटित हो रहा है, उसके बारे में जागरूक रहें. हर क्षण को होशपूर्वक महसूस करें. उसी क्षण में रहें, अपने मन को कहीं और जाने की अनुमति न दें. यदि मन पुरानी आदतों के कारण विचरण करता है, तो इसे फिर से वापस ले आयें. निराश न हों. यदि मन चलायमान ही रहता है, तो ऐसा मत कहें कि यह असंभव है. अपने मन को फिर एक बार लौटा के लायें. देर-सबेर जब आप वर्तमान के अहसास का स्वाद चखेंगे, आप कुछ क्षणों को महसूस करना शुरू कर देंगे. और एक बार जब आप वर्तमान को महसूस करने लगते हैं, तब आप अस्तित्व के दरवाजे के निकट होते हैं. आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं. इस आयाम में शांति का मतलब है अतीत या भविष्य में मस्तिष्क की कोई हलचल नहीं. कोई खलबली नहीं. केवल वर्तमान में रहिए. जल्द ही एक ऐसा समय आयेगा, जब आप वर्तमान में रहते हुए पूरा दिन गुजार सकते हैं. और जैसे ही एक बार ऐसा होगा, आप जान जायेंगे कि स्थिरता क्या चीज है.

-ओशो

कुछ अलग

नेम प्लेट पर बहू-बेटियों के नाम

सरस्वती रमेश
टिप्पणीकार
saramesh17@gmail.com

हरियाणा से एक छोटी-सी खबर आयी थी. अंबाला के खेड़ागनी गांव में घरों के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर अब पुरुष मुखिया के नाम की बजाय घर की बहू-बेटियों का नाम लिखा जा रहा है. सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी डिग्रियां भी लिखी जा रही हैं. महिला ग्राम सभा की इस पहल से बेटियों को निश्चित ही सुकून महसूस हो रहा होगा. नेम प्लेट पर अपना नाम देख बेटियों को अहसास हो रहा होगा कि जिस घर में उनका जन्म हुआ, उस घर पर उनका भी अधिकार है. यूं तो कानूनन यह कोई नयी बात नहीं है. कानून पिता की संपत्ति में बेटी को भी अधिकार देता है. लेकिन हमारे यहां ऐसी परंपरा नहीं है. इसी कारण शादी के साथ ही बेटियों को पराया मान लिया जाता है.

हमारे यहां की अधिकतर परंपराएं हमारे पूर्वजों की बनायी हुई हैं. हम उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते आये हैं. उन परंपराओं के साथ जीते आये हैं. परंपराओं को अपनी पहचान भी मान बैठते हैं. लेकिन समय के साथ उनमें कुछ बदलाव भी आते रहते हैं. समय की मांग कह कर हम उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं. दरअसल, सभ्यता के विकास के साथ कुछ परंपराएं जब बोझ लगने लगीं, तो उन्हें बदलने की दरकार महसूस हुई. उन्हें बदला भी गया. कुछ को सिरे से खत्म कर दिया गया. बेटियों को पराया धन मानने की भी परंपरा रही है. बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की, उसके ससुराल को उसका असली घर और उसे ससुराल वालों की अमानत माना जाता है. इस परंपरा ने बेटी-बेटे के भेद को जन्म दिया. महिलाओं का जीवन भी कष्टकर बना दिया. शादी के बाद ससुराल में किसी कारणवश प्रताड़ित हुई बेटियां चाहकर भी पुराने घर लौट नहीं पातीं. मतलब, पराया धन मानने की परंपरा ने उन्हें कहीं का नहीं रहने दिया. मायके वालों ने ससुराल को उनका घर कहा और ससुराल वालों ने मायके को. यह स्थिति आज भी बनी हुई है. लेकिन अब वक्त आ गया है बोझ बन गयी इस गलत परंपरा को बदलने का. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. शहर में रहने वाले शिक्षित परिवार अपनी संपत्ति में बेटी-बेटा दोनों को बराबर का हिस्सा दे रहे हैं. दोनों की परवरिश और शिक्षा में भी कोई भेद नहीं किया जा रहा है.

हरियाणा के खेड़ागनी गांव में आया बदलाव परंपरा बदलने की कड़ी का ही हिस्सा है. यह बदलाव प्रेरणादायी है. बदलाव का ही परिणाम है कि उस गांव के लोग अपनी बेटियों को ऊंची से ऊंची डिग्री दिलाने की कोशिश करने लगे हैं, ताकि उनके दरवाजे पर लगी नेम प्लेट में उसे अंकित कर वे गर्व महसूस कर सकें. यह सब समाज में सकारात्मक बदलाव का सूचक है. ऐसी मानुषी परंपराएं हर जगह फैलनी चाहिए.

आपके पत्र

चरित्रवान होना जरूरी है

प्रभात खबर के संपादकीय पेज पर 'बोधि वृक्ष' कॉलम में शीर्षक 'चरित्र रूपी धन' लेख पढ़कर अच्छा लगा. इस लेख के जरिये हमने चरित्र की अहमियत जानी. कहा भी गया है कि 'इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र' किसी पहचान के मोहताज नहीं होते. यदि आपके पास चरित्र रूपी धन है, तो आप अपने दम पर सब कुछ पा सकते हैं. पर उसी चरित्र को खोने के बाद आप सब कुछ खो सकते हैं. आज समाज, परिवार और देश को चरित्रवान लोगों की अत्यंत जरूरत है, तभी हम विकसित देश बन पायेंगे.

जीतेंद्र कुमार, रांची

भीड़ में धक्का-मुक्की से बचें

बिहार के नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर में दर्शन करने गये श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू होने और भगदड़ मचने से जहां कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गयी, वहीं कई घायल हो गये. किसी विशेष अवसर पर होने वाले आयोजन के बारे में स्थानीय प्रशासन को पता होना चाहिए कि कब, कहां, कितनी और कैसी व्यवस्था करनी है. व्यवस्था के चाक-चौबंद होने पर भगदड़ मचने का प्रश्न ही नहीं उठता है. आम जन को भी भीड़ में धक्का-मुक्की करने से बचना चाहिए और एक-दूसरे को रास्ता देते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ फैक्स करें : 0651-2544006 ■ मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

क्विक बाइट्स

केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री से मिले संजय सेठ

रांची. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें प्रस्तावित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की जानकारी दी गयी. साथ ही महोत्सव में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप शामिल होने का आमंत्रण दिया गया.

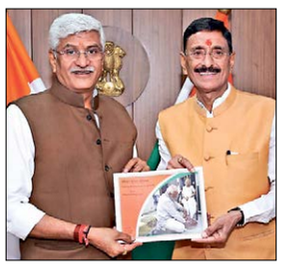

अंबा ने राज्यपाल को विष्णुगढ़ घटना की जानकारी दी

रांची. राज्यपाल संतोष गंगवार से बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की. उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में विगत दिनों बच्ची के साथ हुई घटना से अवगत कराया. साथ ही अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किये जाने की बात कही. राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच सीबीआइ से कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा और पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की.

विष्णुगढ़ मामले में आयोग ने जांच समिति बनायी

रांची. राष्ट्रीय महिला आयोग ने विष्णुगढ़ में बच्ची के साथ हुई घटना पर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. यह समिति दो अप्रैल को घटनास्थल का दौरा करेगी. टीम तथ्यों का संकलन कर प्रशासन की ओर से अब तक की गयी कार्रवाई का आकलन करेगी. श्रीमती रहाटकर ने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा. राज्य प्रशासन को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं.

असम में चुनाव प्रचार के लिए डिब्रूगढ़ गये बाबूलाल

रांची. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी असम विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को डिब्रूगढ़ पहुंचे. दो अप्रैल को श्री मरांडी सुबह 10 बजे चिन्नमरा इस्टेट स्थित टीटाबार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे संतक टी इस्टेट पूजा मैदान में नजीरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में सभा कर समर्थन मांगेंगे.

भाजपा सरकार ने असम में व्यवस्था चौपट कर दी : बंधु

रांची. असम के नाजिरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व असम विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक बंधु तिर्की शामिल हुए. श्री तिर्की ने कहा कि असम की जनता हिमंता सरकार को सत्ता से हटाना चाहती है. भाजपा सरकार ने यहां पूरी व्यवस्था चौपट कर दी है.

अपराध व गो तस्करी को लेकर डीजीपी को दिया ज्ञापन

रांची. झारखंड में बढ़ते अपराध, गो तस्करी और सनातन धर्म के पर्व-त्योहारों के दौरान शोभायात्रा पर हो रहे हमले के विरोध में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला. सदस्यों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा. भाजपा नेताओं ने कहा कि रामनवमी, सरहुल और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में शोभायात्राओं पर पथराव की वारदातें आम हो गयी हैं. वहीं, खूंटी के मुरहू में रामनवमी जुलूस पर पथराव का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला सुनियोजित था. उन्होंने मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने और निर्दोष को रिहा करने की मांग की.प्रतिनिधिमंडल में राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, बालमुकुंद सहाय, नवीन जायसवाल व सीमा शर्मा शामिल थे.

राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट : भाजपा

रांची. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान विधि व्यवस्था सुधारने पर नहीं है. राज्य में बालू, कोयला और लोहा माफियाओं का खेल सरकार के संरक्षण में चल रहा है.

जनता में भय पैदा कर रही है भाजपा : कांग्रेस

रांची. प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने और जनता में भय पैदा करने का षड्यंत्र रच रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा एनसीआरबी के तथ्यों की बाजीगरी कर झूठा नैरेटिव बना रही है. उन्होंने कहा कि विष्णुगढ़ घटना के आरोपियों को पुलिस ढूंढ़ निकालेगी.

विधानसभा में 25 कमेटियां गठित, मनोज व कल्पना को अहम जिम्मेवारी

ब्यूरो प्रमुख, रांची

झारखंड विधानसभा ने कमेटियों का गठन कर दिया है. स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने 25 अलग-अलग कमेटियों के गठन पर अपनी सहमति दे दी है. भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है. गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को महिला व बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है. वहीं, विधानसभा की महत्वपूर्ण विशेषाधिकार कमेटी के पदेन सभापति स्पीकर रबींद्र नाथ महतो होंगे. एससी-एसटी, अल्पसंख्यक व पिछड़ा कमेटी का जिम्मा झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को दिया गया है. कांग्रेस विधायक डॉ रामेश्वर उरांव को आंतरिक संसाधन व केंद्रीय सहायता समिति का सभापति बनाया गया है. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को जिला परिषद व पंचायती राज समिति का जिम्मा दिया गया है.

इस प्रकार है कमेटी

कमेटी	सभापति
नियम समिति	स्पीकर रबींद्र नाथ महतो
विशेषाधिकार समिति	स्पीकर रबींद्र नाथ महतो
याचिका समिति	स्पीकर रबींद्र नाथ महतो
लोकलेखा समिति	मनोज यादव
प्राक्कलन समिति	हेमलाल मुर्मू
सहकारी उपक्रम समिति	नीरल पूर्ति
प्रत्यायुक्त विधान समिति	सरयू राय
एससी-एसटी, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग समिति	स्टीफन मरांडी
महिला व बाल विकास समिति	कल्पना सोरेन
आवास समिति	दशरथ गगराई
प्रश्न व ध्यानाकर्षण समिति	बसंत सोरेन
सरकारी आश्वासन समिति	अरूप चटर्जी
शून्य काल समिति	भूषण तिर्की
विधायक निधि अनुश्रवण निधि	सीपी सिंह
पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण समिति	उदय शंकर सिंह
जिला परिषद व पंचायती राज समिति	प्रदीप यादव
गैर सरकारी संकल्प समिति	प्रकाश राम
पुस्तकालय विकास समिति	सत्येंद्र नाथ तिवारी
अनागत प्रश्न समिति	सुरेश पासवान
निवेदन समिति	उमाकांत रजक
सदाचार समिति	रामचंद्र सिंह
युवा कल्याण, संस्कृति व पर्यटन समिति	सविता महतो
सामान्य प्रायोजन समिति	डॉ नीरा यादव
आंतरिक संसाधन व केंद्रीय सहायता समिति	डॉ रामेश्वर उरांव
खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले समिति	विकास कुमार मुंडा

आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर प्रमुख जन गोष्ठी

संघ केवल संगठन नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है : आंबेकर

प्रमुख संवाददाता, रांची

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि वर्ष 1925 में विजयादशमी के अवसर पर एक छोटे से प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ संघ आज विशाल सामाजिक-सांस्कृतिक शक्ति के रूप में विकसित हो चुका है. आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही पूरे देश में उसके कार्य और विचार को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है. संघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि यह एक अनुभूति का विषय है. श्री आंबेकर बुधवार को संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम रांची) में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे.

श्री आंबेकर ने कहा कि संघ को शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त करना कठिन है, इसे अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है. उन्होंने संघ के संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन और उनके राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन किया. डॉ हेडगेवार ने अपने जीवन के अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की पराधीनता का मुख्य कारण समाज की असंगठित स्थिति थी. जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजित समाज को संगठित किये बिना राष्ट्र की स्वतंत्रता और उन्नति संभव नहीं है. इसी विचार के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य समाज को संगठित करना और राष्ट्र को सशक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि संघ ने व्यक्ति निर्माण को केंद्र में रखा है. शाखा के माध्यम से अनुशासन, संस्कार, समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना विकसित की जाती है. आज देशभर में हजारों शाखाएं संचालित हो रही हैं. उन्होंने संघ के पंच परिवर्तन के संकल्प का विस्तार से उल्लेख किया. प्रांत संपर्क प्रमुख राजीव कमल बिष्टू ने गोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला.

कार्यक्रम में बोलते सुनील आंबेकर.

कार्यक्रम में ये हुए शामिल

मौके पर प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा, रांची महानगर संघचालक पवन मंत्री, आइआइएम के निदेशक दीपक श्रीवास्तव, साईं नाथ विवि के कुलपति प्रो एसपी अग्रवाल, डॉ गोपाल पाठक, सुनील बादल, सुमन श्रीवास्तव, संजय कुमार, डॉ अजीत सिन्हा, डॉ रश्मि, डॉ जिज्ञासा ओझा, जेयूटी के कुलपति डॉ डीके सिंह व संघ के मंटू कुमार मौजूद थे.

सहकारिता बैंक में सीइओ के लिए तीन नाम भेजे गये

रांची. झारखंड सहकारिता बैंक में सीइओ के पद पर पदस्थापन के लिए तीन नामों की अनुशंसा की गयी है. इंटरव्यू बोर्ड ने तीन लोगों की सूची आरबीआइ, मुंबई को भेजा है. इसमें एक नाम पर अंतिम निर्णय होगा. बैंक में सीइओ की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष विभा सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी थी. कमेटी ने प्रदीप कुमार लाल, राजेश वाजपेयी और संजोई बनर्जी के नाम की अनुशंसा की है. रिजर्व बैंक इन्हीं में से एक नाम पर विचार करेगा. आरबीआइ 90 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय लेगा. मई 2025 से सीइओ का पद खाली है.

अंतिम दिन लटक गया 63 करोड़ का भुगतान

रांची. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व पीएम जन मन योजना के करीब 63 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन फंस गये. इस राशि का भुगतान नहीं हो सका. ऐसे में राशि सरेंडर हो गयी. विभाग को यह राशि भुगतान के लिए मिली थी. राशि का आवंटन भी विलंब से हुआ था. इसमें केंद्र व राज्य दोनों का शेयर था. इंजीनियरों ने बताया कि सामान्य स्थिति में इस मद की राशि सरेंडर नहीं होती है, लेकिन आवंटन विलंब व एसएनए स्पर्श के कारण मामला फंस गया.

असम अब पूछ रहा है-हमारा हक और पहचान कब : हेमंत

असम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन.

विशेष संवाददाता, रांची

- असम चुनाव में हेमंत सोरेन के साथ मैदान में उतरीं कल्पना
- कल्पना ने चाय बागान मजदूरों के साथ चाय की पत्ती तोड़ी

असम विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का साथ देने अब कल्पना सोरेन भी मैदान में उतर गयीं है. दोनों अलग-अलग इलाकों में प्रचार अभियान में जुटे हैं. हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई के बोगापानी टी स्टेट में बुधवार को एक सभा की. उन्होंने कहा कि जनसभा में मिला जनसमर्थन बता रहा है कि चाय बागान का समाज अब जाग चुका है. जैसे ही मैं आपके बीच पहुंचा हूं, सत्ता में बेचैनी बढ़ गयी है. सीएम ने कहा कि सालों तक आपको वोट बैंक समझा गया. अब जब आप हक, सम्मान और एसटी दर्जे की बात कर रहे हैं, तो सबको जमीन पर आना पड़ रहा है. असम अब पूछ रहा है-हमारा हक कब? हमारी पहचान कब? सीएम ने सभा के पूर्व असम के लोकगायक भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि दी.

आपका अधिकार दिलाना हमारी जिम्मेदारी : कल्पना

कल्पना ने चबुआ विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी भूबेन मुरारी के पक्ष में वोट मांगा. उन्होंने सांसद जोबा मांझी के साथ चबुआ विधानसभा स्थित चाय बागान में कार्यरत मजदूरों से बातचीत की. कल्पना ने मजदूरों के साथ चाय की पत्ती भी तोड़ी. कल्पना ने कहा कि आपका संघर्ष ही हमारी पहचान है और आपका अधिकार दिलाना हमारी जिम्मेदारी. मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि आपके सम्मान, आपके अधिकार और आपके भविष्य के लिए हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं.

टैक्स से 97 हजार करोड़ मिलने का अनुमान

रांची. राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2026-27 में टैक्स से करीब 97 हजार करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. राज्य वित्त आयोग ने इसका चार फीसदी निकायों पर खर्च करने की अनुशंसा की है. आयोग ने अपनी रिपोर्ट से राज्य सरकार को अवगत कराया है. आयोग की अनुशंसा लागू होने पर शहरी स्थानीय निकायों को करीब 1555 करोड़ और पंचायती राज संस्थाओं को 2333 करोड़ रुपये मिलेंगे. आयोग ने दूसरी रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट के मुकाबले शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को कम राशि देने की अनुशंसा की है. आयोग ने पहली रिपोर्ट में राज्य को अपने टैक्स और नन-टैक्स में से पांच प्रतिशत राशि देने की अनुशंसा की थी. सरकार ने पहली रिपोर्ट पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को सिर्फ टैक्स में चार प्रतिशत की हिस्सेदारी देने का फैसला किया था. राज्य वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में सरकार को सिर्फ टैक्स में चार प्रतिशत हिस्सेदारी देने की अनुशंसा की है.सरकार ने आयोग की अनुशंसा लागू करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.

झारखंड में 72 हजार करोड़ खर्च, कई विभाग लक्ष्य से दूर

प्रमुख संवाददाता, रांची

- बजट का 78 .68% ही उपयोग हुआ, कुछ विभागों ने लक्ष्य पार किया, तो कई रहे फिसड्डी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्त होते ही राज्य सरकार के योजनागत खर्च की तस्वीर साफ हो गयी है. जारी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार 91,741.53 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 72,183.65 करोड़ रुपये (78.68%) ही खर्च हो सके. वहीं, संशोधित अनुमान 95,019.67 करोड़ रुपये के मुकाबले यह खर्च 75.97 प्रतिशत रहा. कई विभाग निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके.

इन विभागों का बेहतर प्रदर्शन : ऊर्जा विभाग ने 98.56 प्रतिशत खर्च कर बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि जल संसाधन विभाग ने 101.88 प्रतिशत खर्च कर लक्ष्य को पार कर लिया. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 137 प्रतिशत से अधिक खर्च कर संशोधित अनुमान से भी अधिक व्यय किया. वहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 145 प्रतिशत से अधिक खर्च कर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 20,281.78 करोड़ रुपये (92.19%) खर्च किये. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 83.92 प्रतिशत राशि खर्च की.

कई विभाग पीछे : कई महत्वपूर्ण विभाग खर्च के मामले में पीछे रह गये. ग्रामीण विकास विभाग ने 45.85 प्रतिशत राशि ही खर्च किया. वहीं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 33 प्रतिशत, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग 31.60 प्रतिशत और वाणिज्य कर विभाग 31.90 प्रतिशत राशि ही खर्च कर पाये. वहीं, परिवहन विभाग केवल 8.69 प्रतिशत राशि खर्च कर फिसड्डी रहा. यह आंकड़ा विभागीय कार्यप्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करता है.

झारखंड

रामगढ़ के राधा गोविंद विवि में नहीं होगी जेइइ मेंस की परीक्षा

वरीय संवाददाता, रामगढ़

राधा गोविंद विवि, रामगढ़ में दो से आठ अप्रैल तक होनेवाली जेइइ मेंस की परीक्षा अब इस केंद्र में नहीं होगी. यह जानकारी टीसीएस (हीरानंदानी मुंबई हेड क्वार्टर) के परीक्षा संचालक ने एक अप्रैल को विवि के कुलसचिव डॉ निर्मल कुमार मंडल को इमेल भेज कर दी है. टीसीएस ने यह निर्णय 29 मार्च को राधा गोविंद विवि केंद्र में कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ का मामला उजागर होने के बाद लिया है. इस संबंध में रामगढ़ थाना में मामला भी दर्ज किया गया है.

विवि में 29 मार्च को कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने की घटना सामने आयी थी. कुलसचिव

टीसीएस ने लिया निर्णय

डॉ निर्मल कुमार मंडल के आवेदन पर छह लोगों को नामजद और अज्ञात पर मामला दर्ज कराया गया है. तीन नामजद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब पुलिस ने 70 कंप्यूटर, एक वाहन व तीन मोबाइल भी जब्त किये थे. रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से एनटीए और टीसीएस को घटना की रिपोर्ट भेजी गयी है. इसके बाद टीसीएस ने उक्त फैसला लिया. राधा गोविंद विवि के कुलसचिव डॉ निर्मल कुमार मंडल ने बुधवार को कहा कि कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने वाले लोग टीसीएस के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे.

मेरी बेटी नक्सली नहीं, सरेंडर फर्जी : पिता

प्रतिनिधि, मनोहरपुर

- पश्चिमी सिंहभूम के छोटानागरा निवासी मंगरी होनहागा ने 30 मार्च को राउरकेला पुलिस के सामने किया था सरेंडर
- पिता ने आत्मसमर्पण पर उठाये सवाल बेटी को बचाने की लगायी गुहार
- गांव के युवक पर काम का झांसा देकर बेटी को फंसाने का लगाया आरोप

ओडिशा की राउरकेला पुलिस के पश्चिमी सिंहभूम जिले की छोटानागरा निवासी मंगरी होनहागा उर्फ मुगदी होनहागा (19 वर्ष) के आत्मसमर्पण के दावे पर परिजनों ने सवाल खड़े कर दिये हैं. मंगरी के पिता मंगल होनहागा और परिजनों ने सरेंडर को फर्जी बताया है. पिता ने बताया कि उनकी बेटी कभी भी नक्सली संगठन में शामिल नहीं थी. उसे साजिश के तहत फंसाया गया है. पिता ने बताया कि गांव का एक युवक फरवरी में उसे काम दिलाने के नाम पर बाहर ले गया था. अब उसे नक्सली बता कर ओडिशा में सरेंडर करा दिया गया है. उन्होंने मामले की जांच कर युवक के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी बेटी को वापस लाने की मांग की है. मालूम हो कि राउरकेला पुलिस ने मंगरी को नक्सली बताकर 30 मार्च को आत्मसमर्पण कराया है. मामले में 30 मार्च को राउरकेला पुलिस हेडक्वार्टर में डीआइजी ब्रजेश राय ने बताया था कि छोटानागरा थाना के दोलाइगाढ़ा के लेपटापी गांव निवासी महिला नक्सली मंगरी होनहागा जनवरी 2026 में कुमडीह में हुए मुठभेड़ में शामिल थी. वहां से जान बचाकर किसी तरह भाग निकली थी. वह केबलांग थाना क्षेत्र के बांको में हुए विस्फोटक लूट में भी शामिल थी.

मुठभेड़ के वक्त बहन के घर पर थी मंगरी : पुलिस के दावों को सिरे से खारिज करते हुए मंगरी के पिता मंगल ने बताया कि जिस वक्त कुमडीह में मुठभेड़ हुआ था, उनकी बेटी मंगरी अपनी बड़ी बहन रोइबारी बहंदा के घर मारंगपोंगा में रह रही थी. क्षेत्र में बढ़ते नक्सली खतरों के कारण ही उसे वहां भेजा गया था.

मंगरी ने कहा : नक्सलियों के लिए बनाती थी खाना, सात और साथी थे

राउरकेला. राउरकेला पुलिस के समक्ष सोमवार को सरेंडर करनेवाली मंगरी होनहागा ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए दोहराया कि वह नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के साथ जुड़ी थी. वह उस दस्ते की सदस्य थी, जिसमें सात और साथी थे. वह नक्सलियों के लिए खाना बनाने का काम करती थी. ओडिशा सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया. उधर, ओडिशा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी तरह की जांच प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद सरेंडर कराया गया है. ओडिशा सरकार की सरेंडर नीतियों का लाभ मंगरी को दिया जा रहा है.

> हमने सभी तरह की पूछताछ करने के बाद ही सरेंडर की प्रक्रिया को पूरा कराया है. मंगरी ने अपने साथियों के नाम बताये हैं, दस्ते का जिक्र किया है. हमारे पास सभी तरह के साक्ष्य हैं. ओडिशा सरकार की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर मंगरी ने सरेंडर किया और जिम्मेदार पुलिस होने के नाते हमने उसका सहयोग किया, ताकि वह मुख्यधारा से जुड़े.
>
> **नीतेश वाधवानी,** एसपी, राउरकेला

अपहरण केस में मेदिनीनगर से आठ अपराधी हुए गिरफ्तार

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

- शहर के एक नेता ने पांच लाख में दी थी हत्या की सुपारी, 15 कारतूस व एसयूवी बरामद

मेदिनीनगर पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र से अपहरण की कोशिश के मामले में आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों में शहर के कसाई मोहल्ला का सद्दाम कुरैशी व वसीम अहमद, भट्टी मोहल्ला का छोटू चंद्रवंशी, रौशन चंद्रवंशी, किशु गुप्ता, बेलवाटिका का सूरज चंद्रवंशी, पनेरी गली कुंड मोहल्ला का रितेश चंद्रवंशी व पहाड़ी मोहल्ला का वसीम अकरम शामिल है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि आरोपी सद्दाम कुरैशी के पास से नाइन एमएम का पिस्टल व दो कारतूस, वसीम अकरम के पास से एक देसी कट्टा व दो कारतूस, रौशन चंद्रवंशी के पास से तीन कारतूस, रितेश चंद्रवंशी के पास से तीन कारतूस, वसीम अहमद के पास से तीन कारतूस व सूरज चंद्रवंशी के पास से दो कारतूस बरामद किये गये हैं.

स्कॉर्पियो से जिले से बाहर भागने की फिराक में थे सभी : एसपी ने बताया कि सोमवार को भट्टी मोहल्ला के पास सद्दाम कुरैशी व उसके साथियों ने आनंद कुमार रवि का अपहरण करने की कोशिश की थी. लेकिन विरोध करने पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घटनास्थल पर काफी लोगों के जमा होने के बाद अपराधी उसे छोड़ भाग गये. इसके बाद शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था.

क्रिकेटर वैभव के पिता परिवार संग पहुंचे देवघर

देवघर. क्रिकेट की दुनिया में तेजी से उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के परिवार ने बुधवार को बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी, मां आरती सूर्यवंशी, बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी और छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी मंदिर पहुंचे. मंदिर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती मंदिर में दर्शन-पूजन संपन्न कराया गया. पूजा के बाद पूरे परिवार ने सामूहिक आरती कर वैभव की सफलता और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. मौके पर वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने भावुक होकर कहा कि बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्हें जमीन तक बेचनी पड़ी, लेकिन आज वैभव के शानदार प्रदर्शन और लोगों के प्यार ने पूरे परिवार को नयी पहचान दिलायी है. यह भी कहा कि छोटा बेटा भी क्रिकेट में अच्छा कर रहा है.

झॉलीवुड. 16-17 अप्रेल से शुरू होगी शूटिंग, धालभूमगढ़ निवासी कृष्णा सोरेन हैं फिल्म के निर्माता-निर्देशक

दो करोड़ से बनेगी सबसे महंगी संताली हॉरर फिल्म 'चुड़किन'

- संताली फिल्म में पहली बार दिखेगा हॉलीवुड एक्टर
- धालभूमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में होगी शूटिंग

दशमत सोरेन, जमशेदपुर

झॉलीवुड (झारखंड सिनेमा) अब वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. चर्चित फिल्म "सुंडी" की अपार सफलता के बाद "सांवता स्टूडियोज" और "सफेद हाथी मोशन पिक्चर्स" ने अपने नये मेगा प्रोजेक्ट "चुड़किन" की घोषणा कर दी है. यह फिल्म संताल समुदाय की पौराणिक कथाओं, परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित "फोल्क हॉरर" होगी, जो क्षेत्रीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है. इसे दो करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो सबसे महंगी संताली सिनेमा होगी. झॉलीवुड के निर्माता-निर्देशकों के अनुसार, अबतक की सबसे महंगी संताली फिल्म "चांदो लिखोन" व "सीतानाला रे सगुन सुपड़ी" है, जिसे करीब 25-30 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था. इसकी शूटिंग धालभूमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में होगी.

लोक कथाओं को पर्दे पर उतारेंगे कृष्णा

पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड के सुंडीसोन निवासी और चर्चित फिल्म निर्माता- निर्देशक कृष्णा सोरेन इस फिल्म को बनायेंगे. उन्होंने बताया कि "चुड़किन" की कहानी किसी रटे-रटाए फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि गांवों की उन सदियों पुरानी कहानियों से जुड़ी है, जो जनमानस में गहराई से रची-बसी है. फिल्म की शूटिंग 16-17 अप्रैल से शुरू होगी. इसे झारखंड के घने जंगलों और दूर-दराज के गांवों में फिल्माया जाएगा, जहां की भौगोलिक स्थिति सस्पेंस के एक जीवंत पात्र के रूप में नजर आएगी. कृष्णा सोरेन मराठी और हिंदी में 60 फिल्मों का निर्माण कर चुके है. कृष्णा अभी मुंबई में रह कर काम कर रहे हैं.

इन फिल्मों में किया है काम

डियर मॉली (2018), पिंपल (2018), नीलकंठ मास्टर (2015), द साइलेंस (2015), बायोस्कोप (2014), साजिंदे, गोदाकाथ, सुंडी, घरवाली फिलिंग, लव लगान लोचा, सरदार दी गेम चेंजर, पारो, श्रीमति अंब्रेला समेत 60 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य किया है.

हॉलीवुड एक्टर की एंट्री : इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव होगा. निर्माता एक "इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम" के माध्यम से फिल्म में एक हॉलीवुड अभिनेता को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं. यदि यह संभव हुआ, तो संताली सिनेमा के इतिहास में पहली बार होगा, जब कोई विदेशी कलाकार झारखंड की माटी से जुड़ी कहानी का हिस्सा बनेगा.

जंप स्केयर्स नहीं, माहौल से पैदा होगा खौफ : निर्देशक कृष्णा सोरेन के अनुसार, "चुड़किन" पारंपरिक डरावनी फिल्मों से अलग होगी. इसमें डर पैदा करने के लिए महज चौंकाने वाले दृश्यों का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि फिल्म के माहौल, ध्वनि प्रभाव और लोक-बिंबों के जरिए दर्शकों के मन में सिहरन पैदा की जाएगी.